

भारतीय रिज़र्व बैंक  
**बुलेटिन**



सितंबर 2025

खंड 79 अंक 9

संपादक समिति  
इंद्रनील भट्टाचार्य  
अनुजित मित्रा  
रेखा मिश्र  
अनुपम प्रकाश  
सुनील कुमार  
स्नेहल हेरवाडकर  
पंकज कुमार  
वी. धन्या  
श्वेता कुमारी  
अनिर्बन सान्याल  
सुजाता कुंडू

संपादक  
आशीष थॉमस जॉर्ज

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित आलेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2025

सर्वाधिकार सुरक्षित।  
सामग्री के पुनः उत्पादन की अनुमति है,  
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन की सदस्यता के लिए कृपया 'हाल के प्रकाशन' खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को  
<https://bulletin.rbi.org.in> पर देखा जा सकता है।

# विषय-वस्तु

## भाषण

नवाचार और विवेक को संतुलित करना- भारत के वित्तीय भविष्य में एआई की भूमिका श्री एम राजेश्वर राव	1
---	---

## आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति	9
वर्ष 2024-25 के दौरान भारत के वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह	43
फिनटेक ग्राहकों के अनुभव की अनकही कहानी	53
एनबीएफसी क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा	67
नकदी मांग पर यूपीआई का प्रभाव - राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर से साक्ष्य	79
क्या उपभोग असमानता घट रही है? - 2022-23 का एनएसएसओ सर्वेक्षण हमें क्या बताता है	97
अवसंरचना - भारत की विकास एक्सप्रेस का एक इंजन	107

वर्तमान सांख्यिकी	127
-------------------	-----

हाल के प्रकाशन	181
----------------	-----



## भाषण

नवाचार और विवेक को संतुलित करना- भारत के वित्तीय भविष्य में एआई की भूमिका  
श्री एम राजेश्वर राव



# नवाचार और विवेक को संतुलित करना- भारत के वित्तीय भविष्य में एआई की भूमिका\*

श्री एम राजेश्वर राव

विशिष्ट अतिथिगण, प्रतिभागियों, देवियों और सज्जनों, एक बहुत बहुत शुभ संध्या।

मुझे बैंकिंग परिवर्तन शिखर सम्मेलन में 'बैंकिंग डैट बिल्ड भारत: एआई-पावर्ड, क्रेडिट-ड्रिवेन' विषय पर वित्तीय क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और प्रमुख हितधारकों की इस सभा को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है, जो अत्यंत उचित और प्रासंगिक है और विकसित भारत की भावना को समाहित करता है।

## परिचय

भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने समय-समय पर नई तकनीकों को अपनाने और अनुकूलित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। 1980 के दशक में कम्प्यूटरीकरण के शुरुआती दिनों से शुरू होकर, 1990 के दशक में एटीएम के प्रसार तक, 2000 के दशक में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का विस्तार, 2010 के दशक से भुगतान के लिए अंतर-संचालित बुनियादी ढांचे, डेटा रिपॉजिटरी और डेटा साझाकरण के लिए, बैंकिंग क्षेत्र ने बदलते समय की आवश्यकताओं के लिए सफलतापूर्वक अनुकूलन किया है और इस अवधि के साथ बैंकिंग को अधिक कुशल और समावेशी बना दिया है। बैंकिंग अब डिजिटल लोकतंत्रीकरण द्वारा संचालित विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। इसका एक प्रमुख उदाहरण घरेलू एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) है, जिसने भारत को डिजिटल भुगतान में एक वैश्विक लीडर बना दिया है जो हमारे विश्वास को पुष्ट करता है कि जिम्मेदार नवाचार प्रगति का एक शक्तिशाली वाहक हो सकता है।

\* 16 सितंबर 2025 को मुंबई में 'बैंकिंग डैट बिल्ड भारत: एआई-पावर्ड क्रेडिट-ड्रिवेन' पर सीएनबीसी-टीवी18 बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन सम्मेलन के तीसरे संस्करण में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव द्वारा दिया गया मुख्य भाषण। चांदनी त्रेहन सलूजा और अभिषेक कुमार नरवाल द्वारा प्रदान की गई जानकारी के हम आभारी हैं।

भारत सरकार ने "विकसित भारत" यानी 2047 तक भारत को एक विकसित देश में बदलने का एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण व्यक्त किया है। यह वित्तीय क्षेत्र और विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र में हमारी तकनीकी यात्रा में अगले कदम के लिए मार्ग बनाता है। विकसित भारत के तहत, प्रत्येक वयस्क के लिए लक्ष्य न केवल एक बैंक खाता होना है, जो बड़े पैमाने पर जन धन योजना<sup>1</sup> के तहत हासिल किया गया लक्ष्य है, बल्कि किरायायती ऋण, बीमा और निवेश विकल्पों तक भी पहुंच है। बैंकिंग क्षेत्र का प्रयास यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि बैंकिंग के लाभ, विशेष रूप से ऋण पहुंच के लाभ, सभी क्षेत्रों के ग्राहकों को निष्पक्ष, पारदर्शी और किरायायती आधार पर उपलब्ध कराए जाएं।

## आरबीआई द्वारा किए गए उपाय

पिछले पांच वर्षों में, वर्ष 2019-20 से 2024-25 के बीच, बैंक ऋण वृद्धि औसतन लगभग 10.5 प्रतिशत रही है। यह भी देखा गया है कि खुदरा ऋण का हिस्सा 33 प्रतिशत<sup>3</sup> तक बढ़ गया है, जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है, जो मार्च 2025 तक कुल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत है। नई प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर विचार करने से पहले, मैं ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों पर संक्षेप में बात करना चाहता हूं।

आरबीआई ने घर्षण को कम करके, पहुंच बिंदुओं को बढ़ाकर और वित्तीय सेवा वितरण की लागत को कम करके ऋण की पहुंच और गहराई दोनों का विस्तार करने के लिए कई उपाय किए हैं।<sup>4</sup> प्रमुख पहलों में आधार-आधारित केवाईसी, केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री, संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंड, आंशिक ऋण वृद्धि दिशानिर्देश और खाता एग्रीगेटर ढांचा शामिल हैं। ऋण के बढ़ते डिजिटलीकरण के जवाब में, व्यापक क्षेत्रों में धन प्रवाह

<sup>1</sup> खाते वर्ष 2015 में 14.72 करोड़ से बढ़कर अगस्त 2025 तक 56.16 करोड़ से अधिक हो गए हैं, जिसमें लगभग 67 प्रतिशत ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 33 प्रतिशत जन धन खाते शहरी/मेट्रो में खोले गए हैं - <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155102&ModuleId=3> क्षेत्र।

<sup>2</sup> भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, 2024-25 – सारणी 44 - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक – चुनिंदा समुच्चय- समायोजित बैंक ऋण (28 जुलाई 2023 से बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर)।

<sup>3</sup> भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, 2024-25 – सारणी 45 - गैर-खाद्य सकल बैंक ऋण की क्षेत्रीय तैनाती - गैर-समायोजित व्यक्तिगत ऋणों का हिस्सा।

को सक्षम करते हुए पारदर्शिता, निष्पक्षता, डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल ऋण दिशानिर्देश<sup>4</sup> पेश किए गए थे। आरबीआई ने एमएसएमई के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस), बैंकों और एनबीएफसी के बीच सह-ऋण मॉडल और लक्षित पुनर्वित्त योजनाओं जैसे ढांचे के माध्यम से औपचारिक ऋण पहुंच को भी सक्षम किया है।

हाल ही में, आरबीआई ने अपनी सहायक कंपनी आरबीआई इनोवेशन हब (आरबीआईएच) के सहयोग से, ऋणदाताओं को निर्बाध डिजिटल डेटा प्रवाह को सक्षम करने के लिए फ्रिक्शनलेस क्रेडिट<sup>5</sup> के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के एक प्रोटोटाइप का परीक्षण किया है। इस पर आधारित, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई)<sup>6</sup> को वित्तीय और गैर-वित्तीय डेटा जैसे डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) डेटा, संपत्ति रिकॉर्ड और उपग्रह डेटा के साथ-साथ ई-केवाईसी, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) जैसी सेवाओं तक पहुंच को एकीकृत करके क्रेडिट डिलीवरी को बदलने के लिए विकसित किया जा रहा है। इस इकोसिस्टम का उद्देश्य कम सेवा वाले सेगमेंट के लिए ऋण को तेज, सस्ता और अधिक सुलभ बनाना है। साथ में, यह डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और एक सक्षम विनियामक ढांचा समावेशी ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

### औपचारिक ऋण तक पहुंच में अंतराल

ऐसा कहने के बाद, अभी भी बहुत दूरी तय करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रेडिट प्रवेश में अंतर बना हुआ है। आज भी, भारत की लगभग 25 प्रतिशत वयस्क आबादी के पास संस्थागत ऋण तक औपचारिक पहुंच है, जबकि एमएसएमई क्षेत्र (जो सकल घरेलू उत्पाद का ~ 30 प्रतिशत है)<sup>7</sup> में, उनकी ऋण जरूरतों का केवल एक हिस्सा औपचारिक संस्थानों द्वारा पूरा किया जाता है। जबकि आरबीआई द्वारा विकसित वित्तीय

समावेशन सूचकांक में लगातार सुधार हुआ है, जो मार्च 2021 में 53.9 से बढ़कर मार्च 2025<sup>11</sup> में 67.0 हो गया है, जो खाता स्वामित्व और ऋण पहुंच में वृद्धि को दर्शाता है। समावेशन और ऋण पहुंच के बीच का अंतर बैंकिंग समूहों के लिए एक चुनौती और अवसर है। ऋण को न केवल मात्रा और संख्या के संदर्भ में बढ़ने की आवश्यकता है, बल्कि इसे उत्पादक, एमएसएमई, बुनियादी ढांचे, अनौपचारिक क्षेत्रों और ग्रामीण आबादी जैसे उच्च गुणक प्रदान करने वाले क्षेत्रों की ओर भी निर्देशित करने की आवश्यकता है, ताकि न केवल "विकसित भारत" के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके बल्कि "समावेशी विकसित भारत" भी प्राप्त किया जा सके।

### बैंकिंग में नई लहर- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

अगली क्रेडिट क्रांति को चलाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। समय के साथ, वित्त में प्रौद्योगिकी की भूमिका परिचालन दक्षता में सुधार से पहले मैनुअल, खंडित प्रक्रियाओं को पूरी तरह से स्वचालित और केंद्रीकृत करने में स्थानांतरित हो गई है। उभरती प्रौद्योगिकियों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आंतरिक संचालन और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने से लेकर तेज, अधिक सहज ग्राहक अनुभव प्रदान करने तक अपनी विशाल क्षमता के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि भारत में लगभग 70% बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (बीएफएसआई) संगठनों के पास वित्तीय वर्ष 2024-25 में एंटरप्राइज लेवल एआई कार्यनीति है। बैंकों की वार्षिक रिपोर्टों के आरबीआई के एक अध्ययन से भी एआई के संदर्भ में तेज वृद्धि देखी गई है, जो इसके बढ़ते कार्यनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। जबकि मांग-पक्ष कारक (लाभप्रदता, प्रतिस्पर्धा, अनुपालन दक्षता) और आपूर्ति-पक्ष वाहक (तकनीकी प्रगति, डेटा वृद्धि, नए व्यवसाय मॉडल) एआई अपनाने को प्रभावित करते हैं, आपूर्ति-पक्ष बल प्राथमिक उत्प्रेरक बने रहते हैं।

<sup>4</sup> <https://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Mode=0&Id=10598>

<sup>5</sup> <https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12848&Mode=0>

<sup>6</sup> [https://rbi.org.in/scripts/BS\\_PressReleaseDisplay.aspx?prid=56200](https://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=56200)

<sup>7</sup> <https://rbi.org.in/unified-lending-interface/>

<sup>8</sup> <https://newsroom.transunioncibil.com/more-than-160-million-indians-are-credit-underserved/>

<sup>9</sup> <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2142170>

<sup>10</sup> [https://www.sidbi.in/uploads/Understanding\\_Indian\\_MSME\\_sector\\_Progress\\_and\\_Challenges\\_13\\_05\\_25\\_Final.pdf](https://www.sidbi.in/uploads/Understanding_Indian_MSME_sector_Progress_and_Challenges_13_05_25_Final.pdf)

<sup>11</sup> [https://www.rbi.org.in/scripts/FS\\_PressRelease.aspx?prid=60875&fn=2754](https://www.rbi.org.in/scripts/FS_PressRelease.aspx?prid=60875&fn=2754) दिनांक 22 जुलाई 2025

<sup>12</sup> नैसकॉम एआई एडॉप्शन इंडेक्स - भारत]

<sup>13</sup> आरबीआई बुलेटिन – भारतीय बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे अपना रहे हैं? [https://rbi.org.in/Scripts/BS\_ViewBulletin.aspx?Id=22931]



एक अनुशासन के रूप में एआई दशकों में विकसित हुआ है और इसने मशीन लर्निंग सिस्टम का उदय देखा है जो ऐतिहासिक डेटा से अक्सर उच्च सटीकता के साथ निर्णय लेने के लिए सीख सकते हैं। भारतीय बैंकों और गैर-बैंकों ने लगभग एक दशक पहले एआई यात्रा शुरू की थी, मुख्य रूप से उस समय बड़ी मात्रा में सूचना और पूरक विश्लेषण को संभालते थे, जो स्थापित प्रणालियों को विस्थापित किए बिना मूल्य जोड़ते थे। तब से इसे अपनाने की प्रक्रिया दक्षता बढ़ाने के लिए बैंक-ऑफिस कार्यों के लिए एआई की तैनाती से लेकर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, आईटी संचालन को अनुकूलित करने, केवाईसी के लिए चेहरे की पहचान, क्रेडिट स्कोरिंग, दावा प्रसंस्करण और ग्राहक केंद्रित सेवाओं जैसे अधिक विविध उपयोग के मामलों में स्थानांतरित हो गई है। जैसा कि 2023 और 2024<sup>14</sup> में आरबीआई द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में देखा गया है, तीन-चौथाई से अधिक बैंकों ने ग्राहक सेवा के लिए एआई-संचालित चैटबॉट तैनात किए हैं। यह एक मौलिक बदलाव का प्रतीक है जिसमें एआई अब केवल एक प्रवर्तक नहीं है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, उत्पाद डिजाइन और ग्राहक जुड़ाव का एक हिस्सा है।

### क्रेडिट जीवनचक्र में एआई

हालांकि, बैंक ऋण देने के कुछ क्षेत्रों में एआई का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट जीवनचक्र के अन्य क्षेत्रों में इसके उपयोग के लिए संभावित उपयोग के मामले हैं। मैं उनमें से कुछ पर प्रकाश डालना चाहूंगा:

#### (i) ऋण समावेशन

एक महत्वपूर्ण उपयोग का मामला क्रेडिट का मूल्यांकन और वितरण करने के तरीके में होगा। इसके लिए व्यापक डेटा आधारित और अधिक परिष्कृत विश्लेषण के साथ मौजूदा मूल्यांकन विधियों को पूरक करने की आवश्यकता होगी, जिससे वित्तीय संस्थान संभावित उधारकर्ताओं के जोखिम और क्षमता पर अतिरिक्त दृष्टिकोण प्राप्त कर सकें। यह लाखों "क्रेडिट अदृश्य" की क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण गेम चेंजर होगा, यानी, बिना औपचारिक क्रेडिट इतिहास वाले या क्रेडिट ग्राहकों के लिए नए लोग। ग्राहकों के पास विभिन्न प्रकार

के डिजिटल फुटप्रिंट की उपलब्धता को देखते हुए, एआई का लाभ वैकल्पिक डेटा स्रोतों को पढ़ने के लिए, उनकी साख का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब होगा कि आर्स्टि-आधारित ऋण से नकदी-प्रवाह और वैकल्पिक डेटा-आधारित ऋण में एक आदर्श बदलाव, समावेशी डिजिटल वित्त की दिशा में एक यात्रा को बढ़ावा देगा। भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक डेटा की क्षमता को भी पहचाना है और "ग्रामीण क्रेडिट स्कोर"<sup>15</sup> जैसी पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य यूपीआई लेनदेन, सरकारी सब्सिडी प्राप्ति और उपयोगिता भुगतान सहित वैकल्पिक वित्तीय डेटा का विश्लेषण करके औपचारिक ऋण पहुंच प्रदान करना है।

#### (ii) टर्नअराउंड समय

एआई बैंकों को बड़ी मात्रा में ग्राहक डेटा को जल्दी से संसाधित करने में सक्षम बनाता है, जिससे क्रेडिट निर्णय और सेवा वितरण में तेजी आती है। यह एमएसएमई कार्यशील पूंजी जैसे समय-संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष रूप से मूल्यवान है, जहां एआई बैंक स्टेटमेंट, भुगतान इतिहास, जीएसटी फाइलिंग, ई-चालान, टीआरडीईएस प्राप्ति और सार्वजनिक रिकॉर्ड जैसे विविध डेटासेट का विश्लेषण कर सकता है। यह ऋणदाताओं को मौसमी, आपूर्ति शृंखला, इन्वेंट्री चक्र, ग्राहक एकाग्रता और एमएसएमई की समग्र साख का आकलन करने में भी सहायता करता है।

#### (iii) ऋण मूल्यांकन

बैंक साख और स्थिर वित्तीय व्यवहार के संकेत देने वाले पैटर्न का पता लगाने के लिए बड़ी मात्रा में लेन-देन संबंधी डेटा का विश्लेषण करके व्यवहार विश्लेषण का लाभ उठाने के लिए एआई एल्गोरिदम को अपना सकते हैं, जिससे अधिक सटीक क्रेडिट आकलन और बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रिया हो सके।

#### (iv) स्वनिर्धारित ऋण समाधान

ग्राहकों की प्राथमिकताओं और व्यवहार का गतिशील रूप से आकलन करने की एआई की क्षमता बैंकों को किसी व्यक्ति की वित्तीय क्षमता के अनुरूप अनुकूलित क्रेडिट समाधान प्रदान करने के लिए सशक्त बना सकती है। यह न केवल ऋण पहुंच में सुधार करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि

<sup>14</sup> भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट - 2023-24 (अध्याय IV का पैरा 10)

<sup>15</sup> <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112198>

उधारकर्ताओं को उचित और संरचित वित्तीय उत्पाद प्राप्त हों जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

#### (v) पूर्व चेतावनी संकेत और प्रावधान

एआई-आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ऋणदाताओं को गतिशील जोखिम स्कोरिंग और वास्तविक समय चूक संभाव्यता ट्रेकिंग के माध्यम से क्रेडिट पोर्टफोलियो की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने में मदद कर सकती है। वित्तीय तनाव के शुरुआती संकेतों को चिह्नित करके, ये सिस्टम उधारकर्ताओं को कोर्स-करेक्ट करने का मौका देते हुए ऋणदाता के तुलन-पत्र की रक्षा करते हैं। अंततः, लक्ष्य केवल अधिक उधार देना नहीं है, बल्कि बेहतर उधार देना है।

#### (vi) दस्तावेज प्रबंधन

एआई दस्तावेजों से जानकारी को पढ़ने और संसाधित करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) जैसी तकनीकों का उपयोग करके दस्तावेज सत्यापन को स्वचालित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है - विशेष रूप से हस्तलिखित दस्तावेज जो आम तौर पर असंरचित होते हैं, जिससे डेटा के स्वचालित निष्कर्षण की अनुमति मिलती है और इस प्रकार अस्वीकृति कम हो जाती है। यह जालसाजी, छेड़छाड़ या संशोधनों का पता लगाने के लिए दस्तावेजों की दृश्य विशेषताओं की भी जांच कर सकता है और बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड को सटीक रूप से संसाधित कर सकता है, प्रमुख डेटा को वर्गीकृत कर सकता है, निकाल सकता है और मान्य कर सकता है, जिससे दक्षता में सुधार होता है और ऋण देने की प्रक्रिया में त्रुटियों को कम किया जा सकता है।

#### (vii) ग्राहक सहायता और शिकायत निवारण

एआई का एक आशाजनक उपयोग मामला बहुभाषी चैटबॉट और वॉयस असिस्टेंट का विकास है जो ग्राहकों को उनकी मूल भाषा में बैंकों के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। यह एक क्रांतिकारी बदलाव है क्योंकि उपयोगकर्ता अनुभव को स्थानीयकृत करके, एआई विभिन्न भाषाओं, साक्षरता स्तरों और क्षमताओं में अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं का आत्मविश्वास से उपयोग करने में सक्षम बना सकता है।

बैंक एआई संचालित वर्चुअल असिस्टेंट का उपयोग करने के साथ भी प्रयोग कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों को ग्राहकों के प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम बनाया जा सके जो ग्राहक अनुभव को बढ़ा सकते हैं। ग्राहकों के प्रश्नों का समय पर समाधान बैंकिंग प्रणाली

में विश्वास बढ़ाता है और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाते हुए गहरे जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। जैसे-जैसे डिजिटल पहुंच का विस्तार हुआ है, वैसे-वैसे ग्राहकों की शिकायतें भी बढ़ी हैं। यह एआई के लिए एक और उपयोग के मामले पर प्रकाश डालता है। यह शिकायतों को कुशलतापूर्वक वर्गीकृत कर सकता है, प्राथमिकता दे सकता है और उन्हें रूट कर सकता है, पैटर्न का पता लगाकर और मुद्दों को शिकायतों में बदलने से पहले मूल कारणों को संबोधित करके तेजी से, सक्रिय समाधान को सक्षम कर सकता है।

#### (viii) ऋण सेवा

एआई-संचालित ऋण सर्विसिंग प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत पुनर्भुगतान समाधान बना सकते हैं और सर्विसिंग और पोर्टफोलियो प्रबंधन में परिचालन त्रुटियों को कम कर सकते हैं। वे प्राथमिकता वाली आउटरीच कार्यनीतियों के माध्यम से संग्रह और वसूली का समर्थन करके ऋण सेवा के नए तरीके भी प्रदान कर सकते हैं। एआई वसूली के लिए शुरू किए गए उपायों के ऑडिट योग्य ट्रेल्स के अनुपालन को मजबूत करने में मदद कर सकता है।

#### (ix) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और साइबर सुरक्षा

20. एआई वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा करने में भी क्षमता रखता है। जैसे-जैसे साइबर अपराधी परिष्कृत हमलों के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं, विनियमित संस्थाएं (आरई) ग्राहकों की सुरक्षा और खतरों का पता लगाने के लिए एआई-संचालित उपकरणों का लाभ उठा सकती हैं। एआई वास्तविक समय में बड़े लेनदेन की मात्रा की निगरानी कर सकता है, उन विसंगतियों को चिह्नित कर सकता है जो धोखाधड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने में सहायता कर सकते हैं।

#### क्रेडिट क्रांति के लिए सहयोग

फिनटेक तेजी से आगे बढ़ने के साथ, आरई क्रेडिट जीवनचक्र में उनके साथ तेजी से साझेदारी कर रहे हैं। एक प्रमुख मॉडल-डिजिटल लेंडिंग में केवाईसी, क्रेडिट मूल्यांकन और संग्रह जैसी प्रक्रियाओं को सीधे फिनटेक प्लेटफॉर्म में अंतर्निहित करना शामिल है। जबकि इस तरह के सहयोग वित्तीय समावेशन और नवाचार को बढ़ाते हैं, वे धुंधली जवाबदेही, डेटा दुरुपयोग, अपर्याप्त शिकायत निवारण और संभावित गलत बिक्री जैसे जोखिम भी लाते हैं। इसे संबोधित करने का मार्गदर्शक सिद्धांत यह आधार बना हुआ है कि उपयोग किए गए मॉडल की परवाह किए बिना, जवाबदेही अंततः विनियमित इकाई के पास है।

## एआई के जोखिम और चुनौतियाँ - नए आयाम और नैतिक अनिवार्यता

तकनीकी प्रगति चुनौतियों के साथ आती है जिन्हें आरई को पहचानना चाहिए, क्योंकि ये जोखिम नवाचार के लाभों को कमजोर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वीडियो-आधारित ई-केवाईसी पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले <sup>16</sup> ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनिवार्य स्वचालित प्रक्रियाएं विकलांग लोगों के लिए बाधाएं पैदा कर सकती हैं, बहिष्करण से बचने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने में निष्पक्षता और पहुंच की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। एआई, उचित नियंत्रण के बिना, एल्गोरिथम पूर्वाग्रह, पारदर्शिता की कमी, नैतिक चिंताओं और प्रणालीगत कमजोरियों जैसे जोखिम पेश कर सकता है। यह तीसरे पक्ष की निर्भरता, एकाग्रता, मॉडल, साइबर और डेटा गोपनीयता जोखिमों जैसे मौजूदा जोखिमों को भी बढ़ा सकता है। मैं कुछ पर प्रकाश डालता हूँ:

### (i) तृतीय-पक्ष निर्भरता

जैसे-जैसे एआई अपनाना बढ़ता है, वित्तीय संस्थान बाहरी प्रदाताओं, क्लाउड प्लेटफॉर्म, एआई विक्रेताओं और डेटा एग्रीगेटर के जटिल नेटवर्क पर भरोसा करते हैं। ये अन्योन्याश्रितताएं कमजोरियां पैदा करती हैं जहां एक लिंक में व्यवधान या उल्लंघन कई संस्थानों में फैल सकता है, जिससे महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित हो सकती हैं। इन परतों की जटिलता और अस्पष्टता से जोखिमों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, जो किसी का ध्यान नहीं जा सकता है और झटके के दौरान तेजी से फैल सकता है।

### (ii) बाजार सहसंबंध

एआई की एक महत्वपूर्ण भेद्यता इसकी वित्तीय प्रणाली में व्यवहारों को सिंक्रनाइज करने की क्षमता है। जब संस्थान ओवरलैपिंग डेटा पर प्रशिक्षित समान मॉडल का उपयोग करते हैं, तो आस्ति मूल्य निर्धारण, क्रेडिट मूल्यांकन, व्यापार और अन्य पर उनके निर्णय संरेखित हो सकते हैं, जिससे छिपे हुए संबंध बन सकते हैं। यह बाजार के तनाव को बढ़ा सकता है, तेजी से आघात फैला सकता है, चलनिधि की कमी को और बढ़ा सकता है, आस्ति की कीमत में अस्थिरता बढ़ा सकता है, और बाजार के अपने उतार-चढ़ाव को और बढ़ा सकता है।

<sup>16</sup> [https://api.sci.gov.in/supremecourt/2024/17879/17879\\_2024\\_13\\_1501\\_61229\\_Judgement\\_30-Apr-2025.pdf](https://api.sci.gov.in/supremecourt/2024/17879/17879_2024_13_1501_61229_Judgement_30-Apr-2025.pdf)

### (iii) साइबर जोखिम

वित्तीय प्रणालियों में एआई का एकीकरण - विशेष रूप से नई परस्पर विधियों और विशेष प्रदाताओं पर बढ़ती निर्भरता के माध्यम से साइबर खतरे के परिदृश्य को अप्रत्याशित तरीकों से विस्तारित करता है। एआई की ताकतें, जैसे बड़े डेटासेट पर निर्भरता, खुले इंटरफेस और स्वचालित निर्णय, भी कमजोरियां पैदा करती हैं। मैलीशियस एक्टर प्रतिकूल हमलों या समझौता किए गए प्रशिक्षण डेटा के माध्यम से इनका फायदा उठा सकते हैं, संभावित रूप से एआई आउटपुट को भ्रष्ट कर सकते हैं। यहां तक कि एक भी उल्लंघन कई आरई में महत्वपूर्ण संचालन को बाधित कर सकता है और पूरे क्षेत्र में एआई में विश्वास को कम कर सकता है।

### (iv) मॉडल जोखिम

स्पष्ट नियमों और अच्छी तरह से निर्धारित मान्यताओं पर निर्मित पारंपरिक मॉडलों के विपरीत, एआई मॉडल घने, अपारदर्शी एल्गोरिदम के माध्यम से काम करते हैं, जिसे हम "ब्लैक बॉक्स" भी कहते हैं और उनके द्वारा उपभोग किए जाने वाले डेटा के साथ विकसित होते हैं। यह उन मॉडलों के भीतर पूर्वाग्रह के जोखिम का परिचय देता है जहां पक्षपाती डेटा, अपारदर्शी डिजाइन, या अप्रयुक्त धारणाएं मॉडल के पक्षपाती परिणामों को जन्म दे सकती हैं। इस तरह की विकृतियों से अनुचित क्रेडिट मूल्यांकन हो सकता है, योग्य खंडों को छोड़कर, या इसके विपरीत ऋण का विस्तार किया जा सकता है जहां जोखिमों को कम करके आंका जाता है।

### (v) डेटा जोखिम

एआई केवल उतना ही मजबूत है जितना कि डेटा जो इसे आकार देता है और इससे डेटा गुणवत्ता से उत्पन्न होने वाली कई कमजोरियां पैदा होती हैं। वर्तमान में, जबकि अधिकांश वित्तीय डेटा संरचित हैं, इसका अधिकांश भाग सिस्टम में खंडित है, अक्सर असंगत प्रारूपों में, कभी-कभी अधूरा या पुराना, या ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों थोड़ा अलग होता है। जब ऐसा डेटा एआई मॉडल में प्रवाहित होता है, तो यह ऐसे परिणाम उत्पन्न कर सकता है जो प्रामाणिक लग सकते हैं, लेकिन उप-इष्टतम और कुछ मामलों में गलत आउटपुट उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे मॉडलों पर अत्यधिक निर्भरता चुपचाप डेटा अंतराल को बड़े पैमाने पर गलत निर्णयों और गलत व्यावसायिक निर्णयों में बदल सकती है।

### (vi) कानूनी निश्चितता और बौद्धिक संपदा अधिकार मुद्दे

एआई मॉडल को अक्सर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा, जैसे समाचार, लेख और व्याख्यात्मक वीडियो आदि पर प्रशिक्षित किया जाता है, और इससे बौद्धिक संपदा और कॉपीराइट उल्लंघन हो सकता है।

### (vii) एकाग्रता जोखिम

रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट<sup>17</sup> ने क्लाउड/एआई सेवाओं के महत्वपूर्ण तृतीय-पक्ष प्रदाताओं में उच्च बाजार संकेंद्रण की ओर इशारा किया है, यह देखते हुए कि तकनीकी खिलाड़ियों की एक छोटी संख्या पर भारी निर्भरता विफलता के एकल बिंदु पैदा कर सकती है। इस तरह के संकेंद्रण जोखिम कुछ प्रदाताओं के ऊर्ध्वाधर एकीकरण से जटिल होते हैं, जो न केवल मॉडल बल्कि अंतर्निहित बुनियादी ढांचे और डेटासेट की आपूर्ति भी करते हैं।

### (viii) धोखाधड़ी और दुष्प्रचार

जबकि एआई वित्तीय संस्थानों की कई प्रक्रियाओं को बदल रहा है, जनरेटिव एआई के उदय ने धोखाधड़ी की बाधाओं को भी कम कर दिया है, जिससे अनैतिक लोगों के हाथों में शक्तिशाली धोखे के साधन आ गए हैं। डीपफेक परेशान करने वाली सटीकता के साथ आवाजों, चेहरों और दस्तावेजों की नकल कर सकते हैं, जबकि एआई-जनित फ्रिशिंग लालच, नकली पहचान और जाली क्रेडेंशियल्स पारंपरिक चेक से आगे निकल सकते हैं।

इन बहुआयामी जोखिमों के आलोक में, जिनमें से कुछ के बारे में मैंने बात की है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि बैंकिंग क्षेत्र में एआई को एक जिम्मेदार और सीमित तरीके से अपनाया जाना चाहिए। एआई के लाभों के बारे में उत्साह को विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन पर हावी नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में, निम्नलिखित पहलू और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

### (i) शासन

डेटा की अखंडता, मॉडलों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और एआई को अपनाने से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एक मजबूत शासन अपरिहार्य है। वित्तीय संस्थानों के पास एआई अपनाने के लिए एक व्यापक कार्यनीति होनी चाहिए। इसके साथ स्पष्ट नीतियों, जोखिम की भूख, महत्वपूर्णता, और प्रभाव

आकलन के साथ-साथ नैतिक मानक भी होना चाहिए जो संगठन के माध्यम से चले आ रहे हैं। नवाचार लक्ष्यों और संस्थागत स्थिरता के बीच संरेखण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, बैंकिंग जैसे विनियमित उद्योग में, यह समझना आवश्यक है कि एक मॉडल अपने निर्णयों पर कैसे पहुंचता है, जिससे व्याख्या एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन जाती है। इस प्रकार, वित्तीय संस्थानों को व्याख्यात्मक एआई ढांचे में निवेश करने की आवश्यकता है जो ऋण निर्णयों के लिए स्पष्ट, ऑडिट योग्य कारण प्रदान करते हैं। एआई-संचालित मॉडल जोखिम के प्रबंधन के लिए मजबूत अभिशासन महत्वपूर्ण है।

### (ii) ह्यूमन-इन-द-लूप

जबकि एआई स्वचालित और अनुशंसा कर सकता है, मनुष्यों को निर्णयों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। वित्तीय संस्थानों को व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए एआई को अपनाते समय ह्यूमन-इन-द-लूप के सिद्धांत को लागू करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का उपयोग मानवीय निर्णयों का समर्थन करने और बढ़ाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाता है न कि उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए।

### (iii) डेटा की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखना

उच्च गुणवत्ता वाला डेटा वित्त में सुरक्षित और प्रभावी एआई की रीढ़ है। जबकि आरबीआई पहले से ही पर्यवेक्षी रिपोर्ट, विनियामक रिटर्न और सर्वेक्षणों के माध्यम से डेटा एकत्र करता है, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ गठबंधन करने वाले मॉडल जोखिम दिशानिर्देशों की शुरुआत, जल्द ही विनियमित संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले एआई मॉडल पर डेटा को शामिल करने के लिए इस दायरे का विस्तार करेगी। इसलिए वित्तीय संस्थानों को मजबूत डेटा कार्यनीतियों को अपनाना चाहिए, जिसमें विविध, विश्वसनीय संकेतक शामिल हों जो एआई अपनाने के पैमाने और संबंधित कमजोरियों दोनों को दर्शाते हैं।

जब एआई का उपयोग क्रेडिट निर्णय या वित्तीय समावेशन के लिए किया जाता है, विशेष रूप से वैकल्पिक डेटा के माध्यम से, तो ग्राहक डेटा केंद्रीय हो जाता है, जिससे गोपनीयता और सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 जिम्मेदार डेटा उपयोग के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, और वित्तीय संस्थानों को सहमति-आधारित, गोपनीयता-प्रथम डेटा प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

<sup>17</sup> आरबीआई एफएसआर - जून 2025 (अध्याय 1 का पैरा 1.42) <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/0FSR/JUNE20253006258AE798B4484642AD861CC35BC2CB3D8E.PDF>



#### (iv) अनुसंधान और विकास

नए अवसरों को खोलने के लिए जीवनचक्र को उधार देने में एआई की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास में निरंतर निवेश महत्वपूर्ण है। वित्तीय संस्थानों के अनुसंधान प्रयासों को डेटा गुणवत्ता और पहुंच में सुधार, ऋण समावेशन को बढ़ाने के लिए नए एआई एल्गोरिदम विकसित करने और ऋण मूल्यांकन में पूर्वाग्रह, निष्पक्षता और व्याख्या से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ प्रदाताओं के एकाग्रता जोखिम का प्रबंधन करने के लिए इन-हाउस क्षमताओं में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

#### (v) उद्योग सहयोग

वित्तीय संस्थानों, फिनटेक कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों सहित उद्योग हितधारकों के बीच सहयोग और ज्ञान-साझाकरण नवाचार को बढ़ावा देने और एआई-संचालित क्रेडिट प्रक्रियाओं में आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक है। यह जिम्मेदार एआई उपयोग के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, मानकों और ढांचे के विकास को बढ़ावा दे सकता है, क्रेडिट मूल्यांकन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा दे सकता है। कुछ प्रारंभिक क्षेत्र जहां उद्योग सहयोगात्मक रूप से काम कर सकता है, वे हैं एआई वर्गीकरण में सामंजस्य स्थापित करना और सामान्य बेंचमार्क और मेट्रिक्स विकसित करना।

#### नई प्रौद्योगिकियों के लिए नियामक रेलिंग

जैसे-जैसे एआई अपनाने का जोर बढ़ रहा है, विनियामकीय निगरानी एक कुशल, जिम्मेदार और निष्पक्ष स्वीकृति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। आरई में मॉडल-संचालित ऋण आकलन और निर्णय लेने के बढ़ते उपयोग को स्वीकार करते हुए, आरबीआई ने क्रेडिट<sup>18</sup> में मॉडल जोखिम प्रबंधन पर एक मसौदा परिपत्र जारी किया था, जिसमें शासन, सत्यापन, निगरानी और जवाबदेही पर अपेक्षाएं निर्धारित की गई थीं। इस आधार पर निर्माण करते हुए और न केवल ऋण कार्यों के लिए बल्कि कार्यात्मक और परिचालन डोमेन में प्रक्रियाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के लिए भी आरई द्वारा मॉडलों के बढ़ते उपयोग को मान्यता देते हुए, बैंक

इन दिशानिर्देशों के दायरे का विस्तार करने की प्रक्रिया में है और सभी मॉडलों पर लागू व्यापक मॉडल जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश जारी करेगा। चूंकि एआई जैसी तकनीकों को आम तौर पर पूरे क्षेत्र में समान रूप से नहीं अपनाया जाता है और विभिन्न पैमानों के साथ विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की उपस्थिति के कारण, आनुपातिकता के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी आरई अपने व्यवसाय मॉडल और ग्राहकों की जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त तकनीकों को अपना सकें, जबकि व्याख्यात्मकता, एल्गोरिथम पूर्वाग्रह, लचीलापन और अति-स्वचालन जैसे जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकें। इस दृष्टिकोण को जारी रखते हुए, जिम्मेदार, कुशल और नैतिक एआई (फ्री-एआई)<sup>20</sup> के लिए फ्रेमवर्क पर समिति की हाल ही में जारी रिपोर्ट ने भरोसेमंद एआई के लिए सात मार्गदर्शक सूत्र निर्धारित किए हैं, और आरई द्वारा एक मजबूत मॉडल जोखिम प्रबंधन ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया है।

#### निष्कर्ष

दशकों से, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने सार्थक तकनीकी प्रगति को एकीकृत करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। जैसा कि एआई वित्तीय सेवाओं को बदलता है, यह स्पष्ट है कि यह एक ऐसा विकास है जो केवल एक अपग्रेड नहीं है बल्कि उत्पादों, प्रक्रियाओं और संचालन को प्रभावित करने वाला एक बड़ा बदलाव है। जोखिम के दृष्टिकोण से, वित्तीय प्रणाली पर एआई अपनाने के दीर्घकालिक प्रभाव अनिश्चित बने हुए हैं, लेकिन संभावित दूरगामी परिणाम प्रदर्शित करते हैं। इसलिए वित्तीय क्षेत्र के लिए यह अनिवार्य है कि वह दूरदर्शिता के साथ एआई अपनाने के साथ, न केवल नवाचार में निवेश करे, बल्कि मजबूत शासन संरचना का निर्माण करके, निर्भरताओं में विविधता लाकर, उभरते जोखिमों के निरंतर मूल्यांकन में संलग्न होकर और यह सुनिश्चित करे कि उनकी एआई कार्यनीतियाँ वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता के अनुरूप हों। यह सुनिश्चित

<sup>19</sup> आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2024-25: VI.19 अध्याय VI (विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता)

<sup>20</sup> फ्री-एआई समिति की रिपोर्ट [https://rbidocsrbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/FREEAIR130820250A24FF2D4578453F824C72ED9F5D5851.PDF]

<sup>18</sup> [https://www.rbi.org.in/scripts/bs\\_viewcontent.aspx?id=4479](https://www.rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?id=4479)

करना कि एआई-संचालित निर्णय नैतिक, निष्पक्ष और पारदर्शी हों, एक टिकाऊ, एआई-संचालित वित्तीय भविष्य के निर्माण में सर्वोपरि होगा। इसके लिए "आशावादी सतर्कता" की आवश्यकता होती है, जिसमें बैंकिंग में एआई और अन्य तकनीकों से न तो डरते हैं और न ही आँख बंद करके अपनाया जाता है, बल्कि "नेविगेशन" किया जाता है। आरबीआई, अपनी ओर से, एक सक्षम विनियामक वातावरण प्रदान करना जारी रखेगा ताकि हम एक साथ मिलकर एक बैंकिंग प्रणाली का निर्माण कर सकें जो वास्तव

में भारत का निर्माण करे, और न केवल भारत का निर्माण करे, बल्कि भारत को बदल दे।

मैं इस विचार के साथ समाप्त करता हूँ "विश्वास बैंकिंग की मुद्रा है"। यहां तक कि जब हम एल्गोरिदम और डिजिटल इंटरफेस का उपयोग करके क्रेडिट कवरेज का विस्तार करते हैं, तो विश्वास बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी होगी।

धन्यवाद।

# आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

वर्ष 2024-25 के दौरान भारत के वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

फिनटेक ग्राहकों के अनुभव की अनकही कहानी

एनबीएफसी क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा

नकदी मांग पर यूपीआई का प्रभाव - राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर से साक्ष्य

क्या उपभोग असमानता घट रही है? - 2022-23 का एनएसएसओ सर्वेक्षण हमें क्या बताता है

अवसंरचना - भारत की विकास एक्सप्रेस का एक इंजन





## अर्थव्यवस्था की स्थिति\*

प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर अमेरिकी व्यापार शुल्क लगाने और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की राजकोषीय स्थिति को लेकर नई चिंताओं के मद्देनजर वैश्विक अनिश्चितता बनी रही। घरेलू कारकों से प्रेरित, 26-2025 की पहली तिमाही के दौरान पाँच तिमाहियों की उच्च वृद्धि दर से स्पष्ट रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय सुदृढ़ता प्रदर्शित की। ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों से व्यापार करने में आसानी, कम खुदरा कीमतों और उपभोग वृद्धि कारकों में मजबूती के माध्यम से उत्तरोत्तर निरंतर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ी, लेकिन लगातार सातवें महीने लक्ष्य दर से काफी नीचे रही। नीतिगत दरों में कटौती का लाभ उठाने में मदद करने के लिए प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में रही। अगस्त-सितंबर के दौरान भारतीय शेयर बाजारों में द्विदिशात्मक गतिविधियाँ देखी गईं। मजबूत सेवा निर्यात और मजबूत विप्रेषण प्राप्ति के समर्थन से, भारत का चालू खाता घाटा पहली तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ।

### परिचय

प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ अमेरिकी व्यापार नीति की अनिश्चितताओं, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) की राजकोषीय स्थिति पर नई चिंताओं और भू-राजनीतिक जोखिमों के मद्देनजर वैश्विक अनिश्चितता बनी रही। आर्थिक परिदृश्य पर अनिश्चितताओं के बादल छाए रहने के बावजूद, वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अगस्त में 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया, जिसमें विनिर्माण पीएमआई विस्तार क्षेत्र में पहुँच गया और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में भी जोरदार वृद्धि हुई। अगस्त में वैश्विक

\* यह आलेख रेखा मिश्रा, आशीष थॉमस जॉर्ज, शशि कांत, विश्वजीत मोहंती, दुर्गा जी, श्रेया कंसल, यामिनी झाम्ब, जेसिका मारिया एंथोनी, हरेंद्र कुमार बेहरा, वृंदा गुप्ता, आकाश राज, अमृता बसु, संजना सेजवाल, लव कुमार शांडिल्य, प्रशांत कुमार, श्रीतमा रे, प्रतिभा केडिया, नीलावा दास, अर्चना दिलीप, सुमित रॉय, योगेश राणा, अवनीश कुमार, पुलस्त्य बंदोपाध्याय, सुप्रियो मंडल, पलक गोयल, युवराज कश्यप, रस्मी रंजन बेहरा और समृद्धि द्वारा तैयार किया गया है। उप गवर्नर, डॉ. पूनम गुप्ता द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और टिप्पणियों को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया गया है। राखे पलुवई बालचंद्रन, सुभद्रा शंकरन और अभिनव नारायणन की सहकर्म समीक्षा को भी स्वीकार किया जाता है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

जिस कीमतों में काफी हद तक गिरावट आई, हालाँकि अगस्त के उत्तरार्ध से चुनिंदा जिनसों, खासकर स्वर्ण और कॉफी की कीमतों में तीव्र वृद्धि देखी गई।

अगस्त में सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बॉण्ड प्रतिफल में मजबूती जारी रही क्योंकि ऋण स्थिरता संबंधी चिंताएँ केंद्र में रहीं। दूसरी ओर, वैकल्पिक सुरक्षित-आश्रय आस्तियों की माँग ने स्वर्ण की कीमतों को रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँचा दिया। फेड द्वारा ब्याज दरों में ढील दिए जाने की बढ़ती उम्मीदों के कारण अगस्त के अंत से अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल में गिरावट आई है। इसके बाद सितंबर में, प्रतिफल में और गिरावट आई और फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद स्थिर हो गया। इन कारकों को दर्शाते हुए, अमेरिकी डॉलर भी अगस्त और सितंबर के अधिकांश समय में गिरता रहा। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के इक्विटी बाजार अगस्त में मुख्य रूप से 2025 की दूसरी तिमाही की मजबूत आय, फेड द्वारा ब्याज दरों में ढील दिए जाने की उम्मीदों और बिगटेक शेयरों को लेकर आशावाद के कारण उछाल में रहे। सितंबर में फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती ने, विशेष रूप से अमेरिका में, तेजी को और मजबूत किया। जोखिम-मुक्त निवेशक धारणाओं के कारण अगस्त में उभरते बाजारों में इक्विटी प्रवाह कम रहा।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में मुद्रास्फीति के रुझान अलग-अलग रहे। जहाँ उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ स्थिर मुद्रास्फीति से जूझ रही थीं, वहीं ईएमडीई में अवस्फीति देखी गई। अगस्त-सितंबर में, प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति की तुलना में घरेलू संवृद्धि और बेरोजगारी की चिंताओं को प्राथमिकता देते हुए अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों में कटौती की।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय सुदृढ़ता प्रदर्शित की, जैसा कि घरेलू कारकों द्वारा संचालित, 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान पाँच तिमाहियों की उच्च वृद्धि दर से स्पष्ट है। उपभोग व्यय और स्थायी निवेश गतिविधियाँ मजबूत रहीं, जिससे निवल निर्यात में गिरावट नगण्य रही। आर्थिक गतिविधि के उच्च-आवृत्ति संकेतकों ने अगस्त में स्थिर वृद्धि दर्शायी, ग्रामीण माँग मजबूत रही, हालाँकि शहरी माँग में कुछ कमजोरी बनी रही।

27 अगस्त, 2025 से अमेरिका को भारत के निर्यात पर 50 प्रतिशत का आयात शुल्क लागू होगा।<sup>1</sup> इसका तात्कालिक प्रभाव क्षेत्र-विशिष्ट हो सकता है, क्योंकि अमेरिका को भारत के लगभग 45 प्रतिशत व्यापारिक निर्यात को शुल्क से छूट प्राप्त है, जिसमें प्रमुख निर्यात उत्पाद, विशेष रूप से स्मार्टफोन और दवाइयाँ, शामिल हैं। व्यापार नीति की अनिश्चितताओं के बावजूद, अप्रैल-अगस्त 26-2025 के दौरान व्यापारिक निर्यात में सुदृढ़ता देखा गया है।

जीएसटी परिषद की 3 सितंबर की बैठक में लिए गए निर्णयों ने जीएसटी व्यवस्था में प्रमुख संरचनात्मक सुधारों को गति दी है, जिससे दरें और प्रक्रियाएँ सरल हुई हैं। दरों के सरलीकरण के अलावा, इन सुधारों ने उलटे शुल्क ढांचे<sup>2</sup> से जुड़ी चुनौतियों का भी समाधान किया है और प्रक्रियाओं को व्यापार-अनुकूल बनाया है, जिससे विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स को लाभ हुआ है। कुल मिलाकर, इन सुधारों से कर संग्रह में उछाल आने, अनुपालन में सुधार होने और जीवनयापन में और अधिक सुगमता के साथ-साथ व्यापार करने में भी आसानी होने की उम्मीद है।

सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति में बढ़त हुई, लेकिन लगातार सातवें महीने लक्ष्य दर से काफी नीचे रही। खाद्य समूह ने समग्र मुद्रास्फीति में वृद्धि में मुख्य रूप से योगदान दिया। मूल मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई) में भी मामूली वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से स्वर्ण की कीमतों में तेजी के कारण हुई।

सितंबर की शुरुआत से ही कुल मिलाकर वित्तीय स्थितियाँ अनुकूल हो गई हैं। अगस्त और सितंबर (19 सितंबर तक) के दौरान प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में रही। भारित औसत कॉल दर - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - मोटे तौर पर कॉरिडोर के निचले आधे हिस्से में रही।

<sup>1</sup> 6 अगस्त, 2025 को अमेरिका ने भारत के आयात पर 31 जुलाई 2025 को लगाए गए 25 प्रतिशत के अतिरिक्त 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया।

<sup>2</sup> मानव निर्मित वस्त्र और उर्वरक क्षेत्र के लिए उलटे शुल्क ढांचे को ठीक किया गया है।

निश्चित आय वर्ग में, सितंबर में सरकारी बॉण्ड प्रतिफल में नरमी आई, क्योंकि सरकार ने राजकोषीय मजबूती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। फरवरी से अगस्त 2025 के दौरान रेपो दर में 100 आधार अंकों की संचयी कमी का बैंक ऋण और जमा दरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगस्त में बैंकों द्वारा ऋण वृद्धि थोड़ी बढ़कर दो अंकों में पहुँच गई, जबकि जमा वृद्धि स्थिर रही। 26-2025 के दौरान अब तक, वाणिज्यिक क्षेत्र में खाद्येतर बैंक ऋण का प्रवाह धीमा रहा; हालाँकि, गैर-बैंक स्रोतों से प्रवाह ने इसकी भरपाई कर दी।

अगस्त-सितंबर के दौरान भारतीय शेयर बाजारों में नीतिगत घोषणाओं और प्रमुख मैक्रो-डेटा रिलीज़ के कारण द्विदिशात्मक हलचल देखी गई। एसएंडपी सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड और जीएसटी सुधारों की घोषणा के बाद अगस्त के मध्य में तेजी से उछाल दर्ज करने के बाद, अगस्त के अंत तक भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ लागू होने से शेयर बाजारों में गिरावट आई। इसके बाद, सितंबर की शुरुआत में पहली तिमाही के मजबूत जीडीपी संवृद्धि दर और जीएसटी परिषद द्वारा दरों को युक्तिसंगत बनाने के फैसले के कारण शेयर बाजारों में तेजी आई। हालाँकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने बिकवाली जारी रखी, लेकिन मजबूत घरेलू संस्थागत खरीद ने इस निकासी की भरपाई कर दी।

वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं में वृद्धि के बावजूद, भारत के बाह्य क्षेत्र ने सुदृढ़ता दिखाया। 26-2025 की पहली तिमाही में चालू खाता घाटा पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ, जिसे मजबूत सेवा निर्यात और मजबूत धन विप्रेषण प्रवाह का समर्थन प्राप्त था। इन रुझानों से पूरे वर्ष घाटा कम और सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है। जुलाई में निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह 38 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया, जिसमें उच्च सकल एफडीआई और धीमी प्रत्यावर्तन और बाह्य एफडीआई का योगदान रहा। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि पर्याप्त बना रहा, जो बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को दर्शाता है।

इस पृष्ठभूमि में, आलेख का शेष भाग चार खंडों में विभाजित है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित

हो रहे घटनाक्रमों को समाहित करता है। खंड III घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन प्रस्तुत करता है। खंड IV भारत की वित्तीय स्थितियों का सार प्रस्तुत करता है, जबकि खंड V समापन टिप्पणियाँ प्रस्तुत करता है।

## II. वैश्विक व्यवस्था

प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ अमेरिकी व्यापार नीति की अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण वैश्विक घटनाक्रमों पर अनिश्चितता का साया मंडरा रहा है। अगस्त में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय स्थिरता को लेकर चिंताएँ प्रमुखता से उभरीं, जिसका वित्तीय बाजारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अमेरिका में, श्रम बाजार की नरमी और बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच, बढ़ते शेयर बाजारों के साथ-साथ उपभोक्ता भावना में भी कमजोरी देखी गई।

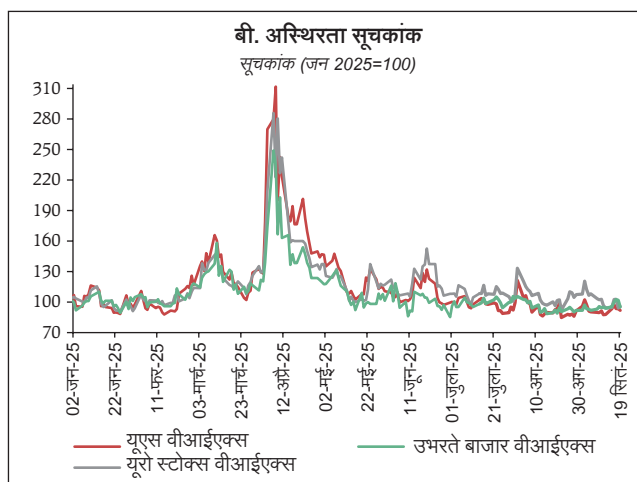
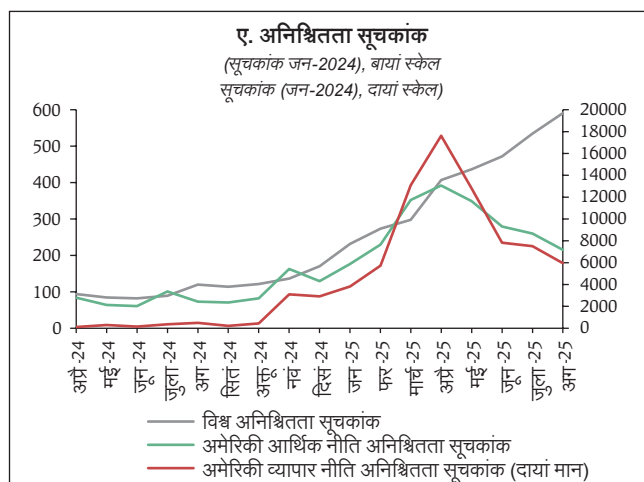
व्यापार नीति अनिश्चितताओं और सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ऋण स्थिरता पर नई चिंताओं के कारण अगस्त में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता उच्च स्तर पर बनी रही। अमेरिका और कई व्यापारिक साझेदारों के बीच टैरिफ समझौतों के बाद, अमेरिका में आर्थिक और व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांकों में मामूली गिरावट आई। बढ़ती राजकोषीय स्थिरता संबंधी चिंताओं

ने अगस्त में, विशेष रूप से यूरोप में, वित्तीय बाजार में अस्थिरता बढ़ा दी (चार्ट II.1ए और II.1बी)।

वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अगस्त में 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया, जो उत्पादन और नए कारोबार में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई, जुलाई में उच्च उत्पादन के कारण संकुचन के बाद, अगस्त में विस्तार क्षेत्र में पहुँच गया - जो आंशिक रूप से संभावित टैरिफ वृद्धि से पहले उत्पादन में अग्रिम वृद्धि को दर्शाता है। पीएमआई सेवाओं में लगातार तेज़ वृद्धि जारी रही (सारणी II.1)।

पीएमआई सूचकांकों के अनुसार, अगस्त में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और यूरोज़ोन सहित प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में, चीन और भारत में व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि हुई, जहाँ भारत ने एक दशक में अपनी उच्चतम दर दर्ज की, जबकि ब्राज़ील और रूस में संकुचन जारी रहा (चार्ट II.2ए)। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नए निर्यात ऑर्डरों में संकुचन देखा गया, जबकि भारत में विस्तार जारी रहा (चार्ट II.2बी)। वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक अपने ऐतिहासिक औसत से नीचे चला गया (अनुबंध चार्ट ए1)।

चार्ट II.1: अनिश्चितता संकेतक



**टिप्पणीयाँ:** 1. विश्व अनिश्चितता सूचकांक (डब्ल्यूयूआई) की गणना इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंटी रिपोर्टों में "अनिश्चित" (अथवा इसके विपर्यय) शब्द के प्रतिशत की गणना करके की जाती है।  
2. आर्थिक नीति अनिश्चितता (ईपीयू) सूचकांक भविष्य की आर्थिक नीतियों के आसपास अनिश्चितता के स्तर को मापता है, जो प्रमुख समाचार पत्रों के लेखों में "अर्थव्यवस्था," "नीति" और "अनिश्चितता" जैसे विशिष्ट कीवर्ड की आवृत्ति से प्राप्त होती है। व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक सरकारी व्यापार नीति निर्णयों की अप्रत्याशा को मापता है।

**स्रोत:** ब्लूमबर्ग; [www.policyuncertainty.com](http://www.policyuncertainty.com); और विश्व अनिश्चितता सूचकांक (डब्ल्यूयूआई) डेटाबेस।

## सारणी II.1 वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक

	अग-24	सित-24	अक्तू-24	नव-24	दिस-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25
पीएमआई समग्र	52.9	51.9	52.3	52.4	52.6	51.8	51.5	52.1	50.8	51.2	51.7	52.4	52.9
पीएमआई विनिर्माण	49.6	48.7	49.4	50.1	49.6	50.1	50.6	50.3	49.8	49.5	50.4	49.7	50.9
पीएमआई सेवाएं	53.9	52.9	53.1	53.1	53.8	52.2	51.5	52.7	50.8	52.0	51.8	53.4	53.4
पीएमआई निर्यात आदेश	49.0	48.5	48.9	49.3	48.7	49.6	49.7	50.1	47.5	48.0	49.1	48.5	48.9
पीएमआई निर्यात आदेश: विनिर्माण	48.4	47.5	48.3	48.6	48.2	49.4	49.6	50.1	47.3	48.0	49.2	48.2	48.7
पीएमआई निर्यात आदेश: सेवाएं	50.8	51.6	50.7	51.3	50.3	50.2	50.2	50.1	48.2	47.9	48.7	49.4	49.3

50

&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;संकुचन ..... विस्तार&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;

**टिप्पणीयाँ:** 1. क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई), एक प्रसार सूचकांक, पिछले महीने की तुलना में प्रत्येक चर में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि प्रत्येक चर बढ़ा/सुधरा है, गिरा/बिगड़ा है या अपरिवर्तित रहा है। पीएमआई मान >50 विस्तार को दर्शाता है, <50 संकुचन को दर्शाता है और =50 'कोई परिवर्तन नहीं' को दर्शाता है।

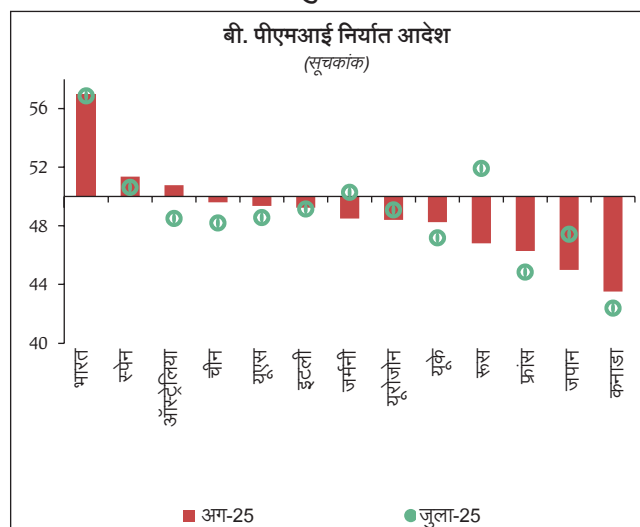
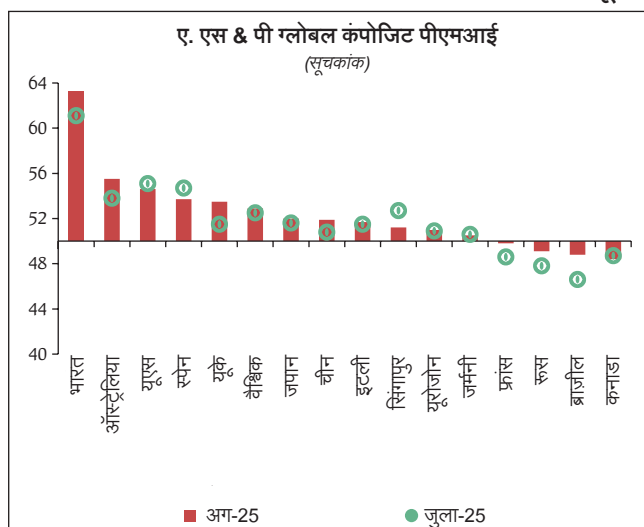
2. हीटमैप अप्रैल 2023 से मई 2025 तक के डेटा पर लागू किया जाता है। मानचित्र रंग कोडित है - लाल सबसे कम मूल्य को दर्शाता है, पीला 50 (या कोई परिवर्तन नहीं) को दर्शाता है, और हरा प्रत्येक पीएम श्रृंखला में उच्चतम मूल्य को दर्शाता है।

**स्रोत:** एस & पी ग्लोबल।

जुलाई के मुकाबले अगस्त में कमोडिटी की कीमतों में कमी आई। वैश्विक खाद्य कीमतें पिछले महीने से काफी हद तक अपरिवर्तित रहीं क्योंकि मांस और चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी अनाज और डेयरी की कीमतों में गिरावट से संतुलित हो गई।<sup>3</sup> वैश्विक बाजारों में आपूर्ति की अधिकता और अमेरिकी मध्यस्थता के बाद रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंधों में ढील की उम्मीदों के कारण अगस्त में कच्चे तेल की कीमतें कमजोर हुईं।

ओपेक प्लस द्वारा उत्पादन बढ़ाने की घोषणा के बाद सितंबर में कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट दर्ज की गई। फिर भी, उच्च आवृत्ति वाले कमोडिटी मूल्य संकेतकों ने अगस्त के उत्तरार्ध से चुनिंदा कमोडिटी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दिखाई। ब्राजील में आपूर्ति की कमी के कारण कॉफी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। सीमित दायरे में रहने के बाद, अगस्त के अंत से स्वर्ण की कीमतें 'सुरक्षित-हेवन' की मांग के

## चार्ट II.2: क्रय प्रबंधकों का सूचकांक: विभिन्न क्षेत्राधिकारों में तुलना

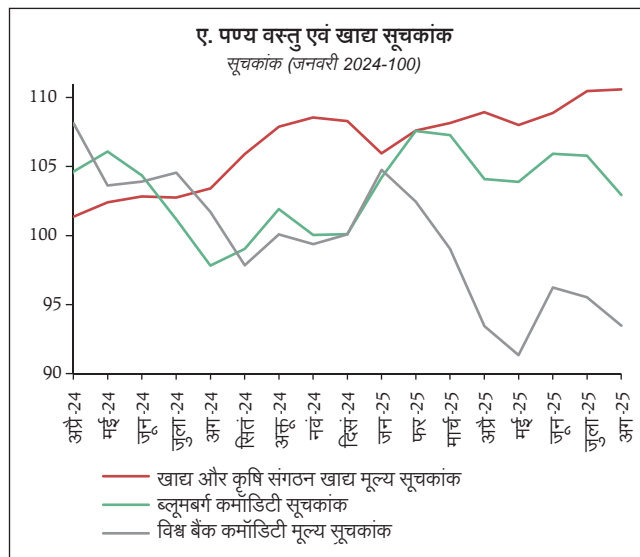


**टिप्पणीयाँ:** 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने का संकेत देता है, जबकि 50 से ऊपर का स्तर विस्तार का संकेत देता है और 50 से नीचे का स्तर संकुचन का संकेत देता है।

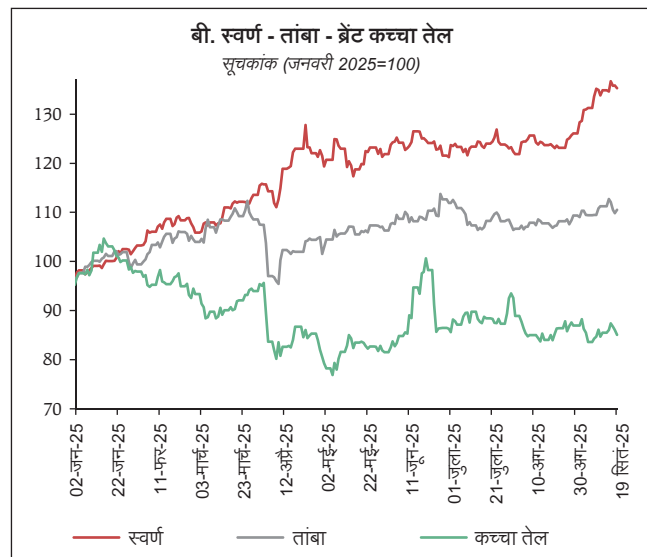
**स्रोत:** एस & पी ग्लोबल।

<sup>3</sup> अगस्त 2025 माह के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन के खाद्य मूल्य सूचकांक के अनुसार।

चार्ट II.3: पण्य वस्तु और खाद्य कीमतें



टिप्पणीयां: खाद्य और कृषि संगठन; ब्लूमबर्ग; और विश्व बैंक पिक शीट

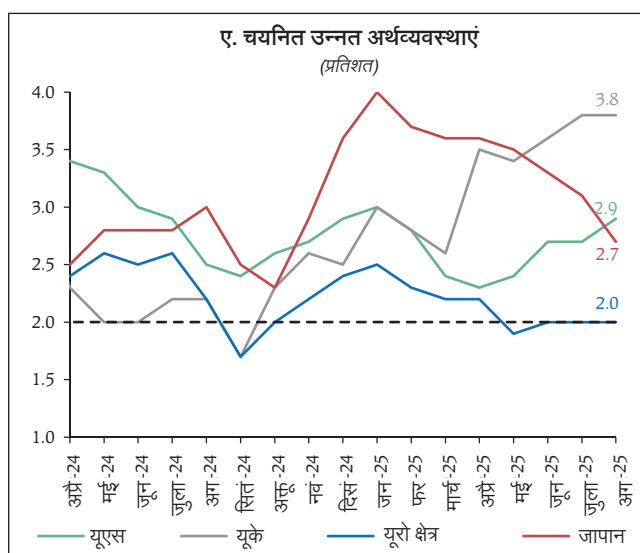


कारण बढ़कर सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई (चार्ट II.3ए और 3बी)।

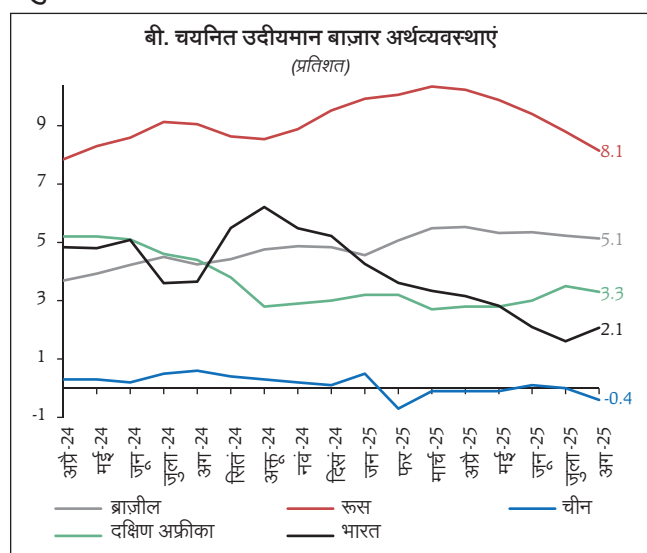
उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उदीयमान बाजार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में मुद्रास्फीति के रुझान अलग-अलग रहे। जहाँ उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ स्थिर मुद्रास्फीति से जूझती रहीं, वहीं उदीयमान बाजार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में अवस्फीति देखी गई। अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य

सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर 2.9 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी के बाद से सबसे अधिक है, हालाँकि मुख्य मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत पर स्थिर रही। यूरो क्षेत्र में, अगस्त में मुख्य मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत पर स्थिर रही, जबकि सेवाओं की मुद्रास्फीति में नरम ऊर्जा कीमतों के साथ-साथ थोड़ी नरमी देखी गई। यूके में भी मुद्रास्फीति 3.8 प्रतिशत पर स्थिर रही। जापान में मुख्य मुद्रास्फीति घटकर 2.7 प्रतिशत हो गई, जो अक्टूबर 2024 के बाद से सबसे कम है (चार्ट II.4ए)। प्रमुख उदीयमान

चार्ट II.4: हेडलाइन मुद्रास्फीति



टिप्पणीयां: ब्लूमबर्ग और ओईसीडी





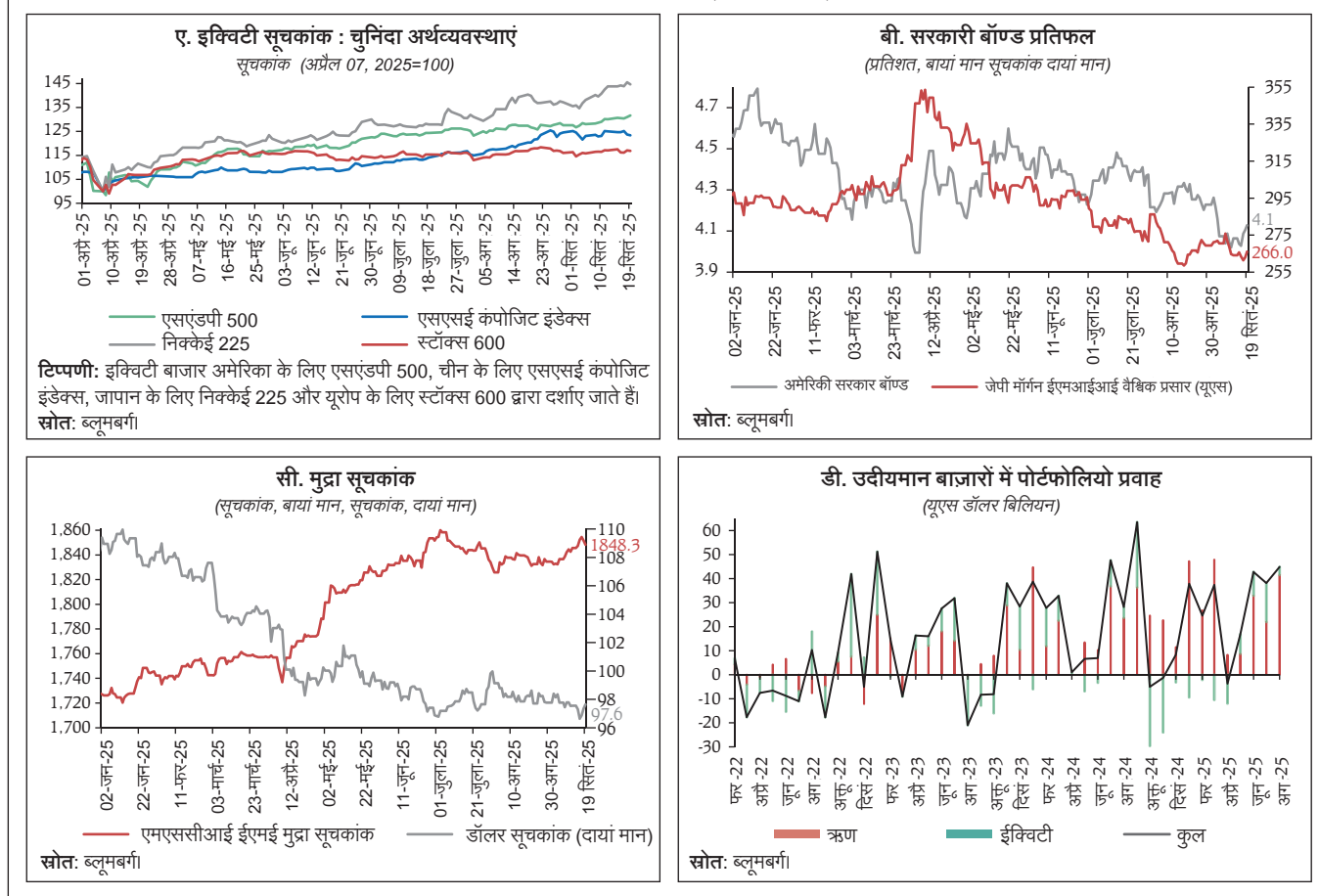
बाज़ार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में, ब्राज़ील में मुद्रास्फीति में नरमी जारी रही, लेकिन यह लक्ष्य स्तर से ऊपर रही (अनुबंध चार्ट ए2)। कीमतों में लगातार गिरावट ने चीन को दो महीने के अंतराल के बाद फिर से अपस्फीति में धकेल दिया है। रूस में, हालाँकि यह नरमी की राह पर है, मुद्रास्फीति लक्ष्य से काफी ऊपर बनी रही। अगस्त में दक्षिण अफ्रीका की वार्षिक मुद्रास्फीति कम हुई (चार्ट II.4बी)।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के शेयर बाजार अगस्त में तेजी से बढ़े, जिसकी मुख्य वजह 2025 की दूसरी तिमाही की मज़बूत कमाई, फेड द्वारा ब्याज दरों में ढील की उम्मीद और बिगटेक शेयरों को लेकर आशावाद रहा। सितंबर में फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती ने, खासकर अमेरिका में, इस तेजी को और मज़बूत किया। यूरोप STOXX 600 इंडेक्स अगस्त के अंत में सुस्त कमाई के कारण मामूली रूप से गिरा। सितंबर में, फ्रांस की सॉवरेन रेटिंग में गिरावट के कारण शेयर बाजारों में मंदी रही। जापान के शेयर

बाजारों ने अगस्त में अमेरिका-जापान व्यापार समझौते के समर्थन से मज़बूत प्रदर्शन दर्ज किया। बेहतर कारोबारी विश्वास और 2025 की दूसरी तिमाही के उम्मीद से बेहतर जीडीपी आंकड़ों के दम पर सितंबर में सूचकांकों में और तेजी आई। अमेरिका-चीन व्यापार युद्धविराम समझौते के 90 दिनों के विस्तार से अगस्त में चीनी शेयर बाजारों में तेजी आई, जिसे महीने के अंत में आवास क्षेत्र में प्रोत्साहन उपायों से और बल मिला। हालाँकि, विनियामकीय सख्ती, कमजोर उपभोक्ता खर्च और कारखाना उत्पादन के आंकड़ों की आशंकाओं के बीच सितंबर में सूचकांकों में मामूली गिरावट देखी गई (चार्ट II.5ए)।

अगस्त के अधिकांश समय में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के बॉण्ड बाजार लंबी अवधि की उधारी लागतों में पर्याप्त वृद्धि से जूझते रहे, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की राजकोषीय सेहत को लेकर नई चिंताओं के बीच कई वर्षों के उच्चतम स्तर को छू गई। अगस्त के अंत में, जुलाई के कमजोर मुद्रास्फीति आंकड़ों

चार्ट II.5: वैश्विक वित्तीय बाजार



और आर्थिक जोखिमों के संतुलन में बदलाव के बारे में फेड की सूचना के कारण सितंबर की बैठक में फेड द्वारा नीतिगत दरों में ढील दिए जाने की बढ़ती उम्मीदों के बाद अमेरिका में प्रतिफल में नरमी आई<sup>4</sup> इसके बाद सितंबर में, प्रतिफल में और गिरावट आई और फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद स्थिर हो गया (चार्ट 11.5बी)। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) पर ईएमई बॉण्ड का प्रसार अगस्त के मध्य तक कम हुआ और महीने के अंत में इसमें तेजी आई। सितंबर में, उभरते बाजार की आस्तियों में मजबूत रुचि के कारण प्रसार मोटे तौर पर स्थिर रहा।

फेड द्वारा नीतिगत दरों में ढील दिए जाने के कारण अगस्त और सितंबर में अब तक अमेरिकी डॉलर में गिरावट आई है (चार्ट 11.5सी)। जोखिम-मुक्त निवेशक धारणा के कारण उभरते बाजारों में इक्विटी प्रवाह अगस्त में कम रहा। दूसरी ओर, ऋण प्रवाह में तेजी से वृद्धि हुई (चार्ट 11.5डी)।

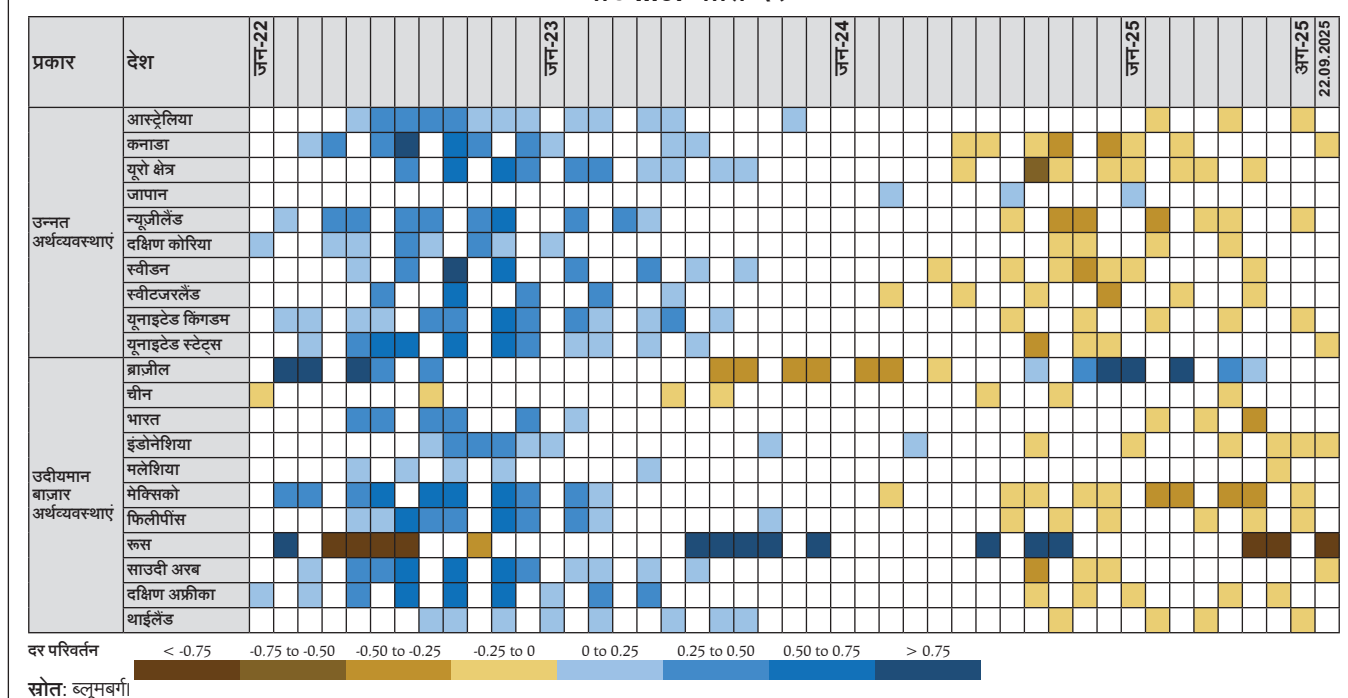
अगस्त-सितंबर में, प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति की तुलना में घरेलू संवृद्धि और बेरोजगारी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों को कम करने का विकल्प

चुना। अगस्त में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने बेंचमार्क ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कमी की। सितंबर में, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी नीति दर में 25 आधार अंकों की कमी की। इसीबी ने लगातार दूसरी बार अपनी नीति दर को अपरिवर्तित रखा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी सितंबर में अपनी ब्याज दरें स्थिर रखीं। ईएमडीई में, इंडोनेशिया, मेक्सिको और थाईलैंड ने अपनी नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की। चीन ने अगस्त में लगातार तीसरे महीने अपनी बेंचमार्क उधार दर स्थिर रखी। सितंबर में, मलेशिया के केंद्रीय बैंक ने अपनी एक दिवसीय नीति दर को स्थिर रखा, जबकि रूस ने मुद्रास्फीति के दबाव में कमी का हवाला देते हुए इसे कम कर दिया (चार्ट 11.6)।

### III. देश घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय सुदृढ़ता प्रदर्शित किया है, जैसा कि 26-2025 की पहली तिमाही में अपेक्षा से बेहतर वृद्धि से स्पष्ट है। संवृद्धि के दो चालक - उपभोग और निवेश - मजबूत बने रहे। कम मुद्रास्फीति के माहौल में मजबूत ग्रामीण रिटेंशन द्वारा समग्र माँग की स्थिति मजबूत बनी हुई है।

चार्ट 11.6: नीति दरें



<sup>4</sup> मौद्रिक नीति और फेड की रूपरेखा की समीक्षा - अध्यक्ष जेरोम एच. पॉवेल द्वारा «संक्रमण में श्रम बाजार: जनसांख्यिकी, उत्पादकता और समष्टि आर्थिक नीति» में भाषण, जो कि कैनेसस सिटी, जैक्सन होल, व्योमिंग के फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित एक आर्थिक संगोष्ठी है।

## समग्र माँग

वास्तविक जीडीपी वृद्धि ने गति पकड़ी और 26-2025 की पहली तिमाही में पांच तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो पिछली तिमाही में 7.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) से बढ़कर 7.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई। उपभोग और स्थिर निवेश क्रमशः 4.7 प्रतिशत अंक और 2.7 प्रतिशत अंकों का योगदान देने वाले प्रमुख चालक बने रहे। निजी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि मजबूत ग्रामीण माँग और मुद्रास्फीति में कमी के कारण बनी रही। केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के उच्च राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान और सब्सिडी को छोड़कर) के कारण सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में त्वरित वृद्धि देखी गई। निवल निर्यात संवृद्धि पर एक भार बन गया और पिछली तिमाही में अपने सकारात्मक योगदान को उलट दिया क्योंकि आयात विस्तार ने निर्यात वृद्धि को पीछे छोड़ दिया। (चार्ट III.1 और अनुबंध सारणी ए1)। नॉमिनल के हिसाब से, जीडीपी बढ़ोतरी तीन तिमाही में सबसे कम 8.8 प्रतिशत रही। नॉमिनल और वास्तविक जीडीपी बढ़ोतरी के बीच का अंतर कम होने का कारण जीडीपी डिफ्लेटर में तेजी से कमी आना और अब तक के सबसे निचले स्तर 0.9 प्रतिशत पर आना था (अनुबंध चार्ट ए6)।

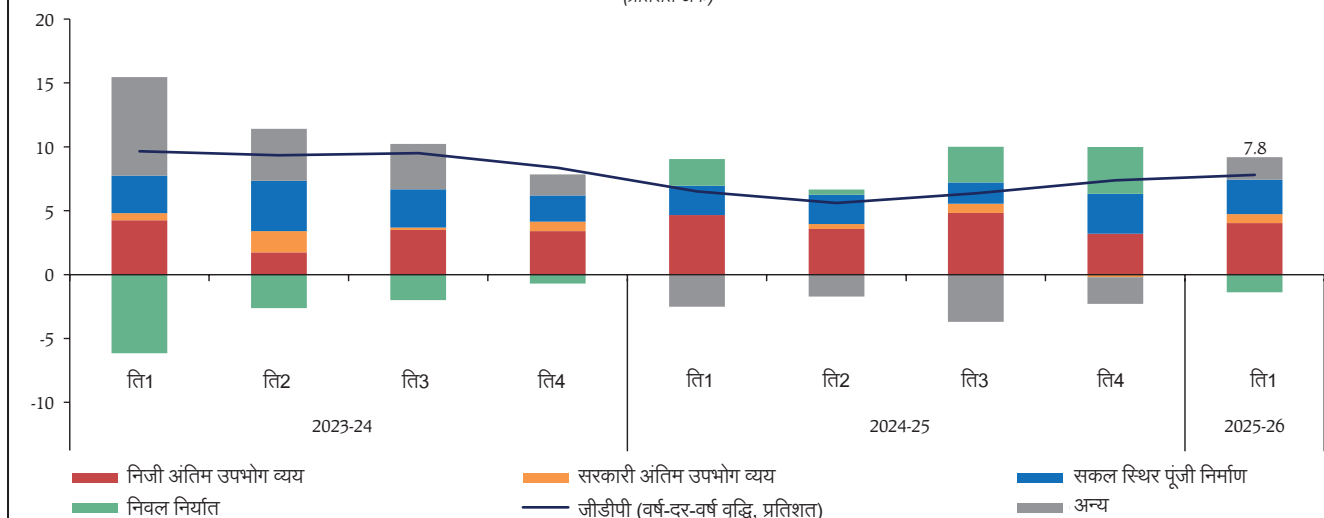
अगस्त में समग्र आर्थिक गतिविधि के उच्च-आवृत्ति संकेतक मजबूत बने रहे। जीएसटी ई-वे बिलों में तेज़ वृद्धि हुई और वे दूसरे सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गए, जो त्योहारी मौसम के लिए इन्वेंट्री स्टॉकिंग और भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ से पहले ऑर्डर में वृद्धि को दर्शाता है। बिजली की माँग और पेट्रोलियम खपत में तेज़ी आई, लेकिन जीएसटी राजस्व और टोल संग्रह में वृद्धि मोटे तौर पर स्थिर रही। डिजिटल भुगतान में मात्रा के हिसाब से दो अंकों की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मूल्य के हिसाब से वृद्धि में नरमी देखी गई (सारणी III.1)।

अगस्त के दौरान, ग्रामीण माँग मजबूत रही, जिसमें मजबूत खुदरा ट्रैक्टर बिक्री और अनुकूल मानसून तथा घटती मुद्रास्फीति से दोपहिया वाहनों की बिक्री में सुधार शामिल है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोजगार की घरेलू माँग अगस्त में कम हुई, जो खरीफ की ज्यादा बुआई के कारण रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की उपलब्धता को दर्शाती है। शहरी माँग में कुछ कमजोरी बनी रही, जैसा कि ऑटोमोबाइल बिक्री में मामूली वृद्धि और घरेलू हवाई यात्री यातायात में कमी से संकेत मिलता है (सारणी III.2)।

अगस्त में रोजगार की स्थिति के विभिन्न संकेतकों ने मिली-जुली तस्वीर पेश की। शहरी बेरोजगारी में भारी गिरावट के

चार्ट III.1: जीडीपी वृद्धि में भारत योगदान

(प्रतिशत अंक)



टीप्पणी: अन्य में स्टॉक, कीमती सामान और सांख्यिकीय विसंगतियों में परिवर्तन शामिल हैं।

स्रोत: एनएसओ



सारणी III.1: उच्च आवृत्ति संकेतक- आर्थिक गतिविधि													
	अग-24	सितं-24	अक्तू-24	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला -25	अग-25
जीएसटी ई-वे बिल	12.9	18.5	16.9	16.3	17.6	23.1	14.7	20.2	23.4	18.9	19.3	25.8	22.4
जीएसटी राजस्व	10.0	6.5	8.9	8.5	7.3	12.3	9.1	9.9	12.6	16.4	6.2	7.5	6.5
टोल संग्रह	6.8	6.5	7.9	11.9	9.8	14.8	18.7	11.9	16.6	16.4	15.5	14.8	12.7
बिजली की मांग	-5.0	-0.8	-0.4	3.7	5.1	1.3	2.4	5.7	2.8	-4.8	-2.3	2.6	3.9
पेट्रोलियम की खपत	-3.1	-4.4	4.1	10.6	2.0	3.0	-5.2	-3.1	0.2	0.7	0.5	-3.9	2.6
जिनमें से पेट्रोल	8.6	3.0	8.7	9.6	11.1	6.7	5.0	5.7	5.0	9.2	6.8	5.9	5.5
डीजल	-2.5	-1.9	0.1	8.5	5.9	4.2	-1.3	0.9	4.2	2.1	1.5	2.4	1.2
विमानन टरबाइन ईंधन	8.1	10.4	9.4	8.5	8.7	9.4	4.2	5.7	3.9	4.3	3.3	-2.3	-2.9
डिजिटल भुगतान-मात्रा	34.9	36.3	40.3	30.1	33.1	33.0	26.7	30.8	30.0	29.2	28.3	30.9	28.8
डिजिटल भुगतान-मूल्य	16.7	21.5	27.5	9.5	19.6	18.6	9.5	17.3	18.4	12.6	17.4	16.6	5.6



**टिप्पणियाँ:** 1. व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना सभी संकेतकों के लिए की गई है।  
2. हीटमैप अप्रैल 2023 से अगस्त 2025 तक डेटा पर लागू किया जाता है। अगस्त 2025 के लिए डिजिटल भुगतान डेटा अंतिम है।  
3. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा सीमा को एक कलर ग्रेडिएंट योजना में अनुवाद करता है जिसमें लाल रंग से संबंधित डेटा शृंखला के उच्चतम मूल्यों के अनुरूप सबसे कम मूल्य और हरे रंग को दर्शाता है।  
**स्रोत:** वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन); आरबीआई; केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीएलए), और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार।

कारण अखिल भारतीय बेरोज़गारी दर घटकर 5.1 प्रतिशत रह गई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हुई वृद्धि के कारण अगस्त में श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई<sup>5</sup> नौकरी जॉबस्पीक सूचकांक के अनुसार, व्हाइट-कॉलर नौकरियों की सूची में मामूली वृद्धि हुई, जिसका प्रमुख कारण एआई/एमएल और बीमा, यात्रा/आतिथ्य, बीपीओ/आईटीईएस और रियल एस्टेट जैसे गैर-आईटी क्षेत्रों में नियुक्तियाँ रहीं।

विनिर्माण और सेवा दोनों के लिए पीएमआई रोज़गार सूचकांक विस्तार में रहे (सारणी III.3)।

वित्त वर्ष 26-2025 (अप्रैल-जुलाई) के दौरान, केंद्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक रहे<sup>6</sup> यह मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियों में मंदी के साथ-साथ अधिक राजस्व और पूंजीगत व्यय के कारण था (चार्ट III.2ए)। राजस्व प्राप्तियों में नरमी का मुख्य

सारणी III.2: उच्च आवृत्ति संकेतक- ग्रामीण और शहरी मांग														
		अग-24	सितं-24	अक्तू-24	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला -25	अग-25
शहरी मांग	घरेलू हवाई यात्री यातायात	6.7	7.4	9.6	13.8	10.8	14.1	12.1	9.9	9.7	2.6	3.7	-2.5	-1.1
	खुदरा यात्री वाहन बिक्री	-4.5	-18.8	32.4	-13.7	-2.0	15.5	-10.3	6.3	1.6	-3.1	2.5	-0.8	0.9
ग्रामीण मांग	खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री	2.9	-9.3	32.1	11.2	-12.5	6.6	-7.2	-0.7	2.9	5.4	4.8	-4.3	2.8
	खुदरा ट्रैक्टर बिक्री	-11.4	14.7	3.1	29.9	25.8	5.2	-14.5	-5.7	7.6	2.8	8.7	11.0	30.1
	खुदरा दोपहिया वाहन बिक्री	6.3	-8.5	36.3	15.8	-17.6	4.2	-6.3	-1.8	2.3	7.3	4.7	-6.5	2.2
	'मनरेगा': काम की मांग	-16.0	-13.4	-7.6	3.9	8.2	14.4	2.8	2.2	-6.5	4.4	4.4	-12.3	-26.1
		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>												
		< <संकुचन-----विस्तार> >												



**टिप्पणियाँ:** 1. सभी संकेतकों के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।  
2. हीटमैप अप्रैल 2023 से अगस्त 2025 तक डेटा पर लागू किया जाता है।  
3. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा सीमा को एक कलर ग्रेडिएंट योजना में बदलता है जिसमें लाल रंग से संबंधित डेटा शृंखला के उच्चतम मूल्यों के अनुरूप सबसे कम मूल्य और हरे रंग को दर्शाता है।  
4. अगस्त 2025 के लिए घरेलू हवाई यात्री ट्रैफिक की वृद्धि दर का डेटा रोज़ाना के डेटा को मिलाकर आकलित किया गया है।  
**स्रोत:** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फेडरेशन (एफएडीए) और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

<sup>5</sup> पीएलएफएस अगस्त 2025 मासिक बुलेटिन 15 सितंबर, 2025 को जारी किया जाएगा।  
<sup>6</sup> लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार।

सारणी III.3: उच्च आवृत्ति संकेतक- रोजगार

	अग-24	सितं-24	अक्तू-24	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला -25	अग-25
बेरोजगारी दर (पीएलएफएस: अखिल भारतीय)									5.1	5.6	5.6	5.2	5.1
बेरोजगारी दर (पीएलएफएस ग्रामीण)									4.5	5.1	4.9	4.4	4.3
बेरोजगारी दर (पीएलएफएस शहरी)									6.5	6.9	7.1	7.2	6.7
नौकरी जॉब स्पीक सूचकांक	-3.4	6.0	10.0	2.0	8.7	3.9	4.0	-1.5	8.9	0.3	10.5	6.8	3.4
ईपीएफओ निवल वेतन जोड़	53.5	52.1	53.3	52.9	53.4	54.8	54.5	53.4	54.2	54.9	55.1	53.3	53.1
पीएमआई रोजगार: विनिर्माण	53.1	53.4	54.3	56.6	55.5	56.3	56.2	52.5	53.9	57.1	55.1	51.4	52.2



< <संकुचन ----- विस्तार> >

**टिप्पणियाँ:** 1. सभी पीएलएफएस संकेतक वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में हैं और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए हैं।  
2. नौकरी सूचकांक और ईपीएफओ निवल वेतन वृद्धि के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।  
3. हीट मैप अप्रैल 2023 से अगस्त 2025 तक के डेटा पर लागू किया गया है।  
4. हीट मैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक रंग ग्रेडिएंट स्कीम में परिवर्तित करता है, जिसमें लाल रंग न्यूनतम मानों को दर्शाता है और हरा रंग संबंधित डेटा शृंखला के उच्चतम मानों को दर्शाता है।  
5. सभी पीएमआई मान सूचकांक के रूप में दर्शाए जाते हैं। 50 से अधिक पीएमआई मान विस्तार को दर्शाता है, 50 से कम संकुचन को और 50 'कोई परिवर्तन नहीं' को दर्शाता है। पीएमआई हीट मैप्स में, लाल रंग न्यूनतम मान को दर्शाता है, पीला रंग 50 (या कोई परिवर्तन नहीं) को दर्शाता है, और हरा रंग प्रत्येक पीएमआई शृंखला में उच्चतम मान को दर्शाता है।  
**स्रोत:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार; एस एंड पी ग्लोबल; कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और इन्फो एज।

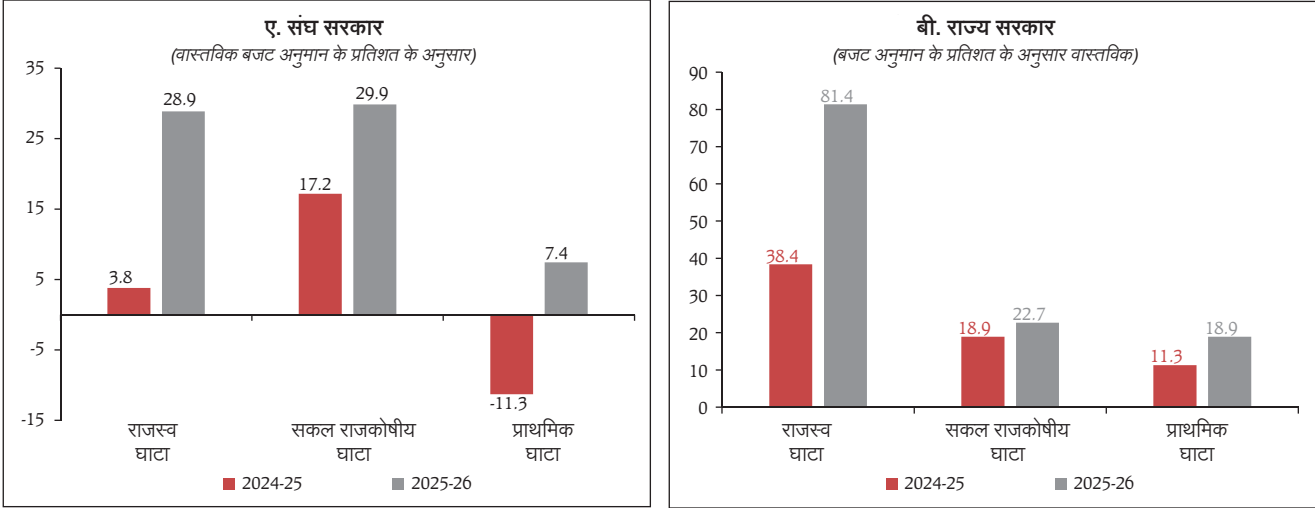
कारण प्रत्यक्ष कर संग्रह, विशेष रूप से आयकर में कमी है।<sup>7</sup> हालांकि, अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि मोटे तौर पर पिछले वर्ष के अनुरूप थी।

अप्रैल-जुलाई 2025 के दौरान राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा, वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों के अनुपात के रूप में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक रहा

(चार्ट III.2बी)। यह मुख्यतः राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में वृद्धि में कमी और बिक्री कर/वैट में वृद्धि में कमी के कारण था। जुलाई में राजस्व व्यय मजबूत रहा जबकि पूंजीगत व्यय धीमा रहा।

जीएसटी परिषद की 3 सितंबर की बैठक में लिए गए निर्णयों ने जीएसटी व्यवस्था में प्रमुख संरचनात्मक सुधारों को

चार्ट III. 2: प्रमुख राजकोषीय संकेतक (जुलाई के अंत तक)



**टिप्पणियाँ:** 1. बजट अनुमानों के प्रतिशत के अनुसार ऋणात्मक प्राथमिक घाटे की संख्या प्राथमिक अधिशेष को इंगित करती है।  
2. चार्ट बी में, डेटा 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है।

**स्रोत:** लेखा महानियंत्रक; और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।

<sup>7</sup> प्रत्यक्ष करों में, आयकर राजस्व में कमी आई, हालाँकि कॉरपोरेट कर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई 26-2025 के अंत तक आयकर में 9.9 प्रतिशत की कमी आई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में इसमें 53.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

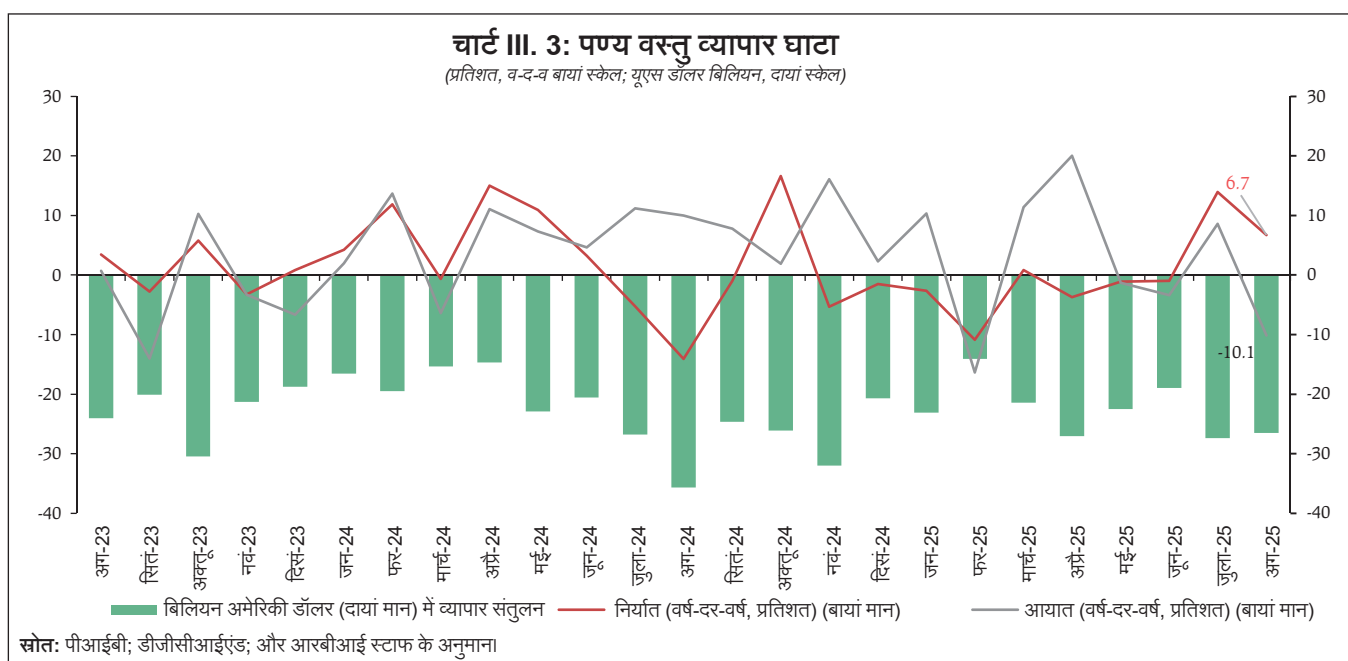
गति दी, जिससे दरें और प्रक्रियाएं सरल हो गईं। चार मौजूदा स्लैब (18, 12, 5 और 28 प्रतिशत) को मुख्य रूप से दो (5 और 18 प्रतिशत) में सुव्यवस्थित किया गया है, जिसमें सभी क्षेत्रों में युक्तिकरण किया गया है। नया ढांचा आम आदमी की जरूरतों को प्रशासन में आसानी के साथ संतुलित करने के लिए बनाया गया है। अधिकांश आवश्यक वस्तुओं पर अब या तो 'शून्य' या 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और मोटर वाहनों पर 18 प्रतिशत कर लगेगा (अनुबंध सारणी ए2)। विलासिता और पाप वस्तुओं के लिए एक नई श्रेणी भी बनाई गई है, जो 40 प्रतिशत कर योग्य है। दर सरलीकरण के अलावा, सुधार उल्टे शुल्क ढांचे से संबंधित चुनौतियों का भी समाधान करते हैं। प्रक्रियाओं को व्यवसाय के अनुकूल भी बनाया गया है कुल मिलाकर, इन सुधारों से कर-वृद्धि में वृद्धि, अनुपालन में सुधार, तथा जीवन-यापन में सुगमता के साथ-साथ व्यापार करने में भी सुगमता आने की उम्मीद है।

### व्यापार

गैर-तेल घाटे में कमी के कारण व्यापारिक व्यापार घाटा अगस्त 2024 में 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च घाटे से अगस्त 2025 में 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम हो गया (चार्ट III.3)।<sup>8</sup>

व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में लगातार दूसरे महीने वृद्धि हुई (अनुबंध चार्ट ए3)।<sup>9</sup> इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, रत्न एवं आभूषण, पेट्रोलियम उत्पाद; तथा दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स का प्रदर्शन अच्छा रहा, जबकि तम्बाकू, सभी प्रकार के रेडीमेड वस्त्र और लौह अयस्क ने निर्यात में नकारात्मक योगदान दिया।

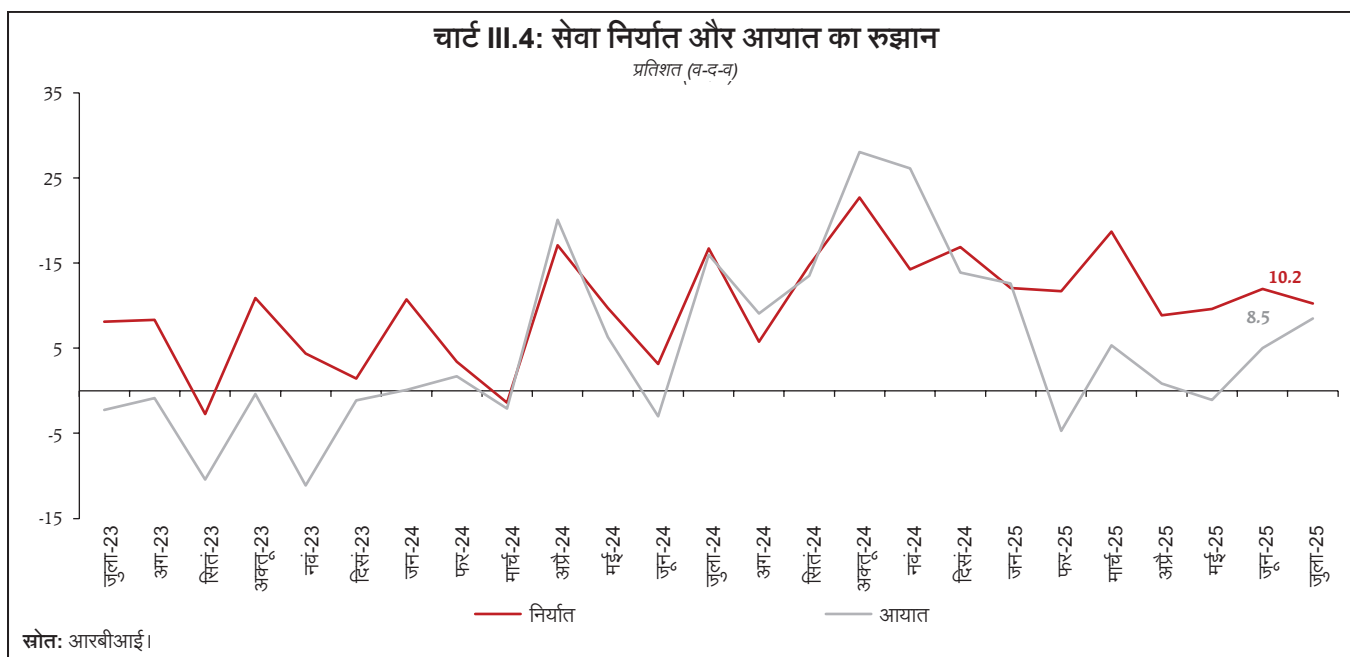
अगस्त 2025 में व्यापारिक वस्तुओं के आयात में कमी आई (अनुबंध चार्ट ए4)।<sup>10</sup> पेट्रोलियम कच्चे तेल और उसके उत्पादों, उर्वरकों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, वनस्पति तेल और मशीनरी ने महीने के दौरान आयात वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया। सोना, परिवहन उपकरण, कोयला, कोक और ब्रिकेट, चाँदी, और लोहा एवं इस्पात के आयात में कमी आई।



<sup>8</sup> तेल व्यापार घाटा अगस्त में बढ़कर 8.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले 7.9 अरब अमेरिकी डॉलर था। कुल व्यापार घाटे में इसकी हिस्सेदारी अगस्त में बढ़कर 33.2 प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 22.2 प्रतिशत थी। गैर-तेल घाटा अगस्त में घटकर 17.7 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि एक वर्ष पहले यह 27.7 अरब अमेरिकी डॉलर था।

<sup>9</sup> अगस्त में 35.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर [6.7 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)]

<sup>10</sup> अगस्त में 61.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर [10.1 प्रतिशत की गिरावट (वर्ष दर वर्ष)]



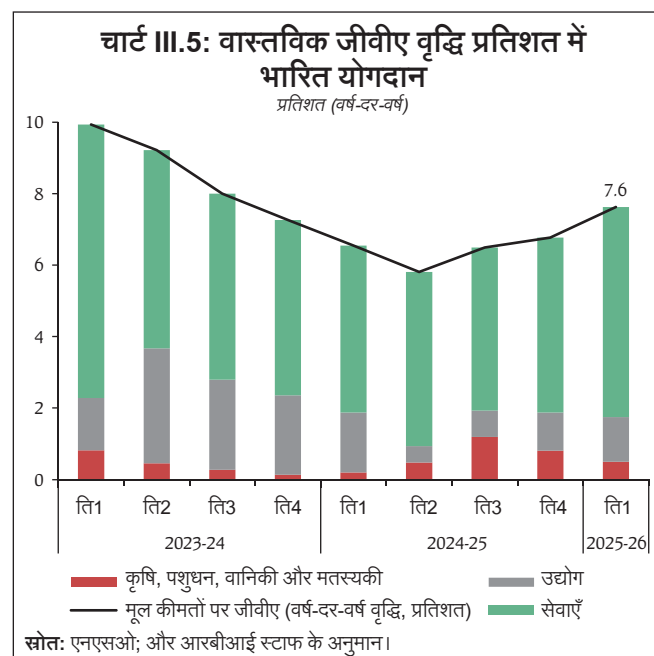
जुलाई 2025 में सेवा व्यापार मजबूत बना रहा। निवल सेवा निर्यात आय 12.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 16.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई (चार्ट III.4)। सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं के बल पर सेवा निर्यात में वृद्धि हुई। इसी समय, आयात में भी तेजी से वृद्धि हुई, जो सॉफ्टवेयर, व्यावसायिक और यात्रा सेवाओं के आयात में वृद्धि को दर्शाता है।

### समग्र आपूर्ति

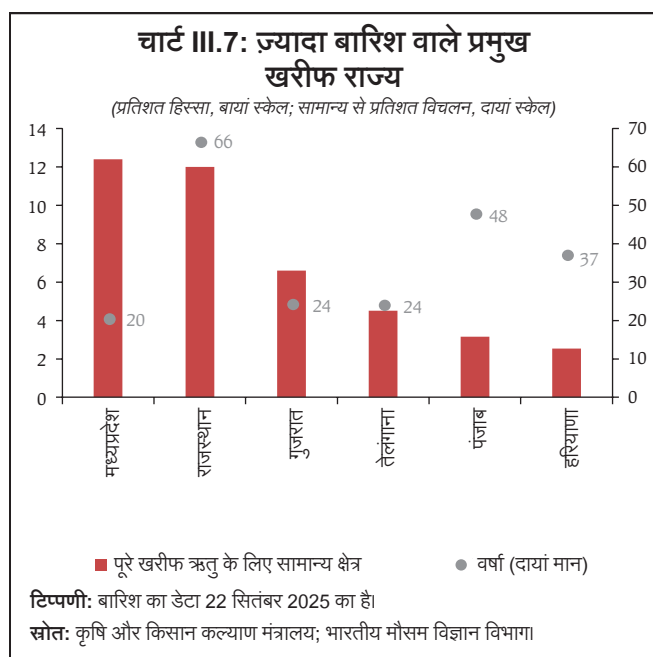
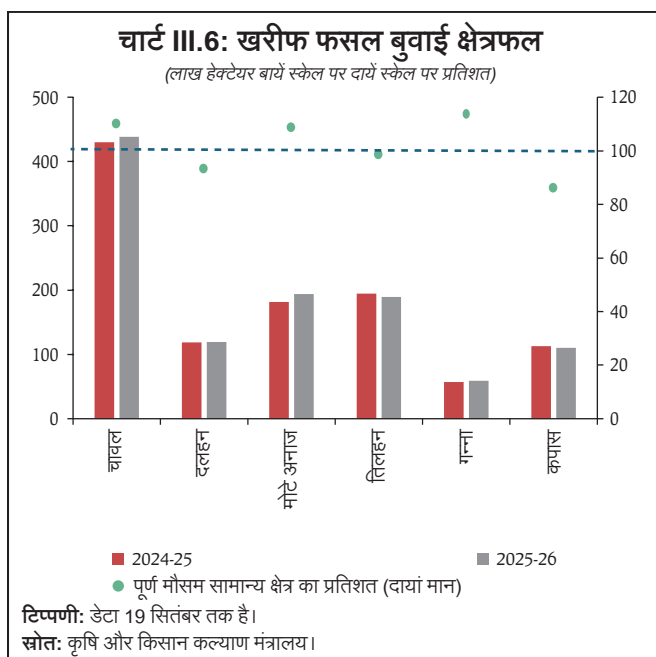
आपूर्ति पक्ष पर, बुनियादी कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) ने पिछली तिमाही में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में ति1: 2025-26 में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वास्तविक जीवीए वृद्धि में तिमाही गति एक मजबूत सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से प्रेरित थी। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में पिछली तिमाही की तुलना में क्रमिक रूप से कमी आई, फिर भी उनका प्रदर्शन वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मजबूत रहा, जो सुदृढ़ता को दर्शाता है (चार्ट III.5 और अनुबंध सारणी ए3)। उद्योग और सेवाएं क्रमशः 1.3 और 5.9 प्रतिशत अंकों का योगदान करते हुए प्रमुख चालक बने रहे। विनिर्माण और निर्माण में उच्च मांग और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलने से मजबूत विस्तार हुआ।

### कृषि

सामान्य से अधिक मानसूनी वर्षा के कारण खरीफ की बुवाई पूरे सीजन के लिए सामान्य क्षेत्रफल से अधिक रही (चार्ट III.6)<sup>11</sup> बुवाई क्षेत्र में वृद्धि मुख्यतः चावल, मक्का, उड़द और गन्ने के क्षेत्र में हुई, जबकि तिलहन और कपास के क्षेत्र में गिरावट



<sup>11</sup> सितम्बर, 2025 तक खरीफ की बुवाई 1115.9 लाख हेक्टेयर थी, जो सामान्य क्षेत्र का लगभग 101.8 प्रतिशत है।



आई। तुअर की कीमतों में गिरावट और इथेनॉल उत्पादन में मक्के की बढ़ती माँग के कारण तुअर के रकबे पर मक्का का बिज़ हो रहा है।<sup>12</sup>

1 जून से 22 सितंबर, 2025 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर संचयी वर्षा सामान्य स्तर से 7 प्रतिशत अधिक रही, जबकि कुछ प्रमुख खरीफ उत्पादक राज्यों में अत्यधिक वर्षा हुई (चार्ट III.7)। जलाशयों का स्तर क्षमता के 90 प्रतिशत तक पहुँच गया है, जो आगामी रबी मौसम के लिए शुभ संकेत है (चार्ट III.8)।

खरीफ और रबी विपणन सत्रों में पर्याप्त खरीद के कारण सरकार के पास चावल और गेहूँ का संयुक्त स्टॉक संतोषजनक बना रहा।<sup>13</sup>

**उद्योग और सेवाएँ**

**औद्योगिक गतिविधि के मासिक संकेतक**

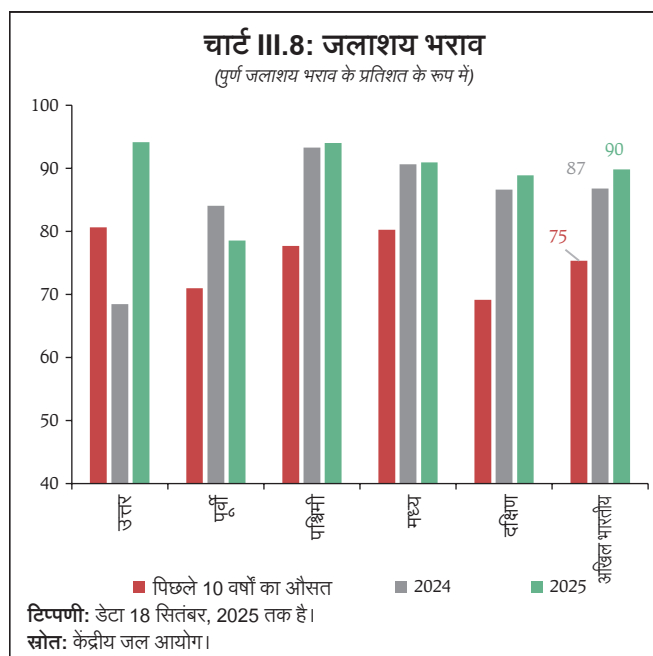
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वर्ष-दर-वर्ष बदलाव के आधार पर मापी गई औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि जुलाई 2025 में चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई।

<sup>12</sup> पिछले वर्ष की तुलना में तुअर की खेती में 0.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि मक्का की खेती में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

<sup>13</sup> 1 सितंबर, 2025 तक सार्वजनिक स्टॉक बफर मानक से 2 गुना था।

क्षेत्रीय स्तर पर, विनिर्माण क्षेत्र ने पिछले छह महीनों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की। इस्पात और कोयले में दो अंकों में वृद्धि के कारण अगस्त में आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में तेज़ उछाल आया।

अगस्त के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक विनिर्माण गतिविधि में विस्तार की ओर इशारा करते हैं, इसके पीएमआई लगभग 18 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुँच गए हैं, मांग की



स्थिति में चल रहे सुधार से कारखाने के ऑर्डर में वृद्धि हुई है। तिपहिया और दोपहिया वाहनों के मजबूत उत्पादन के कारण ऑटोमोबाइल उत्पादन मजबूत रहा। जीएसटी सुधारों से पहले डिस्पैच के पुनर्संयोजन के कारण यात्री वाहनों का उत्पादन घट गया। जीएसटी दर में कटौती के समर्थन से आगामी त्योहारी सीजन में यात्री वाहनों का उत्पादन और बिक्री बढ़ने की संभावना है। थर्मल कोयले के उत्पादन में सुधार के साथ पारंपरिक बिजली उत्पादन में सुधार हुआ। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन ने अपनी गति बनाए रखी (सारणी III.4)। आपूर्ति शृंखला का दबाव अगस्त 2025 में थोड़ा बढ़ा,

लेकिन अपने ऐतिहासिक औसत स्तर से नीचे रहा (अनुबंध चार्ट ए5)।

#### सेवा गतिविधि के मासिक संकेतक

भारत के सेवा क्षेत्र ने अगस्त में अपनी संवृद्धि गति बरकरार रखी, सेवा पीएमआई ने जून 2010 के बाद से सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात उच्च बना रहा और खुदरा वाणिज्यिक वाहन खंड में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। बंदरगाह यातायात में जुलाई की तुलना में धीमी गति से वृद्धि हुई। इस्पात की खपत में वृद्धि तेज़ हुई जबकि सीमेंट उत्पादन में कमी आई (सारणी III.5)।

सारणी III.4: उच्च आवृत्ति संकेतक- उद्योग

	अग-24	सितं-24	अक्तू-24	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फ़र-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25
आईआईपी-शीर्षक	0.0	3.2	3.7	5.0	3.7	5.2	2.7	3.9	2.6	1.9	1.5	3.5	
आईआईपी विनिर्माण	1.2	4.0	4.4	5.5	3.7	5.8	2.8	4.0	3.1	3.2	3.7	5.4	
आईआईपी पूंजीगत वस्तुएँ	0.0	3.5	2.9	8.9	10.5	10.2	8.2	3.6	14.0	13.3	3.0	5.0	
पीएमआई विनिर्माण	57.5	56.5	57.5	56.5	56.4	57.7	56.3	58.1	58.2	57.6	58.4	59.1	59.3
पीएमआई निर्यात आदेश	54.4	52.9	53.6	54.6	54.7	58.6	56.3	54.9	57.6	56.9	60.6	57.3	56.1
पीएमआई विनिर्माण : भावी उत्पादन	62.1	61.6	62.1	65.5	62.5	65.1	64.9	64.4	64.6	63.1	62.2	57.6	60.5
आठ प्रमुख सूचकांक	-1.5	2.4	3.8	5.8	5.1	5.1	3.4	4.5	1.0	1.2	2.2	3.7	6.3
विद्युत उत्पादन: पारंपरिक	-3.8	-1.3	0.5	2.7	4.5	-1.3	2.4	4.8	-1.8	-8.2	-6.1	-0.8	1.0
विद्युत उत्पादन: नवीकरणीय	-3.7	12.5	14.9	19.0	17.9	31.9	12.2	25.2	28.0	18.2	28.7	26.4	
ऑटोमोबाइल उत्पादन	4.4	10.1	10.0	8.0	1.3	9.4	2.3	6.5	-1.7	5.2	1.2	10.7	8.1
यात्री वाहन उत्पादन	0.7	-3.4	-4.0	6.5	9.2	3.7	4.5	11.2	10.8	5.4	-1.8	0.1	-4.1
ट्रैक्टर उत्पादन	-1.0	2.7	0.4	24.7	20.9	23.7	-7.8	18.5	20.5	9.1	9.8	11.5	9.4
दोपहिया वाहनों का उत्पादन	4.9	12.9	13.3	8.8	-0.6	10.3	1.6	5.6	-4.1	4.7	1.4	12.3	10.0
तिपहिया वाहनों का उत्पादन	9.0	3.9	-6.7	-5.5	7.6	16.2	6.5	6.0	4.1	16.9	8.6	24.0	15.8
कच्चा इस्पात उत्पादन	3.9	0.3	4.2	4.5	8.3	7.4	6.0	8.5	9.3	11.0	12.6	14.0	11.1
तैयार इस्पात उत्पादन	3.0	0.7	4.0	2.8	5.3	6.7	6.7	10.0	6.6	7.0	10.9	13.8	13.0
पूंजीगत वस्तुओं का आयात	12.3	10.9	7.0	4.7	6.1	15.5	-0.5	8.6	21.5	14.3	2.6	12.2	

< संकुचन ..... विस्तार >>

टिप्पणियाँ : 1. सभी संकेतकों (पीएमआई को छोड़कर) के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।

2. हीट मैप प्रत्येक संकेतक के डेटा रेंज को एक रंग ग्रेडिएंट स्कीम में परिवर्तित करता है, जिसमें लाल रंग न्यूनतम मानों को दर्शाता है और हरा रंग संबंधित डेटा शृंखला के उच्चतम मानों के अनुरूप होता है।

3. हीट मैप अप्रैल 2023 से अगस्त 2025 तक के डेटा पर लागू होता है, आईआईपी और बिजली उत्पादन: नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर, जहाँ डेटा जून 2025 तक है।

4. सभी पीएमआई मान सूचकांक के रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं। >50 से अधिक पीएमआई मान विस्तार को दर्शाता है, <50 से कम संकुचन को दर्शाता है और =50 कोई परिवर्तन नहीं को दर्शाता है। पीएमआई हीट मैप में, लाल रंग न्यूनतम मान को दर्शाता है, पीला रंग 50 (या कोई परिवर्तन नहीं) को दर्शाता है, और हरा रंग प्रत्येक पीएमआई शृंखला में उच्चतम मान को दर्शाता है।

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; एस एंड पी ग्लोबल; केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय; भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसायटी (एसआईएम); आर्थिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार; संयुक्त संयंत्र समिति; वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।



सारणी III.5: उच्च आवृत्ति संकेतक- सेवाएँ													
	अग-24	सितं-24	अक्तू-24	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फ़र-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25
पीएमआई सेवाएँ	60.9	57.7	58.5	58.4	59.3	56.5	59.0	58.5	58.7	58.8	60.4	60.5	62.9
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	11.1	11.2	10.3	10.7	9.0	11.1	7.7	6.8	13.0	5.0	3.4	5.5	7.4
घरेलू हवाई माल	0.6	14.0	8.9	0.3	4.3	6.9	-2.5	4.9	16.6	2.3	2.6	4.8	
अंतरराष्ट्रीय हवाई माल	20.7	20.5	18.4	16.1	10.5	7.1	-6.3	3.3	8.6	6.8	-1.2	4.2	
बंदरगाह माल यातायात	6.7	5.8	-3.4	-5.0	3.4	7.6	3.6	13.3	7.0	4.3	5.6	4.0	2.5
खुदरा वाणिज्यिक वाहन बिक्री	-6.0	-10.4	6.4	-6.1	-5.2	8.2	-8.6	2.7	-1.0	-3.7	6.6	0.2	8.6
होटल अधिभोग	0.7	2.1	-5.3	11.1	-0.2	1.2	0.6	1.9	7.2	-2.8	-0.3	-2.4	
पर्यटक आगमन	-4.2	0.4	-1.4	-0.1	-6.6	-0.2	-8.6	-13.7	-3.8				
इस्पात खपत	14.1	13.5	12.7	12.3	11.4	11.4	11.3	11.5	6.0	7.1	7.9	7.7	8.2
सीमेंट उत्पादन	-2.5	7.6	3.1	13.1	10.3	14.3	10.7	12.2	6.3	9.7	8.2	11.6	6.1



< संकुचन ----- विस्तार >

- टिप्पणियाँ:**
- सभी संकेतकों (पीएमआई को छोड़कर) के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
  - हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा सीमा को एक कलर ग्रेडिएंट में बदल देता है जिसमें लाल रंग से संबंधित डेटा शृंखला के उच्चतम मूल्यों के अनुरूप सबसे कम मूल्य और हरे रंग को दर्शाता है।
  - हीटमैप अप्रैल 2023 से अगस्त 2025 तक डेटा पर लागू किया जाता है, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो और होटल अधिभोग के अलावा, जहां डेटा जुलाई 2025 तक है। पर्यटकों के आगमन के लिए नवीनतम डेटा अप्रैल 2025 तक है।
  - अगस्त 2025 की वृद्धि दर के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात पर डेटा की गणना दैनिक डेटा एकत्र करके की जाती है।
  - सभी पीएमआई मान सूचकांक के रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं। >50 से अधिक पीएमआई मान विस्तार को दर्शाता है, <50 से कम संकुचन को दर्शाता है और =50 कोई परिवर्तन नहीं को दर्शाता है। पीएमआई हीट मैप में, लाल रंग न्यूनतम मान को दर्शाता है, पीला रंग 50 (या कोई परिवर्तन नहीं) को दर्शाता है, और हरा रंग प्रत्येक पीएमआई शृंखला में उच्चतम मान को दर्शाता है।

**स्रोत:** फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए); इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; एचवीएस एनारॉक; पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार; संयुक्त संयंत्र समिति; आर्थिक सलाहकार कार्यालय; और एस और पी ग्लोबल।

मुद्रास्फीति

मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति<sup>14</sup> में मामूली वृद्धि हुई, और यह वृद्धि मुख्यतः खाद्य समूह से हुई (चार्ट III.9)। जुलाई में 1.6 प्रतिशत की तुलना में अगस्त में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 2.1 प्रतिशत रही।

जून-जुलाई में अपस्फीति के बाद, अगस्त में खाद्य समूह में शून्य मुद्रास्फीति दर्ज की गई। तेल और वसा, अंडे, मांस और मछली तथा चीनी जैसे उप-समूहों में मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई। अनाज, फल, दूध, तैयार भोजन और गैर-मादक पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति में कमी देखी गई। सब्जियों, दालों और मसालों में अपस्फीति जारी रही (चार्ट III.10)।

अगस्त में ईंधन और प्रकाश मुद्रास्फीति में कमी आई, जबकि एलपीजी के लिए मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही।

<sup>14</sup> राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 12 सितंबर, 2025 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

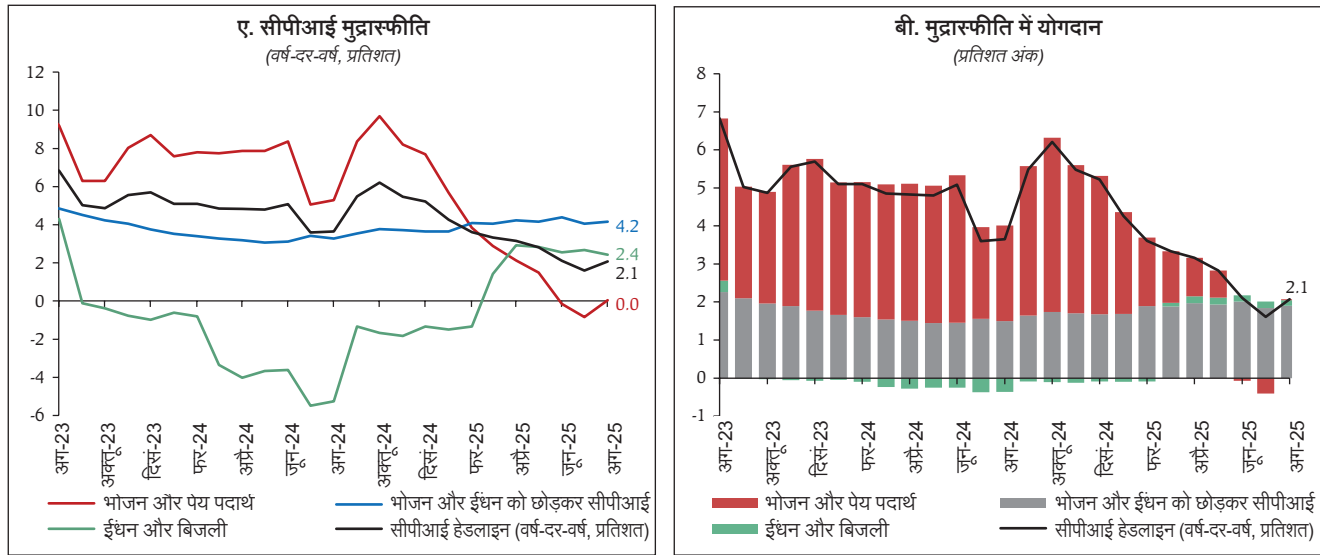
जबकि बिजली के लिए इसमें कमी आई<sup>15</sup> केरोसिन की कीमतें निरंतर अपस्फीति में रहीं।

मूल मुद्रास्फीति जुलाई के 4.1 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त में 4.2 प्रतिशत हो गई। मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्यतः 'व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव'<sup>16</sup> उप-समूह के कारण हुई, जो स्वर्ण की बढ़ती कीमतों के कारण हुई। अगस्त में मूल मुद्रास्फीति में स्वर्ण का योगदान लगभग 28 प्रतिशत रहा। हालाँकि, कपड़े और जूते, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, और परिवहन एवं संचार जैसे अन्य उप-समूहों में मुद्रास्फीति में कमी आई।

अगस्त में ग्रामीण और शहरी दोनों ही मुद्रास्फीति क्रमशः 1.7 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत तक बढ़ गई। राज्य-स्तरीय मुद्रास्फीति दरें (-) 1.40 प्रतिशत और 9.04 प्रतिशत के

<sup>15</sup> ईंधन और प्रकाश उपसमूह में मुद्रास्फीति अगस्त में 2.4 प्रतिशत थी।  
<sup>16</sup> सीपीआई बास्केट में 'व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव' उप-समूह में साबुन, हेयर ऑयल और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों के अलावा स्वर्ण और चांदी जैसी कीमती धातु की वस्तुएं भी शामिल हैं।

चार्ट III.9: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और कारण



स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

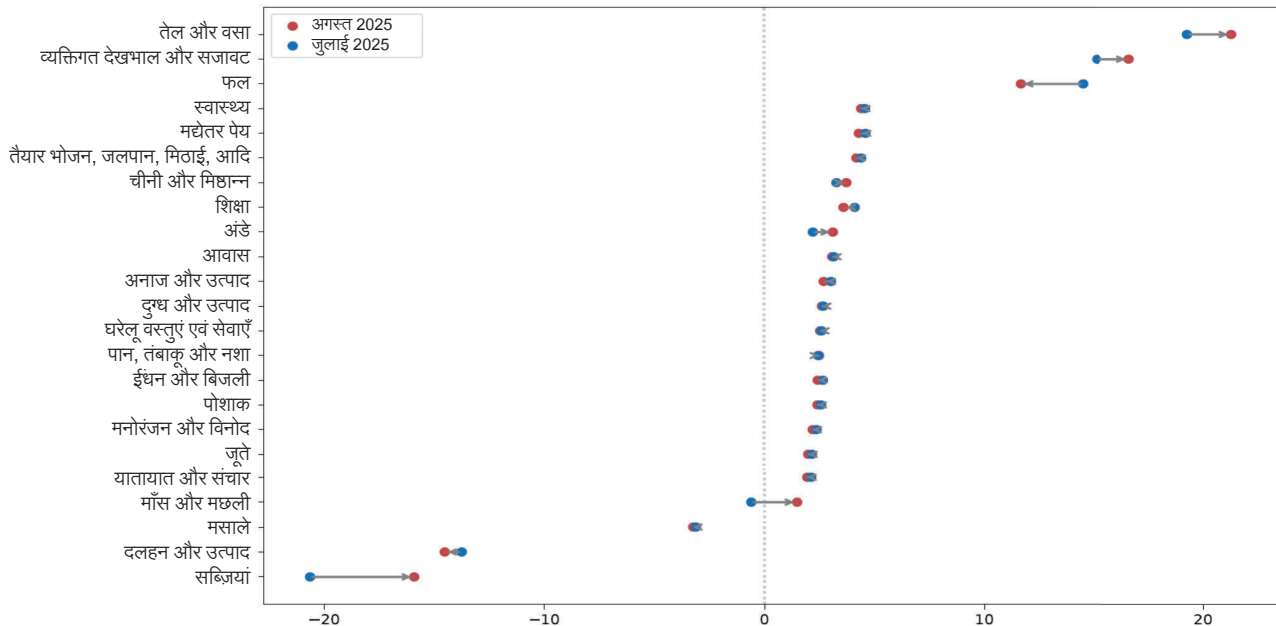
बीच रही, लेकिन अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे रही, केवल दो राज्यों में मुद्रास्फीति अधिक दर्ज की गई (चार्ट III.11)।

सितंबर के अब तक (19 तारीख तक) उच्च-आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य आँकड़े अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हैं। दालों में मिला-जुला रुख रहा, तुअर/अरहर दाल और

मूंग दाल की कीमतों में गिरावट और चना दाल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। खाद्य तेलों में, सरसों, सूरजमुखी और पाम तेल की कीमतों में मजबूती आई, जबकि मूंगफली तेल की कीमतों में कमी आई। टमाटर की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट के साथ प्रमुख सब्जियों (आलू, प्याज और टमाटर) की कीमतों में नरमी आई (चार्ट III.12)।

चार्ट III.10: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति

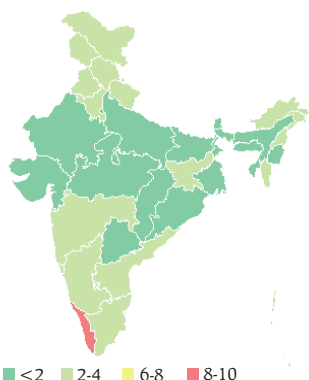
(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत)



स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।



**चार्ट III.11: मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण: अगस्त 2025 (सीपीआई-संयुक्त)**  
(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)



मुद्रास्फीति की सीमा	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या
<2	18
2-4	17
4-6	0
6-8	1
8-10	1

मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या
गिरावट	16
स्थिर	0
वृद्धि	21

टिप्पणी: मानचित्र केवल उदाहरण के लिए है।

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

**सारणी III.6: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें**

वस्तु	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		सितं-24	अग-25	सितं-25^	अग 25	सितं-25^
पेट्रोल	₹/लीटर	100.97	101.12	101.12	0.0	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	90.42	90.53	90.53	0.0	0.0
केरोसिन (सब्सिडी वाला)	₹/लीटर	45.78	44.47	44.25	3.4	-0.5
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	813.25	863.25	863.25	0.0	0.0

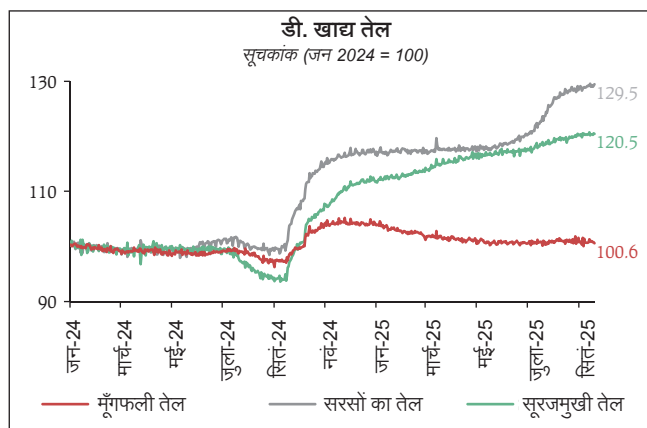
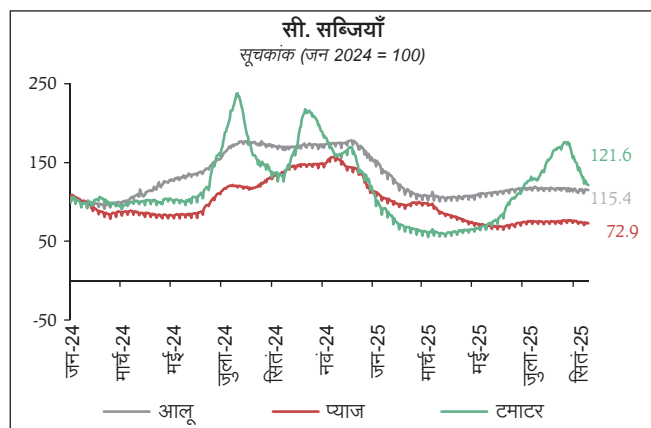
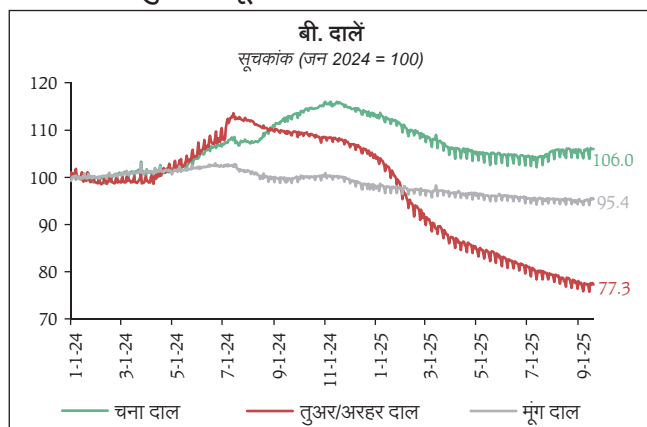
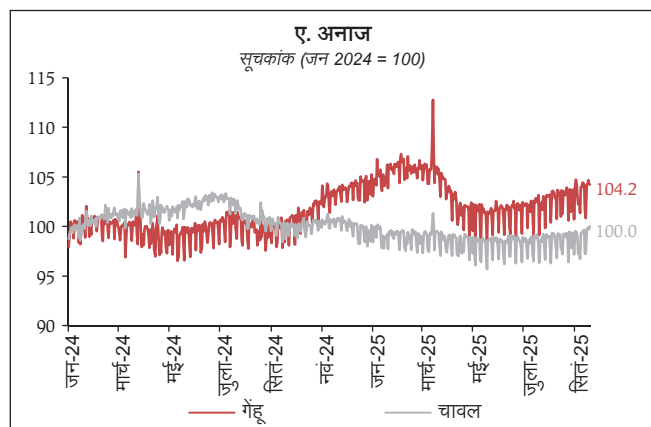
^: 1-19 सितंबर 2025 की अवधि के लिए।

**टिप्पणी:** केरोसिन के अलावा, ये कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसिन के लिए, ये कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाले मूल्यों का औसत दर्शाती हैं।

**स्रोत:** आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

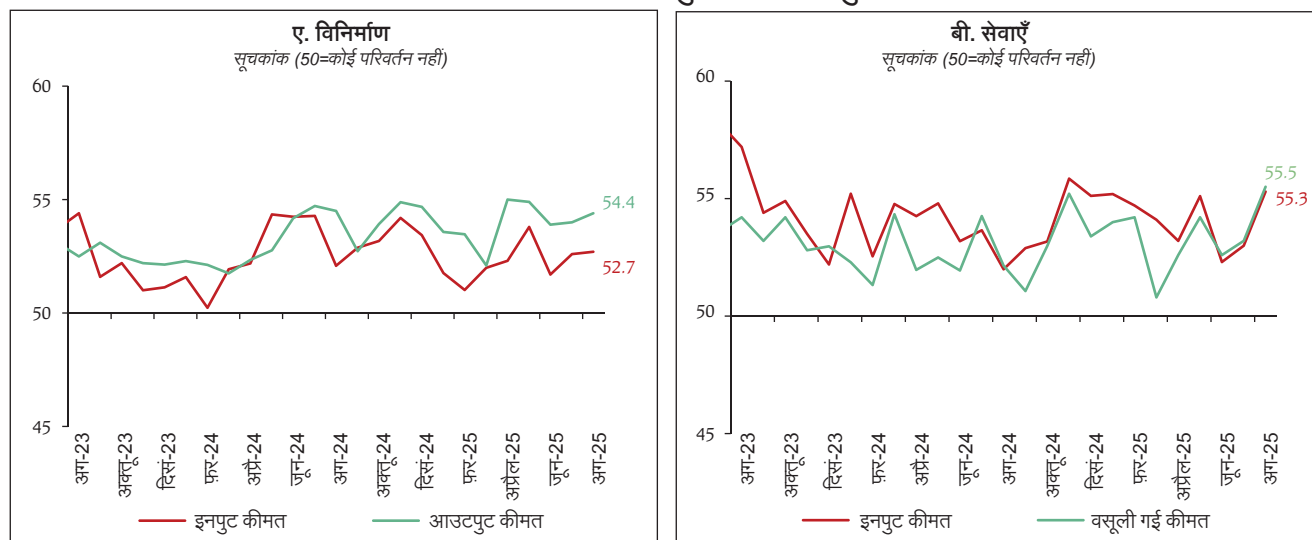
सितंबर में पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा बिक्री कीमतें (19 तारीख तक) अपरिवर्तित रहीं। केरोसिन की कीमतों में थोड़ी कमी आई, जबकि रसोई गैस की कीमतें अपरिवर्तित रहीं (सारणी III.6)।

**चार्ट III.12: डीसीए आवश्यक पण्य वस्तुओं के मूल्य**



स्रोत: उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार; और भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ के अनुमान।

चार्ट III.13: पीएमआई: इनपुट और आउटपुट कीमतें



टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं दर्शाता है और 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।

स्रोत: एस और पी।

अगस्त 2025 के पीएमआई में विनिर्माण क्षेत्र के लिए इनपुट कीमतों में वृद्धि की दर में वृद्धि दर्ज की गई, जो धातुओं, चमड़े और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की बढ़ी हुई कीमतों के कारण बढ़ी। सेवाओं में भी, वेतन वृद्धि के कारण इनपुट लागत में वृद्धि हुई। मांग की स्थिति में मजबूती के कारण सेवाओं और विनिर्माण दोनों कंपनियों के लिए विक्रय मूल्यों में भी तेजी आई (चार्ट III.13)।

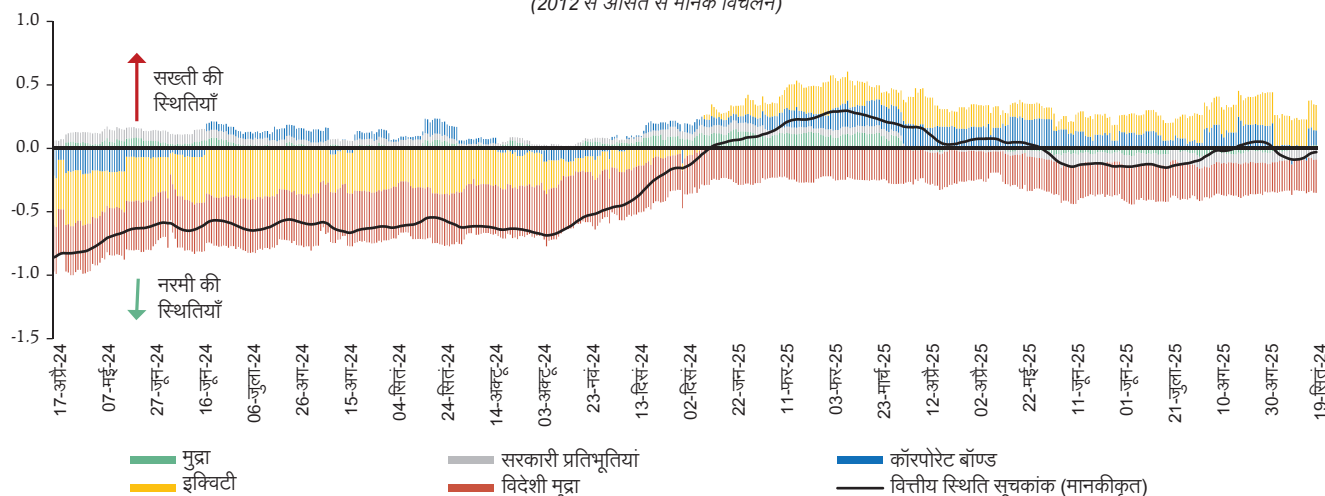
#### IV. वित्तीय स्थितियाँ

सितंबर की शुरुआत से समग्र वित्तीय स्थितियाँ अनुकूल हो गई हैं, जिसका मुख्य कारण कॉर्पोरेट बाण्ड बाजार में नरमी है (चार्ट IV.1)।

अगस्त और सितंबर (19 सितंबर तक) के दौरान प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में रही। 6 सितंबर से प्रभावी नकद आरक्षित

चार्ट IV.1: भारत के लिए दैनिक वित्तीय स्थिति सूचकांक

(2012 से औसत से मानक विचलन)



टिप्पणियाँ: वित्तीय स्थिति सूचकांक (एफसीआई) अपने ऐतिहासिक औसत पर आधारित एक मीट्रिक प्रदान करता है; इस संदर्भ में, एफसीआई का शून्य मान, एफसीआई में शामिल सभी वित्तीय संकेतकों के ऐतिहासिक औसत स्तर पर संचालित एक वित्तीय प्रणाली के अनुरूप होता है। परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए, मानकीकृत एफसीआई का उपयोग किया जाता है।<sup>17</sup>

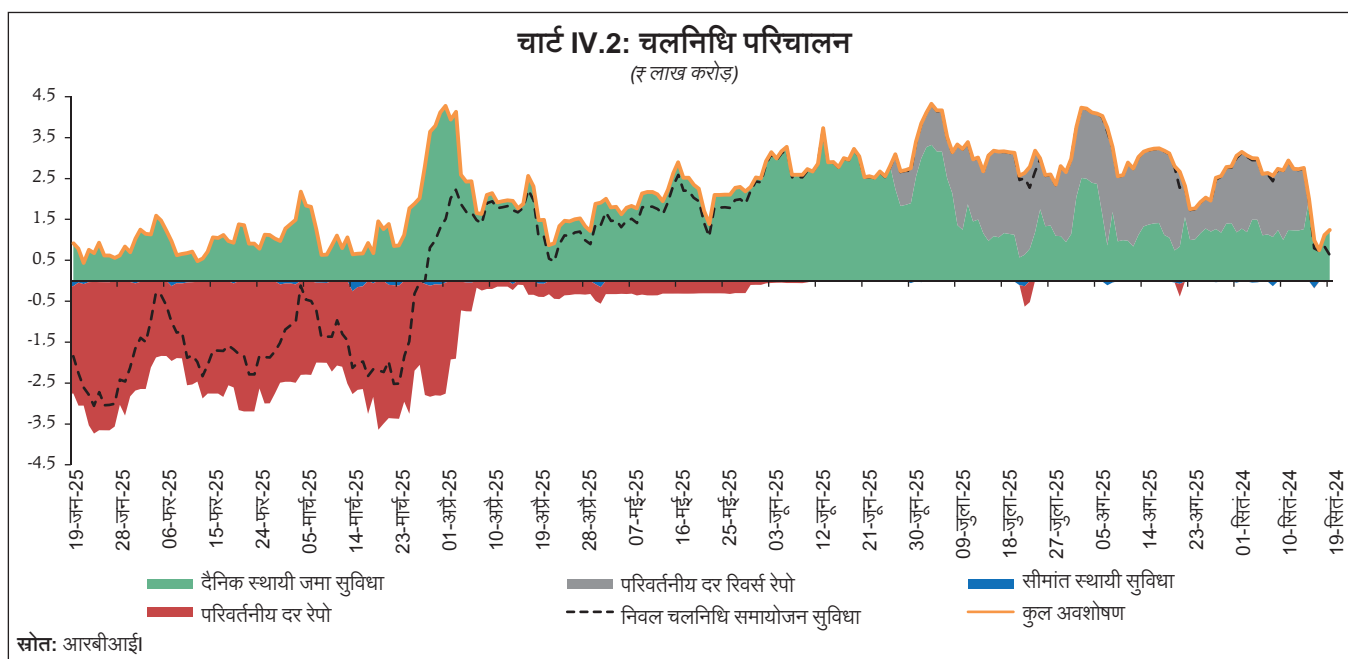
स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

<sup>17</sup> विस्तृत कार्यप्रणाली के लिए देखें [https://आरबीआई.org.in/Scripts/BS\\_ViewBulletin.aspx?Id=23451](https://आरबीआई.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=23451)

अनुपात में 25 बीपीएस की कमी ने बैंकिंग प्रणालीगत चलनिधि की सहायता की। चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण 16 अगस्त से 19 सितंबर 2025 के दौरान ₹2.4 लाख करोड़ रहा, जबकि इससे पहले की एक महीने की अवधि में यह ₹3.09 लाख करोड़ था (चार्ट IV.2)। इस अवधि के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित करने और पॉलिसी रेपो दर के साथ एकदिवसीय मुद्रा बाज़ार दरों को संरेखित करने के लिए 5 परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामियों (एक दिवसीय से -8 दिवसीय परिपक्वता) का आयोजन किया। अधिशेष चलनिधि की स्थिति के बीच, स्थायी जमा सुविधा के तहत औसत शेष राशि लगातार ऊंची बनी रही और बैंकों का सीमांत स्थायी सुविधा का सहारा कम रहा।<sup>18</sup> रिज़र्व बैंक ने टैक्स आउटफ्लो की वजह से होने वाले चलनिधि के दबाव को कम करने के लिए 21 अगस्त और 16 से 19 सितंबर को परिवर्तनीय रेट रेपो नीलामी भी की।

### मुद्रा बाज़ार

अधिशेष चलनिधि के बीच, भारत औसत कॉल दर – मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य – आम तौर पर अगस्त में कॉरिडोर के निचले आधे हिस्से और सितंबर के पहले आधे हिस्से में मँडराती रही। हालांकि, यह 19-15 सितंबर के दौरान सख्त हो गई क्योंकि कर बहिर्वाह के कारण सिस्टम चलनिधि कम हो गई (चार्ट IV.3ए)।<sup>19</sup> संपार्श्विक खंडों में रातोंरात दरें – त्रिपक्षीय और बाज़ार रेपो – और बेंचमार्क सुरक्षित एकदिवसीय रुपया दर बड़े पैमाने पर गैर-संपार्श्विक दर के साथ बढ़ी। तीन महीने के खजाना बिल, जमा प्रमाणपत्र और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्रों पर प्रतिफल इस अवधि के दौरान कम हो गया (चार्ट IV.3बी)।<sup>20</sup> मुद्रा बाज़ार में औसत जोखिम प्रीमियम (3 महीने के वाणिज्यिक पत्र और -91 दिवसीय खजाना बिल पर प्रतिफल के बीच का अंतर) मामूली रूप से बढ़ा।<sup>21</sup>



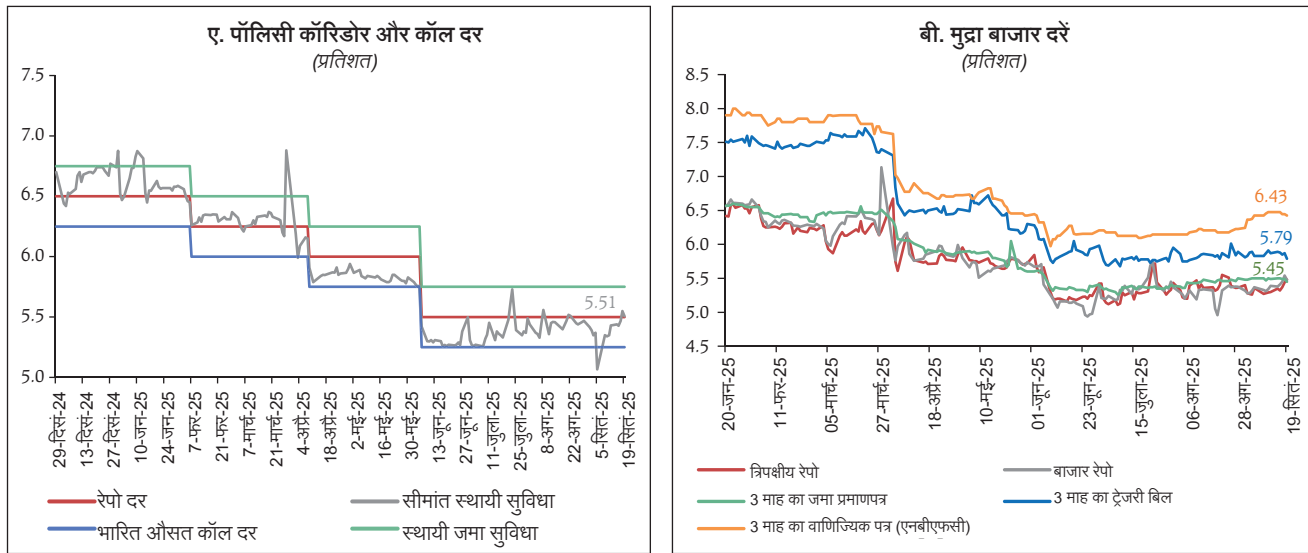
<sup>18</sup> स्थायी जमा सुविधा के अंतर्गत जमाशेष राशि 16 अगस्त से 19 सितंबर, 2025 के दौरान 1.21 ₹ लाख करोड़ थी, जबकि इससे पिछले एक महीने की अवधि में यह 1.32 ₹ लाख करोड़ थी। इस अवधि के दौरान एमएसएफ औसतन 0.03 ₹ लाख करोड़ रहा।

<sup>19</sup> 16 अगस्त से 19 सितंबर, 2025 की अवधि के दौरान प्रसार औसत (-) 8 बीपीएस रहा, जबकि 16 जुलाई से 15 अगस्त, 2025 की अवधि के दौरान प्रसार औसत (-) 6 बीपीएस रहा।

<sup>20</sup> 3 महीने के खजाना बिल, एनबीएफसी द्वारा जारी 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र, और 3 महीने के जमा प्रमाणपत्र पर औसत प्रतिफल 16 जुलाई से 15 अगस्त 2025 की अवधि की तुलना में 16 अगस्त से 19 सितंबर 2025 की अवधि के दौरान क्रमशः 9 बीपीएस, 18 बीपीएस और 5 बीपीएस तक बढ़ गई।

<sup>21</sup> अगस्त 16 से 19 सितंबर 2025 की अवधि के दौरान 86 बीपीएस तक बढ़ गया, जबकि पूर्ववर्ती एक माह की अवधि में यह 76 बीपीएस था।

चार्ट IV.3: पॉलिसी कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दरें



स्रोत: आरबीआई; भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड; और ब्लूमबर्ग।

### सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार

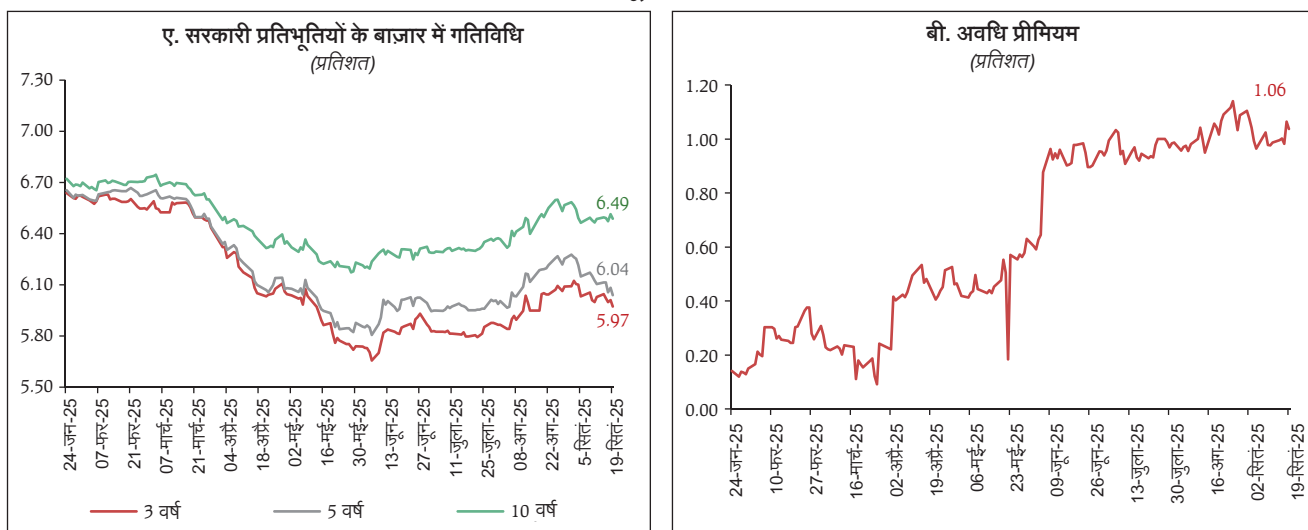
निश्चित आय खंड में, अगस्त में प्रतिफल में वृद्धि हुई, लेकिन सितंबर में इसमें नरमी आई, क्योंकि बाजारों ने सरकार द्वारा राजकोषीय मजबूती के मार्ग पर पुनः जोर देने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। औसत अवधि प्रीमियम (-10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों और -91दिवसीय खजाना बिल के प्रतिफल के बीच का अंतर) 16 अगस्त से 19 सितंबर, 2025

के दौरान पिछले एक महीने की अवधि की तुलना में 7 आधार अंकों (बीपीएस) बढ़ गया (चार्ट IV.4ए और IV.4बी)।

### कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार

कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल में अवधि और रेटिंग स्पेक्ट्रम में मिश्रित उतार-चढ़ाव देखा गया, जबकि संबंधित जोखिम-मुक्त दरों पर उनके प्रसार में गिरावट आई (सारणी IV.1)। कॉर्पोरेट बॉण्ड

चार्ट IV.4: सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में गतिविधि



टिप्पणी: चार्ट बी में, टर्म प्रीमियम की गणना 10 साल की जी-सेक उपज और 91-दिवसीय खजाना बिल प्रतिफल के बीच के अंतर के रूप में की जाती है।

स्रोत: ब्लूमबर्ग; एफआईएमएमडीए; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी IV.1: कॉरपोरेट बॉण्ड- दरें और स्प्रेड						
लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) (संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक)		
	16 जुलाई 2025- 15 अगस्त 2025	16 अगस्त 2025- 18 सितंबर 2025	अंतर	16 जुलाई 2025- 15 अगस्त 2025	16 अगस्त 2025- 18 सितंबर 2025	अंतर
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
(i) एएए (1-वर्ष)	6.56	6.58	2	93	91	-2
(ii) एएए (3-वर्ष)	6.95	7.01	6	97	94	-3
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.13	7.10	-3	95	81	-14
(iv) एए (3-वर्ष)	8.02	7.94	-8	204	199	-5
(v) बीबीबी- (3-वर्ष)	11.64	11.38	-26	567	567	0

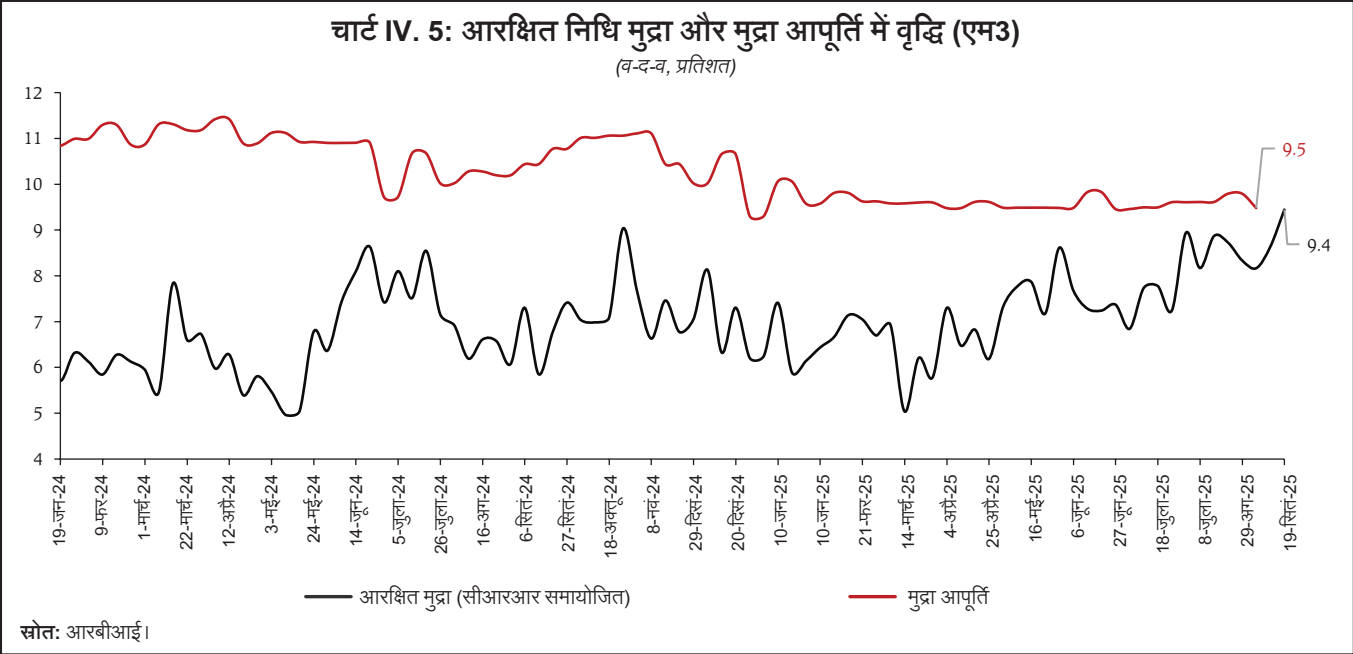
टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के लिए औसत के रूप में की जाती है।  
स्रोत: एफआईएमएमडीए।

जारी करने की संख्या संचयी आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रही, हालाँकि जुलाई में इसमें कुछ गिरावट आई<sup>22</sup>

मुद्रा और ऋण

नकद आरक्षित अनुपात में बदलावों के पहले दौर के प्रभाव को समायोजित करते हुए, आरक्षित निधि मुद्रा वृद्धि

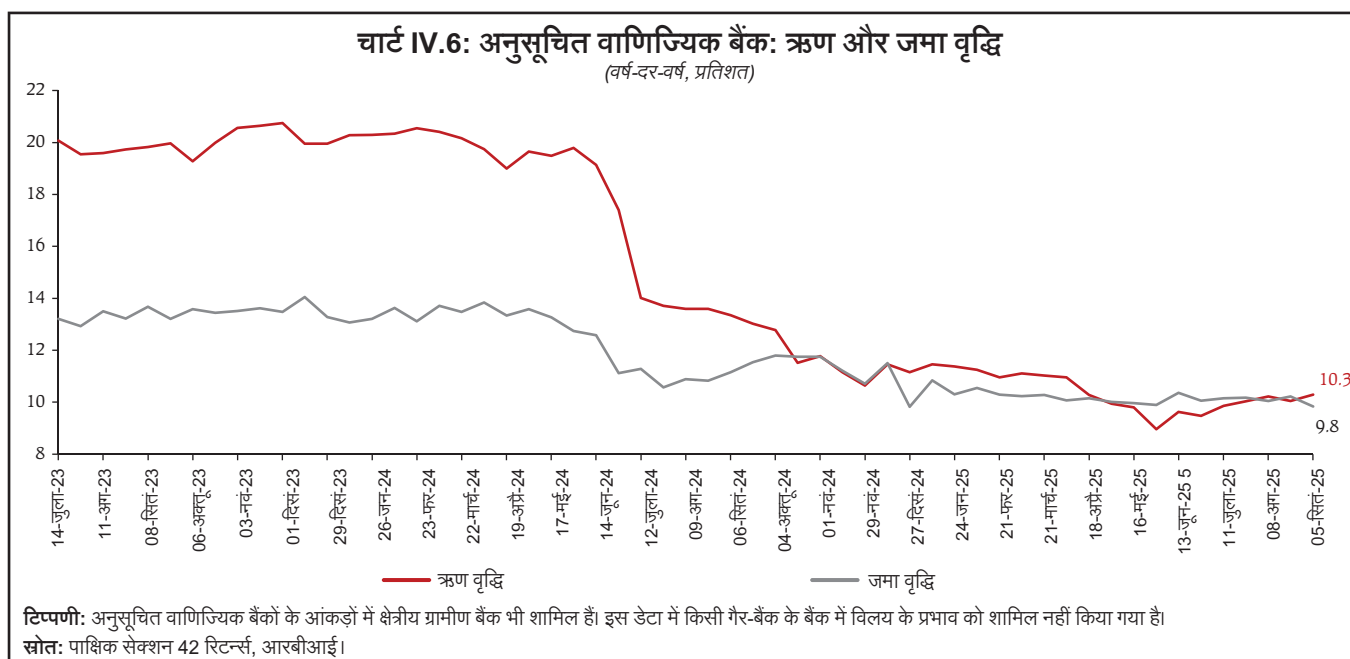
सितंबर में बढ़ी, जो संचलन में मुद्रा में वृद्धि के अनुरूप थी। संचलन मुद्रा में वृद्धि त्योहारी मौसम और खरीफ की फसल की गतिविधियों से पहले मुद्रा की बढ़ती मांग को दर्शाती है। अगस्त के दौरान मुद्रा आपूर्ति (एम<sub>3</sub>) में वृद्धि मोटे तौर पर स्थिर रही (चार्ट IV.5)<sup>23, 24</sup>



<sup>22</sup> जुलाई 2025 में घटकर 0.58₹ लाख करोड़ रह गया, जबकि जून 2025 में यह 1.08₹ लाख करोड़ था। संचयी आधार पर (अप्रैल से जुलाई), यह 26-2025 में 3.5₹ लाख करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 2.5₹ लाख करोड़ था।

<sup>23</sup> 19 सितंबर 2025 तक आरक्षित निधि मुद्रा (सीआरआर के लिए समायोजित) में 9.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई [22 अगस्त, 2025 तक 8.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)]। 19 सितंबर, 2025 तक प्रचलन में मुद्रा में 8.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई [22 अगस्त, 2025 तक 8.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)]।

<sup>24</sup> 5 सितंबर 2025 तक मुद्रा आपूर्ति में 9.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई [8 अगस्त, 2025 तक 9.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)]। इसमें एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव भी शामिल है (1 जुलाई 2023 से प्रभावी)।



अगस्त में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि थोड़ी बढ़कर दो अंकों में पहुँच गई, जबकि जमाराशि वृद्धि स्थिर रही (चार्ट IV.6 और अनुबंध चार्ट ए7)।<sup>25</sup> 2025-26 के दौरान अब तक, वाणिज्यिक क्षेत्र में खाद्येतर बैंक ऋण का प्रवाह कम हुआ है; हालाँकि, गैर-बैंक स्रोतों से प्रवाह ने इसकी भरपाई कर दी है। परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह एक वर्ष पहले इसी अवधि की तुलना में अधिक रहा।

जुलाई में सभी प्रमुख क्षेत्रों में बैंक ऋण वृद्धि में मामूली सुधार दर्ज किया गया (अनुबंध चार्ट ए8)।<sup>26, 27</sup> सेवा क्षेत्र में, ऋण वृद्धि ने अपनी ऊपरी गति बनाए रखी, जिसका मुख्य कारण व्यापार और वाणिज्यिक अचल संपत्ति रही। व्यक्तिगत ऋणों में वृद्धि को मुख्यतः आवास ऋणों और स्वर्ण एवं अन्य व्यक्तिगत ऋण खंडों में तेजी का समर्थन प्राप्त हुआ। एमएसएमई को दिए

जाने वाले मजबूत ऋण वृद्धि के कारण उद्योग को दिए जाने वाले ऋण में मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

**जमा और उधार दरें**

फरवरी से अगस्त 2025 के दौरान रेपो दर में हुई संचयी 100 आधार अंकों की कमी का असर उधार और जमा दरों पर मजबूत रहा है। मौजूदा सहजता के दौर में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर में क्रमशः 53 आधार अंकों और 49 आधार अंकों की गिरावट आई है। जमा पक्ष पर, नई और बकाया जमाराशियों पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों में भी कमी आई है (सारणी IV.2)।

नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर में गिरावट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी बैंकों के

<sup>25</sup> अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि 5 सितंबर, 2025 तक 10.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी [एक महीने पहले 10.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)]। जमा वृद्धि 5 सितंबर, 2025 तक 9.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी [एक महीने पहले 10.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)]।

<sup>26</sup> जुलाई के अंत तक, खाद्येतर बैंक ऋण में वृद्धि 9.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही, जो जून 2025 में दर्ज 9.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) से अधिक है। खाद्येतर ऋण डेटा महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के लिए पाक्षिक खंड-42 विवरणी पर आधारित है, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को कवर करता है।

<sup>27</sup> क्षेत्रीय खाद्येतर ऋण आँकड़े क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा देने वाले चुनिंदा बैंक शामिल हैं। आँकड़ों में एक गैर-बैंक के एक बैंक में विलय का प्रभाव भी शामिल है।

## सारणी IV.2: बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(बीपीएस में भिन्नता)

		सावधि जमा दरें		उधार दरें				
अवधि	रेपो दर	डब्ल्यूएडी-टीडीआर-नया जमा	डब्ल्यूएडी-टीडीआर-बकाया जमा	ईबीएलआर	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)	डब्ल्यूएलआर -नया रुपया उधार		डब्ल्यूएलआर-बकाया रुपया उधार
						समग्र	ब्याज दर प्रभाव #	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
सख्ती की अवधि मई 2022 से जनवरी 2025	+250	259	206	250	175	181	193	115
नरमी की अवधि फरवरी 2025 से अग* 2025	-100	-101	-17	-100	-40	-53	-60	-49

टिप्पणी: ईबीएलआर पर डेटा 32 घरेलू बैंकों से संबंधित है।

\*: डब्ल्यूएडीटीडीआर और डब्ल्यूएलआर पर डेटा जून 2025 से संबंधित है। #: स्थिर मात्रा में।

डब्ल्यूएलआर: भारित औसत उधार दर; डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर;

एमसीएलआर: निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत; ईबीएलआर: बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर।

स्रोत: आरबीआई।

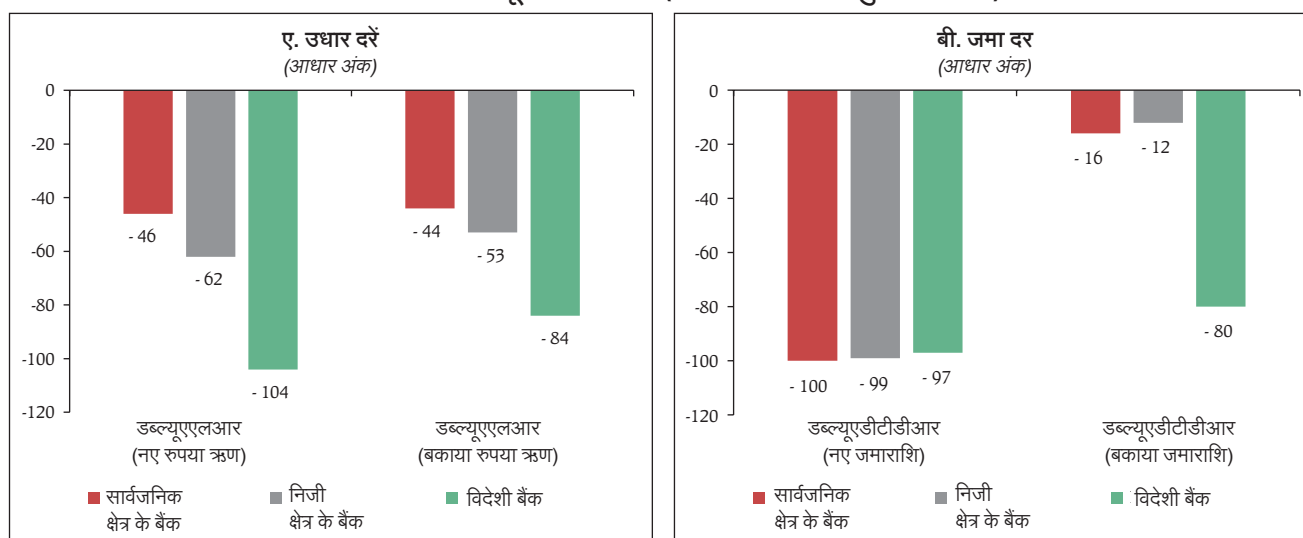
मामले में अधिक थी (चार्ट IV.7)। जमा पक्ष पर, निजी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए संचरण अधिक था।

## इक्विटी बाजार

एसएंडपी सॉवरन रेटिंग अपग्रेड और जीएसटी सुधारों की घोषणा के बाद अगस्त के मध्य में भारतीय शेयर बाजारों में तेजी आई। इसके बाद, महीने के अंत में शेयर बाजारों में गिरावट आई क्योंकि भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त अमेरिकी आयात शुल्क लागू हो गया। सितंबर की शुरुआत में निवेशकों

की धारणा में सुधार के साथ बाजारों की शुरुआत सकारात्मक रही, जिसे 26-2025 की पहली तिमाही के लिए अपेक्षा से अधिक जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों और मजबूत पीएमआई आंकड़ों के जारी होने से बल मिला। विदेशी निवेशकों की बिकवाली की गतिविधि घरेलू निवेशकों की निरंतर खरीदारी रुचि से पूरी तरह संतुलित रही (चार्ट IV.8)। घरेलू संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी के रुझान के परिणामस्वरूप उनकी शेयर बाजार में हिस्सेदारी एफपीआई से अधिक हो गई है (अनुबंध चार्ट ए9)।

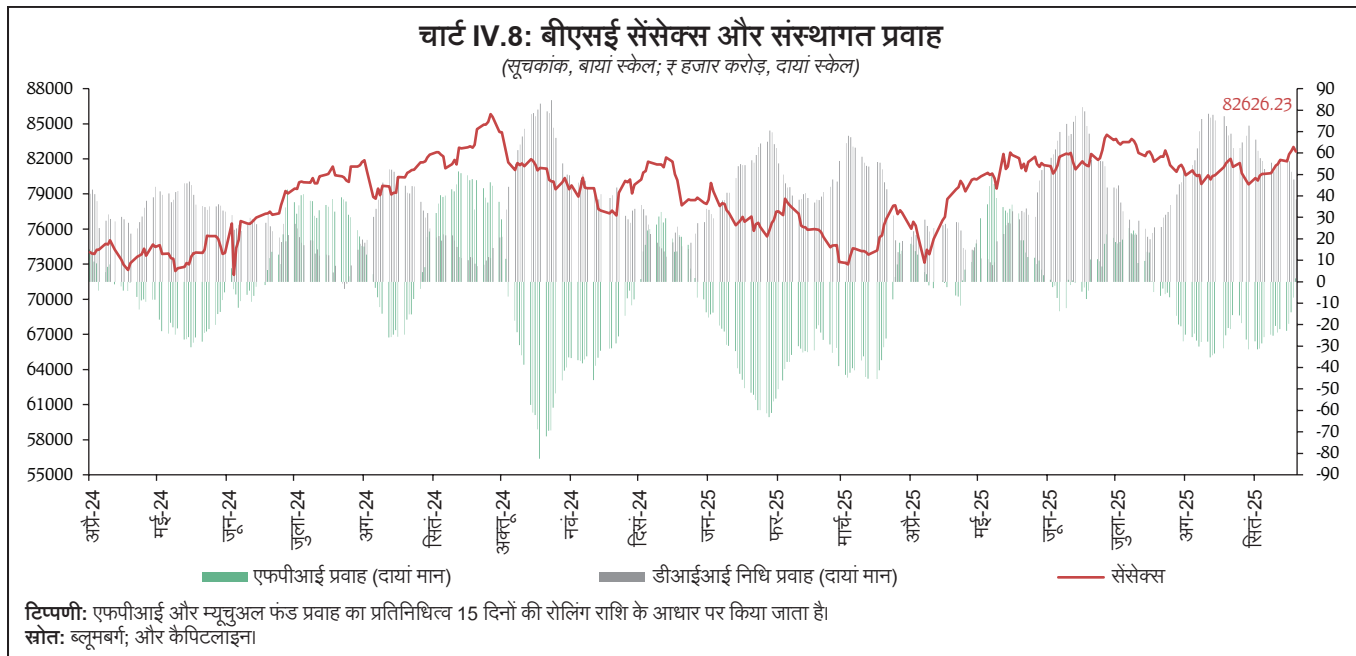
## चार्ट IV.7: बैंक समूहों में संचरण (फरवरी 2025 – जुलाई 2025)



टिप्पणी: फरवरी से जुलाई 2025 के दौरान संचरण की गणना जनवरी 2025 की भारित औसत उधार और जमा दरों को जुलाई 2025 की भारित औसत दरों से घटाकर की जाती है।

स्रोत: आरबीआई।





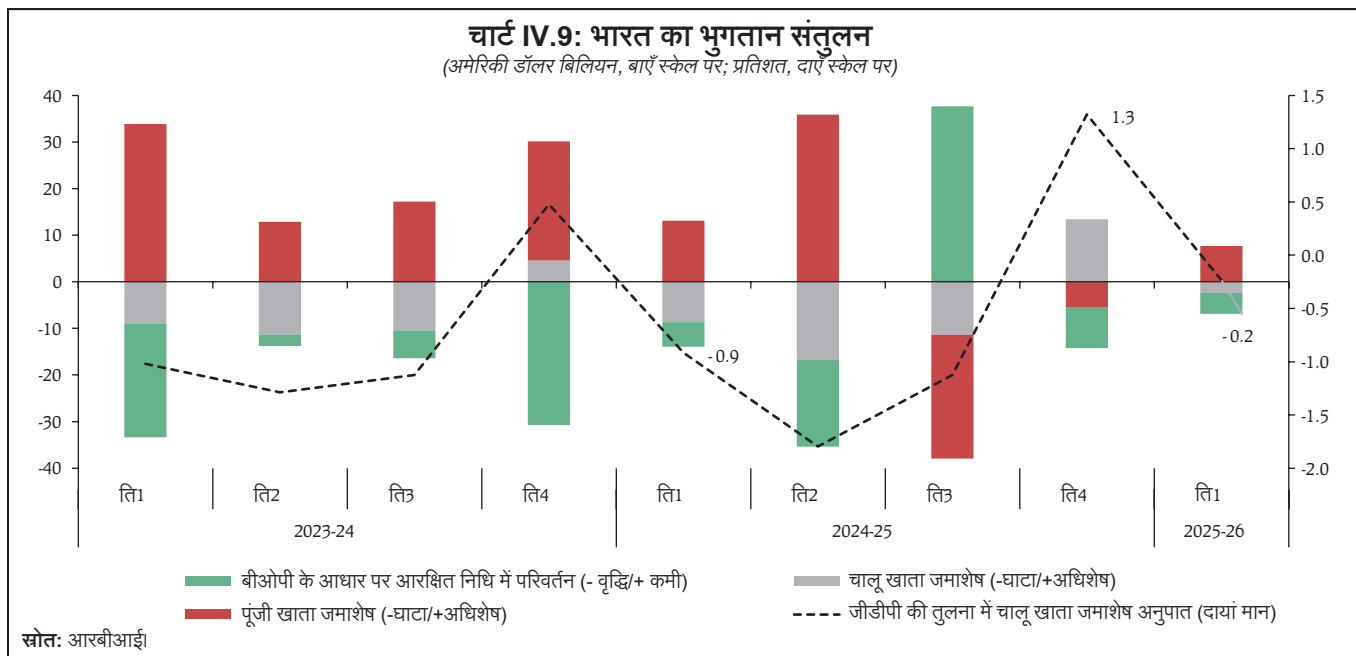
### भुगतान संतुलन

भारत का चालू खाता शेष 26-2025 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बेहतर हुआ, जिसे मजबूत सेवा निर्यात और मजबूत विप्रेषण प्राप्तियों से समर्थन मिला (चार्ट IV.9)।<sup>28</sup> 2025-26 की पहली तिमाही में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि (भुगतान संतुलन के आधार पर)

में वृद्धि हुई क्योंकि निवल पूंजी प्रवाह चालू खाता घाटे से अधिक था।

### वित्त के बाहरी स्रोत

जुलाई में निवल एफडीआई 38 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो मजबूत सकल एफडीआई और कम प्रत्यावर्तन और बाहरी एफडीआई निवेश के कारण था।<sup>29</sup> सकल आवक

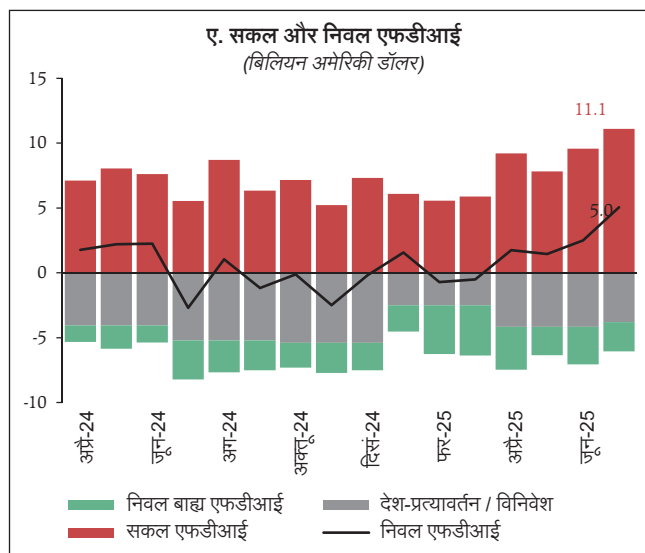


<sup>28</sup> 2025-26 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू खाता जमाशेष (-) 0.2 प्रतिशत था, जबकि 25-2024 की पहली तिमाही में यह (-) 0.9 प्रतिशत था।

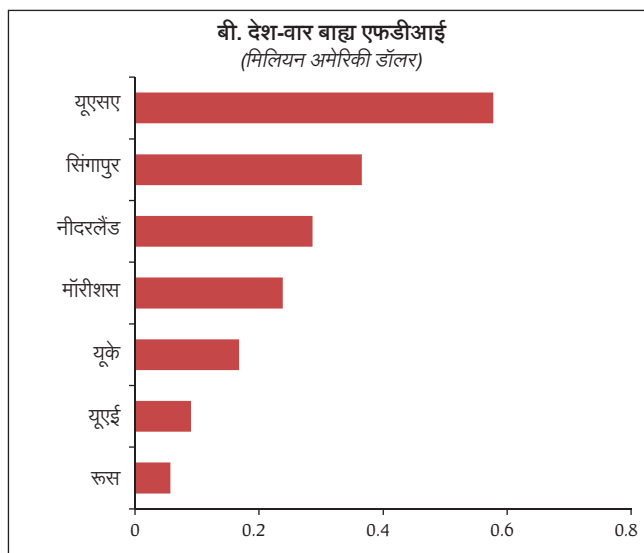
<sup>29</sup> जुलाई 2025 में निवल एफडीआई 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।



चार्ट IV.10: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह



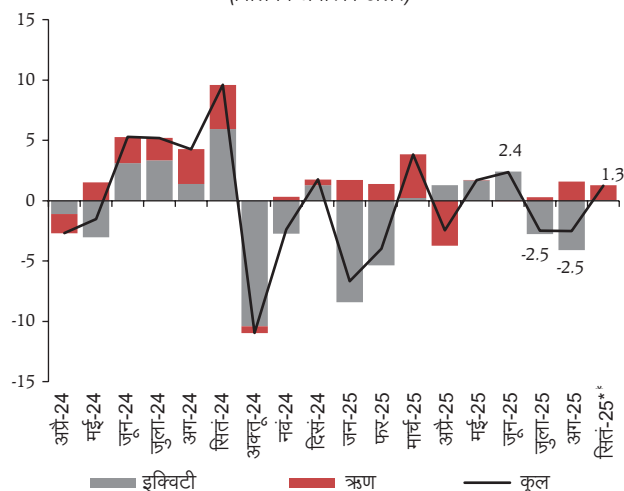
स्रोत: आरबीआई।



एफडीआई एक वर्ष पहले से दोगुना हो गया (चार्ट IV.10 ए)। सिंगापुर, उसके बाद नीदरलैंड, मॉरीशस, यूएस और यूई, ने कुल अंतर्वाह का तीन-चौथाई से अधिक हिस्सा हासिल किया। संचार, कंप्यूटर और व्यावसायिक सेवाओं सहित विनिर्माण और सेवाएं शीर्ष प्राप्तकर्ता क्षेत्र थे। एफडीआई के प्रत्यावर्तन और बाहरी एफडीआई दोनों में कमी आई। बाहरी एफडीआई, मुख्य रूप से वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक सेवाओं के साथ-साथ विनिर्माण की ओर निर्देशित था, जिसमें यूएस, सिंगापुर, नीदरलैंड, मॉरीशस और यूके प्रमुख गंतव्य थे (चार्ट IV.10 बी)। इन बदलावों ने एक साथ निवल एफडीआई में वृद्धि की।

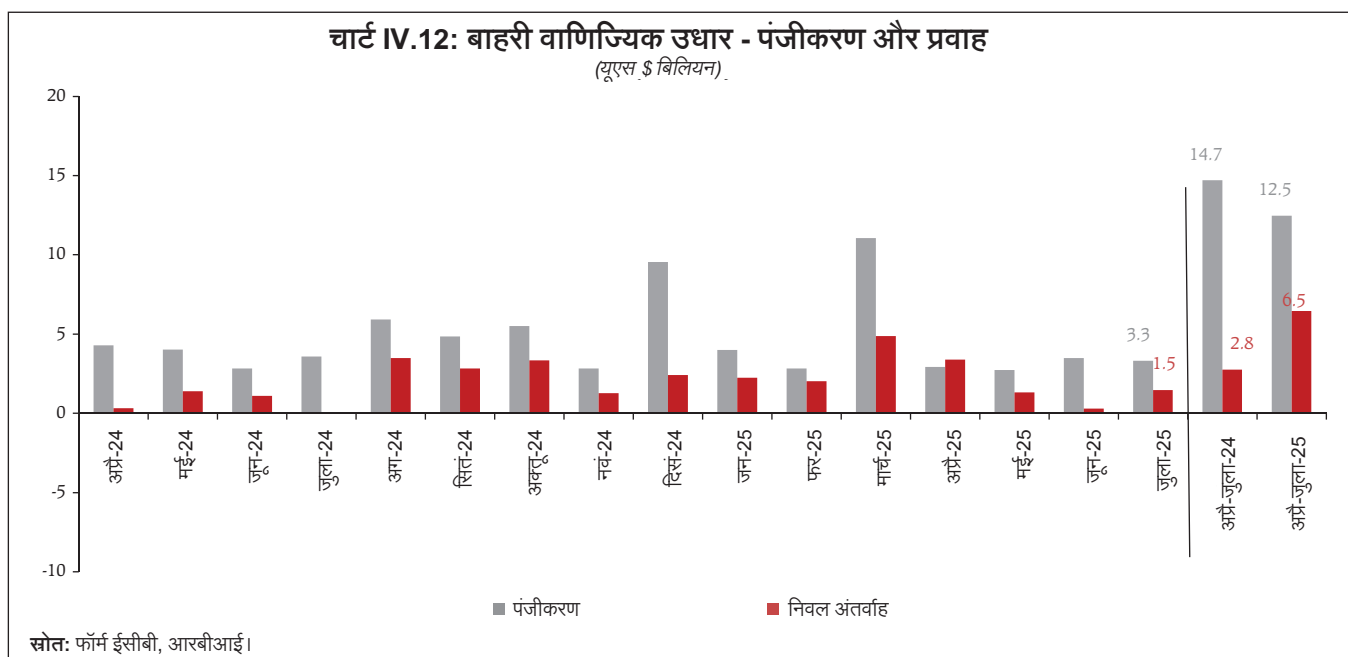
अगस्त में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया, जिसका मुख्य कारण, भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ की अमेरिकी घोषणा के बाद बढ़े जोखिम-मुक्त रुझान के बीच इक्विटी का बहिर्वाह था (चार्ट IV.11)। इसके विपरीत, एसएंडपी ग्लोबल द्वारा भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार के कारण ऋण क्षेत्र में निवल अंतर्वाह देखा गया। सितंबर में अब तक (18 सितंबर तक) कुल मिलाकर निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सकारात्मक रहा, जो मुख्य रूप से अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती के कारण निरंतर ऋण अंतर्वाह के कारण हुआ।

अप्रैल-जुलाई 2025 के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधारों के पंजीकरण में कमी आई। मंदी के बावजूद, अंतर्वाह बहिर्वाह से अधिक रहा, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक निवल अंतर्वाह हुआ (चार्ट IV.12)। उल्लेखनीय रूप से, इस अवधि के दौरान पंजीकृत कुल बाह्य वाणिज्यिक उधारों का 40 प्रतिशत पूंजीगत व्यय के लिए था।

चार्ट IV.11: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश  
(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

टिप्पणियाँ: 1. ऋण में हाइब्रिड इस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत निवेश भी शामिल है।  
2. 22 सितंबर जुलाई तक के आंकड़े।

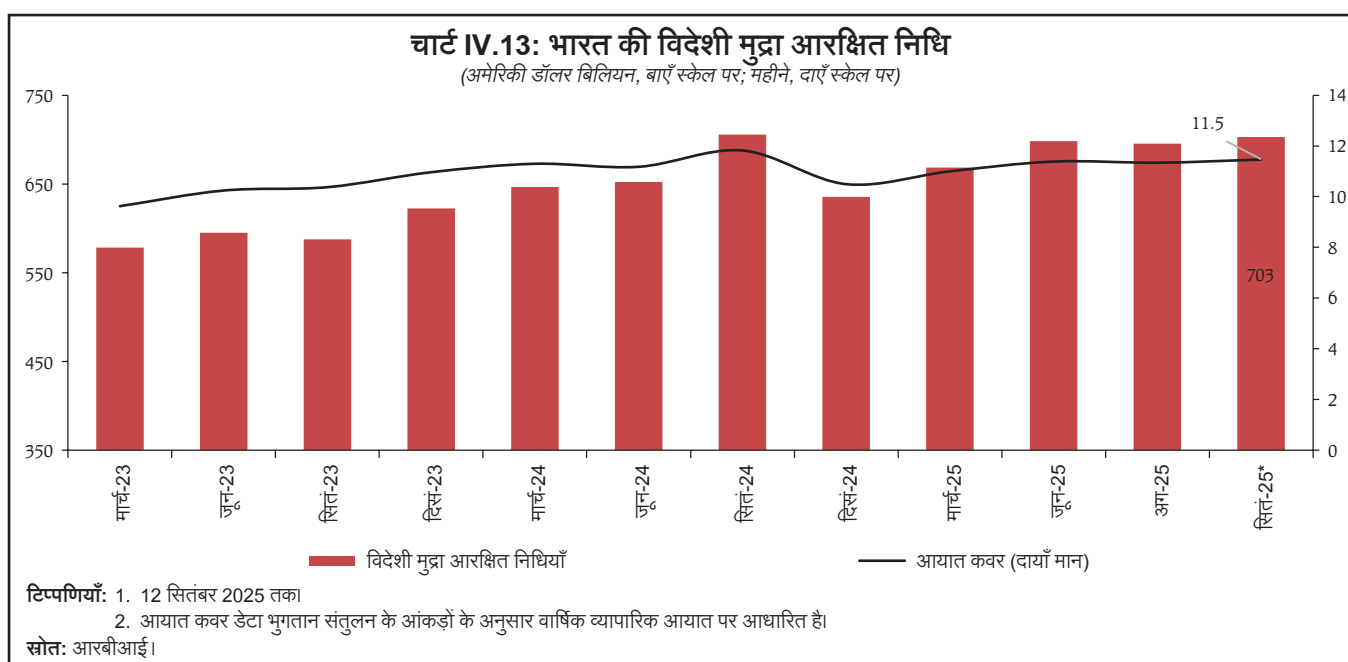
स्रोत: नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)।



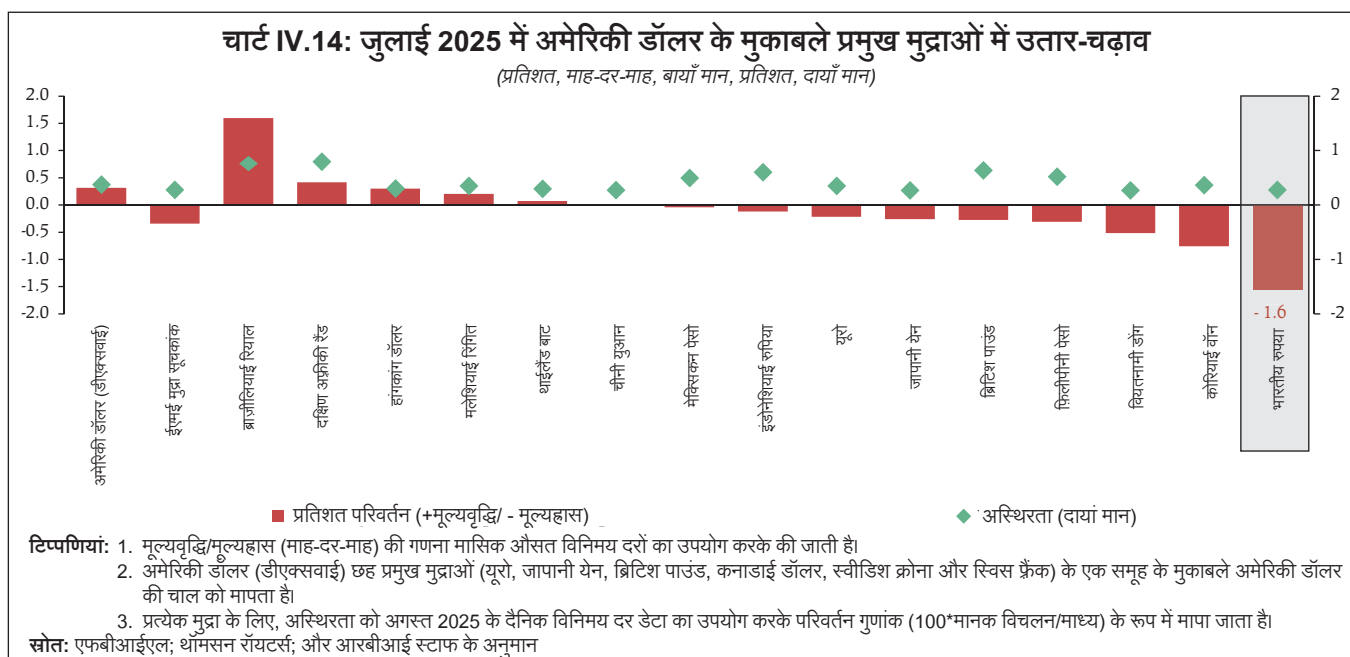
भारत का विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि पर्याप्त बना हुआ है, जो 11 महीने से अधिक के माल आयात और मार्च 2025 के अंत तक बकाया 95 प्रतिशत से अधिक विदेशी ऋण के लिए कवर प्रदान करता है (चार्ट IV.13)<sup>30</sup>

#### विदेशी मुद्रा बाजार

प्रमुख मुद्राओं के मिले-जुले प्रदर्शन के बीच अगस्त में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट दर्ज की गई। यह भारत-अमेरिका टैरिफ तनाव में वृद्धि, एफपीआई के बहिर्वाह और अमेरिकी डॉलर में मजबूती को दर्शाता है (चार्ट IV.14)।



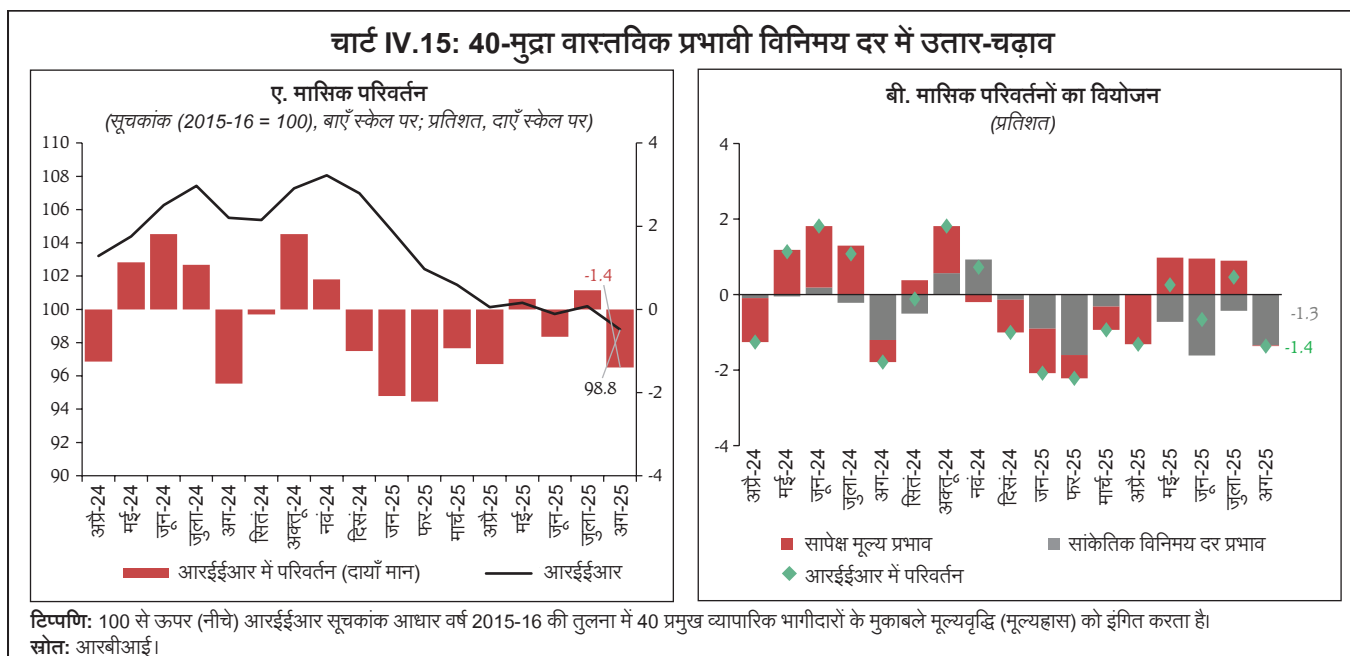
<sup>30</sup> वस्तुओं और सेवाओं के लिए आयात कवर लगभग नौ महीने का था।



वास्तविक प्रभावी संदर्भ में, अगस्त में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ (चार्ट IV.15ए)। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में अवमूल्यन मुख्यतः नॉमिनल प्रभावी विनिमय दर में अवमूल्यन के कारण हुआ, जिसका सीमांत सापेक्ष मूल्य प्रभाव था (चार्ट IV.15बी)।

## V. निष्कर्ष

हालाँकि अमेरिका द्वारा उच्च आयात शुल्क लगाने से घरेलू समष्टि-परिदृश्य पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, लेकिन उसके बाद के घटनाक्रमों ने अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ता को रेखांकित किया है। एसएंडपी द्वारा सॉवरेन रेटिंग में सुधार इसकी मज़बूत



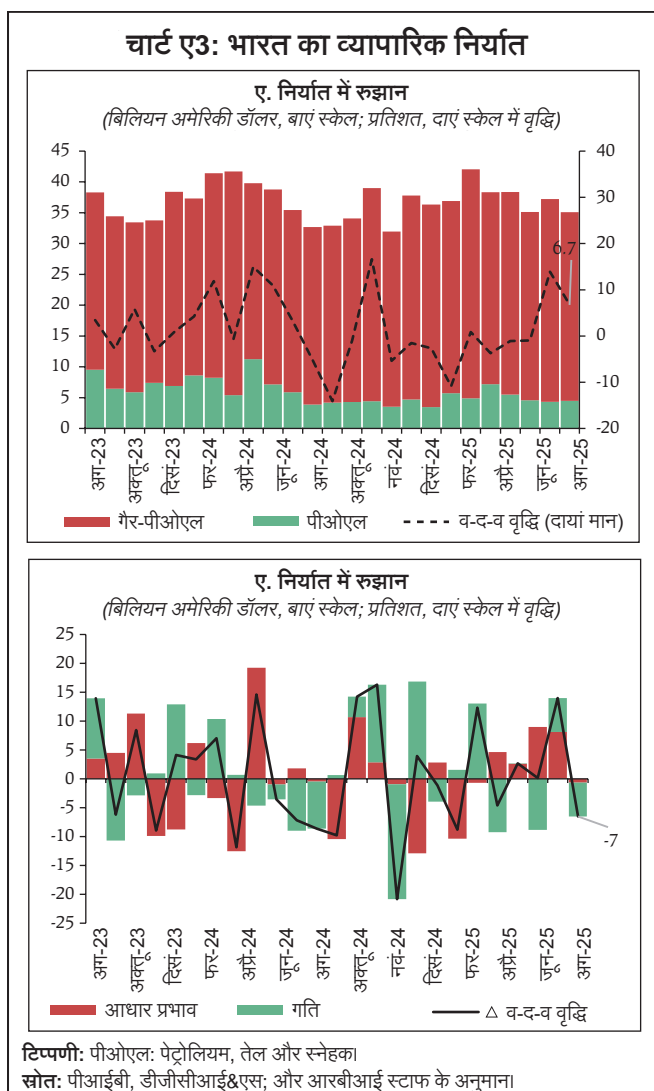
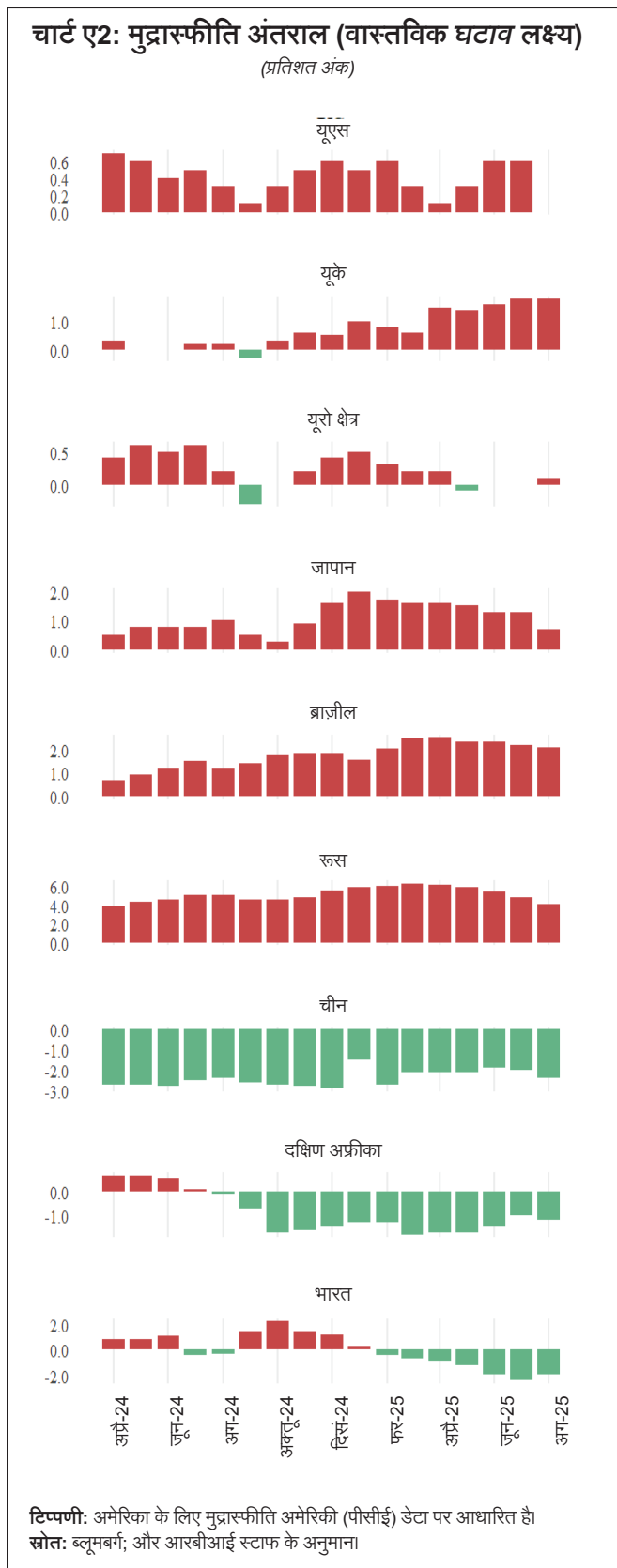
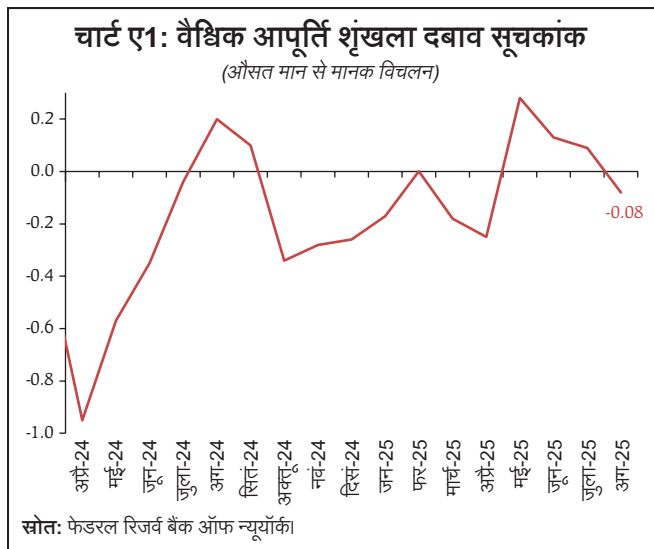
वृहद-बुनियादी बातों की स्वीकृति थी। 26-2025 की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुमानों ने घरेलू संवृद्धि के चालकों की सुदृढ़ता को और पुष्ट किया। अगस्त के उच्च आवृत्ति संकेतक, विनिर्माण और सेवा गतिविधियों को दशक के उच्चतम स्तर पर दर्शाते हैं।

इस परिदृश्य में, दूसरी छमाही के लिए संवृद्धि का दृष्टिकोण आशावादी है। स्वस्थ कॉर्पोरेट तुलन पत्र और सरकार द्वारा संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना अर्थव्यवस्था के उज्ज्वल बिंदु हैं। ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों से व्यापार करने में आसानी, कम खुदरा कीमतों और उपभोग संवृद्धि चालकों

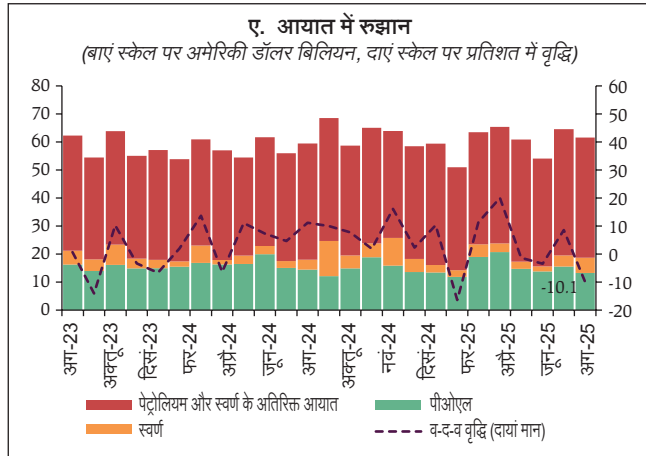
की मजबूती में उल्लेखनीय लाभ के माध्यम से उत्तरोत्तर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। अधिक खरीफ बुवाई से कृषि क्षेत्र में निरंतर संवृद्धि की गति बढ़ने की उम्मीद है, साथ ही खाद्य कीमतों पर भी नियंत्रण रहेगा। अग्रिम-भारित मौद्रिक नीति सहज उपायों का संचरण अच्छा रहा है। परिवारों के लिए आयकर राहत और रोजगार बढ़ाने वाले उपायों<sup>31</sup> के साथ, दूसरी छमाही में उपभोग मांग में निरंतर वृद्धि और संभावित रूप से उच्च निवेश और मजबूत संवृद्धि गति के एक अच्छे चक्र के लिए मंच तैयार है, जो लगातार वैश्विक अनिश्चितताओं पर काबू पा रहा है।

<sup>31</sup> सरकार की रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। अधिक जानकारी के लिए कृपया <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2141129> देखें।

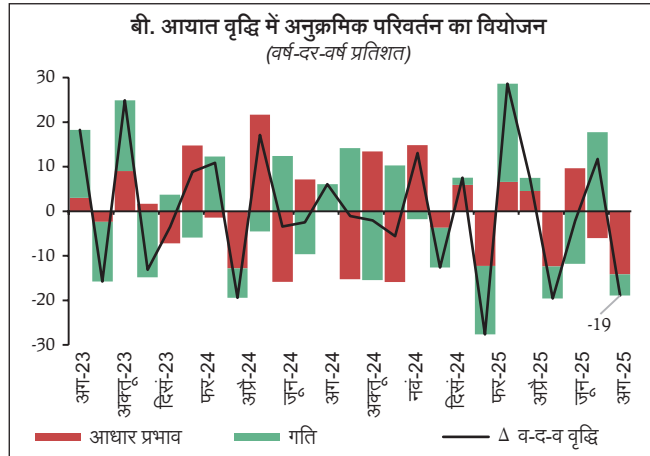
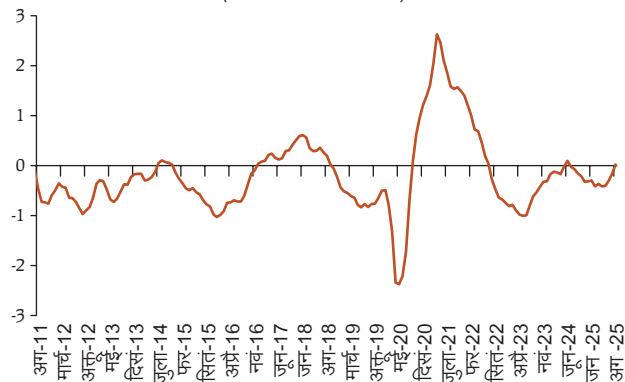
## अनुबंध



चार्ट ए4: भारत का व्यापारिक आयात

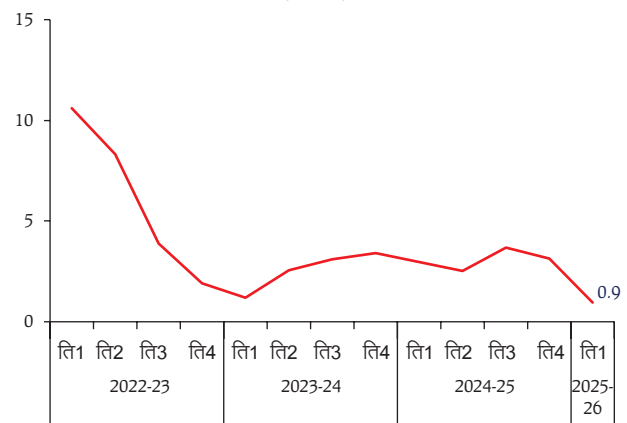


स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई और एस और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट ए5: भारत के लिए आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक  
(औसत से मानक विचलन)

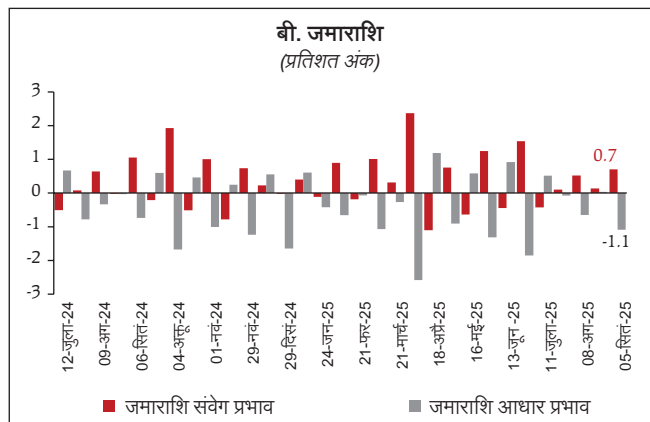
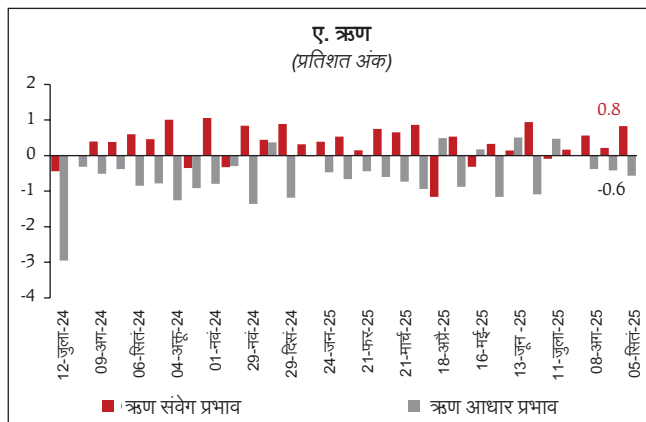
**टिप्पणी:** आईएसपीआई लंबी अवधि के औसत (मार्च 2005 से शुरू होने वाली समय शृंखला) से प्रत्येक महीने में आपूर्ति शृंखला की स्थिति के विचलन को दर्शाता है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट ए6: जीडीपी डिफ्लेटर  
(प्रतिशत)

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई और एस और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट ए7: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक: ऋण और जमाराशि वृद्धि

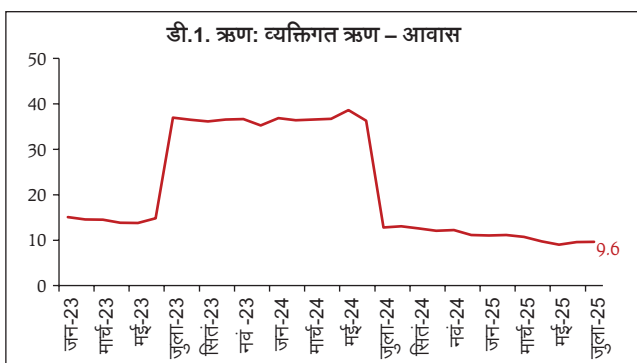
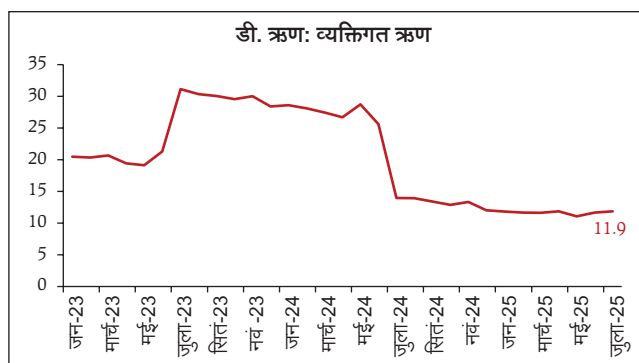
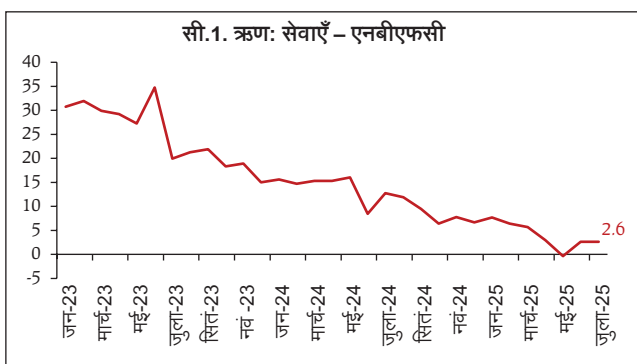
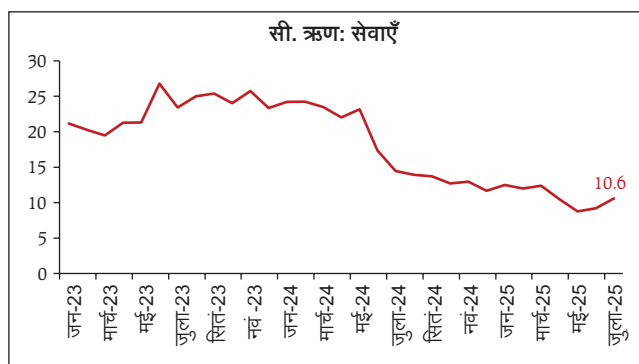
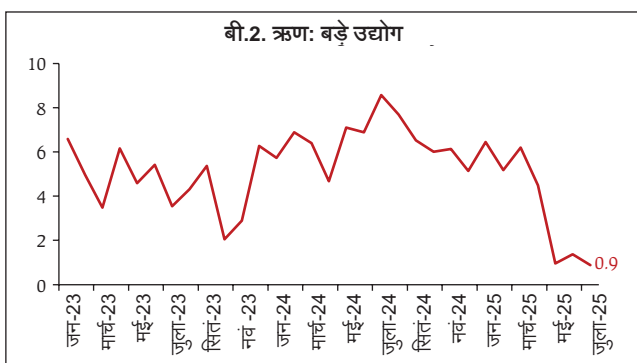
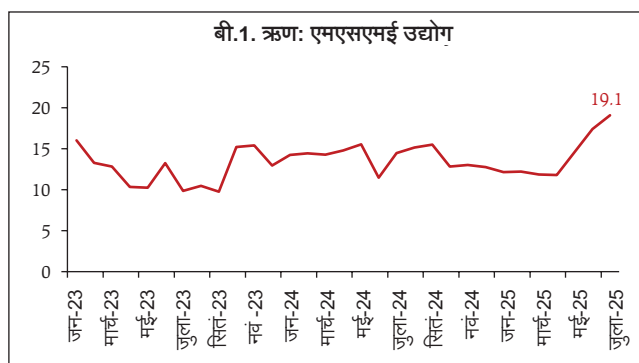
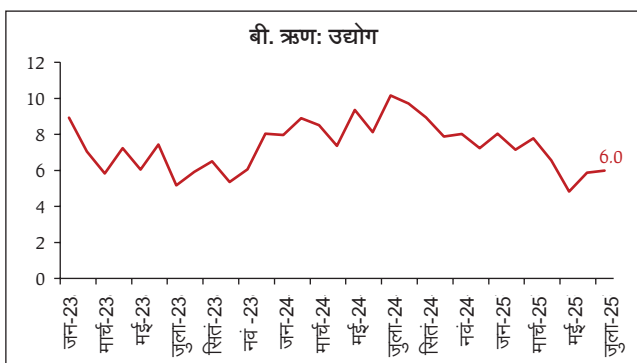
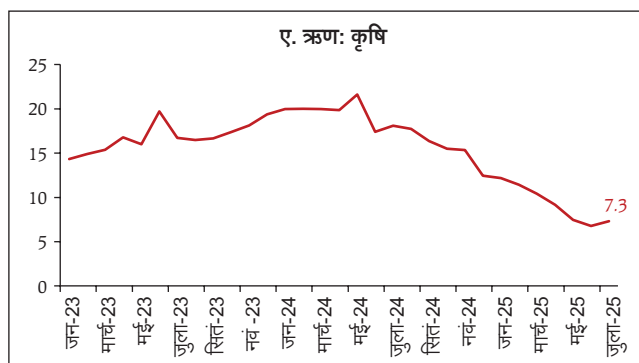


**टिप्पणी:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आंकड़ों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। आंकड़ों में किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

स्रोत: पाक्षिक खंड 42 विवरणी, आरबीआई।

### चार्ट ए8: बैंक ऋण का क्षेत्रवार आबंटन

(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत)

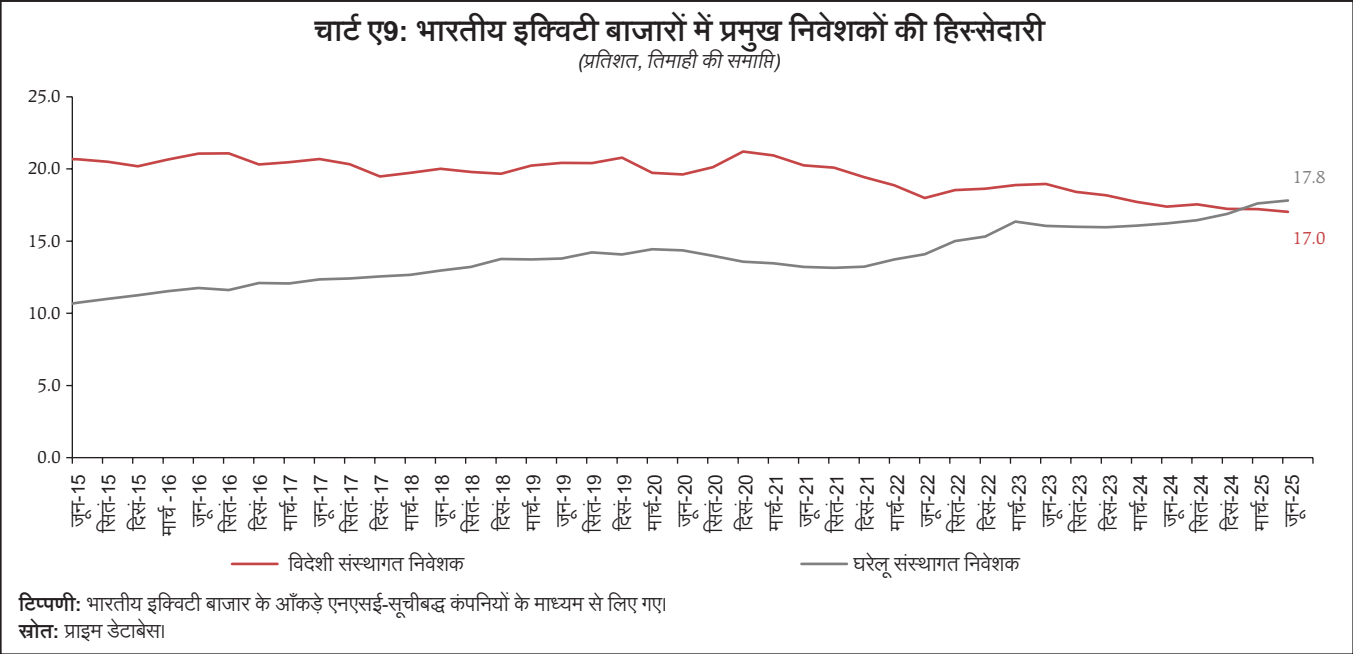


**टिप्पणियाँ:** 1. आंकड़े अनंतिम हैं। क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण आंकड़े क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें चुनिंदा बैंक शामिल हैं, जो महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार तक सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा हैं। एसआईबीसी विवरणी के अंतर्गत आने वाले बैंक समूह हैं - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और लघु वित्त बैंक।

2. आंकड़ों में किसी गैर-बैंक के किसी बैंक में विलय के प्रभाव को शामिल किया गया है।

**स्रोत:** आरबीआई





सारणी ए1: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि												
(वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, प्रतिशत में)												
घटक	2024-25 में हिस्सा (प्रतिशत)	भारित योगदान (प्रतिशत अंक)		2023-24				2024-25				2025-26
		2023-24	2024-25	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	
I. कुल उपभोग व्यय	65.6	4.0	4.3	7.1	5.1	5.3	6.3	7.0	6.1	8.3	4.7	7.1
निजी	56.5	3.2	4.0	7.4	3.0	5.7	6.2	8.3	6.4	8.1	6.0	7.0
सरकारी	9.1	0.8	0.2	5.3	20.1	2.3	6.6	-0.3	4.3	9.3	-1.8	7.4
II. सकल पूंजी निर्माण	36.8	3.8	2.5	8.9	11.9	12.4	9.1	6.2	7.7	4.9	7.8	6.4
स्थिर निवेश	33.7	3.0	2.4	8.4	11.7	9.3	6.0	6.7	6.7	5.2	9.4	7.8
III. निवल निर्यात												
निर्यात	21.6	0.5	1.4	-7.0	4.6	3.0	7.7	8.3	3.0	10.8	3.9	6.3
आयात	22.5	3.3	-0.9	18.0	14.3	11.3	11.4	-1.6	1.0	-2.1	-12.7	10.9
सकल घरेलू उत्पाद	100.0	9.2	6.5	9.7	9.3	9.5	8.4	6.5	5.6	6.4	7.4	7.8

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

सारणी ए2: 56वीं जीएसटी परिषद की मुख्य सिफारिशें					
	से (प्रतिशत, जीएसटी दर)	तक (प्रतिशत, जीएसटी दर)		से (प्रतिशत, जीएसटी दर)	तक (प्रतिशत, जीएसटी दर)
दैनिक आवश्यक वस्तुएँ			किसान और कृषि		
केस तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, नहाने का साबुन, बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम	18	5	ट्रैक्टर के टायर और पुर्जे	18	5
मक्खन, घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड	12	5	निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म-पोषक तत्व	12	5
पहले से पैक नमकीन, भुजिया, मिक्सचर	12	5	ड्रिप सिंचाई प्रणाली और सिंप्रकलर	12	5
बर्तन	12	5	मिट्टी में गहराई तक जाने, खेती करने, कटाई और थ्रेसिंग के लिए खेती, बागवानी या वानिकी मशीनें	12	5
दूध की बोतलें, क्लिनिकल डायपर, वगैरह	12	5			
सिलाई मशीनें और पुर्जे	12	5			
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र			ऑटोमोबाइल		
व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा	18	'शून्य'	पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (कुछ खास तरह की)	28	18
थर्मामीटर	18	5	डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (कुछ खास तरह की)	28	18
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन	12	5	तीन पहिया वाहन	28	18
सभी डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक	12	5	मोटर साइकिलें (कुछ प्रकार की)	28	18
ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स	12	5	माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन	28	18
सुधारात्मक चश्मे	12	5			
शिक्षा			इलेक्ट्रॉनिक उपकरण		
मानचित्र, चार्ट और ग्लोब	12	'शून्य'	एयर कंडिशनर	28	18
पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल	12	'शून्य'	टेलीविजन (कुछ प्रकार)	28	18
अभ्यास पुस्तकें और नोटबुक	12	'शून्य'	मॉनिटर और प्रोजेक्टर	28	18
रबड़	5	'शून्य'	बर्तन धोने की मशीनें	28	18

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय

सारणी ए3: वास्तविक सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) वृद्धि												
(वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, प्रतिशत में)												
क्षेत्रक	2024-25 में हिस्सेदारी (प्रतिशत)	भारित योगदान (प्रतिशत अंक)		2023-24				2024-25				2025-26
		2023-24	2024-25	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1
I. कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन	14.4	0.4	0.7	5.7	3.7	1.5	0.9	1.5	4.1	6.6	5.4	3.7
II. उद्योग	21.5	2.4	1.0	6.6	15.3	12.6	9.9	7.8	2.1	3.5	4.7	5.8
खनन और उत्खनन	2.0	0.1	0.1	4.1	4.1	4.7	0.8	6.6	-0.4	1.3	2.5	-3.1
उत्पादन	17.2	2.1	0.8	7.3	17.0	14.0	11.3	7.6	2.2	3.6	4.8	7.7
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ	2.4	0.2	0.1	4.1	11.7	10.1	8.8	10.2	3.0	5.1	5.4	0.5
III. सेवाएँ	64.1	5.8	4.8	12.1	8.3	8.5	8.0	7.2	7.4	7.5	7.9	9.0
निर्माण	9.1	0.9	0.8	9.2	14.6	10.0	8.7	10.1	8.4	7.9	10.8	7.6
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ	18.5	1.4	1.1	11.0	5.4	8.0	6.2	5.4	6.1	6.7	6.0	8.6
वित्तीय, अचल संपत्ति और पेशेवर सेवाएँ	23.8	2.4	1.7	15.0	8.3	8.4	9.0	6.6	7.2	7.1	7.8	9.5
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	12.7	1.1	1.1	9.3	8.9	8.4	8.7	9.0	8.9	8.9	8.7	9.8
IV. मूल कीमतों पर जीवीए	100.0	8.6	6.4	9.9	9.2	8.0	7.3	6.5	5.8	6.5	6.8	7.6

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

## वर्ष 2024-25 के दौरान भारत के वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

अमित पवार<sup>^</sup>, अभिनंदन बोराड<sup>^^</sup>, पवन कुमार\*, जॉन वी गुरिया<sup>^^</sup>, और विशाल रैना<sup>^</sup> द्वारा

1990 के दशक की शुरुआत से भारतीय वित्तीय प्रणाली एक विविध संरचना में विकसित हुई है, जो वित्तीय क्षेत्र सहित भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख सुधारों के प्रभाव को दर्शाती है। वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के प्रवाह का विश्लेषण समष्टि-वित्तीय निगरानी और अर्थव्यवस्था के विकास दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस आलेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 2024-25 के दौरान बैंक ऋण विस्तार में नरमी आई, लेकिन घरेलू और विदेशी दोनों बैंकेतर स्रोतों ने भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए निधीयन की कमी को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2024-25 के दौरान बैंकेतर स्रोतों से वित्तपोषण में वृद्धि, काफी हद तक घरेलू इक्विटी बाजार में उछाल, बैंकेतर वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण और अल्पकालिक बाहरी ऋण में उछाल के बीच इक्विटी निर्गम से प्रेरित थी। बैंक ऋण में नरमी के बीच, वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा बैंकेतर स्रोतों का सहारा अर्थव्यवस्था की उभरती निधीयन जरूरतों को पूरा करने में वित्तीय प्रणाली की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। बैंकिंग प्रणाली से वित्तपोषण सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है, हालांकि हाल की अवधि में बैंकेतर स्रोतों से वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह बढ़ गया। मार्च 2025 के अंत तक, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया खाद्येतर बैंक ऋण मार्च 2024 के अंत में 54.5 प्रतिशत से बढ़कर 55.1 प्रतिशत हो गया। कुल मिलाकर, सकल घरेलू

उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बैंकों और बैंकेतर स्रोतों से बकाया ऋण मार्च 2024 के अंत में 80.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 के अंत में 81.9 प्रतिशत हो गया।

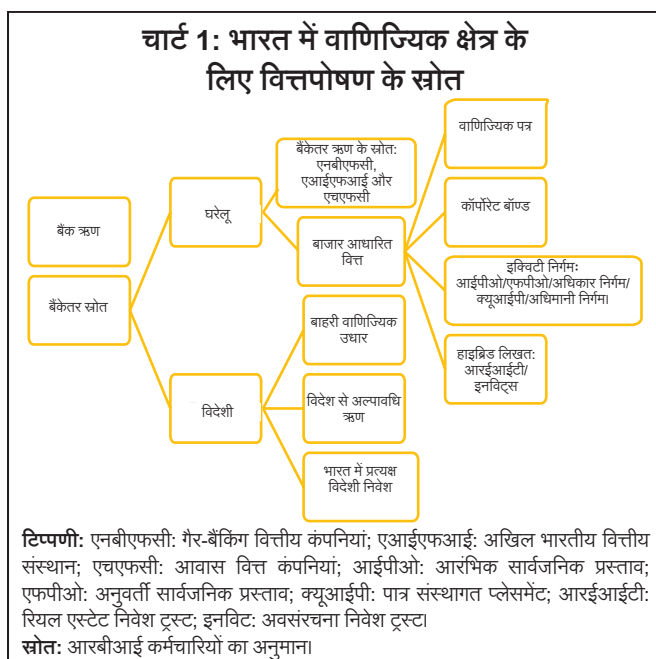
### परिचय

1990 के दशक की शुरुआत में भुगतान संतुलन संकट के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों के एक शृंखला की शुरुआत के परिणामस्वरूप भारतीय वित्तीय प्रणाली एक विविध संरचना में विकसित हुई है। भारतीय वित्तीय प्रणाली का यह विकास मुख्य रूप से इसके विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित क्रमिक सुधारों द्वारा संचालित हुआ है, जो एक बढ़ती अर्थव्यवस्था की विकसित आवश्यकताओं के जवाब और समर्थन में हैं (आरबीआई, 2024ए)। भारत की वित्तीय प्रणाली, जिसकी विशेषता परंपरागत रूप से ऋण प्रदान करने के लिए बैंक केंद्रित मध्यस्थता रही है, बैंकेतर वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं (एनबीएफआई) के बढ़ते महत्व और वाणिज्यिक क्षेत्र की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार आधारित उपकरणों के बढ़ते उपयोग द्वारा चिह्नित एक संरचनात्मक परिवर्तन से गुजरी है। तदनुसार, हाल के वर्षों में कॉर्पोरेट बॉण्ड और इक्विटी निर्गम जैसे बाजार आधारित वित्तपोषण साधनों के साथ-साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और अल्पकालिक व्यापार ऋण जैसे बाहरी स्रोतों का सहारा काफी बढ़ गया है, हालांकि बैंकिंग प्रणाली से वित्तपोषण सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है।

भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए वित्तपोषण के स्रोत विविध और विविध हैं (चार्ट 1)। इन्हें मुख्य रूप से बैंक ऋण और बैंकेतर स्रोतों (घरेलू और विदेशी सहित) में विभाजित किया गया है।

चूंकि भारतीय वित्तीय प्रणाली काफी हद तक बैंक-प्रभुत्व वाली रही है, इसलिए वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के प्रवाह और अर्थव्यवस्था के संवृद्धि के दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए बैंक ऋण वृद्धि को एक प्रमुख पैरामीटर के रूप में देखा जाता है। बैंक ऋण वृद्धि में नरमी की व्याख्या अक्सर कमजोर कुल मांग के संकेत के रूप में की जाती है और इसलिए, निकट अवधि के विकास दृष्टिकोण के लिए एक संभावित

<sup>^</sup> लेखक मौद्रिक नीति विभाग से हैं। <sup>^^</sup> लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। \* लेखक पर्यवेक्षण विभाग से हैं। वे डॉ. राजीव रंजन, श्री इंद्रनील भट्टाचार्य और श्री मल्लवाराणु रमैया के मार्गदर्शन और सुझावों के लिए आभारी हैं। इस अनुच्छेद में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।



जोखिम। हालांकि, वित्तपोषण के बैंकेतर स्रोतों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, बैंकों, गैर-बैंकों और अन्य स्रोतों को कवर करने वाले वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के प्रवाह के व्यापक स्पेक्ट्रम के आकलन पर विचार करने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में, यह आलेख वित्तपोषण के कई स्रोतों के आधार पर 2024-25 के दौरान भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए वित्तीय संसाधनों और बकाया ऋण के प्रवाह का विश्लेषण करता है। आलेख के शेष भाग का गठन इस प्रकार किया गया है: खंड दो भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों के प्रवाह पर समेकित विवरण प्रस्तुत करता है। खंड तीन बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण की प्रवृत्तियों और संरचना पर चर्चा करता है, जिसके बाद खंड चार में बैंकेतर स्रोतों (घरेलू और विदेशी सहित) से वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों के प्रवाह का विश्लेषण किया गया है। खंड पांच भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों और बैंकेतर स्रोतों से बकाया ऋण पर चर्चा करता है। खंड छह निष्कर्षों पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करता है।

## II. वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह

भारत में कार्यरत बैंकों और गैर-बैंकों (घरेलू और विदेशी स्रोतों सहित) से वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के प्रवाह पर विवरण इस क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के कुल प्रवाह को प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। इस विवरण में वित्तीय प्रवाह

को निवल आधार पर कैप्चर किया जाता है (यानी, चुकौती / मोचन / प्रत्यावर्तन के लिए समायोजित सकल प्रवाह), क्योंकि निवल प्रवाह वाणिज्यिक क्षेत्र और इसके निवेश व्यवहार के लिए वास्तविक निधि और चलनिधि की उपलब्धता को दर्शाता है।

कुल स्तर पर, यह देखा गया है कि खाद्येतर बैंक ऋण का प्रवाह 2024-25 के दौरान ₹3.4 लाख करोड़ तक कम हो गया (सारणी 1 और चार्ट 2)। हालांकि, वर्ष 2024-25 के दौरान बैंकेतर स्रोतों (घरेलू और विदेशी दोनों) से ₹4.5 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि ने बैंक ऋण प्रवाह में कमी को अधिक संतुलित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह ₹1.1 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। 2024-25 के दौरान बैंकेतर घरेलू स्रोतों से प्रवाह ₹3.7 लाख करोड़ बढ़ा, मुख्य रूप से घरेलू इक्विटी बाजार में उछाल और एनबीएफसी द्वारा ऋण में वृद्धि के बीच इक्विटी जारी करने में वृद्धि के कारण। इसी अवधि के दौरान बैंकेतर विदेशी स्रोतों से प्रवाह में ₹0.8 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, मुख्य रूप से विदेश से अल्पकालिक ऋण में वृद्धि के कारण, जो भारत के व्यापारिक आयात में बदलाव को दर्शाता है।

## III. बैंकों से प्रवाह

भारत में, हालांकि हाल के वर्षों में वित्त के बाजार आधारित स्रोत काफी बढ़ गए हैं, बैंक ऋण अभी भी कई क्षेत्रों के लिए निधि का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है। खाद्येतर बैंक ऋण का प्रवाह वर्ष 2023-24 में मजबूत विस्तार के बाद वर्ष 2024-25 के दौरान कम हो गया (चार्ट 3)। यह वर्ष 2023-24 में ₹21.4 लाख करोड़ से घटकर वर्ष 2024-25 में ₹18.0 लाख करोड़ रह गया।

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के उद्देश्य से नवंबर 2023 में एनबीएफसी को गैर-जमानती व्यक्तिगत ऋणों और बैंक ऋण पर जोखिम भार में वृद्धि की।<sup>1</sup>

<sup>1</sup> एनबीएफसी को बैंक ऋण पर जोखिम भार और आवास, शिक्षा, वाहन ऋण और सोने और सोने के आभूषणों पर ऋण को छोड़कर खुदरा ऋण 16 नवंबर, 2023 (<https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/pdfs/regulatorymass8785e7886a044b678fb8af2c6c051807.pdf>) को बढ़ाए गए थे। हालांकि, एससीबी के एनबीएफसी से जोखिमों पर जोखिम भार को 1 अप्रैल 2025 से पूर्व नवंबर 2023 स्तर तक बहाल कर दिया गया है और वही बाहरी रेटिंग के अनुसार है। साथ ही, उपभोक्ता ऋण की प्रकृति में सूक्ष्म वित्त ऋण उच्च जोखिम भार की प्रयोज्यता से बाहर रखे गए हैं और वे 100 प्रतिशत के जोखिम भार के अधीन हैं।

सारणी 1: भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधन का प्रवाह			
(₹ करोड़)			
स्रोत	2022-23	2023-24	2024-25 पी
ए. खाद्येतर बैंक ऋण	18,19,026	21,40,243	17,98,321
बी. बैंकेतर स्रोत (बी1+बी2)	9,03,298	12,63,721	17,10,459
बी1. घरेलू स्रोत	5,27,181	10,20,302	13,85,609
1. गैर-बैंकिंग संस्थाएं द्वारा इक्विटी जारी करना	1,16,111	1,35,008	3,81,161
2. गैर-बैंकिंग संस्थाएं द्वारा कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करना	1,12,822	1,67,374	1,97,795
3. गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा हाइब्रिड लिखत (रीट/इनविट)	6,360	39,024	31,442
4. गैर-बैंकिंग संस्थाएं द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी करना	-78,489	19,712	18,819
5. आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऋण (बैंक उधारी को घटाकर)	72,111	1,41,816	1,34,852
6. आरबीआई द्वारा विनियमित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण	32,419	73,386	99,501
7. गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण (बैंक उधारी को घटाकर)	2,65,846	4,43,982	5,22,037
बी2. विदेशी स्रोत	3,76,118	2,43,419	3,24,850
1. गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधारी	-10,033	27,916	19,201
2. विदेश से लघु अवधि के ऋण	51,136	-6,741	58,860
3. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	3,35,015	2,22,244	2,46,788
सी. संसाधनों का कुल प्रवाह (ए+बी)	27,22,324	34,03,964	35,08,780

पी: अनंतिमा

टिप्पणियां: i) खाद्येतर बैंक ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से जुड़ा है और इसमें सहकारी बैंकों का दिया गया ऋण शामिल नहीं है।

ii) बैंकों, एनबीएफसी और एचएफसी के दिए गए ऋण में व्यक्तिगत ऋण भी शामिल हैं।

iii) सभी आइटम का डेटा नेट बेसिस पर दिया गया है, इक्विटी और हाइब्रिड लिखत को छोड़कर जो ग्रांस् बेसिस पर हैं।

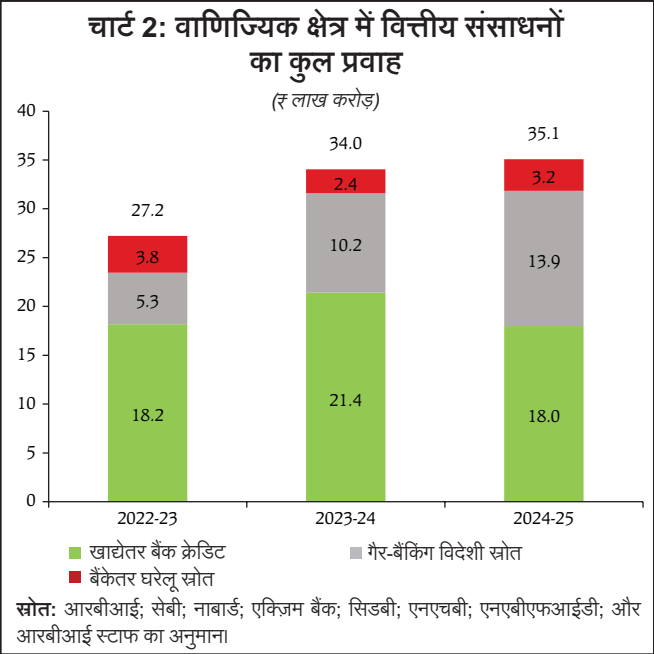
iv) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्विजम बैंक), और राष्ट्रीय अवसरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) शामिल हैं। एआईएफआई द्वारा दिए गए ऋण में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), एनबीएफसी, और एचएफसी को पुनर्वित्तपोषण, और घरेलू और विदेशी सरकारों/संस्थाओं को दिए गए सीधे ऋण शामिल नहीं हैं।

v) एचडीएफसी लिमिटेड से जुड़ा डेटा, जिसका 1 जुलाई 2023 से एचडीएफसी बैंक में विलय हो गया है, उसके विलय से पहले आवास वित्त कंपनियों द्वारा दिए गए ऋण के तहत शामिल है, जबकि इसे विलय के बाद बैंक ऋण के तहत शामिल किया गया है।

vi) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और गैर-वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा दिए गए ऋण के डेटा को कुछ एचएफसी के एनबीएफसी में बदलने के लिए समायोजित किया गया है।

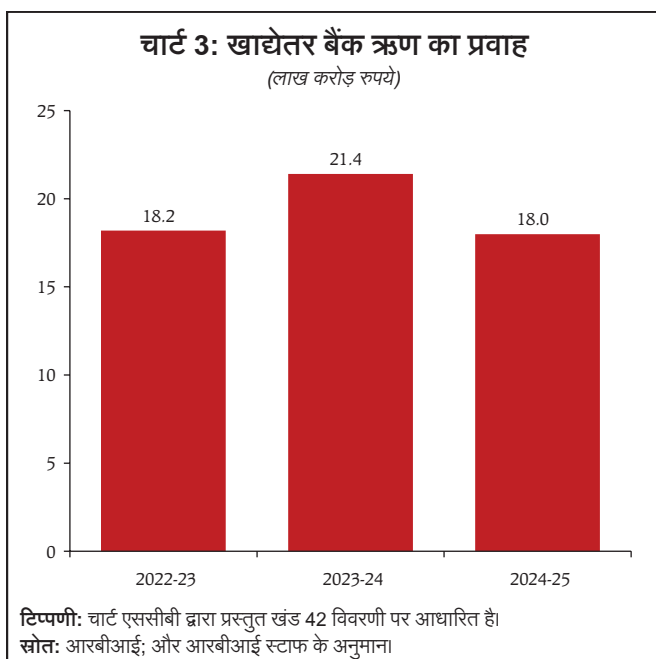
स्रोत: आरबीआई; सेबी; नाबार्ड; एक्विजम बैंक; सिडबी; एनएचबी; एनएबीएफआईडी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

इस विनियामक कार्रवाई ने ऐसे एक्सपोजर पर बैंकों के लिए पूंजी आवश्यकताओं को बढ़ाया, प्रभावी रूप से इन खंडों में उधार देना उनके लिए अधिक महंगा बना दिया। यह निर्णय गैर-जमानती ऋण में संभावित रूप से अस्थिर विकास पर चिंताओं से प्रेरित था, जो अनियंत्रित रहने पर जोखिम पैदा कर सकता था।



खाद्येतर बैंक ऋण प्रवाह का ब्रेक-अप (ए) 'बढ़े हुए जोखिम भार वाले खंड (यानी, लक्षित खंड)', और (बी) 'अपरिवर्तित जोखिम भार वाले खंड (यानी, गैर-लक्षित खंड)' से पता चलता है कि लक्षित खंडों में ऋण प्रवाह 2021-22 में ₹2.5 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 के दौरान ₹6.6 लाख करोड़ हो गया था, जबकि गैर-लक्षित खंडों (चार्ट 4ए) के मामले में यह मामूली रूप से बढ़ गया था। कुल खाद्येतर ऋण प्रवाह में लक्षित खंडों में ऋण प्रवाह का हिस्सा 2021-22 में 21.0 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 38.1 प्रतिशत हो गया (चार्ट 4बी)।

वर्ष 2023-24 में लक्षित क्षेत्रों को ऋण प्रवाह घटकर ₹4.7 लाख करोड़ हो गया और कुल खाद्येतर बैंक ऋण में इसकी



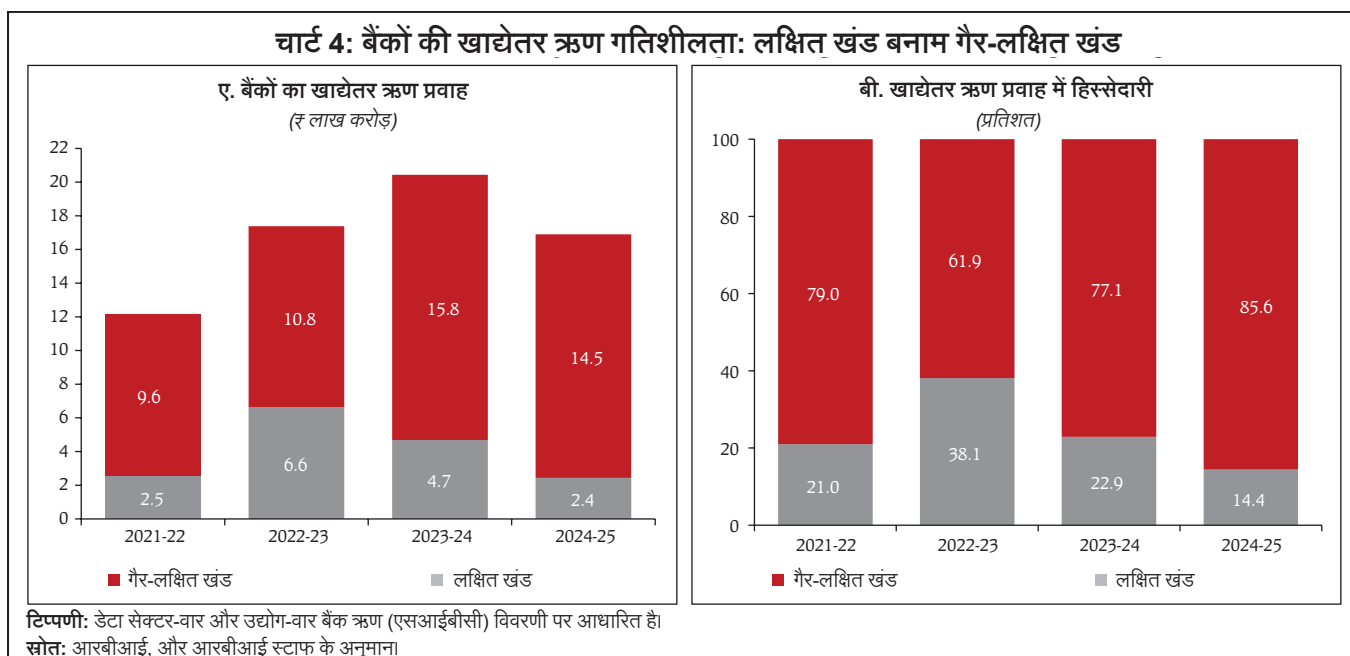
हिस्सेदारी घटकर 22.9 प्रतिशत रह गई। इसका मुख्य कारण नवंबर 2023 में गैर-जमानती ऋण पर बढ़ते जोखिम भार थे। वर्ष 2024-25 में लक्षित क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह और कम होकर ₹2.4 लाख करोड़ हो गया तथा खाद्येतर बैंक ऋण में इसकी हिस्सेदारी घटकर 14.4 प्रतिशत रही जिससे समग्र ऋण प्रवाह प्रभावित हुआ है।

## IV. गैर-बैंकों से प्रवाह

### IV.1. घरेलू स्रोत

#### IV1.1. बाजार स्रोत

हाल के वर्षों में, भारतीय इक्विटी बाजारों की गतिशीलता और एक मजबूत कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के विस्तार, विशेष रूप से अत्यधिक रेटेड जारीकर्ताओं के लिए, कॉर्पोरेट के लिए बाजार-आधारित वित्तपोषण के रास्ते तक पहुंच में काफी वृद्धि हुई है। मजबूत ऋण प्रोफाइल और मजबूत तुलन पत्र वाली फर्मों को प्रतिस्पर्धी लागत पर संसाधन जुटाने के लिए अनुकूल बाजार स्थितियों का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैनात किया गया है। वित्तीय बाजारों में मजबूत प्रदर्शन और कम अस्थिरता की अवधि के दौरान, बाजार-आधारित वित्तपोषण की सापेक्ष लागत पारंपरिक बैंक ऋण की तुलना में कम हो जाती है, जिससे कॉर्पोरेट को पूंजी बाजार उपकरणों के माध्यम से धन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, वाणिज्यिक क्षेत्र ने नियमित रूप से वित्तीय बाजारों का दोहन किया, उनके योगदान में वृद्धि की प्रवृत्ति (चार्ट 5ए)। इस प्रवृत्ति को दर्शाते हुए, गैर वित्तीय संस्थाओं द्वारा 2024-25 के दौरान इक्विटी निर्गमों के माध्यम से संसाधन जुटाने में तेजी आई (चार्ट 5बी)। यह वृद्धि मुख्य रूप से आईपीओ





और एफपीओ की बढ़ी हुई गतिविधि से प्रेरित थी जो खुदरा निवेशकों की भागीदारी में वृद्धि और महामारी के बाद बाजार वातावरण में अनुकूल इक्विटी मूल्यांकन से प्रेरित थी। 2024-25 में ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता सेवाओं और दूरसंचार क्षेत्रों में सर्वाधिक इक्विटी-आधारित निधि जुटाई गई - विशेष रूप से सार्वजनिक निर्गम और अधिकार निर्गम के माध्यम से (चार्ट 5सी)।

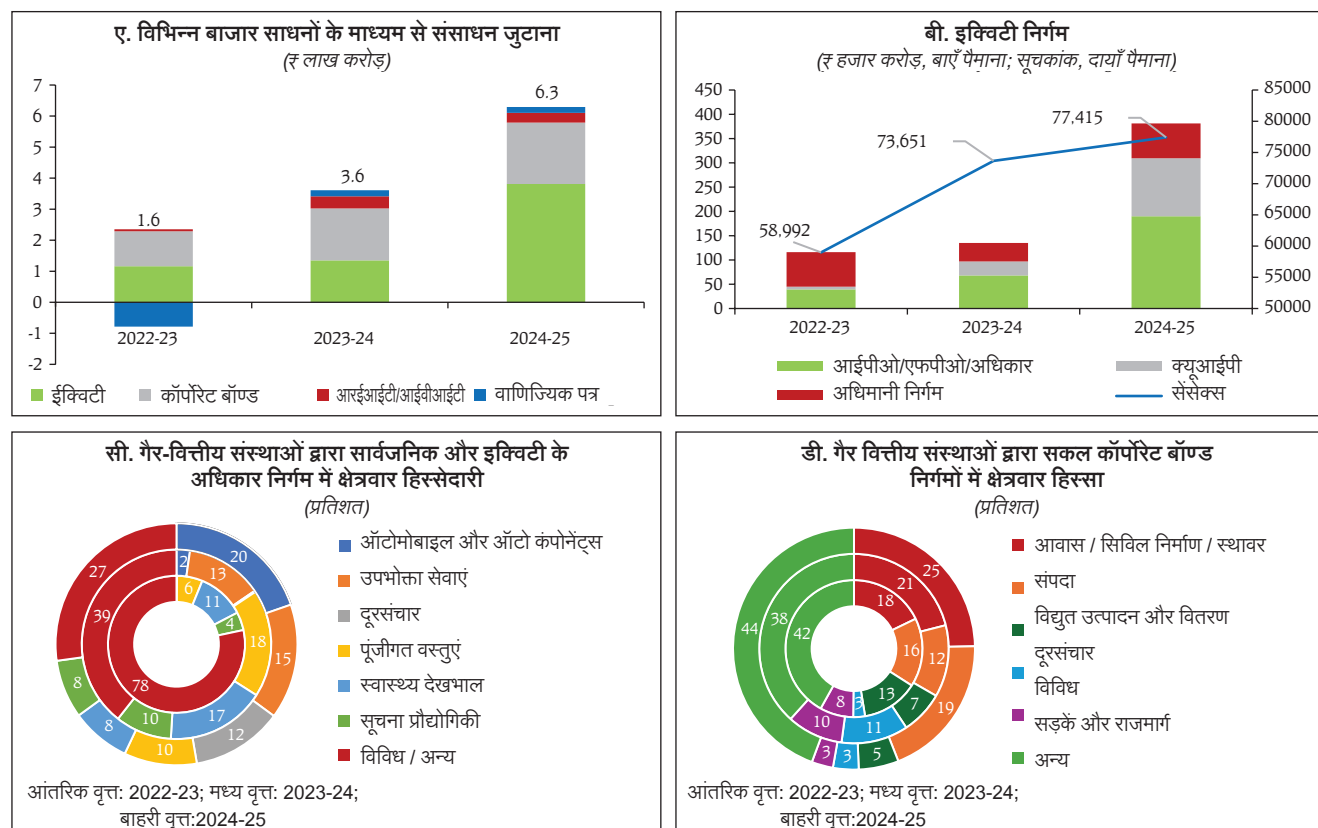
कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल में नरमी के बीच 2024-25 में गैर-वित्तीय संस्थाओं से कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करने में भी वृद्धि हुई। मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025 में कॉर्पोरेट के एएए-रेटेड 3-वर्षीय बॉण्ड पर मासिक औसत उपज 33 बीपीएस गिर गई। पूंजी-गहन क्षेत्र जैसे आवास, नागरिक निर्माण, अचल संपत्ति, बिजली उत्पादन और वितरण, और दूरसंचार प्रमुख जारीकर्ताओं के रूप में उभरे, जो बांड बाजार में गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा

कुल संसाधन जुटाने का लगभग आधा हिस्सा था (चार्ट 5डी)। यह अवसंरचना और क्षमता-निर्माण परियोजनाओं को निधि देने के लिए बाजार-आधारित दीर्घकालिक ऋण पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।

इसके अलावा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनवित) जैसे हाइब्रिड मार्केट इंस्ट्रूमेंट निधीयन का एक और रास्ता बन गए हैं। हालांकि इक्विटी और बॉण्ड की अपेक्षा कम परंतु उनका बढ़ता योगदान- पिछले तीन वर्षों में आस्ति-समर्थित और आय आर्जित करने वाले साधनों के लिए बढ़ती निवेशक माँग को इंगित करता है।

अल्पकालिक चलनिधि और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च रेटिंग वाले कॉर्पोरेट ने मुद्रा बाजार

चार्ट 5: बाजार स्रोतों से प्रवाह



**टिप्पणी:** चार्ट 5ए में, इक्विटी में आईपीओ, एफपीओ, अधिकार निर्गम, पत्र संस्थागत प्लेसमेंट और अधिमानी आबंटन के माध्यम से गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन शामिल हैं; और कॉर्पोरेट बॉण्ड और वाणिज्यिक पत्र, गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवल जारी किए जाते हैं। क्षेत्रवार कुल हिस्सेदारी राउंडिंग ऑफ के कारण 100 प्रतिशत तक नहीं बढ़ सकती है।

**स्रोत:** सेबी; प्राइम डेटाबेस; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

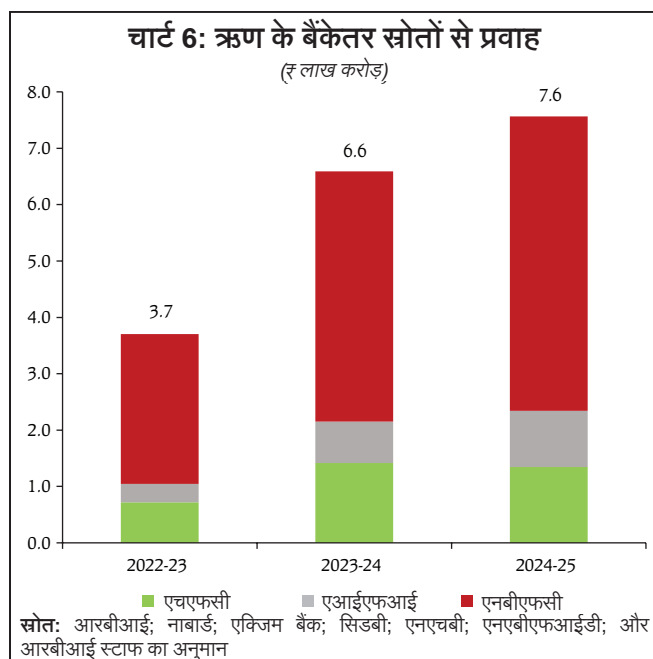
के वाणिज्यिक पत्र खंड तक पहुंच जारी रखी है। वाणिज्यिक पत्र निर्गम अन्य उपकरणों की तुलना में अधिक अस्थिर होने पर भी कई परस्पर संबंधित कारकों से प्रभावित होते हैं जिनमें प्रचलित अल्पकालिक ब्याज दरें, बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि, कॉर्पोरेट ऋण रेटिंग और मौसमी कार्यशील पूंजी चक्र शामिल हैं। आम तौर पर मौद्रिक सहजता और तंत्र में अधिशेष चलनिधि की अवधि वाणिज्यिक पत्र (वाणिज्यिक पत्र) निर्गमन का समर्थन करती है क्योंकि कॉर्पोरेट कम उधार लागतों का लाभ उठाते हैं। इसके विपरीत सख्त ब्याज दरों के माहौल में वाणिज्यिक पत्र निर्गमन बढ़ती उपज और रोलओवर जोखिम बढ़ने के कारण मध्यम हो सकता है। सख्त मौद्रिक परिस्थितियों के बीच वर्ष 2022-23 में वाणिज्यिक पत्र निर्गम में गिरावट के बाद वर्ष 2023-24 और 2024-25 में एक स्थिर मौद्रिक वातावरण के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक पत्र निर्गम में वृद्धि हुई।

#### IV.1.2. बैंकेतर ऋण के स्रोत

भारत में ऋण के प्रमुख गैर-बैंक स्रोतों में, एनबीएफसी, एआईएफआई और एचएफसी पारंपरिक बैंकिंग चैनल के पूरक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संस्थाएं उन क्षेत्रों और उधारकर्ता खंडों तक ऋण पहुंच की सुविधा में तेजी से महत्वपूर्ण हो गई हैं जहाँ तक पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली की कम या अपर्याप्त पहुंच है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनबीएफसी, एआईएफआई और एचएफसी द्वारा विस्तारित कुल ऋण में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो भारत की ऋण परितंत्र में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। हालांकि, इन तीनों श्रेणियों के संस्थाओं में से, बैंकेतर ऋण का प्रमुख स्रोत एनबीएफसी ही रहा है (चार्ट 6)। उद्योग और खुदरा क्षेत्रों को एनबीएफसी के ऋण का एक बड़ा हिस्सा दिया गया था, जिसमें मार्च 2024 के अंत तक उद्योगों को दिए गए अधिकांश ऋण बिजली क्षेत्र के थे (आरबीआई, 2024बी)।<sup>2</sup> इसके अलावा, एचएफसी के मामले में, व्यक्तियों को आवास ऋण उनके ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

<sup>2</sup> नवीनतम उपलब्ध डेटा के अनुसार।



#### IV.1.2. विदेशी स्रोत

निधीयन के बाहरी स्रोत, विशेष रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए भारत की बाहरी वित्तपोषण जरूरतों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एफडीआई - पूंजी का एक स्थिर और ऋण से इतर सृजन स्रोत - न केवल घरेलू निवेश के संवर्धन में योगदान देता है, बल्कि व्यापक संरचनात्मक लाभ में भी योगदान देता है। इनमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बेहतर प्रबंधकीय प्रथाएं, बढ़ी हुई उत्पादकता और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण में वृद्धि शामिल है। इसके अलावा, एफडीआई निवेशक विश्वास और संस्थागत विश्वसनीयता के आमान के रूप में कार्य करता है, जिससे बाजार की भावना और चलनिधि में सुधार होता है।

भारत की विदेश निवेश नीति के अनुसार, एफडीआई में अनिवासी निवेशकों द्वारा (ए) गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों या (बी) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की पोस्ट-इश्यू पेड-अप इक्विटी पूंजी (पूरी तरह से डायल्यूटेड आधार पर) में इक्विटी लिखतों के माध्यम से निवेश शामिल है। 2024-25 के दौरान, प्रत्यावर्तन में वृद्धि के बावजूद भारत में निवल एफडीआई प्रवाह में वृद्धि हुई (चार्ट 7ए)। सेवा क्षेत्र में 2024-25 में सकल एफडीआई

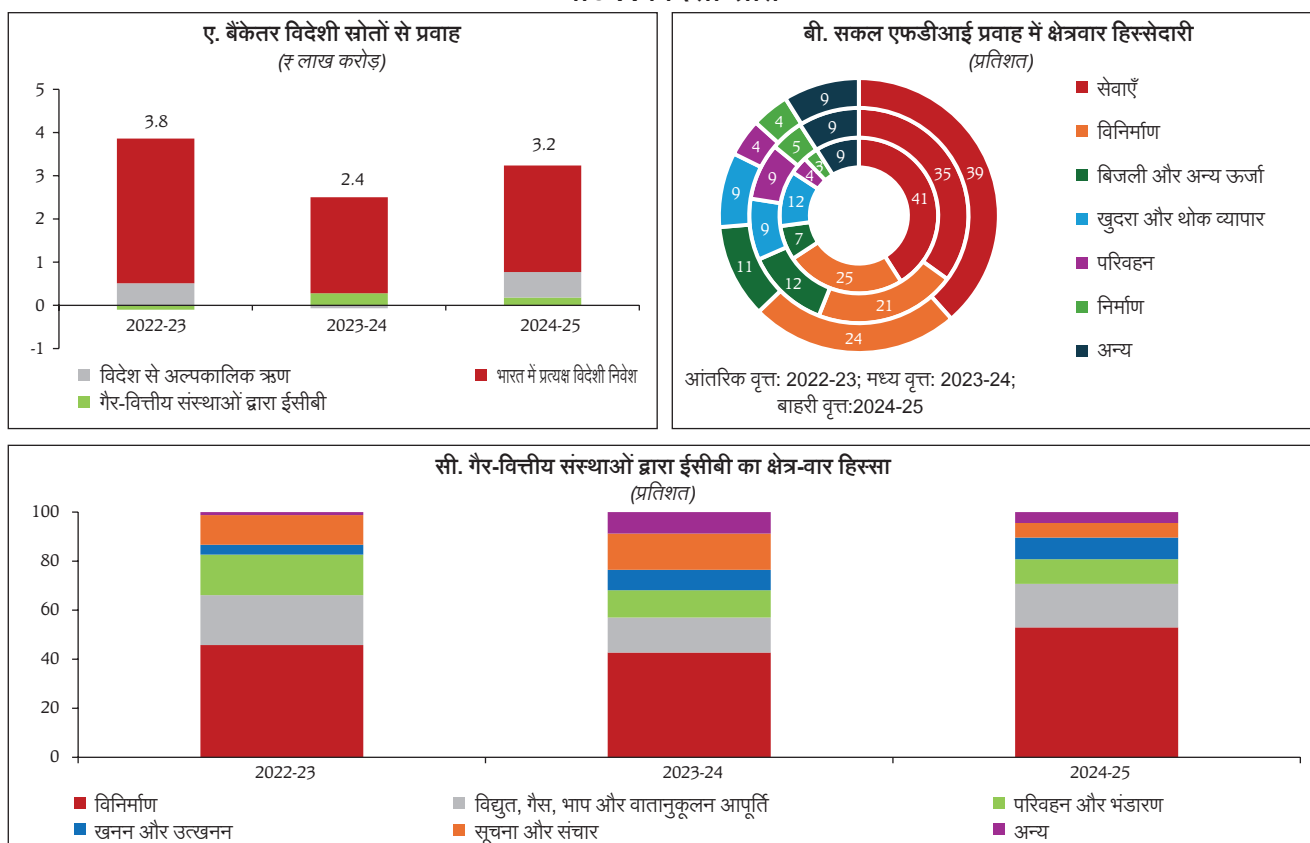
प्रवाह का सबसे बड़ा हिस्सा था, इसके बाद विनिर्माण, बिजली और अन्य ऊर्जा क्षेत्र, खुदरा और थोक व्यापार और परिवहन थे (चार्ट 7बी)।

कॉरपोरेट के लिए दीर्घकालिक विदेशी पूंजी तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) बना हुआ है।<sup>3</sup> ईसीबी को ज्यादातर तीन साल की न्यूनतम औसत परिपक्वता की आवश्यकता होती है और लागत पर विनियामक सीमाएं और अंतिम उपयोग प्रतिबंधों के अधीन हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, गैर-वित्तीय संस्थाओं में निवल ईसीबी प्रवाह ने वैश्विक ब्याज दर चक्रों, बदलती वैश्विक चलनिधि स्थितियों और पुनर्भुगतान दायित्वों को दर्शाते हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनशीलता प्रदर्शित की है। गैर-वित्तीय क्षेत्रों में विनिर्माण और बिजली, गैस, भाप और वातानुकूलन आपूर्ति क्षेत्र ईसीबी में सबसे बड़ी

हिस्सेदारी रखते हैं (चार्ट 7सी)। निधि के अंतिम उपयोग के संदर्भ में कुल ईसीबी का आधे से अधिक हिस्सा पूंजी या क्षमता विस्तार जैसे कि आयात या पूंजीगत वस्तुओं की स्थानीय सोर्सिंग, नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण और विदेशों में अधिग्रहण पर उपयोग किया जाता है जबकि लगभग एक तिहाई पहले के ईसीबी और बकाया रुपये ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है।<sup>4</sup>

विदेश से अल्पकालिक ऋण (यानी, अल्पकालिक व्यापार ऋण) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के व्यापारिक व्यापार के प्रदर्शन के साथ सकारात्मक सहसंबंध देखा है। 2024-25 में, भारत के व्यापारिक आयात में उछाल के बीच विदेशों से अल्पकालिक ऋण में वृद्धि हुई।

चार्ट 7: विदेशी स्रोत



टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण क्षेत्रवार कुल शेयर 100 प्रतिशत तक नहीं बढ़ सकता है।

स्रोत: आरबीआई; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

<sup>3</sup> ईसीबी में बैंक ऋण, फ्लोटिंग/फिक्स्ड रेट नोट/बॉण्ड/डिबेंचर (पूरी तरह से और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय लिखतों के अलावा), तीन साल से अधिक के व्यापार ऋण, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी), विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बॉण्ड (एफसीईबी), वित्तीय पट्टा और विदेशों में जारी किए गए प्लेन वैनिला रुपया मूल्यवर्ग के बॉण्ड (जो या तो निजी रूप से रखे जा सकते हैं या मेजबान देश के नियमों के अनुसार एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए जा सकते हैं)।

<sup>4</sup> पिछले तीन वर्षों के औसत पर आधारित।

## V. वाणिज्यिक क्षेत्र को बकाया ऋण

मार्च 2025 के अंत में खाद्येतर बैंक ऋण बढ़कर ₹182.1 लाख करोड़ हो गया जो मार्च 2025 की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 55.1 प्रतिशत है। इसी तरह इस अवधि के दौरान बैंकेतर स्रोतों से बकाया ऋण बढ़कर ₹88.9 लाख करोड़ हो गया जो सकल घरेलू उत्पाद का 26.9 प्रतिशत है। इसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों और बैंकेतर स्रोतों से कुल बकाया ऋण बढ़ कर ₹270.9 लाख करोड़ हो गया जो मार्च 2025 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद का 81.9 प्रतिशत था जबकि यह मार्च 2024 के अंत तक ₹241.7 लाख करोड़ यानी सकल घरेलू उत्पाद का 80.2 प्रतिशत था।

## VI. निष्कर्ष

भारतीय वित्तीय प्रणाली के क्रमिक उदारीकरण ने वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए निधि के विविध स्रोतों के निर्माण की सुविधा प्रदान की है। जबकि बैंकिंग प्रणाली भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए वित्तपोषण का एक प्रमुख स्रोत बनी हुई है, बैंकेतर स्रोत (घरेलू और विदेशी दोनों) भी हाल के वर्षों में वित्त के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरे हैं। इसलिए, बैंकों और बैंकेतर स्रोतों दोनों से प्रवाह को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के कुल प्रवाह का विश्लेषण करना अनिवार्य है।

2024-25 में, हालांकि बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में नरमी आई, बैंकेतर स्रोतों से प्रवाह ने बैंक ऋण में नरमी की भरपाई की, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में प्रवाह में वृद्धि हुई। 2024-25 में बैंक ऋण प्रवाह में नरमी मुख्य रूप से वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के उद्देश्य से नवंबर 2023 में गैर-जमानती ऋण पर जोखिम भार में वृद्धि से उत्पन्न लक्षित क्षेत्रों के लिए ऋण में मंदी के कारण हो सकती है।

बैंकों और बैंकेतर स्रोतों से सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण मार्च 2025 के अंत तक मार्च 2024 के स्तर से वृद्धि हुई। नतीजतन, इस अवधि के दौरान भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में समग्र बकाया ऋण बढ़ गया।

### संदर्भ:

आरबीआई (2024ए)। वित्तीय प्रणाली की बदलती प्रकृति: उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में लचीलेपन और दीर्घकालिक विकास के लिए निहितार्थ। बीआईएस पेपर नंबर 148, 159-180।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की रिपोर्ट: भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर रिपोर्ट, 2023-24।

<sup>5</sup> बैंकेतर स्रोतों पर डेटा में घरेलू स्रोतों के तहत इक्विटी और हाइब्रिड लिखतों को जारी करना और विदेशी स्रोतों के तहत इक्विटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल नहीं है।

परिशिष्ट

सारणी ए1: भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र को बकाया ऋण			
(मार्च के अंत तक)			
(रकम राशि करोड़ में; कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जीडीपी का प्रतिशत हैं)			
स्रोत	2023	2024	2025 पी
ए. खाद्येतर बैंक ऋण	1,36,55,330 (50.8)	1,64,09,083 (54.5)	1,82,07,441 (55.1)
बी. बैंकेतर स्रोत (बी1 + बी2)	74,43,091 (27.7)	77,56,314 (25.7)	88,85,434 (26.9)
बी1. घरेलू स्रोत	53,95,038 (20.1)	56,59,037 (18.8)	66,37,411 (20.1)
1. गैर-बैंकिंग संस्थाएं द्वारा कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करना	16,58,140	18,25,514	20,23,310
2. गैर-बैंकिंग संस्थाएं द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी करना	89,816	1,09,528	1,28,347
3. आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऋण (बैंक उधारी को घटाकर)	10,39,420	5,98,965	6,27,125
4. आरबीआई द्वारा विनियमित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण	3,51,224	4,24,610	5,24,111
5. गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण (बैंक उधारी को घटाकर)	22,56,439	27,00,421	33,34,518
बी2. विदेशी स्रोत	20,48,053 (7.6)	20,97,277 (7.0)	22,48,023 (6.8)
1. गैर-बैंकिंग संस्थाएं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधारी	10,29,403	10,71,240	11,33,592
2. विदेश से लघु अवधि के ऋण	10,18,650	10,26,037	11,14,432
सी. कुल ऋण (ए+बी)	2,10,98,421 (78.5)	2,41,65,397 (80.2)	2,70,92,875 (81.9)

पी: अनंतिम

टिप्पणियां: i) खाद्येतर बैंक ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से जुड़ा है और इसमें सहकारी बैंकों का दिया गया ऋण शामिल नहीं है। सहकारी बैंकों (जैसे, शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला सेंट्रल सहकारी बैंक) के दिए गए ऋण को मिलाकर, मार्च 2023 और 2024 के आखिर में खाद्येतर बैंक ऋण एक के बाद एक ₹1,46,22,252 करोड़ (जीडीपी का 54.4 प्रतिशत) और ₹1,74,63,724 करोड़ (जीडीपी का 58.0 प्रतिशत) था। इसके मुताबिक, मार्च 2023 और 2024 के आखिर में कुल बकाया ऋण एक के बाद एक ₹2,20,65,343 करोड़ (जीडीपी का 82.1 प्रतिशत) और ₹2,52,20,038 करोड़ (जीडीपी का 83.7 प्रतिशत) था।

ii) बैंकेतर स्रोतों के डेटा में घरेलू स्रोतों के तहत इक्विटी और हाइब्रिड लिखतों के जारी होने और विदेशी स्रोतों के तहत इक्विटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल नहीं हैं।

iii) कॉर्पोरेट बॉण्ड के मामले में, मार्च 2024 और 2025 के अंत के लिए बकाया डेटा वित्तीय और गैर-वित्तीय निगमों द्वारा जारी बॉण्ड पर सेबी की नई श्रृंखला के डेटा पर आधारित हैं। मार्च 2023 के अंत के लिए बकाया डेटा की गणना मार्च 2024 के अंत के बकाया डेटा से 2023-24 के प्रवाह को समायोजित करके की जाती है।

iv) बकाया डेटा पर आधारित प्रवाह सारणी1 में दिए गए प्रवाह से मेल नहीं खा सकता है क्योंकि:

(ए) 1 जुलाई, 2023 को एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय;

(बी) कुछ आवास वित्त कंपनियों का गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों में बदलना।

(सी) विदेशी स्रोत के मामले में वैल्यूएशन का असर।

v) डेटा में मौजूदा और नॉन-करंट ट्रेड पेमेंट शामिल नहीं हैं, जो गैर-वित्तीय, गैर-सरकारी पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के मामले में घरेलू देयताओं को दिखाते हैं, क्योंकि डेटा उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: आरबीआई; सेबी; नाबार्ड; एक्जिम बैंक; सिडबी; एनएचबी; एनएबीएफआईडी; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।



## फिनटेक ग्राहकों के अनुभव की अनकही कहानी

आशीष खोब्रागडे, साक्षी अवस्थी,  
मंतिशा एवं राखे बालचंद्रन<sup>^</sup> द्वारा<sup>^</sup>

फिनटेक नवाचारों को आगे बढ़ाने और ग्राहक-केंद्रित नीतियों को आकार देने के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को समझना महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन भारत के फिनटेक इकोसिस्टम में भावनाओं और प्रमुख चिंताओं को उजागर करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके 5.69 मिलियन फिनटेक ऐप समीक्षाओं का विश्लेषण करता है। परिणाम आम तौर पर सकारात्मक उपयोगकर्ता अनुभव प्रकट करते हैं, जिसमें विश्वास और खुशी जैसी भावनाएं सभी क्षेत्रों पर हावी होती हैं। विषय मॉडलिंग ग्राहक सहायता, तकनीकी और ऐप कार्यक्षमता और ऋण संबंधी चिंताओं की पहचान करती है। भिन्नात्मक प्रोबिट मॉडल के अनुभवजन्य निष्कर्ष अनुकूल समीक्षा भावना पर बाजार हिस्सेदारी के सकारात्मक, यद्यपि घटते हुए प्रभाव को उजागर करते हैं, जबकि डेटा गोपनीयता और ऐप अपडेट महत्वपूर्ण वाहकों के रूप में उभरते हैं।

### भूमिका

फिनटेक भुगतान, ऋण और निवेश सहित प्रमुख वित्तीय क्षेत्रों को नया आकार देने में महत्वपूर्ण बन गए हैं, इस प्रकार, सभी देशों में वित्तीय सेवा वितरण को बदल दिया गया है। मौजूदा साहित्य में कहा गया है कि उच्च लेनदेन गति, वैयक्तिकरण, सुरक्षा और पारदर्शिता फिनटेक नवाचारों के लिए ग्राहकों की प्राथमिकताएं बढ़ा रही हैं (फेयेन एवं अन्य., 2023)। भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता फिनटेक इकोसिस्टम, डिजिटल वित्त में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है (आरबीआई, 2024)। 10,000 से अधिक फिनटेक स्टार्टअप के साथ - देश विश्व स्तर पर दूसरे सबसे बड़े ऐप बाजार के रूप में रैंक करता है, जिसने वर्ष

2023 में 26.4 बिलियन डाउनलोड दर्ज किए (ट्रैक्सन, 2024; स्टेटिस्टा, 2024)। ति4 2023 (स्टेटिस्टा, 2024) में डिजिटल वॉलेट और भुगतान ऐप (100 मिलियन), व्यक्तिगत ऋण ऐप (93 मिलियन), और निवेश ऐप (64 मिलियन) के नेतृत्व में अकेले वित्त ऐप्स में 481 मिलियन डाउनलोड हुए। पिछले एक दशक में, फिनटेक फंडिंग 21 प्रतिशत की मजबूत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ी है, जो महामारी के बाद वैश्विक चलनिधि द्वारा संचालित है, जिसमें भुगतान और वैकल्पिक ऋण खंड धन उगाहने पर हावी हैं (ट्रैक्सन, 2024; सरॉय एवं अन्य., 2023)। युवा उपयोगकर्ताओं के बीच विशेष रूप से अपनाने की दर अधिक है, जिसमें 52 प्रतिशत 25 वर्ष से कम आयु के हैं और 51 प्रतिशत अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं (ट्रांसयूनियन सिबिल, 2023)। जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता संरक्षण और प्रणालीगत स्थिरता को संतुलित करते हुए फिनटेक के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, आरबीआई इनोवेशन हब और डिजिटल ऋण मानदंड और एसआरओ फ्रेमवर्क जैसी पहल शुरू की है। आगे देखते हुए, भारत का फिनटेक बाजार अगले पांच वर्षों में 31 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ 110 बिलियन डॉलर से बढ़कर 420 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है (चौधरी, 2024)।

संपन्न फिनटेक इकोसिस्टम, आशाजनक होते हुए भी, अक्सर ग्राहकों के सामने आने वाली अंतर्निहित चुनौतियों को छुपाता है क्योंकि ऑनबोर्ड विविध उपयोगकर्ता और फिनटेक बिजनेस मॉडल उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेजी से विकसित होते हैं। एक ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण - ग्राहकों की जरूरतों को समझने, उनके हितों की रक्षा करने और विश्वास बनाने पर आधारित - व्यावसायिक रणनीतियों में निरंतर प्रतिक्रिया तंत्र को समाहित करने की आवश्यकता होती है (दास, 2023)। प्रयोज्य परीक्षण (नीलसन, 1993), सर्वेक्षण और केंद्रित समूह (मॉर्गन, 1993) सहित इन मुद्दों को हल करने के पारंपरिक तरीके स्केलेबिलिटी, उच्च लागत, समय अंतराल और संभावित उपयोगकर्ता या सर्वेक्षक पूर्वाग्रह द्वारा सीमित हैं। एक नई विधि, जो औपचारिक सर्वेक्षणों से बेहतर है, वास्तविक समय के ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन समीक्षाओं का विश्लेषण कर रही है। प्राथमिक इंटरफेस के रूप में मोबाइल एप्लिकेशन (या

<sup>^</sup> आशीष खोब्रागडे, साक्षी अवस्थी और राखे बालचंद्रन आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से हैं, और मंतिशा डीईपीआर, आरबीआई में एक रिसर्च इंटरन थीं। लेखक बहुमूल्य टिप्पणियों और सुझावों के लिए श्री शरत चंद्र ढल के आभारी हैं। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।



ऐप्स) के साथ, उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षाओं (ह्यूबनेर एवं अन्य., 2018) के माध्यम से तेजी से प्रतिक्रिया साझा करते हैं, जो ऐप को अपनाने और खरीद निर्णयों को प्रभावित करते हैं (बर्गर एवं अन्य., 2016)। हालाँकि, सरासर मात्रा, असंरचित प्रारूप, वर्तनी त्रुटियाँ, इमोटिकॉन्स और बहुभाषी सामग्री - अक्सर अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषाओं के साथ मिलाना - महत्वपूर्ण पद्धतिगत चुनौतियाँ पेश करती हैं।

फिनटेक नवाचारों को आगे बढ़ाने और ग्राहक-केंद्रित नीतियों को आकार देने के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को समझना महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन भारत के फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में भावनाओं और प्रमुख चिंताओं को उजागर करने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स (डिस्टिलबर्ट) और बटॉपिक से डिस्टिल्ड बाइडायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन जैसी उन्नत मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके 5.69 मिलियन फिनटेक ऐप समीक्षाओं का विश्लेषण करता है। परिणाम आम तौर पर सकारात्मक उपयोगकर्ता अनुभव प्रकट करते हैं, जिसमें विश्वास और खुशी जैसी भावनाएं सभी क्षेत्रों पर हावी होती हैं। नकारात्मक समीक्षाओं का विषय मॉडलिंग ग्राहक सहायता, तकनीकी और ऐप कार्यक्षमता और ऋण संबंधी चिंताओं की पहचान करता है। फ्रैक्शनल प्रोबिट मॉडल (एफपीएम) के अनुभवजन्य निष्कर्ष अनुकूल समीक्षा भावना पर बाजार हिस्सेदारी के सकारात्मक, हालांकि कम होने वाले प्रभाव को उजागर करते हैं, जबकि डेटा गोपनीयता और ऐप अपडेट महत्वपूर्ण ड्राइवर्स के रूप में उभरते हैं। अध्ययन के परिणामों की व्याख्या करते समय, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नकारात्मक ऐप समीक्षाओं ने संबंधित फिनटेक द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई के लिए प्रेरित किया हो सकता है, हालांकि ग्राहकों ने अपनी समीक्षाओं को अपडेट नहीं किया होगा। फिर भी, ऐप्स में आवर्ती मुद्दे उनकी व्यापकता को उजागर करते हैं और फिनटेक, एसआरओ और नीति निर्माताओं से ध्यान आकर्षित करते हैं।

अध्ययन निम्नानुसार आयोजित किया जाता है: खंड II प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा करता है। खंड III डेटा और कार्यप्रणाली का विवरण देता है, जबकि खंड IV प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। खंड V कुछ नीतिगत दृष्टिकोणों के साथ समाप्त होता है।

## II. साहित्य समीक्षा

सामाजिक नेटवर्क, ऑनलाइन उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ता के अनुकूल एप्लिकेशन इंटरफेस के प्रसार ने डेटा की मात्रा में काफी वृद्धि की है, जिससे पाठ-आधारित अनुसंधान के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं (झाओ एवं अन्य., 2020)। ऐप समीक्षाएं उपयोगकर्ता संतुष्टि के एक मूल्यवान क्राउड-सोर्स संकेतक के रूप में उभरी हैं (वासा एवं अन्य., 2012)। उपयोगकर्ता की अपेक्षाओं और ऐप उपयोग के संबंध में इन समीक्षाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विविध अंतर्दृष्टि के बावजूद, कई ऐप्स में समीक्षाओं की बढ़ती मात्रा का व्यवस्थित और समय पर विश्लेषण एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है (ह्यूबनेर एवं अन्य., 2018)।

असंरचित डेटा के बड़े सेटों से सूक्ष्म अंतर्दृष्टि निकालने के लिए मशीन लर्निंग तकनीक आवश्यक हो गई है (पेंग और ली, 2008)। साक्ष्य बताते हैं कि विश्वास, खुशी, भय और क्रोध जैसी ग्राहक भावनाओं की पहचान करने के लिए भावना विश्लेषण लागू करना (ओमोटोशो, 2021) बैंक प्रतिक्रियाशीलता, ऐप कार्यक्षमता और परिचालन विफलताओं के बारे में उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया की समझ को बढ़ाता है (बाल्सीओग्लू, 2024)। ऐप की गुणवत्ता और बिक्री में मूल्यवान अंतर्दृष्टि निकालने के लिए विषय मॉडलिंग तकनीकों का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है (खालिद एवं अन्य., 2014; लियांग एवं अन्य., 2015)। ऐप संतुष्टि को बढ़ाने वाले कारकों में डाउनलोड की संख्या, ऐप श्रेणी (पैगानो और मालेज, 2013), ऐप कार्यक्षमता (लुइज़ एवं अन्य., 2018), और डिलीवरी दक्षता और ग्राहक सहायता जैसे लाभ शामिल हैं (कुमार एवं अन्य., 2023)। उपयोग में आसानी, कथित उपयोगिता, कथित मूल्य, प्रदर्शन प्रत्याशा, उपयोगकर्ता अनुभव और कथित गुणवत्ता जैसे कारकों की भी पहचान फिनटेक मोबाइल ऐप्स के लिए प्रासंगिक शब्दों के एक सेट का उपयोग करके की गई है (पेरिया-खलीफी एवं अन्य., 2024)। दुनिया भर में नीति निर्माता निर्णय लेने और नीति विकास को सूचित करने के लिए उपयोगकर्ता-जनित सामग्री, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट का विश्लेषण करने के लिए डेटा एनालिटिक्स टूल का तेजी से लाभ उठा रहे हैं (ड्रिस एवं अन्य., 2019)। इसके अलावा, ऐप समीक्षा डेटा धोखाधड़ी और चूक दरों की भविष्यवाणी करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम कर सकता है (प्रणता एवं अन्य., 2019)।

भारतीय संदर्भ में, जबकि अध्ययनों ने लघु-पाठ सोशल मीडिया डेटा (त्रिवेदी और सिंह, 2021) से अंतर्दृष्टि निकालने के लिए मशीन लर्निंग को लागू किया है, ऑनलाइन समीक्षाओं का उपयोग करके फिनटेक ऐप्स में उपयोगकर्ता के अनुभवों पर शोध सीमित है। पीयर-टू-पीयर (पी2पी) लेंडिंग ऐप पर एक अध्ययन से पता चला है कि उपयोगकर्ता आम तौर पर ऋण प्रसंस्करण समय से संतुष्ट थे, जिसमें उपयोग में आसानी, लागत और जोखिम पर कम जोर दिया गया था (गुप्ता और महाजन, 2023)। एक अन्य अध्ययन ने उपयोगकर्ता भावनाओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 2017 पी2पी ऋण दिशानिर्देशों के सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित किया, जैसा कि वेलेंस अवेयर डिक्शनरी एंड सेंटीमेंट रीजनर (वीएडीआईआर) मॉडल (आरबीआई, 2024) द्वारा मूल्यांकन किया गया है।

इस पृष्ठभूमि में, पेपर फिनटेक अनुप्रयोगों के उपयोगकर्ता को अपनाने और संतुष्टि का गहन मूल्यांकन प्रदान करना चाहता है। पिछले अध्ययनों के विपरीत, यह शोध एक बड़े नमूना आकार का उपयोग करता है और ऐप विशेषताओं, कार्यक्षमताओं, कंपनी फंडिंग चरणों, फिनटेक श्रेणियों, गोपनीयता मुद्दों और विनियामक संबद्धताओं सहित कारकों की एक विस्तृत शृंखला का पता लगाता है।

### III. डेटा और कार्यप्रणाली

#### III.1 नमूना चयन

यह अध्ययन भारत में 107 व्यवसाय-से-ग्राहक (बी2सी) फिनटेक के नमूने का विश्लेषण करता है, जिसमें 61 वैकल्पिक ऋण देने वाले ऐप, 25 भुगतान ऐप और 21 बैंकिंग टेक ऐप शामिल हैं।<sup>1</sup> इन फिनटेक की पहचान ट्रेक्सन डेटाबेस<sup>2</sup> का उपयोग करके की गई और बाद में गूगल प्ले स्टोर पर मैप किया गया। संबद्ध ऐप्स का अंतिम चयन चार मानदंडों पर आधारित था: (ए) फिनटेक एक बी2सी बिजनेस मॉडल का अनुसरण करता है; (बी) फिनटेक

<sup>1</sup> वैकल्पिक ऋण, भुगतान और बैंकिंग तकनीक ऐप्स वे ऐप्स हैं जिनका प्राथमिक व्यवसाय क्रमशः ऋण, भुगतान और बैंकिंग है। यह संभव है कि फिनटेक श्रेणियां आपस में ओवरलैप हों, इसलिए इन श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए प्राथमिक व्यवसाय मॉडल को आधार बनाया गया है।

<sup>2</sup> भुगतान, वैकल्पिक ऋण और बैंकिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत फिनटेक कंपनियों को मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रेक्सन से शॉर्टलिस्ट किया गया और उनकी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से सत्यापित किया गया, जिससे 376 वैध कंपनियां हैं। ये कंपनियां भारत में बी2सी फिनटेक द्वारा जुटाई गई कुल फंडिंग का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा हैं, जिसमें ऐप-आधारित कंपनियों का हिस्सा और भी अधिक है। स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के बिना अधिग्रहित संस्थाओं को हटाने के बाद, 5.69 मिलियन समीक्षाओं वाली 107 फिनटेक कंपनियों को रखा गया, जो ग्राहक चिंताओं का विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत और प्रतिनिधि नमूना बनाती हैं।

जिनके पास भुगतान या ऋण या बैंकिंग के रूप में प्राथमिक व्यवसाय लाइन है; (सी) फिनटेक कंपनियां जिन्होंने तीन वर्ष की औसत डेडपूल आयु (अर्थात् 2022 में या उससे पहले शुरू की गई)<sup>3</sup> की औसत आयु को पार कर लिया है; और (डी) न्यूनतम 50 समीक्षाओं वाले ऐप।

#### III.2 डेटा संग्रह

ओपन-एक्सेस पायथन पैकेज गूगल-प्ले-स्क्रेपर (जोमिंग्यू, 2019) का उपयोग ऐप समीक्षाएं निकालने के लिए किया गया था। अप्रैल 2022 से अगस्त 2024 तक की 5.69 मिलियन से अधिक समीक्षाएं एकत्र की गईं, साथ ही अद्वितीय इंस्टॉलेशन, समीक्षा गणना और प्रमुख ऐप अपडेट जैसे ऐप-विशिष्ट डेटा भी एकत्र किए गए। अध्ययन अवधि के चयन को दो कारकों ने निर्देशित किया: पहला, उपयोगकर्ता की भावनाओं पर कोविड-19 महामारी से संभावित विकृतियों का बहिष्कार और दूसरा, नीतिगत दृष्टिकोण से प्रासंगिकता। पुरानी समीक्षाओं का विश्लेषण करने से भारतीय फिनटेक इकोसिस्टम में वर्तमान चुनौतियों का पता नहीं चल सकता है, जिसके लिए समय पर सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक ऐप के लिए गोपनीयता और डेटा सुरक्षा नीतियों को भी संकलित किया गया था, जिसमें अनुरोधित अनुमतियों जैसे पहलुओं को शामिल किया गया था। गोपनीयता डेटा में 13 से अधिक प्रकार की अनुमतियों का अवलोकन शामिल है जो एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं से अनुरोध कर सकते हैं, जैसे कि पहचान, संपर्क, स्थान, एसएमएस, फोन विवरण, फोटो/मीडिया/फ़ाइलें, भंडारण, कैमरा, माइक्रोफ़ोन, वाईफाई कनेक्शन, डिवाइस और कॉल जानकारी और अन्य। फिनटेक-विशिष्ट डेटा, जिसमें निगमन का वर्ष, जुटाई गई फंडिंग, संस्थापक पृष्ठभूमि, फंडिंग चरण और वार्षिक राजस्व शामिल हैं, ट्रेक्सन डेटाबेस<sup>4</sup> से प्राप्त किए गए थे। गूगल प्ले स्टोर पर संबंधित ऐप पेजों से प्रमुख ऐप अपडेट निकाले गए थे। सभी गैर-श्रेणीबद्ध चर को बाद के क्रॉस-अनुभागीय विश्लेषण के लिए ऐप स्तर पर एकत्रित (औसत) किया गया था।

<sup>3</sup> औसत डेडपूल आयु की गणना बैंकिंग तकनीक, भुगतान और उधार में 429 डेडपूल बी2सी फिनटेक से की जाती है, जहां 'डेडपूल' उन फर्मों को दर्शाता है जो अस्तित्व में नहीं हैं। नीति निर्माण के लिए सार्थक भावना विश्लेषण और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए, अध्ययन केवल तीन वर्ष से अधिक पुराने परिचालन फिनटेक पर केंद्रित है, जिसमें निष्क्रिय या बहुत नए ऐप को बाहर रखा गया है। कोई भी चयन पूर्वाग्रह न्यूनतम है, और अनुभवजन्य विश्लेषण में फिनटेक युग को नियंत्रित किया जाता है।

<sup>4</sup> 26 सितंबर 2024 तक एक्सेस किया गया।

### III.3 भावना विश्लेषण

मौजूदा साहित्य के अनुरूप सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ जैसी समीक्षा भावनाओं की पहचान करने के लिए भावना विश्लेषण किया जाता है (ओमोटोशो, 2021; मिशेव एवं अन्य., 2020)। फिनटेक क्षेत्र में, उपयोगकर्ता की संतुष्टि का आकलन करने और फिनटेक अनुप्रयोगों में ग्राहकों की चिंताओं की पहचान करने के लिए भावना विश्लेषण और गहन शिक्षण मॉडल लागू किए गए हैं (मास्तुरोह और पोहान, 2021; अल रयान एवं अन्य., 2023; ह्यूबनेर एवं अन्य., 2018)। पूर्व-प्रशिक्षित भाषा मॉडल से जुड़े प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) कार्य आमतौर पर या तो फीचर-आधारित या फाइन-ट्यूनिंग दृष्टिकोण<sup>6</sup> को नियोजित करते हैं।<sup>5</sup> भारतीय संदर्भ में, जहां डिजिटल पाठ अक्सर हिंदी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को अंग्रेजी के साथ मिलाते हैं, बीईआरटी जैसे फाइन-ट्यून मॉडल ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है (वधावन और अग्रवाल, 2021)। तदनुसार, यह अध्ययन एक फाइन-ट्यूण्ड डिस्टिलबर्ट, एक तेज और छोटे ट्रांसफार्मर-आधारित मॉडल को नियोजित करता है (सन, 2019)।

डेटा के प्रशिक्षण के लिए, डेटासेट से 4000 अवलोकनों<sup>7</sup> का एक रैंडम नमूना लिया गया था। नमूने में प्रत्येक समीक्षा को मैनुअल रूप से तीन भावनाओं में वर्गीकृत किया गया था, अर्थात्, सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ। इस पूर्व-प्रशिक्षित डिस्टिलबर्ट-आधारित अनकेस्ड मॉडल को लेबल किए गए डेटा पर फाइन-ट्यूण्ड किया गया ताकि प्रत्येक समीक्षा को उपरोक्त तीन भावना श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सके। प्रशिक्षित डेटा के प्रदर्शन के संदर्भ में, डिस्टिलबर्ट मॉडल ने वाडर की तुलना में अधिक सटीकता दिखाई (सारणी 1)।<sup>7</sup> इसके अलावा, डिस्टिलबर्ट में सकारात्मक और नकारात्मक समीक्षाओं के बीच प्रशिक्षण डेटा काफी संतुलित था, जिससे यह पसंदीदा मॉडल बन गया।<sup>8</sup>

<sup>5</sup> फीचर-आधारित दृष्टिकोण भावना स्कोर करने के लिए पूर्वनिर्धारित शब्द सुविधाओं पर निर्भर करता है, जैसा कि वीएडीआईआर में देखा गया है। वीएडीआईआर, एक शब्दकोष और नियम-आधारित भावना विश्लेषण मॉडल, मशीन-लर्निंग-उन्मुख तकनीकों के बीच विशेष रूप से प्रभावी है (हटो और गिल्बर्ट, 2014)। इसके विपरीत, फाइन-ट्यूनिंग दृष्टिकोण में पाठ को भावना श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए बीईआरटी जैसे पूर्व-प्रशिक्षित मॉडल को समायोजित करना शामिल है (देवलीन एवं अन्य., 2018)।

<sup>6</sup> लेबल किए गए डेटासेट का आकार पर्याप्त है क्योंकि ट्रेन और परीक्षण डेटा भविष्यवाणियों में सटीकता स्कोर में अंतर एक प्रतिशत है, जो कोई ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग नहीं होने का संकेत है।

<sup>7</sup> सटीकता उन सभी वर्गीकरणों का अनुपात है जो सही थे, चाहे सकारात्मक हों या नकारात्मक। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है: (टू पॉजिटिव + टू नेगेटिव)/(टू पॉजिटिव + टू नेगेटिव + फॉल्स पॉजिटिव + फॉल्स नेगेटिव)।

<sup>8</sup> ~ 1 प्रतिशत पर तटस्थ समीक्षाओं के साथ, उन्हें छोड़कर सकारात्मक और नकारात्मक समीक्षाओं के बीच असंतुलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्लेषण को सरल बनाता है, जिससे यह एक द्विआधारी वर्गीकरण समस्या बन जाती है।

### सारणी 1: समीक्षा भावना वर्गीकरणकर्ताओं के सटीकता स्कोर

(प्रतिशत में)		
मॉडल	प्रशिक्षण सेट	टेस्ट सेट
वाडर	81.5	81.6
डिस्टिलबर्ट	97.46	96.1

स्रोत : लेखकों की गणना।

### III.4 भावना वर्गीकरण

नेशनल रिसर्च काउंसिल (एनआरसी) - कनाडा इमोशन क्लासिफायर, एक नियम-आधारित दृष्टिकोण, का उपयोग फिनटेक ऐप्स के उपयोगकर्ता को अपनाने से जुड़ी आठ प्रकार की भावनाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे, 'विश्वास', 'प्रत्याशा', 'खुशी', 'आश्चर्य', 'उदासी', 'भय', 'क्रोध', और 'घृणा' (मोहम्मद और टर्नी, 2013)। हालांकि, भावना 'आश्चर्य' को इसके सकारात्मक या नकारात्मक अर्थ के बारे में अस्पष्टता के कारण इस अध्ययन से बाहर रखा गया है।

### III.5 विषय मॉडलिंग

फिनटेक एप्लीकेशन में ग्राहकों की चिंताओं को उजागर करने के लिए, लेबल की गई नकारात्मक समीक्षाओं पर विषय मॉडलिंग का उपयोग किया जाता है। लेटेंट डिस्चिजेट एलोकेशन (एलडीए) और नॉन-नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन (एनएमएफ) जैसे पारंपरिक तरीके समरूप या अत्यधिक व्यापक विषयों को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रभावकारिता छोटे, असंरचित और जटिल पाठ के साथ कम हो जाती है (एगर और यू, 2022)। इसके विपरीत, BERTopic, एक तंत्रिका नेटवर्क मॉडल, अधिक सार्थक और सुसंगत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है (गोटेनडॉर्स्ट, 2022; कृष्णन, 2023)। इस प्रकार, टर्म फ्रीक्वेंसी-इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी (टीएफ-आईडीएफ) के साथ एक अर्ध-पर्यवेक्षित BERTopic को फिनटेक ऐप सेगमेंट में नकारात्मक समीक्षाओं पर लागू किया जाता है। एक विषय मॉडल, ऐप की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक, समीक्षाओं के नमूने पर प्रशिक्षित किया गया था।<sup>9</sup>

<sup>9</sup> एक मजबूत और अच्छी तरह से सामान्यीकृत BERTopic मॉडल बनाने के लिए, अप्रैल 2022 से अगस्त 2024 तक की समीक्षाओं से प्रशिक्षण के लिए समीक्षाओं के विविध और प्रतिनिधि नमूने निकाले गए थे। कंप्यूटिंग बाधाओं के कारण मॉडल को एक छोटे नमूने पर प्रशिक्षित किया गया था, जिसमें प्रत्येक पुनरावृत्ति में 30,000-40,000 समीक्षाओं के यादृच्छिक सबसेट का उपयोग किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः 10, 20 और 30 प्रतिशत वैकल्पिक ऋण, भुगतान और बैंकिंग तकनीकी ऐप के श्रेणी-वार नमूना शेयर प्राप्त हुए। इन प्रशिक्षित मॉडलों का उपयोग तब समीक्षाओं के एक हालिया सेट (अप्रैल 2023 - अगस्त 2024) पर विषयों की भविष्यवाणी करने के लिए किया गया था, जिससे ग्राहक समीक्षाओं में विकसित हो रहे रुझानों में मजबूत वर्गीकरण सुनिश्चित होता है।

प्रशिक्षित मॉडलों का उपयोग तब शेष समीक्षाओं को पहचाने गए विषयों में वर्गीकृत करने के लिए किया गया था।<sup>10</sup> केवल 30 वर्णों से अधिक की समीक्षाओं का विश्लेषण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 5,37,611 समीक्षाएं हुईं; जिसमें वैकल्पिक ऋण के लिए 2,77,003 समीक्षाएं, भुगतान के लिए 1,90,594 और बैंकिंग टेक के लिए 70,014 समीक्षाएं शामिल थीं। विषय मॉडल आउटपुट से, विश्लेषण के लिए केवल सुसंगत और विशिष्ट समूहों पर विचार किया गया था, जिससे अंतिम विश्लेषण में वैकल्पिक ऋण में 26.3 प्रतिशत, भुगतान में 25.4 प्रतिशत और बैंकिंग टेक में 33.7 प्रतिशत समीक्षाओं को बनाए रखा गया था। संक्षिप्तता और बेहतर समझ के लिए, विषयों को बाद में मैन्युअल रूप से 11 व्यापक विषयों में जोड़ा गया था।

## IV. अनुभवजन्य परिणाम

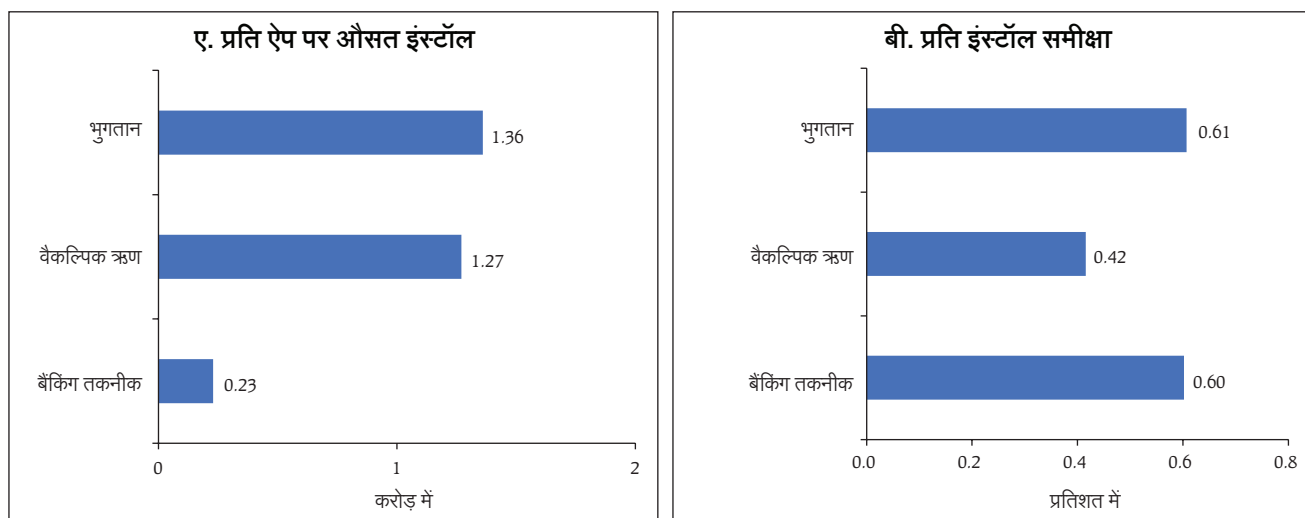
### IV.1 शैलीबद्ध निष्कर्ष

अध्ययन के तहत तीन क्षेत्रों में से, अर्थात्, भुगतान, ऋण और बैंकिंग,<sup>11</sup> ऐप जिनके प्राथमिक व्यवसाय के रूप में भुगतान या ऋण देना है, बैंकिंग की तुलना में स्थापित होने की अधिक संभावना है (चार्ट 1 ए)। अद्वितीय फिनटेक ऐप इंस्टॉलेशन के लिए समीक्षा प्राप्त करने की संभावना 0.54 प्रतिशत है, जो बैंकिंग

प्रौद्योगिकी ऐप की तुलना में भुगतान और ऋण देने वाले ऐप (0.6 प्रतिशत) के लिए मामूली रूप से अधिक है (चार्ट 1बी)। हालाँकि, अध्ययन के तहत ऐप्स को पिछले दो वर्षों के दौरान लगभग छह मिलियन समीक्षाएँ मिली हैं, जो प्रमुख ग्राहक चिंताओं को समझने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं।

भारत में फिनटेक समीक्षाओं का ध्रुवीकरण किया जाता है, जिसमें कुल समीक्षाओं का लगभग 20 प्रतिशत एक सितारा से संबंधित होता है और कुल समीक्षाओं का 67 प्रतिशत पांच सितारों से संबंधित होता है (चार्ट 2)। इस प्रकार, ये चरम समीक्षाएँ फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में कुल समीक्षाओं का लगभग 87 प्रतिशत हिस्सा हैं। भावना विश्लेषण के संदर्भ में, संख्याएँ भिन्न हो सकती हैं। रेटिंग और समीक्षाओं के बीच भावनाओं में विचलन को अंतर्निहित मेट्रिक्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है: जबकि रेटिंग प्रतिक्रियाओं की कुल संख्या को दर्शाती है, जिसमें लिखित प्रतिक्रिया के बिना भी शामिल हैं, भावना विश्लेषण शब्दांकित समीक्षाओं के उप-नमूने तक ही सीमित है, यह सुझाव देते हुए कि चरम अनुभव वाले उपभोक्ताओं को दूसरों की तुलना में एक शब्दबद्ध समीक्षा छोड़ने की अधिक संभावना है (स्कोनमुलर

चार्ट 1 : क्षेत्र-वार फिनटेक ऐप परिदृश्य

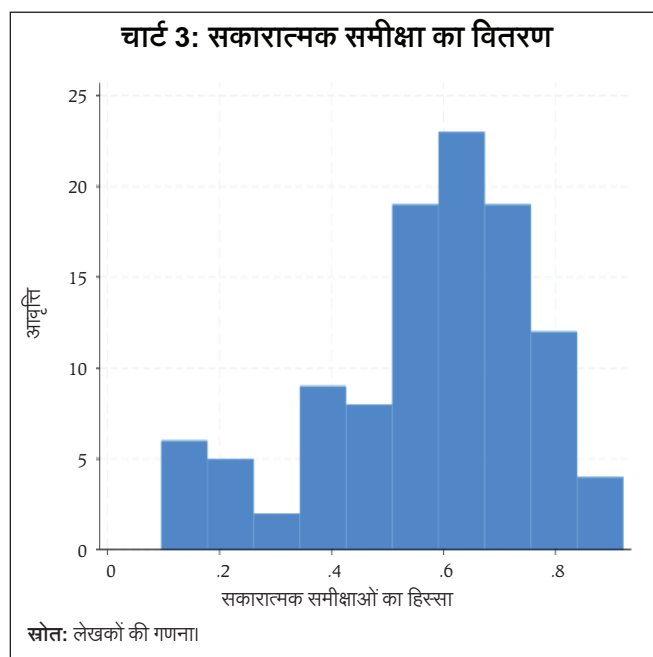
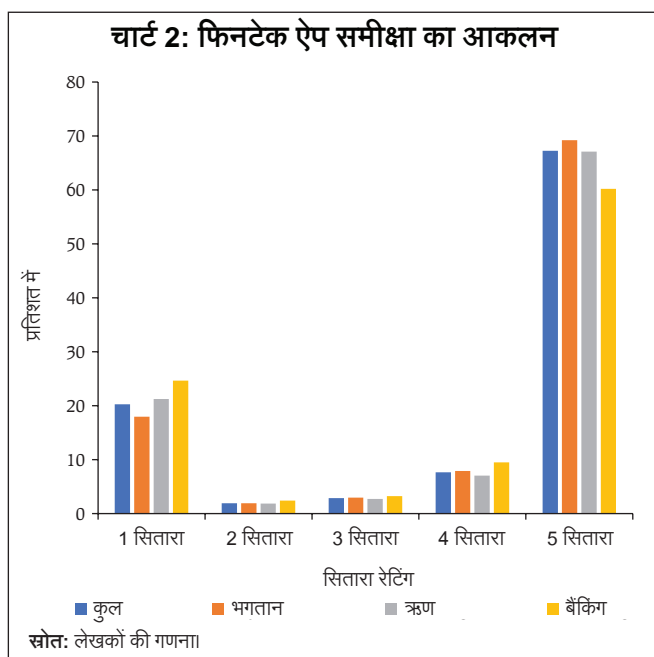


**टिप्पणी:** चार्ट 1(ए) में, प्रत्येक ऐप के लिए क्षेत्रवार औसत इंस्टॉल की गणना इस प्रकार की गई है: कुल अद्वितीय इंस्टॉल / प्रत्येक सेक्टर में ऐप्स की कुल संख्या। चार्ट 1(बी) में, प्रति इंस्टॉल समीक्षा की गणना इस प्रकार की गई है: किसी ऐप की कुल समीक्षाएँ / किसी ऐप के कुल अद्वितीय इंस्टॉल।

**स्रोत:** लेखकों की गणना।

<sup>10</sup> चूंकि BERTopic प्रमुख विषय के साथ समीक्षाओं की पहचान करता है, इसलिए समीक्षाओं को क्रमशः वैकल्पिक ऋण, भुगतान और बैंकिंग तकनीक के लिए 295, 191 और 185 विषयों में वर्गीकृत किया गया था। इसी तरह के विषयों को 11 व्यापक विषयों में जोड़ा गया था (बाद में सारणी 3 में रिपोर्ट किया गया); जबकि अस्पष्ट और असंगत विषयों को छोड़ दिया गया था।

<sup>11</sup> इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रति ऐप औसत इंस्टॉल की गणना करते समय कुल इंस्टॉल (दो भुगतान ऐप और दो बैंकिंग ऐप) के संदर्भ में चार बाहरी ऐप्स को बाहर रखा गया है।



एवं अन्य 2020; हू एवं अन्य., 2017)। इसके अलावा, फिनटेक समीक्षाओं में एक सकारात्मक असंतुलन भी मौजूद है, जिसका अर्थ है कि अधिकांश ऐप्स द्वारा प्राप्त सकारात्मक समीक्षाओं का हिस्सा नकारात्मक समीक्षाओं के हिस्से से अधिक है।

विशेष रूप से, अध्ययन किए गए सभी फिनटेक ऐप में से 61.7 प्रतिशत को 50 से 80 प्रतिशत की सीमा में सकारात्मक समीक्षा मिली। ऐप के एक छोटे से हिस्से (7 फीसदी) को 20 फीसदी से भी कम सकारात्मक समीक्षा मिली। इस प्रकार, भारतीय फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में औसत सकारात्मक समीक्षाओं का वितरण थोड़ा नकारात्मक रूप से तिरछा है (चार्ट 3)। फिनटेक ऐप जो समग्र सकारात्मक औसत से नीचे थे, उनमें से 58 प्रतिशत भुगतान क्षेत्र से संबंधित हैं, 22 प्रतिशत वैकल्पिक ऋण से संबंधित हैं और 20 प्रतिशत बैंकिंग तकनीकी क्षेत्र से संबंधित हैं।

ऐप की अद्वितीय स्थापना (पीआरआई) के प्रति सकारात्मक समीक्षा अधिक प्रासंगिक हो सकती है क्योंकि अधिकांश ग्राहक समीक्षा नहीं छोड़ते हैं। पीआरआई सकारात्मक रूप से 1 से नीचे पीआरआई वाले अधिकांश ऐप्स के साथ विषम है (चार्ट 4 ए)। पीआरआई फिनटेक ऐप्स की विशेषताओं के अनुसार भिन्न होता है। इंस्टॉल के संदर्भ में ऐप्स के सेगमेंट-वार बाजार हिस्सेदारी के

साथ पीआरआई बढ़ता है (चार्ट 4बी)। पीआरआई भी उम्र के साथ बढ़ता है क्योंकि फिनटेक डेडपूल होने की औसत आयु (यानी, 3 वर्ष) को पार कर जाते हैं [चार्ट 4 सी]। फिनटेक के फंडिंग चरणों के साथ इसी तरह का संबंध देखा जाता है, प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक प्रारंभिक वृद्धि के बाद सार्वजनिक फिनटेक (चार्ट 4डी) के लिए हल्की गिरावट आती है।

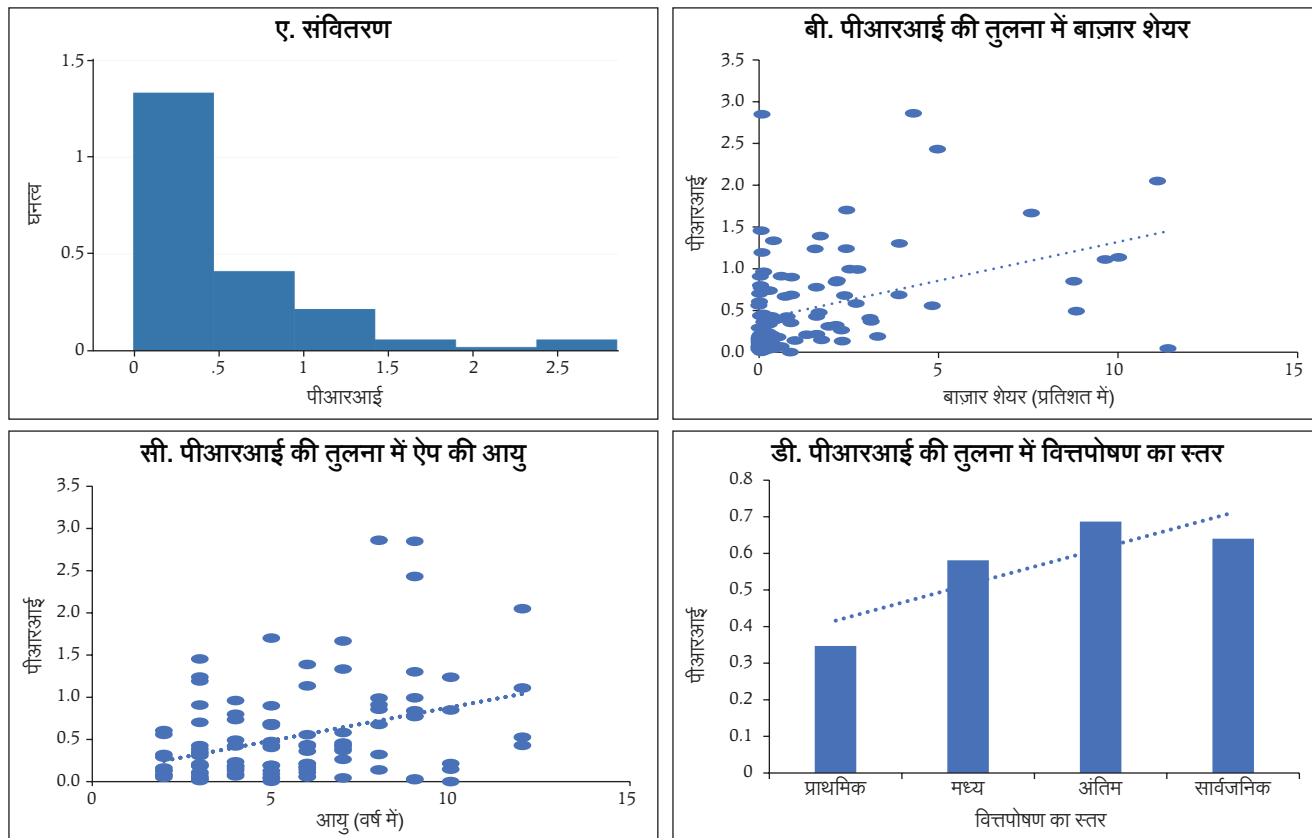
## IV.2 समीक्षाओं में भावनाओं का विश्लेषण

ग्राहक समीक्षाओं में भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ ग्राहकों की संतुष्टि या असंतोष के बारे में अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। मानक साहित्य के बाद, यह अध्ययन तीन सकारात्मक भावनाओं (विश्वास, बेहतर परिणामों और खुशी की प्रत्याशा) और चार नकारात्मक भावनाओं (घृणा, उदासी, भय और क्रोध) की जांच करता है।

भारतीय फिनटेक इकोसिस्टम से जुड़ी सबसे सकारात्मक भावना सभी क्षेत्रों में विश्वास है, इसके बाद अच्छे परिणाम और खुशी की प्रत्याशा है। सभी क्षेत्रों में, लगभग 50 प्रतिशत ग्राहकों ने फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ विश्वास व्यक्त किया है। नकारात्मक भावनाओं में, सबसे अधिक व्यक्त की जाने वाली भावना क्रोध है, उसके बाद उदासी, भय और घृणा है। 14 फीसदी ग्राहकों ने गुस्सा जाहिर किया है। कुल मिलाकर, सकारात्मक



चार्ट 4 : प्रति विशिष्ट संस्थापन के लिए सकारात्मक समीक्षा



**टिप्पणी:** पीआरआई की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:

(सकारात्मक समीक्षाओं का हिस्सा \* 2 वर्षों में समीक्षाओं की संख्या) / (आरंभ से अब तक विशिष्ट संस्थापन / ऐप की आयु \* 2)

**स्रोत:** लेखकों की गणना।

भावनाएं सभी क्षेत्रों में हावी होती हैं, जो आम तौर पर अनुकूल भावना को दर्शाती हैं, लेकिन नकारात्मक भावनाएं लक्षित सुधारों के लिए ध्यान देने की आवश्यकता होती हैं (सारणी 2)।

सारणी 2 : क्षेत्रवार भावना वर्गीकरण

(प्रतिशत में)				
भावनाएं	वैकल्पिक ऋण	बैंकिंग टेक	भुगतान	कुल
सकारात्मक भावनाएं				
भरोसा	47.63	53.31	48.62	48.98
प्रत्याशा	43.50	44.21	43.90	43.73
खुशी	40.69	42.05	43.25	41.55
नकारात्मक भावनाएं				
गुस्सा दिलाना	13.68	15.35	14.99	14.31
उदासी	13.10	12.86	13.10	13.05
डर	11.11	10.86	11.27	11.10
असह्य	10.26	8.28	8.50	9.46

**टिप्पणी:** भावनाओं की उपस्थिति को नमूना अवधि में कुल समीक्षाओं तक बढ़ाया जाता है, जो भावनाओं को व्यक्त करने वाले ग्राहकों के प्रतिशत के बारे में एक सिंहावलोकन प्रदान करता है।

**स्रोत:** लेखकों की गणना।

### IV.3 नकारात्मक समीक्षाओं की विषय मॉडलिंग

नकारात्मक समीक्षा ग्राहकों से लेकर फिनटेक तक एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में कार्य कर सकती है, और नीति निर्माताओं को समष्टि-स्तरीय अंतर्दृष्टि भी प्रदान कर सकती है। उनके अंतर्निहित प्रमुख संदेशों के आधार पर नकारात्मक समीक्षाओं पर विषय मॉडलिंग को नियोजित करना ग्राहकों के सामने आने वाली व्यापक चुनौतियों को समझने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। विषय मॉडलिंग का उपयोग करके नकारात्मक समीक्षाओं के क्षेत्र-वार विश्लेषण द्वारा उजागर किए गए प्रमुख मुद्दों को सारणी 3 में दिया गया है।

सभी क्षेत्रों में पहचानी जाने वाली एक प्रमुख चिंता ग्राहक सहायता और सेवा (सीएसएस) है, जो बैंकिंग प्रौद्योगिकी ग्राहकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंता के रूप में उभरती है, और भुगतान तकनीक और वैकल्पिक ऋण देने वाले तकनीकी उपयोगकर्ताओं

**सारणी 3: फिनटेक ग्राहकों की प्रमुख चिंताएँ**

(प्रतिशत में)

व्यापक चिंताएँ	वैकल्पिक ऋण	भुगतान	बैंकिंग टेक
ऋण/ऋण संबंधी	52.02	15.64	4.66
ग्राहक सहायता और सेवा	11.19	20.52	35.90
तकनीकी समस्याएं और एप्प कार्यक्षमता	7.39	23.74	35.27
उच्च ब्याज दरें और प्रच्छन्न शुल्क	6.78	10.93	0.31
भुगतान प्रसंस्करण और निपटान से संबंधित मुद्दे	7.18	7.96	9.93
खाता संबंधित	6.54	6.02	3.99
कैशबैक/पुरस्कार	3.21	7.83	0.99
उत्पीड़न और अनैतिक प्रथाएं	1.38	0.21	0.93
केवाईसी और सत्यापन संबंधी मुद्दे	1.77	6.41	3.96
प्रचार संदेश और भ्रामक विज्ञापन	0.87	0.58	0.52
उपयोगकर्ता डेटा और गोपनीयता	1.68	0.16	3.54

**टिप्पणी:** आंकड़े प्रत्येक श्रेणी में अंतिम समीक्षाओं की कुल संख्या में समीक्षाओं के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

**स्रोत:** लेखकों की गणना।

के लिए दूसरी सबसे बड़ी चिंता है। इस श्रेणी के भीतर, प्रमुख मुद्दों में अनुत्तरदायी ग्राहक सहायता शामिल है जैसे कि ईमेल, कॉल या चैट प्रश्नों पर देरी या कोई प्रतिक्रिया नहीं; प्रभावी वृद्धि तंत्र की कमी और महत्वपूर्ण या तत्काल मुद्दों के लिए अपर्याप्त समाधान या मानव एजेंट तक पहुंचने में कठिनाइयाँ; ग्राहक सहायता कर्मचारियों से असभ्य या गैर-पेशेवर व्यवहार; तकनीकी मुद्दों, ऋण चुकौती समस्याओं, या खाते से संबंधित प्रश्नों से निपटने में कमी; उपयोगकर्ता की शिकायतों के कार्रवाई योग्य समाधान के बिना स्वचालित और सामान्य प्रतिक्रियाएं; सीमित या अनुपलब्ध समर्थन चैनलों जैसे गायब ग्राहक सेवा नंबरों से निराशा; और कई संचार और शिकायत वृद्धि के बावजूद प्रभावी समाधान की कमी।

एक और प्रमुख चिंता तकनीकी मुद्दे और एप्प कार्यक्षमता है, जो भुगतान तकनीकी ऐप्स के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा है, बैंकिंग तकनीक के लिए दूसरा सबसे बड़ा और वैकल्पिक ऋण तकनीक के लिए तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। विशिष्ट समस्याओं में बार-बार ऐप क्रैश, फ्रीजिंग और लॉडिंग विफलता, लॉगिन करने में असमर्थता, और ईमेल, रोजगार की स्थिति और वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सत्यापन समस्याएं शामिल हैं। ग्राहकों को लगातार बग, गड़बड़ियों

और संगतता समस्याओं के साथ-साथ धीमे ऐप प्रदर्शन, सर्वर डाउनटाइम और अपडेट में देरी का भी सामना करना पड़ता है। भुगतान प्रसंस्करण, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और डेटा सिंक्रनाइजेशन जैसी आवश्यक सुविधाओं में त्रुटियां प्रचलित हैं, साथ ही ऐप अपडेट के बाद आने वाली समस्याएं भी प्रचलित हैं, जिनमें कार्यक्षमता में व्यवधान और जबरन पुनर्स्थापना शामिल हैं। अन्य मुद्दों में स्कैन-एंड-पे जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस सेटअप, पासवर्ड रीसेट और बार-बार मैलवेयर चेतावनी जैसी उपलब्ध सुविधाओं के साथ समस्याएं शामिल हैं।

वैकल्पिक ऋण देने वाले तकनीकी ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए, ऋण और ऋण से संबंधित मुद्दों की शिकायतों में 50 प्रतिशत से अधिक शिकायतें होती हैं। इस व्यापक चिंता के तहत विशिष्ट मुद्दों को तीन उप-विषयों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्, ऋण आवेदन और अनुमोदन के मुद्दे, क्रेडिट सीमा से संबंधित मुद्दे और डेटा विसंगति के मुद्दे। ऋण आवेदन से संबंधित मुद्दों में ऋण आवेदनों या आवेदनों की देरी से प्रसंस्करण शामिल है, जो विस्तारित अवधि के लिए समीक्षा के अधीन हैं, अनुमोदित ऋण वितरित नहीं किए जा रहे हैं, और स्पष्ट कारणों या पारदर्शिता के बिना ऋण और प्रस्ताव अस्वीकृति शामिल हैं। क्रेडिट सीमा के मुद्दों में पुनर्भुगतान के बाद ऋण पात्रता के मुद्दे शामिल हैं, जिसमें अच्छे क्रेडिट स्कोर या भुगतान इतिहास के बावजूद बार-बार अस्वीकृति, औचित्य के बिना कम प्रारंभिक क्रेडिट सीमा या क्रेडिट सीमा में कमी (आवेदन के बाद), और समय पर पुनर्भुगतान के बावजूद क्रेडिट सीमा बढ़ाने में असमर्थता शामिल है। ग्राहकों ने डेटा विसंगति के मुद्दों की ओर भी इशारा किया है जैसे कि स्वीकृत बनाम वितरित ऋण राशियों में त्रुटियां, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को गलत या विलंबित अपडेट और रिपोर्टिंग में त्रुटियों या छिपे हुए दंड के कारण क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव। इसके अतिरिक्त, विषय मॉडलिंग विश्लेषण ने पारिस्थितिकी तंत्र में धोखाधड़ी वाले ऐप्स की व्यापकता को सामने नहीं लाया। यह डिजिटल ऋण धोखाधड़ी को कम करने के प्रयास में भारतीय रिज़र्व बैंक और स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) द्वारा प्ले स्टोर से धोखाधड़ी वाले ऋण देने वाले ऐप्स को हटाने के कारण है।



IV.4 फिनटेक ऐप्स के उपयोगकर्ता अनुभव के निर्धारक - एक अर्थमितीय विश्लेषण

ग्राहक पिछले अनुभागों में प्रस्तुत समीक्षाओं में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। इस खंड में, सकारात्मक समीक्षा भावनाओं के निर्धारकों का विश्लेषण एफपीएम का उपयोग करके किया जाता है, क्योंकि आश्रित चर - ऐप्स की सकारात्मक समीक्षाओं का हिस्सा - शून्य और एक के बीच होता है।

एफपीएम के तीन प्रकार, अर्थात, पूर्ण नमूना (मॉडल 1), आउटलेयर (मॉडल 2) को छोड़कर पूर्ण नमूना और आश्रित चर (मॉडल 3)<sup>12</sup> के माध्य से ±1.78 मानक विचलन से परे टिप्पणियों को छोड़कर एक छंटनी किया गया नमूना प्रस्तुत किया गया है (सारणी 4; औसत सीमांत प्रभाव अनुबंध- सारणी 1 में बताए गए हैं। पसंदीदा मॉडल मॉडल 2 है, जो आउटलेयर को छोड़कर पूर्ण नमूने पर अनुमान प्रदान करता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, चूंकि सभी फिनटेक ऐप उपयोगकर्ता समीक्षा नहीं करते हैं और समीक्षा अक्सर ध्रुवीकृत होती है, प्रति संस्थापन (आरपीआई) की समीक्षा और समीक्षा ध्रुवीयता के लिए प्रतिगमन नियंत्रण<sup>13</sup>

मॉडल इंगित करता है कि सकारात्मक समीक्षाओं का हिस्सा एक निश्चित आयु सीमा तक पहुंचने के बाद समतल हो जाता है। इसके अलावा, बड़े बाजार हिस्सेदारी वाले ऐप्स सकारात्मक समीक्षाओं का काफी अधिक अनुपात प्रदर्शित करते हैं। हालाँकि, यह रिश्ता समय के साथ कम होता जाता है। आयु, ऐप्स की उत्तरजीविता गतिशीलता को दर्शाती है, और बाज़ार हिस्सेदारी, ऐप्स की व्यावसायिक विस्तार रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करती है, सामूहिक रूप से फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर व्यक्तिगत ऐप्स के प्रदर्शन के साथ सकारात्मक समीक्षाओं के संरेखण को उजागर करती है।

दो अतिरिक्त ऐप-विशिष्ट विशेषताएं जो सकारात्मक ऐप समीक्षाओं के हिस्से को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, वे हैं डेटा गोपनीयता और प्रमुख ऐप अपडेट। न्यूनतम जानकारी

<sup>12</sup> सकारात्मक समीक्षाओं (आश्रित चर) के हिस्से के अधिकतम मूल्य के अनुरूप ऊपरी सीमा, 0.921049 है। सकारात्मक समीक्षाओं के कम हिस्से वाले ऐप्स की अनुपातिक संख्या को बाहर करने के लिए, माध्य से 1.78 मानक विचलन का चयन किया गया था।

<sup>13</sup> पोलारिटी की गणना कुल समीक्षाओं के हिस्से के रूप में 1 और 5 स्टार रेटेड समीक्षाओं की संख्या के योग के रूप में की जाती है।

सारणी 4: फिनटेक ऐप्स के उपयोगकर्ता अनुभव के वाहकों ने आंशिक प्रोबिट रिग्रेशन आउटपुट को सारांशित किया

आश्रित चर: सकारात्मक समीक्षाओं का हिस्सा	(1)	(2)	(3)
चर	बेसलाइन	आउटलेयर को छोड़कर बेसलाइन	छंटनी का नमूना- 1.78 एसडी
आयु @	0.114* (0.068)	0.103 (0.065)	0.115** (0.058)
आयु <sup>2</sup>	-0.011** (0.006)	-0.011* (0.005)	-0.010** (0.005)
कुल फंडिंग का लॉग	0.020 (0.023)	0.022 (0.025)	0.003 (0.023)
मध्यम डेटा संग्रह #	0.860*** (0.297)	0.597** (0.244)	0.118 (0.073)
उच्च डेटा संग्रह #	0.662** (0.316)	0.360 (0.265)	-0.030 (0.083)
सेगमेंट बाज़ार शेयर \$	0.057*** (0.018)	0.046** (0.021)	0.045** (0.018)
सेगमेंट बाज़ार हिस्सेदारी <sup>2</sup>	-0.0008*** (0.0003)	-0.0006** (0.0003)	-0.0006** (0.0003)
ऐप का प्रमुख अपडेट!	0.292** (0.156)	0.367** (0.163)	0.190 (0.168)
अपडेट * प्रति इंस्टॉल समीक्षा	0.460** (0.207)	0.545** (0.234)	0.451* (0.238)
इंस्टॉल करने के लिए समीक्षा \$	0.265*** (0.078)	0.256* (0.139)	0.277** (0.134)
विपरीतता	-2.425** (1.171)	-3.95*** (0.949)	-2.732*** (0.899)
अपरिवर्तनीय	0.568 (1.128)	2.153** (0.924)	1.881** (0.864)
टिप्पणियां	91	88	84
लॉग छद्म संभावना	-58.80	-56.86	-55.00
प्रोब > cln <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
छद्म R <sup>2</sup>	0.047	0.047	0.027

**टिप्पणियाँ:**

- कोष्ठक मजबूत मानक त्रुटियों का संकेत देते हैं। \*, \*\*, \*\*\* महत्व के 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- कुल वित्त पोषण के लॉग में अनुपलब्ध टिप्पणियों के कारण नमूना आकार 107 से घटकर 91 हो जाता है।
- मॉडल 2 में, प्रति इंस्टॉल समीक्षा (> 2 प्रतिशत) जैसे चर में तीन बाहरी ऐप्स; पोलारिटी (< 0.7) और ऐप के प्रमुख अपडेट (> 8) को बाहर रखा गया है (प्रत्येक में एक ऐप)।
- मॉडल 3 में, नमूना 1.78 मानक विचलन द्वारा आश्रित चर (यानी, कुल समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा का हिस्सा) के चरम सिरों पर झूठ बोलने वाले ऐप्स को हटाकर छंटनी की जाती है।
- @ में ऐप की उम्र शामिल है न कि फिनटेक।
- # कम डेटा संग्रह वाले ऐप्स के सापेक्ष है (जो 0-4 के बीच कम से कम अनुमति मांगते हैं)। डेटा संग्रह चर का निर्माण फिनटेक ऐप्स द्वारा मांगी गई 13 प्रकार की अनुमतियों के एक सरल एकत्रीकरण के रूप में किया गया है। 10 से 13 अनुमतियों के बीच के मान को 1 (उच्च डेटा संग्रह) लेबल किया गया है; 5 से 9 के बीच 2 (मध्यम डेटा संग्रह) लेबल किया गया है; 0 से 4 के बीच को 3 (कम डेटा संग्रह) लेबल किया गया है। उच्च डेटा संग्रह के परिणामस्वरूप गोपनीयता स्तर कम होता है, जबकि कम डेटा संग्रह उच्च गोपनीयता सुनिश्चित करता है।
- \$ ये चर प्रतिशत के संदर्भ में हैं।
- ! पहली समीक्षा के बाद से ऐप में कोई बड़ा अपडेट (1 अप्रैल, 2022 के बाद)। यह एक डमी चर है, यदि कोई बड़ा अपडेट है, तो यह 1 और 0 के बराबर है, अन्यथा।

**स्रोत:** लेखकों की गणना।

(शून्य से चार अनुमतियाँ) एकत्र करने वाले ऐप्स की तुलना में, उपयोगकर्ता डेटा के मध्यम स्तर (पांच से नौ अनुमतियाँ) की आवश्यकता वाले ऐप्स सकारात्मक समीक्षाओं का एक विशेष रूप से उच्च हिस्सा प्रदर्शित करते हैं। हालांकि, मॉडल इंगित करता है कि डेटा संग्रह में और वृद्धि (दस डेटा बिंदुओं से अधिक) बेसलाइन मॉडल 1 को छोड़कर, सकारात्मक समीक्षाओं के हिस्से को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करती है। यह खोज विषय मॉडलिंग विश्लेषण से अंतर्दृष्टि के अनुरूप है, जो सुझाव देती है कि अनुपातहीन सेवा सुधार के बिना अत्यधिक डेटा संग्रह से ग्राहक असंतोष हो सकता है, जो अनुरोधित अनुमतियों और उपयोगकर्ता संतुष्टि के बीच एक व्युत्क्रम यू-आकार के संबंध का सुझाव देता है।

अपडेट ऐप्स की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका उद्देश्य आम तौर पर ऐप की कार्यक्षमता में सुधार करना होता है। इसके अनुरूप, सकारात्मक समीक्षाओं का हिस्सा उन ऐप्स के लिए काफी अधिक है, जिन्हें अध्ययन अवधि के दौरान प्रमुख अपडेट प्राप्त हुए हैं, ऐसे अपडेट के बिना उन ऐप्स की तुलना में जो इस तरह के अपडेट प्राप्त नहीं करते हैं। यह विषय मॉडलिंग अभ्यास के निष्कर्षों के अनुरूप है, जहां कई ग्राहकों ने ऐप कार्यक्षमता के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला। इस प्रकार, प्रमुख अपडेट इन मुद्दों का समाधान करते हैं, ऐप के प्रदर्शन में सुधार करते हैं और ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर बनाते हैं (पेरिया-खलीफी एवं अन्य., 2024)। प्रमुख अपडेट की उपस्थिति में, सकारात्मक समीक्षाओं का हिस्सा बढ़ते आरपीआई के साथ बढ़ता है, यह दर्शाता है कि अपडेट कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं और अधिक उपयोगकर्ताओं को सकारात्मक अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

मुख्य निष्कर्ष पूरे नमूने में एक समान रहते हैं, जिसमें आउटलेयर को बनाए रखा जाता है (मॉडल 1)। अतिरिक्त मजबूती जांच के लिए, एक तीसरे मॉडल का अनुमान एक छंटनी किए गए नमूने का उपयोग करके लगाया जाता है जिसमें आश्रित चर के  $\pm 1.78$  मानक विचलन के भीतर केवल अवलोकन शामिल होते हैं। परिणाम मोटे तौर पर सुसंगत रहते हैं, जो उनकी मजबूती की पुष्टि करते हैं।

## V. नीति निहितार्थ और निष्कर्ष

उपभोक्ता ऑनलाइन समीक्षाएँ उपयोगकर्ता अनुभवों में लगभग वास्तविक समय की अंतर्दृष्टि प्रदान करके प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 5.69 मिलियन उपयोगकर्ता-जनित समीक्षाओं के एक बड़े डेटासेट का उपयोग करते हुए, यह अध्ययन भावनाओं का विश्लेषण करने और प्रमुख उपयोगकर्ता चिंताओं को दूर करने के लिए उन्नत मशीन लर्निंग तकनीकों को लागू करता है, जो नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों के लिए फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में उपयोगकर्ता संतुष्टि बढ़ाने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

भारतीय फिनटेक ऐप्स, कुल मिलाकर, एक सकारात्मक उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करते हैं। अध्ययन के तहत तीन क्षेत्रों में - भुगतान, वैकल्पिक ऋण, और बैंकिंग तकनीक - भुगतान और ऋण देने वाले क्षेत्रों में ऐप इंस्टॉल होने और प्रति इंस्टॉल समीक्षा प्राप्त करने की अधिक संभावना है। क्षेत्रीय विश्लेषण से पता चलता है कि विश्वास, बेहतर परिणाम की प्रत्याशा और खुशी सहित सकारात्मक भावनाएं सभी क्षेत्रों में प्रचलित हैं, जो आम तौर पर अनुकूल भावना का संकेत देती हैं। हालांकि, क्रोध, भय और उदासी जैसी नकारात्मक भावनाओं की व्यापकता लक्षित सुधारों के क्षेत्रों को रेखांकित करती है। टॉपिक मॉडलिंग के परिणाम ग्राहक सहायता और सेवा को सभी क्षेत्रों में एक प्रमुख चिंता के रूप में उजागर करते हैं, जिसमें अनुत्तरदायी समर्थन, अपर्याप्त शिकायत समाधान और सीमित ग्राहक सेवा संपर्क चैनल जैसे मुद्दे शामिल हैं। ऐप क्रैश, लॉगिन विफलताओं और सर्वर डाउनटाइम सहित तकनीकी समस्याएं और ऐप कार्यक्षमता, भुगतान तकनीक और बैंकिंग तकनीकी ऐप्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। वैकल्पिक ऋण देने वाले ऐप्स के लिए, आधे से अधिक शिकायतें ऋण और ऋण मुद्दों से संबंधित हैं, जैसे कि प्रसंस्करण में देरी, क्रेडिट सीमा संबंधी चिंताएं और डेटा विसंगतियां।

अनुभवजन्य विश्लेषण इंगित करता है कि बाजार हिस्सेदारी का उपयोगकर्ता अनुभव पर सकारात्मक, हालांकि घटता हुआ प्रभाव पड़ता है, जो नवाचार को बनाए रखने के लिए एक प्रतिस्पर्धी फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को उजागर करता है। प्रमुख ऐप विशेषताएं, जैसे डेटा गोपनीयता और प्रमुख

अपडेट, भी सकारात्मक समीक्षाओं के महत्वपूर्ण चालक हैं। प्रमुख अपडेट ऐप की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे सकारात्मक समीक्षाएँ बढ़ती हैं और उपयोगकर्ता जुड़ाव बढ़ता है। गोपनीयता, बदले में, उपयोगकर्ता संतुष्टि के साथ एक व्युत्क्रम यू-आकार के जुड़ाव का अनुसरण करती है, जो डेटा संग्रह के अनुपात में सेवा वितरण में सुधार के महत्व को दर्शाती है। ग्राहक-केंद्रित वित्तीय नवाचारों का बढ़ता महत्व मजबूत विनियामक कार्यनीतियों की आवश्यकता पर जोर देता है, जो उन्नत डेटा एनालिटिक्स और एआई-सहायता प्राप्त उपकरणों द्वारा समर्थित हैं, ताकि उभरती उपयोगकर्ता चिंताओं को दूर किया जा सके और भविष्योन्मुखी नीतियों को सूचित किया जा सके।

## संदर्भ

Al Ryan, A., Mahmud, M. S., Mahi, H. H. C., Hossen, M. S., Shimul, N. I., and Noori, S. R. H. (2023, February). FinTech: Deep Learning-Based Sentiment Classification of User Reviews from Various Bangladeshi Mobile Financial Services. In *International Conference on Computational Intelligence in Data Science* (pp. 126-140). Cham: Springer Nature Switzerland.

Bacıoğlu, Y. S. (2024). Analyzing Customer Sentiments and Trends in Turkish Mobile Banking Apps: A Text Mining Study. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (80), 49-69.

Burgers, C., Eden, A., de Jong, R., and Buningh, S. (2016). Rousing Reviews And Instigative Images: The Impact Of Online Reviews And Visual Design Characteristics On App Downloads. *Mobile Media and Communication*, 4(3), 327-346.

Chaudhary, A. (2024). FinTech, AI and Digital Payments: Shaping the Future of Finance. *NPCI Speeches*.

Das, S. (2023). FinTech and the changing financial landscape [Keynote address]. Global Fintech Festival, Mumbai. Reserve Bank of India. <https://www.rbi.org.in>

Devlin, J., Chang, M., Lee, K., and Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*.

Driss, O. B., Mellouli, S., and Trabelsi, Z. (2019). From Citizens To Government Policy-Makers: Social Media Data Analysis. *Government Information Quarterly*, 36(3), 560-570.

Egger, R., and Yu, J. (2022a). Identifying Hidden Semantic Structures in Instagram Data: a Topic Modelling Comparison. *Tourism Review*.

Egger, R., and Yu, J. (2022b). A Topic Modelling Comparison Between LDA, NMF, Top2Vec, and BERTopic to Demystify Twitter Posts. *Frontiers in Sociology*.

Feyen, E., Frost, J., Gambacorta, L., Natarajan, H., and Saal, M. (2021). Fintech And The Digital Transformation Of Financial Services: Implications For Market Structure And Public Policy. *BIS papers*.

Feyen, E., Natarajan, H., and Saal, M. (2023). Fintech and the Future of Finance: Market and Policy Implications. World Bank Publications.

Fu, B., Lin, J., Li, L., Faloutsos, C., Hong, J., and Sadeh, N. (2013, August). Why People Hate Your App: Making Sense Of User Feedback In A Mobile App Store. In *Proceedings Of The 19th ACM SIGKDD International Conference On Knowledge Discovery And Data Mining* (pp. 1276-1284).

Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural Topic Modelling with a class-based TF-IDF Procedure. *arXiv*. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2203.05794>

Gupta, S. S., and Mahajan, J. (2023). User Sentiment Analysis of Cashkumar Peer-to-Peer (P2P) Lending Platform: Based on Google Reviews. In *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy* (pp. 97-122). Emerald Publishing Limited.

- Hu, N., Pavlou, P. A., & Zhang, J. (2017). On self-selection biases in online product reviews. *MIS quarterly*, 41(2), 449-475.
- Huebner, J., Frey, R. M., Ammendola, C., Fleisch, E., and Ilic, A. (2018, November). What People Like In Mobile Finance Apps: An Analysis Of User Reviews. In *Proceedings of the 17th international conference on mobile and ubiquitous multimedia* (pp. 293-304).
- Hutto, C., and Gilbert, E. (2014). Vader: A Parsimonious Rule-Based Model For Sentiment Analysis Of Social Media Text. In *Proceedings Of The International AAAI Conference On Web And Social Media* (Vol. 8, No. 1, pp. 216-225).
- Khalid, H., Shihab, E., Nagappan, M., and Hassan, A. E. (2014). What Do Mobile App Users Complain About?. *IEEE software*, 32(3), 70-77.
- Krishnan, A. (2023). Exploring The Power Of Topic Modeling Techniques In Analyzing Customer Reviews: A Comparative Analysis. *arXiv preprint arXiv:2308.11520*.
- Kumar, A., Chakraborty, S., and Bala, P. K. (2023). Text Mining Approach To Explore Determinants Of Grocery Mobile App Satisfaction Using Online Customer Reviews. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 73, 103363.
- Liang, T. P., Li, X., Yang, C. T., and Wang, M. (2015). What In Consumer Reviews Affects The Sales Of Mobile Apps: A Multifacet Sentiment Analysis Approach. *International Journal of Electronic Commerce*, 20(2), 236-260.
- Luiz, W., Viegas, F., Alencar, R., Mourão, F., Salles, T., Carvalho, D., ... and Rocha, L. (2018, April). A Feature-Oriented Sentiment Rating For Mobile App Reviews. In *Proceedings of the 2018 world wide web conference* (pp. 1909-1918).
- Masturoh, S., and Pohan, A. B. (2021). Sentiment Analysis Against the Dana E-Wallet on Google Play Reviews Using the K-Nearest Neighbor Algorithm. *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, 17(1), 53-58.
- Mingyu, J. (2019). Google-Play-Scraper. MIT.
- Mishev, K., Gjorgjevikj, A., Vodenska, I., Chitkushev, L., Trajanov, D. (2020). Evaluation of Sentiment Analysis in Finance: From Lexicons to Transformers. *IEEE Access*.
- Mohammad, S. M., and Turney, P. D. (2013). NRC Emotion Lexicon. *National Research Council, Canada*, 2, 234.
- Morgan, D. L. (1996). Focus groups. *Annual review of sociology*, 22(1), 129-152.
- Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.
- Omotosho, B. S. (2021). Analysing User Experience Of Mobile Banking Applications In Nigeria: A Text Mining Approach. *CBN Journal of Applied Statistics*, 12(1), 77-108.
- Pagano, D., and Maalej, W. (2013, July). User Feedback In The Appstore: An Empirical Study. In *2013 21st IEEE International Requirements Engineering Conference (RE)* (pp. 125-134). IEEE.
- Pang, B., and Lee, L. (2008). Opinion Mining And Sentiment Analysis. *Foundations And Trends In Information Retrieval*, 2(1-2), 1-135.
- Perea-Khalifi, D., Irimia-Diéguez, A. I., and Palos-Sánchez, P. (2024). Exploring The Determinants Of The User Experience In P2P Payment Systems In Spain: A Text Mining Approach. *Financial Innovation*, 10(1), 2.
- Pranata, N., and Farandy, A. R. (2019). Big Data-Based Peer-to-Peer Lending Fintech: Surveillance System through Utilization of Google Play Review.
- Reserve Bank of India. (RBI). (2024). Report on Currency and Finance 2023-24. *India's Digital Revolution*.

- Sanh, V. (2019). DistilBERT, A Distilled Version of BERT: Smaller, Faster, Cheaper and Lighter. *arXiv preprint arXiv:1910.01108*.
- Saroy, R., Khobragade, A., Misra, R., Awasthy, S., and Dhal, S. (2023). What Drives Startup Fundraising in India?. *RBI Bulletin*.
- Schoenmueller, V., Netzer, O., and Stahl, F. (2020). The Polarity of Online Reviews: Prevalence, Drivers and Implications. *Journal of Marketing Research*, 57(5), 853-877.
- Statista. (2024). Mobile App Downloads Database.
- Tracxn. (2024). FinTech Trends.
- Trivedi, S. K., and Singh, A. (2021). Twitter Sentiment Analysis Of App Based Online Food Delivery Companies. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 70(8/9), 891-910.
- Vasa, R., Hoon, L., Mouzakis, K., and Noguchi, A. (2012, November). A Preliminary Analysis Of Mobile App User Reviews. In *Proceedings of the 24th Australian computer-human interaction conference* (pp. 241-244).
- Wadhawan, A., and Aggarwal, A. (2021). Towards Emotion Recognition In Hindi-English Code-Mixed Data: A Transformer Based Approach. *arXiv preprint arXiv:2102.09943*.
- Zhao, J., Zeng, D., Xiao, Y., Che, L., and Wang, M. (2020). User Personality Prediction Based On Topic Preference And Sentiment Analysis Using LSTM Model. *Pattern Recognition Letters*, 138, 397-402.



सारणी 1: फिनटेक ऐप्स के वाहक' उपयोगकर्ता अनुभव - सारांशित भिन्नात्मक प्रोबिट औसत सीमांत प्रभाव (एएमई)			
आश्रित चर: सकारात्मक समीक्षाओं का हिस्सा	(1)	(2)	(3)
चर	बेसलाइन	आउटलेयर को छोड़कर बेसलाइन	छंटनी का नमूना-1.78 एसडी
आयु @	0.002 (0.006)	-0.003 (0.006)	0.004 (0.006)
कुल फंडिंग का लॉग	0.007 (0.008)	0.008 (0.010)	0.014 (0.009)
मध्यम डेटा संग्रह #	0.322*** (0.102)	0.225** (0.091)	0.043 (0.028)
उच्च डेटा संग्रह #	0.247*** (0.109)	0.137 (0.096)	-0.011 (0.031)
सेगमेंट मार्केट शेयर \$	0.02*** (0.007)	0.016** (0.007)	0.016*** (0.006)
ऐप का प्रमुख अपडेट !	0.110* (0.057)	0.136** (0.060)	0.071 (0.006)
अपडेट * प्रति इंस्टॉल समीक्षा	0.170*** (0.076)	0.202** (0.086)	0.177** (0.088)
प्रति संस्थापन समीक्षा \$	0.098*** (0.028)	0.095** (0.051)	0.103** (0.050)
विपरीतता	-0.897** (0.431)	-1.463*** (0.345)	-1.018** (0.333)
अवलोकन	91	87	83

टिप्पणियाँ:

- कोष्ठक मजबूत मानक त्रुटियों का संकेत देते हैं। \*, \*\*, \*\*\* महत्व के 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- एएमई एक स्वतंत्र चर में एक-इकाई परिवर्तन के परिणामस्वरूप आश्रित चर में औसत परिवर्तन को मापते हैं, जो अन्य सभी चर को स्थिर रखते हैं।
- कुल वित्त पोषण के लॉग में अनुपलब्ध टिप्पणियों के कारण नमूना आकार 107 से घटकर 91 हो गया है।
- मॉडल 2 में, ग्राहक सहायता चिंताओं जैसे चर में चार बाहरी ऐप (कुल नकारात्मक चिंताओं का >15 प्रतिशत); प्रति इंस्टॉल समीक्षा (> 2 प्रतिशत); पोलरिटी (< 0.7) और ऐप के प्रमुख अपडेट (> 8) को बाहर रखा गया है (प्रत्येक में एक ऐप)।
- मॉडल 3 में, नमूना 1.78 मानक विचलन द्वारा आश्रित चर (यानी, कुल समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा का हिस्सा) के चरम सिरों पर गलत जानकारी देने वाले ऐप्स को हटाकर छंटनी की जाती है।
- @ में ऐप की उम्र शामिल है न कि फिनटेक.7 की।
- # कम डेटा संग्रह वाले ऐप्स के सापेक्ष (जो 0-4 के बीच कम से कम अनुमतियों की तलाश करते हैं)। डेटा संग्रह चर का निर्माण फिनटेक ऐप्स द्वारा मांगी गई 13 प्रकार की अनुमतियों के एक सरल एकत्रीकरण के रूप में किया गया है। 10 से 13 अनुमतियों के बीच के मान को 1 (उच्च डेटा संग्रह) लेबल किया गया है; 5 से 9 के बीच 2 (मध्यम डेटा संग्रह) लेबल किया गया है; 0 से 4 के बीच को 3 (कम डेटा संग्रह) लेबल किया गया है। उच्च डेटा संग्रह के परिणामस्वरूप गोपनीयता स्तर कम होता है, जबकि कम डेटा संग्रह उच्च गोपनीयता सुनिश्चित करता है।
- \$ ये चर प्रतिशत के संदर्भ में हैं।
- ! पहली समीक्षा के बाद से ऐप में कोई बड़ा अपडेट (1 अप्रैल, 2022 के बाद)। यह एक डमी चर है, यदि कोई बड़ा अपडेट है, तो यह 1 और 0 के बराबर है, अन्यथा।

स्रोत: लेखकों की गणना।

## एनबीएफसी क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा

अभ्युदय हर्ष, पल्लवी पंत,  
नंदिनी जयकुमार<sup>#</sup>, रजनीश कुमार चंद्रा और  
बृजेश पी<sup>^</sup> द्वारा<sup>^</sup>

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संस्थान अवसंरचना, वाहनों, आवास और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए वित्त प्रदान करके, कुल मांग में सुधार करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और आर्थिक विस्तार में योगदान करते हैं। ऋण में एनबीएफसी का बढ़ता योगदान, विशेष रूप से औद्योगिक और खुदरा क्षेत्रों में, उनके बढ़ते ऋण-और-जीडीपी अनुपात में स्पष्ट है। इसके अलावा, प्रमुख संकेतकों के संदर्भ में इस क्षेत्र की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है, जैसे आस्तियों पर प्रतिलाभ, इक्विटी पर प्रतिलाभ, निवल ब्याज मार्जिन, जोखिम-भारित आस्ति अनुपात और अनर्जक आस्ति अनुपात के संदर्भ में। बैंकों और वित्तीय बाजारों के साथ अंतर-संबद्धता के साथ-साथ समग्र ऋण में उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि का मौद्रिक नीति संचरण पर प्रभाव पड़ता है।

### भूमिका

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) भारत की वित्तीय प्रणाली के एक महत्वपूर्ण और गतिशील खंड का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत, एनबीएफसी विभिन्न प्रकार की वित्तीय गतिविधियों में लगी हुई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण

और अग्रिमों का प्रावधान, शेयरों और बॉण्ड का अधिग्रहण, किराया-खरीद वित्त और फैक्ट्रिंग शामिल हैं। वे अवसंरचना के विकास, वाहन खरीद (वाणिज्यिक और व्यक्तिगत दोनों), आवास और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कुल मांग को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलता है और समग्र आर्थिक विकास में योगदान होता है। भारत में एनबीएफसी का प्रसार अनुकूलित उत्पाद की पेशकश और विविध और विशिष्ट क्षेत्रों में त्वरित सेवा वितरण के माध्यम से बाजार की स्थितियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता की ओर भी इशारा करता है।

समय के साथ एनबीएफसी का आकार और महत्व बढ़ गया है, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में किसी भी महत्वपूर्ण व्यवधान का वित्तीय प्रणाली और वास्तविक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। एनबीएफसी के बढ़ते प्रणालीगत महत्व को रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए सतर्क और सूक्ष्म विनियामक निरीक्षण द्वारा रेखांकित किया गया है। इस संबंध में एक ऐतिहासिक विकास अक्टूबर वर्ष 2022 से स्केल-आधारित विनियमन (एसबीआर) ढांचे का कार्यान्वयन था, जो एक अधिक सूक्ष्म, जोखिम-आधारित प्रणाली में बदलाव का संकेत देता है जो एनबीएफसी क्षेत्र के भीतर विविधता को स्वीकार करता है। यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और क्षेत्र में नवाचार को सुविधाजनक बनाने के बीच रिज़र्व बैंक द्वारा एक नाजुक संतुलन कार्य को दर्शाता है।

ऋण मध्यस्थता में एनबीएफसी की बढ़ती भूमिका के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय बाजारों के साथ उनके अंतर्संबंध ने वास्तविक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के आवेगों के संचरण में उनके बढ़ते महत्व को उजागर किया है, यहां तक कि बैंक प्राथमिक माध्यम के रूप में भी काम कर रहे हैं।

इसके आलोक में, यह आलेख भारत के एनबीएफसी क्षेत्र के हालिया प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है। आलेख को निम्नलिखित खंडों में व्यवस्थित किया गया है। खंड II वैश्विक संदर्भ में भारत

<sup>#</sup> लेखक मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) में प्रबंधक हैं।

<sup>^</sup> अन्य लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। लेखक परामर्शदाता श्री एम रामय्या से प्राप्त सुझावों और प्रोत्साहन के लिए आभारी हैं। अनाम रेफरी से प्राप्त सुझावों के लिए भी लेखक आभारी हैं। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

<sup>1</sup> यद्यपि मर्चेन्ट बैंकिंग कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकिंग/सब-ब्रोकिंग, निधि कंपनियां, वैकल्पिक निवेश निधि कंपनियां, बीमा कंपनियां और चिट फंड कंपनियां एनबीएफसी हैं, फिर भी उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकरण की आवश्यकता से छूट दी गई है।



के गैर-बैंकिंग क्षेत्र को स्थापित करता है। खंड III एनबीएफसी के तुलन पत्र की जांच करता है, जो भारत की वित्तीय प्रणाली के भीतर उनके बढ़ते महत्व को उजागर करता है। इस पर आधारित, खंड IV इस तेजी से महत्वपूर्ण खंड में मौद्रिक नीति संचरण की प्रभावशीलता के मुद्दे की पड़ताल करता है। खंड V में एनबीएफसी क्षेत्र के वित्तीय और विवेकपूर्ण संकेतकों का विवरण दिया गया है, जिसके बाद अंतिम खंड है जो प्रमुख उभरती चुनौतियों का निष्कर्ष और चर्चा करता है।

## II. एनबीएफआई: एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य

वैश्विक स्तर पर, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान<sup>2</sup> (एनबीएफआई) क्षेत्र की कुल वित्तीय आस्तियों ने दिसंबर 2023 के अंत में बैंकिंग क्षेत्र की 3.3 प्रतिशत की वृद्धि से 8.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मजबूत विस्तार का प्रदर्शन किया। दिसंबर 2023 के अंत में वैश्विक वित्तीय आस्तियों में एनबीएफआई की हिस्सेदारी 49.1 प्रतिशत थी। दुनिया भर में एनबीएफआई द्वारा ऋण देने में भी 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि बैंक ऋण में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मौजूदा उच्च ब्याज दर के माहौल के बावजूद, एनबीएफआई द्वारा उधार भी मजबूत रहा।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के संकीर्ण उपाय में ऋण मध्यस्थता गतिविधियों में शामिल एनबीएफआई संस्थाएं शामिल हैं जो बैंक जैसी कमजोरियों को जन्म दे सकती हैं। इस संकीर्ण उपाय के तहत एनबीएफआई की कुल आस्तियों में एनबीएफआई की हिस्सेदारी करीब 30 प्रतिशत है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए संकीर्ण माप 10.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए, यह 5.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा। भारत और सऊदी अरब को छोड़कर सभी अर्थव्यवस्थाओं में संकीर्ण माप<sup>3</sup> में वृद्धि देखी गई। भारत के लिए, इसका श्रेय आर्थिक कार्य (ईएफ2) को दिया जा सकता है, जो भारत में सबसे बड़ा हिस्सा है और एक बैंक के साथ एक बड़े एनबीएफआई के विलय के कारण संकुचन की सूचना दी गई है (सारणी 1)। ईएफ2 में अल्पकालिक वित्त पोषण पर निर्भर ऋण देने वाले संस्थान शामिल हैं और इसमें वित्त कंपनियों का प्रभुत्व है जो उपभोक्ता वित्त, ऑटो वित्त, खुदरा बंधक प्रावधान, वाणिज्यिक संपत्ति वित्त और साधन वित्त जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं।

एफएसबी ने उन क्षेत्राधिकारों में उपयोग किए जा रहे

### सारणी 1: संकीर्ण माप की संरचना

(दिसंबर 2023 के अंत में)

आर्थिक कार्य (ईएफ)	इकाई प्रकार	शेयर		वृद्धि	
		(प्रतिशत)			
		वैश्विक	भारत	वैश्विक	भारत
ईएफ1	उन विशेषताओं के साथ सामूहिक निवेश साधन जो उन्हें चलने के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं (उदाहरण के लिए, मुद्रा बाज़ार फंड, रियल एस्टेट फंड)	74.1	19.1	10.1	-10.5
ईएफ2	अल्पकालिक वित्त पोषण पर निर्भर ऋण (जैसे, उपभोक्ता ऋण कंपनियां, पट्टे पर देने वाली कंपनियां)	8.5	79.7	7.6	-2.3
ईएफ3	अल्पकालिक वित्त पोषण पर निर्भर बाजार मध्यस्थता (जैसे, ब्रोकर-डीलर, कस्टोडियल खाते)	7.0	0.7	16.2	49.8
ईएफ4	ऋण मध्यस्थता की सुविधा (जैसे, क्रेडिट बीमाकर्ता, मोनोलाइन बीमाकर्ता)	0.2	0.0	0.2	96.1
ईएफ5	प्रतिभूतिकरण आधारित ऋण मध्यस्थता (उदाहरण के लिए, प्रतिभूतिकरण वाहन, संरचित वित्त वाहन)	7.5	0.4	3.8	7.4

**टिप्पणी:** "शेयर" कुल के सापेक्ष एक विशिष्ट ईएफ के अनुपात को दर्शाता है, अर्थात्, ईएफ1, ईएफ2, ईएफ3, ईएफ4, और ईएफ5 का योग, या तो विश्व या भारत के लिए, जैसा लागू हो। इसी तरह, एक विशिष्ट ईएफ की वृद्धि दिसंबर से दिसंबर की तुलना में इसकी व-द-व वृद्धि को संदर्भित करती है।

**स्रोत:** गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता पर वैश्विक निगरानी रिपोर्ट, 2024।

<sup>2</sup> वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) एनबीएफआई क्षेत्र को सभी गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं के व्यापक उपाय के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें सभी वित्तीय संस्थान शामिल हैं जो केंद्रीय बैंक, बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान नहीं हैं।

<sup>3</sup> संकीर्ण माप में पांच आर्थिक कार्य (ईएफ) शामिल हैं, अर्थात् ईएफ1 से ईएफ5।

नीतिगत साधनों पर एक सर्वेक्षण किया जहां ईएफ 2 मौजूद है, जैसे कि भारत। सर्वेक्षण के जवाबों से संकेत मिलता है कि अपनाई गई प्राथमिक नीतियों में बैंकों के लिए विवेकपूर्ण आवश्यकताएं, पूंजी आवश्यकताएं, लीवरेज सीमाएं, महत्वपूर्ण जोखिम पर प्रतिबंध शामिल हैं। इसके अलावा, अधिकांश प्रतिक्रिया देने वाले क्षेत्राधिकारों ने देयताओं पर सीमाओं को लागू करने की सूचना दी है जो एनबीएफआई संस्थाएं बैंकों और जोखिम भरे ग्राहकों से ले सकती हैं (चार्ट 1)। अतिरिक्त उपायों में प्रकटीकरण जनादेश, पंजीकरण और प्राधिकरण प्रक्रियाएं, साथ ही क्रेडिट कार्ड जारी करने सहित गतिविधियों की शृंखला में बाधाएं शामिल थीं।

भारत में, एनबीएफसी ईएफ2 का सबसे बड़ा घटक है। उनके प्रणालीगत महत्व और विविध व्यापार मॉडल को देखते हुए, एनबीएफसी को एसबीआर के माध्यम से विनियमित किया जाता है, जिसमें विनियामक तीव्रता में लेयर-वार प्रगतिशील वृद्धि की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार, बेस लेयर में एनबीएफसी अपने छोटे आकार और सीमित अंतर्संबंध को देखते हुए मध्य और ऊपरी परतों की तुलना में कम कड़े विनियमन के अधीन हैं। पूंजी, विवेकपूर्ण, शासन और प्रकटीकरण दिशानिर्देशों के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणों के लिए मुख्य तथ्य विवरणों को अनिवार्य करने, दंडात्मक प्रभारों पर दिशानिर्देश जारी करने,

ब्याज लेने में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने और जिम्मेदार ऋण आचरण को बढ़ावा देने के लिए हाल के उपायों के साथ ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाने पर समवर्ती रूप से जोर दिया है।

### III. एनबीएफसी सेक्टर 4 का प्रदर्शन

#### III.1. तुलन पत्र

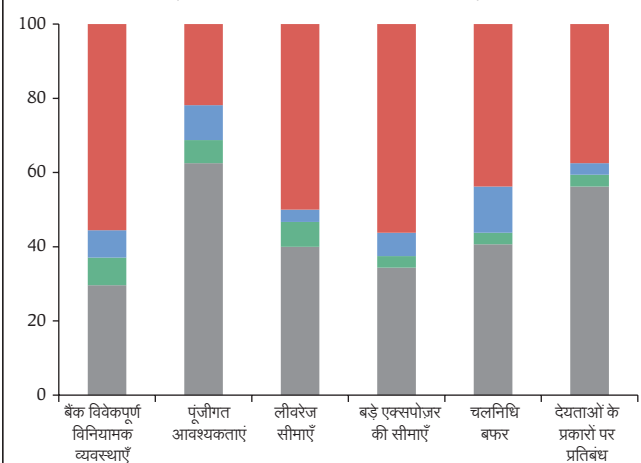
कुल आस्ति/देयताओं के संदर्भ में एनबीएफसी क्षेत्र ने दिसंबर 2024 के अंत तक दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज करना जारी रखा। नवंबर 2023 में एनबीएफसी द्वारा खुदरा ऋणों की चुनिंदा श्रेणियों 5 पर जोखिम-भार में वृद्धि ने असुरक्षित ऋणों और लेयरों में अग्रिमों की वृद्धि में कमी में योगदान दिया। उधार, जो धन का मुख्य स्रोत हैं और एनबीएफसी की कुल देयताओं का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं, एक वर्ष पहले की तुलना में दिसंबर 2024 के अंत में उच्च दर से बढ़ा (सारणी 2)।

#### आस्ति

दिसंबर 2024 के अंत में ऋण और अग्रिम में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में धीमी दर से बढ़ी (चार्ट 2)। दिसंबर 2024 के अंत तक, अप्रतिभूतित ऋण सकल ऋण और अग्रिमों का 24.0 प्रतिशत था, जबकि एक वर्ष पहले यह 26.8 प्रतिशत था। अपर लेयर की एनबीएफसी के अप्रतिभूतित ऋणों में गिरावट दर्ज की गई, जो मोटे तौर पर बढ़े हुए जोखिम-भार के प्रभाव को दर्शाती है।

मध्यम स्तर के एनबीएफसी के क्रेडिट पोर्टफोलियो में अप्रतिभूतित ऋणों की हिस्सेदारी दिसंबर 2022 के अंत में लगभग 32 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2024 के अंत में 25 प्रतिशत हो गई (चार्ट 3ए)। विकास के संदर्भ में, एनबीएफसीयूएल ने मिडिल लेयर के संबंध में अप्रतिभूतित ऋण की वृद्धि में तेज गिरावट देखी, जिसने मामूली वृद्धि दर्ज की (चार्ट 3बी)।

**चार्ट 1: ईएफ2 के अंतर्गत उपयोग किए गए नीतिगत साधन**  
(सर्वेक्षण का उत्तर देने वाले क्षेत्रों का प्रतिशत)



स्रोत: गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता पर ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, 2024।

<sup>4</sup> इस आलेख में विश्लेषण केवल एनबीएफसी-यूएल और एमएल तक ही सीमित है, जिसमें सीआईसी, पीडी और एचएफसी शामिल नहीं हैं।

<sup>5</sup> 16 नवंबर, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से, आरबीआई ने एनबीएफसी को उपभोक्ता ऋण और बैंक ऋण के लिए विनियामक उपायों की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण, स्वर्ण के आभूषणों के लिए ऋण और सूक्ष्म वित्त/एसएचजी ऋणों को छोड़कर, खुदरा ऋण के रूप में वर्गीकृत एनबीएफसी (बकाया और नए) के उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार में वृद्धि शामिल थी।

सारणी 2: एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र  
(दिसंबर के अंत में)

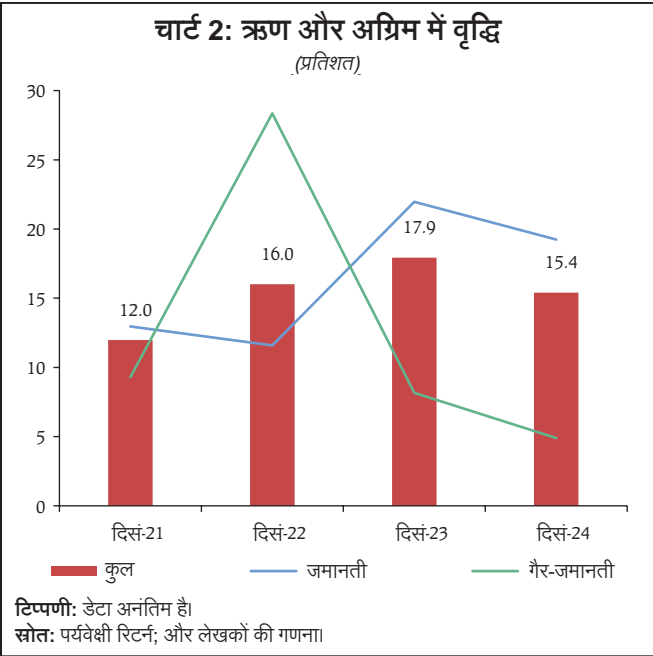
(₹ करोड़)

	2023			2024		
मद	एनबीएफसी	एनबीएफसी-यूएल	एनबीएफसी-एमएल	एनबीएफसी	एनबीएफसी-यूएल	एनबीएफसी-एमएल
शेयर पूंजी	1,37,265 (18.2)	4,552 (-36.3)	1,32,714 (21.8)	1,38,288 (0.7)	2,807 (-38.3)	1,35,481 (2.1)
भंडार और अधिशेष	9,08,398 (15.6)	2,10,254 (15.4)	6,98,144 (15.6)	11,30,508 (24.5)	2,37,014 (12.7)	8,93,494 (28.0)
सार्वजनिक जमा	1,06,435 (-8.1)	85,779 (28.4)	20,656 (-57.9)	1,23,348 (15.9)	1,02,439 (19.4)	20,909 (1.2)
उधार	31,78,623 (14.6)	7,97,075 (13.9)	23,81,549 (14.9)	36,96,651 (16.3)	9,20,520 (15.5)	27,76,131 (16.6)
अन्य देयताएँ	3,37,404 (15.3)	54,013 (1.8)	2,83,391 (18.3)	3,77,917 (12.0)	54,930 (1.7)	3,22,987 (14.0)
कुल देयताएँ/आस्तियां	46,68,126 (14.3)	11,51,673 (14.2)	35,16,453 (14.4)	54,66,712 (17.1)	13,17,710 (14.4)	41,49,002 (18.0)
ऋण और अग्रिम	37,15,229 (17.9)	10,21,556 (18.4)	26,93,673 (17.8)	42,87,573 (15.4)	11,55,044 (13.1)	31,32,529 (16.3)
निवेश	5,15,402 (0.3)	61,122 (-10.7)	4,54,280 (2.0)	7,27,957 (41.2)	75,128 (22.9)	6,52,830 (43.7)
नकद और बैंक बैलेंस	1,62,586 (0.8)	38,836 (-13.4)	1,23,749 (6.2)	1,80,396 (11.0)	54,982 (41.6)	1,25,413 (1.3)
अन्य आस्तित	2,74,909 (6.6)	30,158 (-7.5)	2,44,751 (8.7)	2,70,786 (-1.5)	32,556 (8.0)	2,38,230 (-2.7)

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम हैं।  
2. कोष्ठक में आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्रतिशत में हैं।  
स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न; और लेखकों की गणना।

देयताएँ

एनबीएफसी मुख्य रूप से बाज़ार और बैंकों से धन जुटाती हैं, जो दिसंबर 2024 के अंत में उनके कुल उधार का क्रमशः

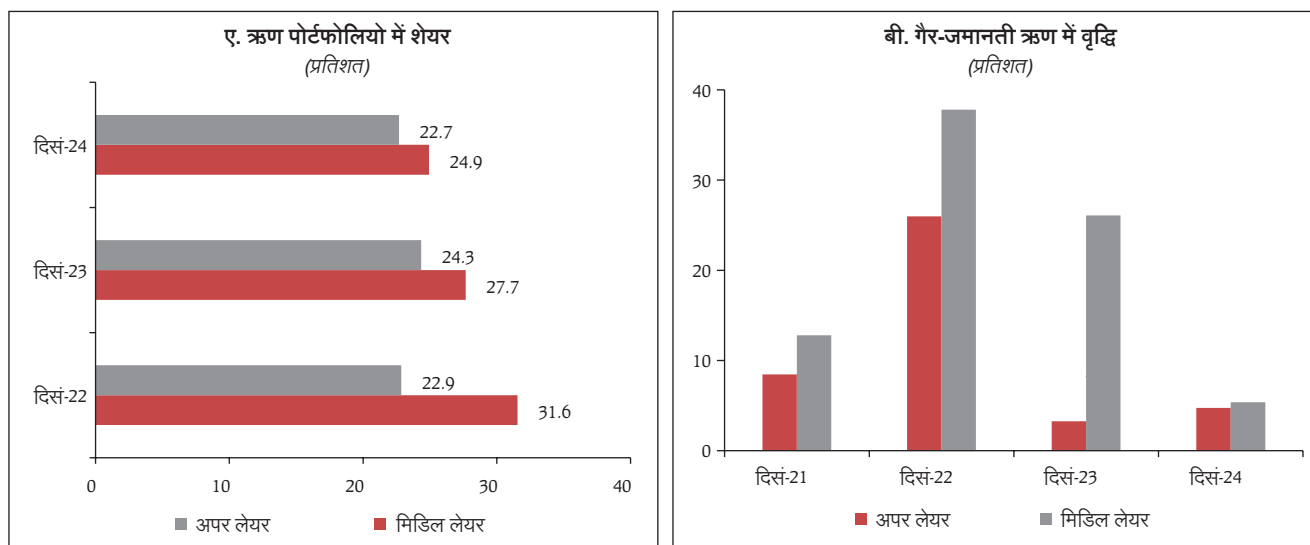


38.7 प्रतिशत और 37.4 प्रतिशत था (चार्ट 4)। इस क्षेत्र में शेयर पूंजी की वृद्धि में काफी गिरावट देखी गई, आंशिक रूप से बाजार की स्थितियों में अनिश्चितता के कारण। अपर लेयर में एनबीएफसी ने दिसंबर 2024 के अंत में शेयर पूंजी में गिरावट का अनुभव जारी रखा।

डिबेंचर जारी करने और अंतर-कॉरपोरेट उधार के माध्यम से जुटाई गई धनराशि उच्च दर से बढ़ी, जबकि दिसंबर 2024 के अंत में बैंक उधार में वृद्धि में कमी दर्ज की गई (सारणी 3)।

घरेलू बाजार के अलावा, एनबीएफसी बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का सहारा ले रही हैं। ईसीबी वित्त पोषण के स्रोतों के विविधीकरण में भी योगदान देता है। कुल ईसीबी (पंजीकरण) में एनबीएफसी की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है (चार्ट 5)।

चार्ट 3 : लेयरों के आधार पर गैर-जमानती ऋण में रुझान



टिप्पणी: डेटा अनंतिम है।

स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न; और लेखकों की गणना।

### III.2. क्षेत्रीय ऋण

एनबीएफसी के ऋण पोर्टफोलियो में उद्योग और खुदरा क्षेत्र को ऋण दिया जाता है, जो इस क्षेत्र के कुल बकाया का लगभग 72 प्रतिशत है (चार्ट 6ए)। दिसंबर 2024 के अंत में, मजबूत खरीफ खाद्यान्न उत्पादन और अच्छी रबी संभावनाओं के कारण कृषि क्षेत्र को ऋण तेज गति से बढ़ा

(आरबीआईए, 2024)। खुदरा ऋण दोहरे अंकों में बढ़ रहे हैं, लेकिन उद्योग और सेवाओं के परिदृश्य में कमी ने उनकी ऋण वृद्धि को कम करने में योगदान दिया है (आरबीआईबी, 2024)। हालांकि, दोनों खंडों में ऋण वृद्धि दोहरे अंकों में बनी रही (चार्ट 6 बी)।

सारणी 3: एनबीएफसी के उधार के स्रोत

(₹ करोड़)

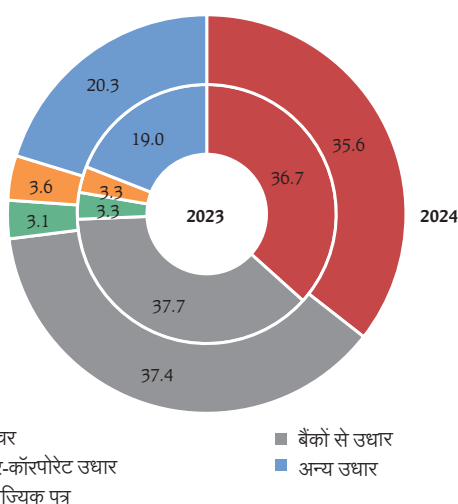
मद	दिसंबर-अंत 2023	दिसंबर-अंत 2024	प्रतिशत भिन्नता	
			दिसंबर- 22 की तुलना में दिसंबर- 23	दिसंबर- 23 की तुलना में दिसंबर- 24
1. डिबेंचर	11,65,408	13,14,517	9.6	12.8
2. बैंकों से उधार	11,98,257	13,84,385	16.8	15.5
3. एफआई से उधार	96,193	93,943	31.4	-2.3
4. अंतर-कॉरपोरेट उधार	1,03,699	1,33,754	2.0	29.0
5. वाणिज्यिक पत्र	1,05,903	1,14,820	37.1	8.4
6. सरकार से उधार	20,206	22,620	-6.0	11.9
7. अधीनस्थ ऋण	65,468	74,374	-7.2	13.6
8. अन्य उधार	4,23,489	5,58,237	24.6	31.8
<b>कुल उधार</b>	<b>31,78,623</b>	<b>36,96,651</b>	<b>14.6</b>	<b>16.3</b>

टिप्पणी: डेटा अनंतिम है।

स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न; और लेखकों की गणना।

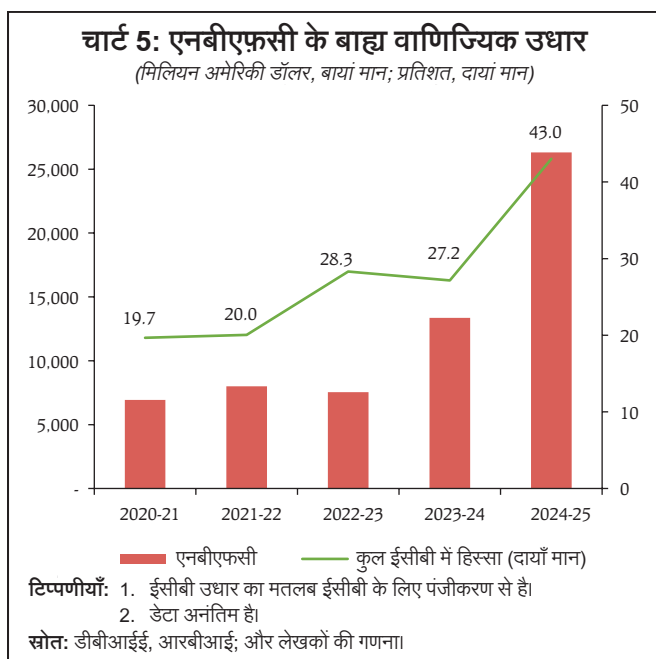
चार्ट 4: उधार के स्रोत

(दिसंबर के अंत में, प्रतिशत)



टिप्पणी: डेटा अनंतिम है।

स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न; और लेखकों की गणना।



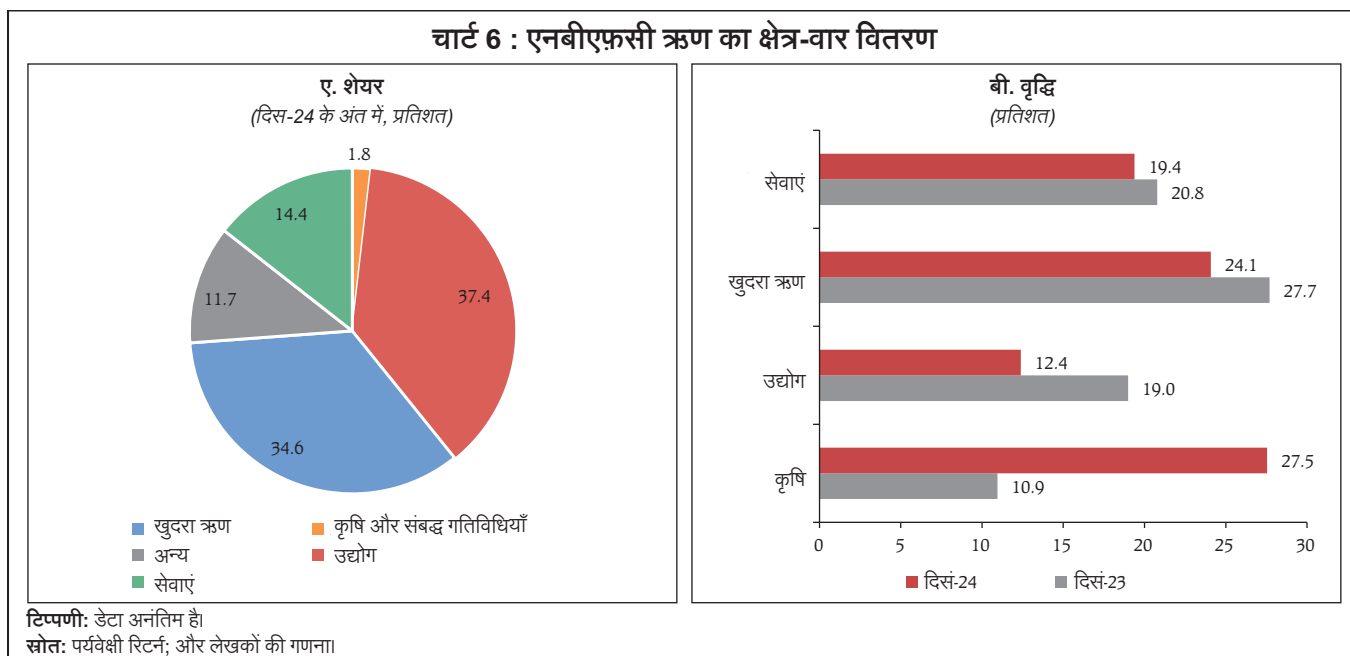
इस क्षेत्र के एक लेयर-वार विश्लेषण से पता चलता है कि सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी की उपस्थिति के कारण मिडिल लेयर में एनबीएफसी द्वारा उद्योग को दिए जाने वाले ऋण के प्रभुत्व को दर्शाता है, इसके बाद खुदरा और सेवा ऋण का स्थान आता है। जबकि अपर लेयर मुख्य रूप से 60 प्रतिशत

से अधिक की हिस्सेदारी के साथ खुदरा ऋण खंड में केंद्रित है, इसके बाद सेवाओं का स्थान है (चार्ट 7)।

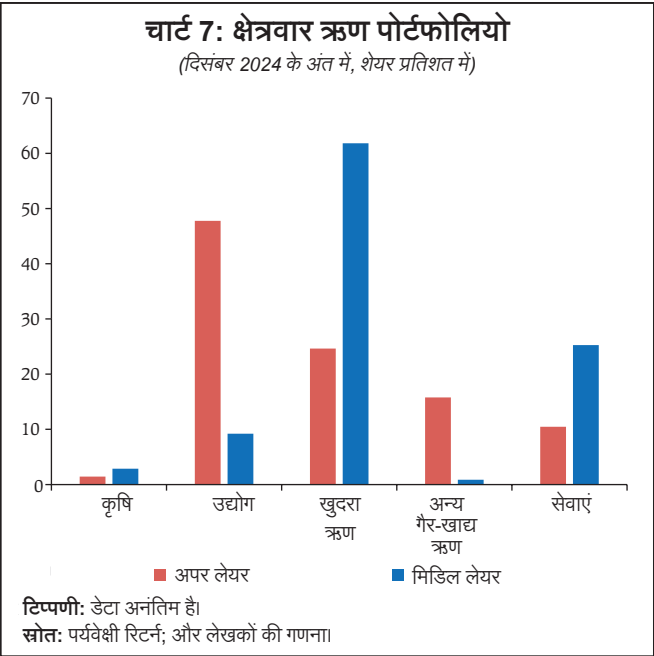
एनबीएफसी के खुदरा पोर्टफोलियो में वाहन और स्वर्ण पर ऋण सबसे बड़ा खंड है, जो कुल खुदरा ऋण का क्रमशः 34.9 प्रतिशत और 12.6 प्रतिशत है। वर्ष 2023-24 में यात्री वाहन बाजार में बढ़ती मांग, बढ़ती आबादी और बढ़ती वार्षिक बिक्री के अनुरूप वाहन ऋण मजबूती से बढ़े। ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों में मजबूत उपस्थिति रखने वाले स्वर्ण ऋण भी समाज के वंचित वर्गों की जरूरतों को पूरा करते हुए दोहरे अंकों में बढ़े। सूक्ष्म वित्त ऋणों में वृद्धि में तेज गिरावट देखी गई (सारणी 4)। माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क (एमएफआईएन) ने सुरक्षा दिशानिर्देश<sup>6</sup> जारी किए हैं, जिसके तहत प्रति उधारकर्ता बकाया ऋण की सीमा तय कर दी गई है।

#### IV. मौद्रिक नीति संचरण

अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अपने पर्याप्त ऋण मध्यस्थता और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ अंतर्संबंध के कारण, एनबीएफसी ने मौद्रिक नीति को व्यापक अर्थव्यवस्था में संचरण की सुविधा प्रदान करने में प्रमुखता प्राप्त की है, भले ही बैंक पारेषण के प्राथमिक चैनल बने हुए हैं। एनबीएफसी की बैंक और बाजार उधारियों पर निर्भरता के परिणामस्वरूप एक



<sup>6</sup> एमएफआईएन - एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) - इस क्षेत्र में उभरते विकास की निगरानी करता है और इसके आधार पर सदस्यों को निर्देश और सलाह जारी करता है। वर्ष 2024 के दौरान, एमएफआईएन ने 8 जुलाई को निर्देश गार्डरल जारी किए, जिससे सूक्ष्म वित्त उधारकर्ता की संख्या एक क्लाइंट को 4 तक सीमित कर दी गई और क्लाइंट को कुल सूक्ष्मवित्त ऋण ₹2 लाख तक सीमित कर दिया गया।



ट्रांसमिशन तंत्र बनता है जो बैंकों की तुलना में अधिक अप्रत्यक्ष<sup>7</sup> है। नीतिगत दर में परिवर्तन एनबीएफसी पर उनके निधियों की लागत के माध्यम से प्रभाव डालता है, जो तब बदलती है जब बाजार और बैंक ब्याज दरें मौद्रिक नीति के अनुरूप होती हैं।

इस संबंध में, यह जांचने का प्रयास किया गया है कि क्या एनबीएफसी की उधारी और उधार दरें, आस्तियों के आकार के आधार पर शीर्ष 100 एनबीएफसी के प्रतिनिधि नमूने द्वारा प्रासंगिक दरों में बदलावों के प्रति प्रतिक्रिया करती हैं। ऋण मूल्य निर्धारण की पद्धति सभी एनबीएफसी में एक समान नहीं है। जहाँ कुछ एनबीएफसी ब्याज दर बेंचमार्क के रूप में अपनी स्वयं की प्रमुख उधार दरों को अपनाते हैं, वहीं अन्य बाह्य बेंचमार्क के रूप में बैंकों की आधार दरों/एमसीएलआर पर निर्भर करते हैं; कुछ के पास अपने ऋण मूल्य निर्धारण के लिए कोई ब्याज दर बेंचमार्क नहीं है। पारदर्शिता की कमी के कारण वित्तीय बाजार के इस क्षेत्र में मौद्रिक नीति के प्रसारण का आकलन करने में कठिनाई हुई है (आरबीआई, 2021; पात्रा, 2022)।

एक गतिशील पैनेल मॉडल का अनुमान एक असंतुलित पैनेल<sup>8</sup> पर सामान्यीकृत विधि (जीएमएम) पद्धति का उपयोग करके लगाया जाता है, जो मार्च 2019 से दिसंबर 2024 तक की अवधि को कवर करता है, जिसमें एनबीएफसी क्षेत्र की 86 प्रतिशत आस्ति (मार्च 2024 के अंत में) शामिल है।

एनबीएफसी की तुलन-पत्र के देयताओं के पक्ष पर पारेषण को समझने के लिए, एनबीएफसी की भारित औसत उधार दर

सारणी 4: एनबीएफसी के खुदरा ऋण

(₹ करोड़)

मर्दाने	दिसंबर 2023 के अंत में	दिसंबर 2024 के अंत में	प्रतिशत भिन्नता	
			दिसंबर-22 की तुलना में दिसंबर-23	दिसंबर-23 की तुलना में दिसंबर-24
1. आवास ऋण	26,364	38,106	-4.4	44.5
2. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	42,343	50,297	43.6	18.8
3. क्रेडिट कार्ड प्राप्य	53,479	60,603	28.7	13.3
4. वाहन/ऑटो ऋण	4,28,654	5,18,408	25.6	20.9
5. शिक्षा ऋण	39,500	62,572	75.6	58.4
6. फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए अग्रिम	124	174	-58.2	40.9
7. शेयरों, बॉण्ड के लिए व्यक्तियों को अग्रिम	16,813	22,432	33.3	33.4
8. स्वर्ण के लिए व्यक्तियों को अग्रिम	1,43,745	1,87,350	20.0	30.3
9. सूक्ष्म वित्त ऋण/एसएचजी ऋण	1,31,795	1,32,819	39.2	0.8
10. अन्य	3,13,740	4,11,962	27.0	31.3
कुल खुदरा ऋण	11,96,557	14,84,724	27.7	24.1

टिप्पणी: डेटा अनंतिम है।  
स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न; और लेखकों की गणना।

<sup>7</sup> चूंकि एनबीएफसी को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) विंडो तक सीधी पहुंच का अभाव है, मौद्रिक नीति संचरण अप्रत्यक्ष रूप से बाजार-आधारित चैनलों के माध्यम से होता है, जिससे उधार लेने की लागत प्रभावित होती है और परिणामस्वरूप ऋण दरें प्रभावित होती हैं।  
<sup>8</sup> यह विश्लेषण डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता पर बाधाओं के कारण शीर्ष 100 एनबीएफसी के नमूने पर केंद्रित है।



(डब्ल्यूएबीआर) को आश्रित चर माना जाता है, जिसकी गणना प्रत्येक एनबीएफसी की उपलब्ध साधन-वार उधार दर का उपयोग करके की जाती है, जिसे उनकी संबंधित बकाया राशियों द्वारा भारित किया जाता है। इसी प्रकार, आस्ति पक्ष पर, भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) की गणना उपलब्ध क्षेत्रीय ऋण दरों का उपयोग करके की जाती है, जो उनकी संबंधित बकाया राशियों द्वारा भारित होती है। रेपो दर, भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर; मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य), और 91 दिन की टी-बिल दर (व्यापक वित्तीय स्थितियों का प्रतिनिधित्व करने वाली बेंचमार्क दर) का उपयोग स्वतंत्र चर के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, दो अन्य दरें जो एनबीएफसी के लिए प्रासंगिक हैं, पर भी विचार किया जाता है: ए और एए-रेटेड एनबीएफसी की औसत बॉण्ड प्रतिफल और एनबीएफसी को बैंक ऋण देने का डब्ल्यूएलआर। ऐसा इसलिए है क्योंकि एनबीएफसी अपनी फंडिंग आवश्यकताओं के लिए काफी हद तक बैंकों और बाजारों पर निर्भर हैं<sup>9</sup>। इन दरों में बदलाव से एनबीएफसी के लिए फंड की लागत प्रभावित होती है, जिससे उनकी उधार दरें प्रभावित होती हैं।

एनबीएफसी-विशिष्ट कारक जैसे आकार (कुल आस्तियों का लॉग), पूंजी पर्याप्तता, (जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी) और लाभप्रदता (कुल आस्ति के लिए निवल लाभ के अनुपात के रूप में ली जाने वाली आस्तियों पर प्रतिलाभ) का उपयोग नियंत्रण के रूप में किया जाता है। व्यापक आर्थिक वातावरण को नियंत्रित करने के लिए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को शामिल किया जाता है। कोविड-19 महामारी के लिए एक डमी, जो जून-सितंबर 2020 के दौरान एक मूल्य लेता है, और अन्यथा शून्य भी शामिल है।

प्रतिगमन के लिए नीचे दिए गए विनिर्देश का उपयोग किया जाता है:

$$Y_{it} = \alpha Y_{it-1} + \sum_{j=1}^n \beta MP_{t-j} + \delta_c X_{it-1}^c + covid_t + \theta_i + \varepsilon_{it}$$

जहाँ  $Y_{it}$  अवधि  $t$  में एनबीएफसी  $i$  का डब्ल्यूएबीआर या डब्ल्यूएलआर है, जैसा भी मामला हो।  $MP_t$ , ब्याज का मुख्य चर है, जो अलग-अलग विनिर्देश में रेपो दर, डब्ल्यूएसीआर, या 91-दिन के टी-बिल दर के लिए होता है। डब्ल्यूएलआर को

निर्भर चर के तौर पर प्रतिगमन में, एनबीएफसी के बॉण्ड प्रतिफल या एनबीएफसी को बैंक उधार का डब्ल्यूएलआर भी ब्याज के अतिरिक्त चर के तौर पर शामिल है। वेक्टर  $X_{i,t-1}^c$  अलग-अलग नियंत्रण को दिखाता है, जिन्हें संभावित अंतर्जातीय चिंता का सामना करने के लिए एक-चौथाई लैग के साथ लिया गया है।  $\theta_i$  उन एनबीएफसी के निर्धारित प्रभाव का नियंत्रण है, जिनका अवलोकन नहीं किया गया है।

परिणाम दर्शाते हैं कि उपर्युक्त विभिन्न प्रासंगिक दरों में परिवर्तन एनबीएफसी के डब्ल्यूएबीआर और डब्ल्यूएलआर पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, जिसका तात्पर्य अपूर्ण होने पर भी संचरण है। रेपो दर, डब्ल्यूएसीआर, 91-दिवसीय टी बिल दर, एनबीएफसी बॉण्ड प्रतिफल और बैंकों के एनबीएफसी के डब्ल्यूएलआर का संयुक्त गुणांक रिपोर्ट किया गया है, जो तीन तिमाहियों में एनबीएफसी के डब्ल्यूएबीआर/डब्ल्यूएलआर पर प्रासंगिक ब्याज दर में परिवर्तन का संचयी प्रभाव देता है। उधार पक्ष पर, रेपो दर में एक प्रतिशत अंक का परिवर्तन तीन तिमाहियों में एनबीएफसी के डब्ल्यूएबीआर में 0.24 प्रतिशत अंक के परिवर्तन से जुड़ा है। डब्ल्यूएसीआर (0.21) और 91-दिवसीय टी बिल दर (0.19) के साथ भी समान परिणाम रिपोर्ट किए गए हैं। सभी विशिष्टताओं में, विलंबित आश्रित चर का गुणांक सकारात्मक और अत्यधिक महत्वपूर्ण है

ऋण देने के पक्ष में, रेपो दर में एक प्रतिशत अंक का परिवर्तन तीन तिमाहियों में एनबीएफसी के डब्ल्यूएलआर में 0.33 प्रतिशत अंक के परिवर्तन से जुड़ा है (जब बैंकों के एनबीएफसी के लिए डब्ल्यूएलआर पर विचार किया जाता है तो 0.36 प्रतिशत अंक का परिवर्तन)। इसी प्रकार, एनबीएफसी के डब्ल्यूएलआर को डब्ल्यूएसीआर (0.22), 91-दिवसीय टी-बिल दर (0.24) और एनबीएफसी बॉण्ड प्रतिफल (0.17) के साथ-साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ पाया गया है (सारणी 6)।

उधार लेने के पक्ष में, संचरण के लिए एक प्रमुख बाधा एनबीएफसी द्वारा सामना किए जाने वाले फंड की उच्च लागत हो सकती है। एनबीएफसी अपनी फंडिंग आवश्यकताओं के लिए बैंक और बाज़ार उधार पर निर्भर करती हैं और बैंकों के विपरीत, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) विंडो तक सीधी पहुंच नहीं होती है। नतीजतन, रेपो दर में कटौती तुरंत फंडिंग की कम

<sup>9</sup> दिसंबर 2024 के अंत में, बैंक उधार (37.4) और डिबेंचर (35.6) एक साथ एनबीएफसी के कुल उधार का 73 प्रतिशत हिस्सा थे।



**सारणी 5: एनबीएफसी के भारित-औसत उधार दरों में संचरण**

	आश्रित चर: डबल्यूएबीआर		
	रेपो दर	डबल्यूएसीआर	91-दिवसीय टी-बिल दर
डबल्यूएबीआर (-1)	0.443*** (0.112)	0.442*** (0.119)	0.448*** (0.113)
आकार	-0.407* (0.209)	-0.418* (0.214)	-0.400* (0.210)
सीआरएआर	-0.00413 (0.00269)	-0.00425 (0.00265)	-0.00442* (0.00252)
आरओए	-0.0659** (0.0281)	-0.0714** (0.0313)	-0.0721** (0.0334)
जीडीपी	-0.00440 (0.00345)	0.000782 (0.00366)	0.00216 (0.00398)
मुद्रास्फीति	0.0216 (0.0301)	0.0230 (0.0256)	0.0367 (0.0236)
कोविड डमी	-0.0369 (0.162)	-0.0651 (0.194)	-0.0928 (0.205)
$\sum_{j=0}^2 \beta MP_{t-j}$ योग गुणांक	<b>0.244***</b> <b>(0.0613)</b>	<b>0.206***</b> <b>(0.0496)</b>	<b>0.190***</b> <b>(0.0437)</b>
स्थिर	7.391*** (2.229)	7.752*** (2.433)	7.494*** (2.350)
अवलोकन	1684	1684	1684
एआर1 (पी-मान)	0.00	0.00	0.00
एआर2 (पी-मान)	0.32	0.27	0.27
हैनसेन-जे (पी-मान)	0.51	0.58	0.54

टिप्पणियाँ: 1. मानक त्रुटियाँ कोष्ठक में हैं।

2. \* पी<0.10, \*\* पी<0.05, \*\*\* पी<0.010.

स्रोत: लेखकों का अनुमान।

लागत में तब्दील नहीं हो सकती है। इसके अलावा, एनबीएफसी को बैंक और बाजार वित्त पोषण भी चलनिधि की स्थिति और जोखिम के कथित स्तरों पर निर्भर हो सकती है, जो पारेषण को और कम कर सकता है। ऋण देने के पक्ष में, चूंकि एनबीएफसी अपेक्षाकृत जोखिम वाले उधारकर्ता खंडों को पूरा करते हैं, इसलिए वे संभावित चूक को ध्यान में रखते हुए उच्च ब्याज दरें वसूलते हैं, जो प्रासंगिक दरों में बदलाव के लिए ऋण दरों के समायोजन को और कम कर सकता है।

## V. वित्तीय और विवेकपूर्ण संकेतक

आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए), इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) और निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) द्वारा दर्शाई गई लाभप्रदता दिसंबर 2024 के अंत में लेयरो में स्वस्थ स्तर पर बनी रही (चार्ट 8)।

**सारणी 6: एनबीएफसी की भारित-औसत उधार दर में संचरण**

	आश्रित चर: डबल्यूएएलआर				
	रेपो दर	डबल्यू एसीआर	91-दिवसीय टी-बिल दर	एनबीएफसी बॉण्ड प्रतिफल	बैंकों की तुलना में एनबीएफसी का डबल्यूएएलआर
डबल्यूएएलआर (-1)	0.492*** (0.0859)	0.500*** (0.0847)	0.502*** (0.0824)	0.507*** (0.0830)	0.519*** (0.0851)
आकार	-1.290*** (0.405)	-1.251*** (0.410)	-1.226*** (0.395)	-1.212*** (0.389)	-1.106*** (0.371)
सीआरएआर	-0.0146 (0.0128)	-0.0137 (0.0138)	-0.0157 (0.0130)	-0.0163 (0.0134)	-0.0165 (0.0123)
आरओए	-0.0518 (0.108)	-0.0416 (0.116)	-0.0405 (0.0986)	-0.0116 (0.0907)	-0.00700 (0.110)
जीडीपी	-0.0119* (0.00615)	-0.0175** (0.00781)	-0.0137 (0.0114)	-0.0112 (0.00772)	-0.0110 (0.00837)
मुद्रास्फीति	-0.0307 (0.113)	-0.0617 (0.0997)	-0.0703 (0.0910)	-0.0361 (0.0857)	-0.0710 (0.0836)
कोविड डमी	0.233 (0.474)	0.175 (0.515)	0.647 (0.728)	-0.00467 (0.453)	-0.129 (0.503)
$\sum_{j=0}^2 \beta MP_{t-j}$ योग गुणांक	<b>0.329***</b> <b>(0.117)</b>	<b>0.221**</b> <b>(0.0844)</b>	<b>0.242***</b> <b>(0.0818)</b>	<b>0.166**</b> <b>(0.0709)</b>	<b>0.357*</b> <b>(0.210)</b>
स्थिर	18.64*** (4.055)	18.92*** (4.164)	18.63*** (4.009)	18.40*** (3.891)	14.91*** (3.648)
अवलोकन	1624	1624	1624	1624	1624
एआर1 (पी-मान)	0.00	0.00281	0.00	0.00	0.00
एआर2 (पी-मान)	0.27	0.26	0.23	0.27	0.25
हैनसेन-जे (पी-मान)	0.48	0.41	0.40	0.47	0.36

टिप्पणियाँ: 1. मानक त्रुटियाँ कोष्ठक में हैं।

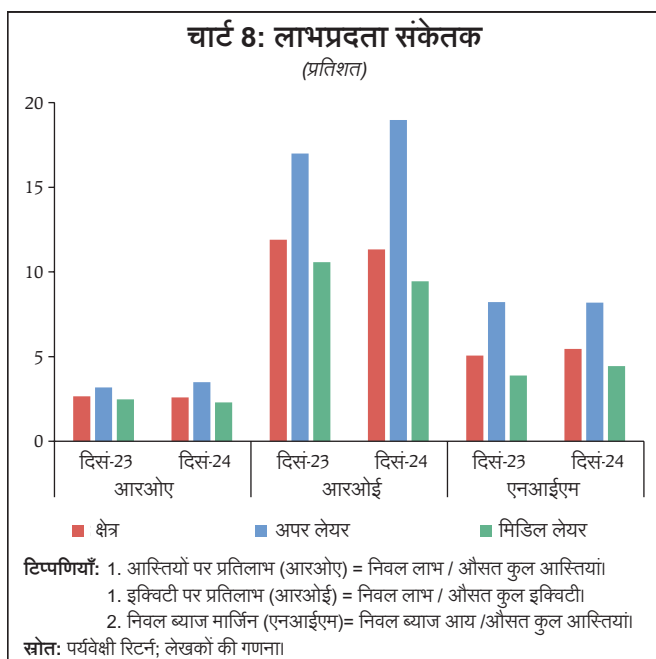
2. \* पी<0.10, \*\* पी<0.05, \*\*\* पी<0.010.

स्रोत: लेखकों का अनुमान।

रिज़र्व बैंक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत प्रमुख संकेतकों की बारीकी से निगरानी कर रहा है, जैसे पूंजी-जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर), टियर-1 पूंजी अनुपात और निवल एनपीए अनुपात (एनएनपीए), जो अक्टूबर 2022 से एनबीएफसी <sup>10</sup> के लिए प्रभावी है। अभी तक बैंक द्वारा किसी भी एनबीएफसी को पीसीए ढांचे के तहत नहीं रखा गया है।

हाल के वर्षों में एनबीएफसी क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रहा है, जैसा कि एनपीए अनुपात में लगातार गिरावट में परिलक्षित होता है। दिसंबर 2024 के अंत में, जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात क्रमशः 3.4 और 1.2 प्रतिशत था। जबकि

<sup>10</sup> <https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=12208&Mode=0>



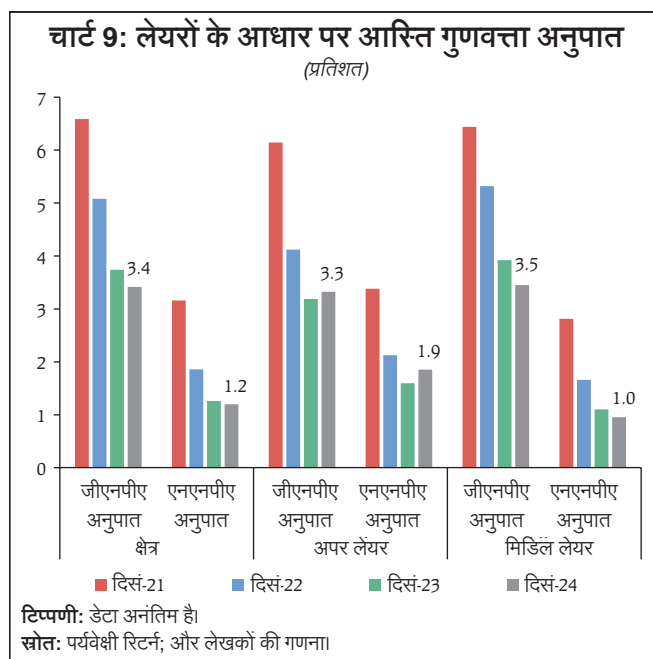
मिडिल लेयर की आस्ति गुणवत्ता समग्र क्षेत्रों के के साथ संरेखण में है, वहीं अपर लेयर में दिसंबर 2024 के अंत में एनपीए अनुपात में थोड़ी वृद्धि देखी गई (चार्ट 9)।

दिसंबर 2024 के अंत में, एनबीएफसी का क्रेडिट पोर्टफोलियो लाभदायी रहा है, कृषि और संबद्ध गतिविधियों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में जीएनपीए अनुपात में कमी के साथ (चार्ट 10)।

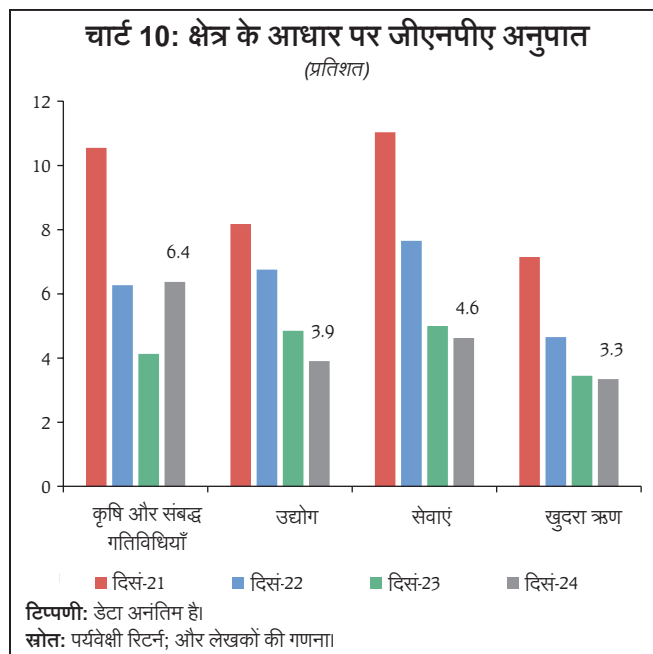
दिसंबर 2023 के अंत में आस्तियों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार के बाद, एनबीएफसी का एमएसएमई क्रेडिट पोर्टफोलियो दिसंबर 2024 के अंत में जीएनपीए अनुपात के स्थिर स्तर के साथ मजबूत बना रहा है (चार्ट 11)।

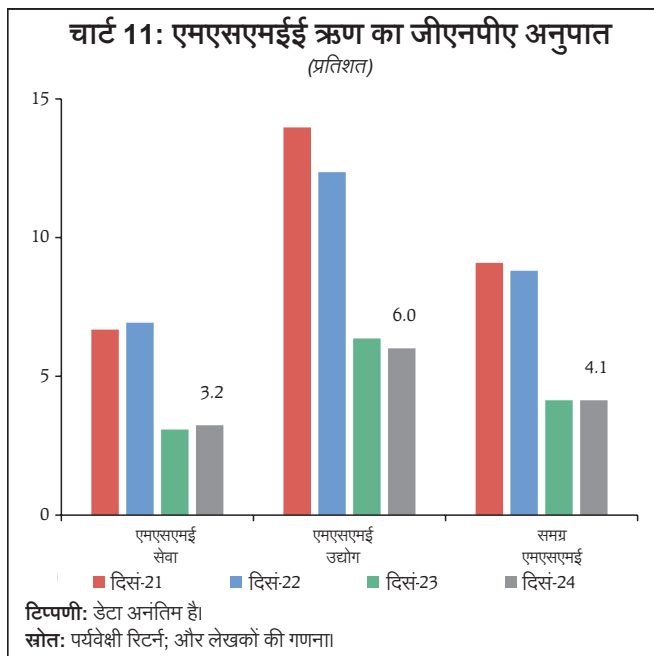
खुदरा ऋणों में मजबूत वृद्धि के बावजूद खुदरा ऋणों की आस्ति गुणवत्ता स्थिर बनी हुई है। हालाँकि, सूक्ष्म वित्त ऋणों के संबंध में जीएनपीए दिसंबर 2024 के अंत में बढ़ गया (चार्ट 12)। सूक्ष्म ऋण देने के क्षेत्र में एसआरओ के साथ-साथ एनबीएफसी को बाजार सहभागियों के बीच जिम्मेदार ऋण प्रथाओं और ऋण अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना चाहिए।

एनबीएफसी ने विनियामक आवश्यकता से परे भी अपने तुलन पत्र पर लगातार पूंजी बफर बनाए रखा है। दिसंबर 2024 के अंत में, समग्र स्तर पर, अपर लेयर और मिडिल लेयर ने क्रमशः 20.6 प्रतिशत और 28.6 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखा (चार्ट



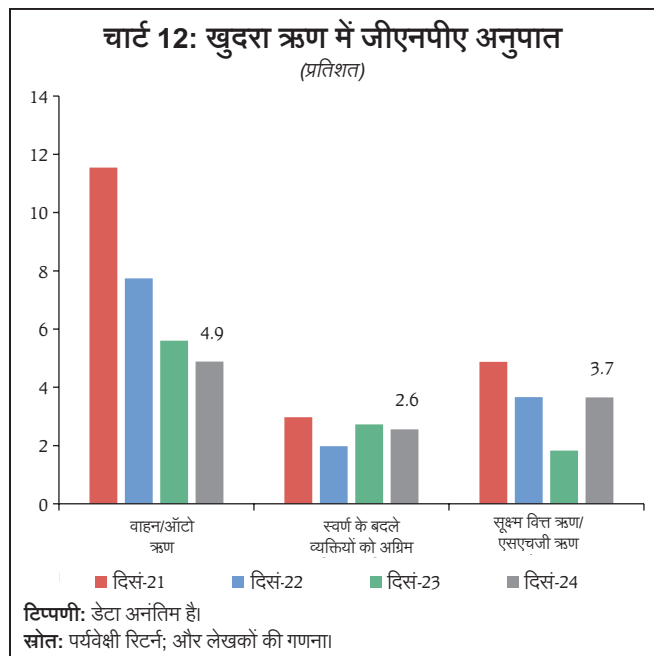
13)। अपर लेयर और मिडिल लेयर के बीच सीआरएआर के स्तर में असमानता मुख्य रूप से स्वामित्व संरचना में अंतर के कारण है। बड़े सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी - जिन्हें नियामक डिजाइन द्वारा मिडिल लेयर में रखा गया है, में समय-समय पर पूंजी निवेश होता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च सीआरएआर होता है। इसके विपरीत, अपर लेयर, जिसमें निजी एनबीएफसी शामिल हैं, लाभ और विकास से प्रेरित होती हैं, अक्सर लीवरेज और जोखिम भरे ऋण बुक के साथ चलती हैं।



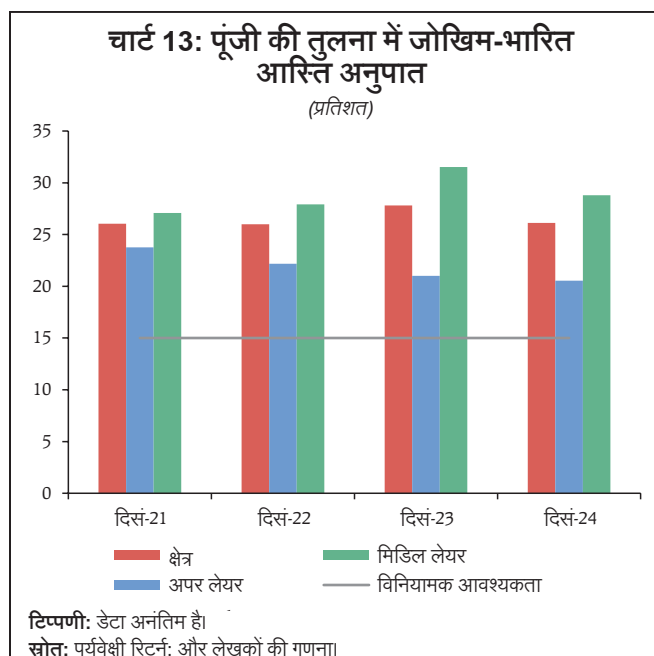


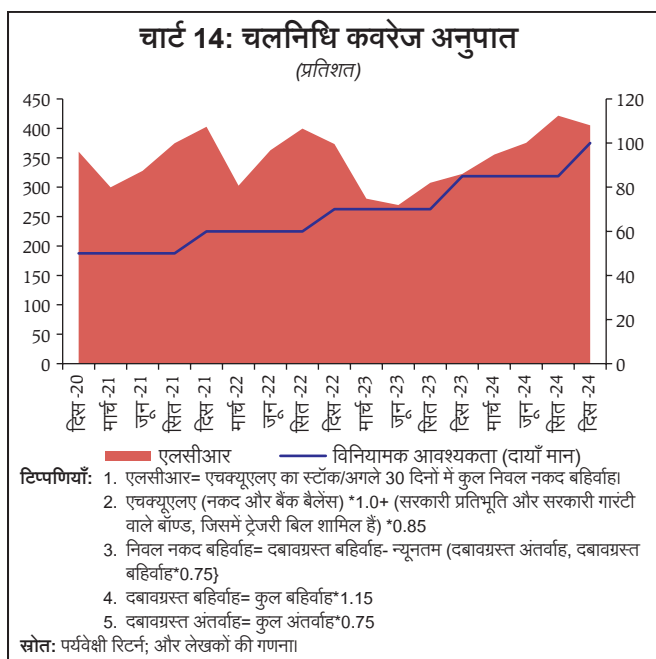
नवंबर 2019 में, रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए अपने चलनिधि जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) ढांचा पेश किया। 30-दिवसीय दबाव परिदृश्य में निवल नकदी बहिर्वाह को कवर करने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले चलनिधि आस्तियों<sup>11</sup> (एचक्यूएलए) के बफर को अनिवार्य करके, एलसीआर एनबीएफसी के अल्पकालिक लचीलेपन को बढ़ाता है। एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, एलसीआर आवश्यकता को 1 दिसंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था। ₹10,000 करोड़ और उससे अधिक की संपत्ति वाले सभी गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी और सभी जमा लेने वाली एनबीएफसी को 1 दिसंबर 2020 को 50 प्रतिशत से शुरू होकर 1 दिसंबर 2024 तक 100 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए न्यूनतम एलसीआर बनाए रखना था। ₹5,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ के बीच की आस्तियों वाली सभी गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी ने 30 प्रतिशत से शुरू होने वाले समान प्रक्षेपवक्र का अनुसरण किया। इस सही परिदृश्य ने एनबीएफसी को क्षेत्रीय चलनिधि और ऋण प्रवाह को संरक्षित करते हुए धीरे-धीरे नए मानदंडों के साथ संरेखित करने की अनुमति दी।

<sup>11</sup> आंकड़ों की कमी के कारण, हम एचक्यूएलए का अनुमान लगाने के लिए रूढ़िवादी दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, जो मौजूदा विनियमों के तहत एनबीएफसी द्वारा बनाए गए वास्तविक एचक्यूएलए की मात्रा को कम करके आंक सकता है।



दिसंबर 2024 तक, यह क्षेत्र नियामक आवश्यकता से परे एलसीआर बनाए रख रहा है (चार्ट 14)। यह सतर्क दृष्टिकोण इस क्षेत्र की दीर्घकालिक आस्तियों के लिए अल्पकालिक वित्तपोषण पर निर्भरता के कारण हो सकता है, जिससे उन्हें चलनिधि असंतुलन और प्रणालीगत जोखिम का सामना करना पड़ता है। एलसीआर ऐसी कमजोरियों को कम करता है, जिससे स्थिरता और बाजार विश्वास को बढ़ावा मिलता है।





## VI. निष्कर्ष

एफएसबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक स्तर पर एनबीएफआई क्षेत्र की वृद्धि पारंपरिक बैंकिंग क्षेत्र के विकास से आगे निकल गई है। भारत में, एनबीएफसी ने दिसंबर 2024 के अंत तक दोहरे अंकों की ऋण वृद्धि दर्ज करना जारी रखा। यह विस्तार उद्योग और खुदरा क्षेत्र को ऋण देने से जीडीपी अनुपात में वृद्धि से स्पष्ट है, जो उनके पोर्टफोलियो पर हावी है। एनबीएफसी क्षेत्र विभिन्न लाभप्रदता और विवेकपूर्ण संकेतकों जैसे आस्तियों पर प्रतिलाभ, इक्विटी पर प्रतिलाभ, निवल ब्याज मार्जिन, जोखिम भारित आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए पूंजी के मामले में मजबूत बना हुआ है। नवंबर 2023 में जोखिम भार में वृद्धि के माध्यम से गैर-जमानती ऋणों की वृद्धि दर में वृद्धि को नियंत्रित किया गया था। वित्त के स्रोतों के संबंध में, एनबीएफसी काफी हद तक बैंक उधार और डिबेंचर पर निर्भर हैं। ऋण मध्यस्थता और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के

साथ अंतर्संबंधों में एनबीएफसी की भूमिका का वित्तीय क्षेत्र और वास्तविक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति आवेगों के संचरण पर प्रभाव पड़ता है। अनुभवजन्य विश्लेषण इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि एनबीएफसी की उधार और उधार दरों में मौद्रिक नीति का संचरण होता है, हालांकि यह अधूरा है।

वाहन ऋण और स्वर्ण के लिए ऋण जैसे क्षेत्रों के लिए संभावनाएं मजबूत दिखाई देती हैं, जो वाहनों की बिक्री में सुधार और स्वर्ण की बढ़ती कीमतों से उत्साहित हैं। एलसीआर की शुरुआत एनबीएफसी के अल्पकालिक आघात-सहनीयता को और मजबूत करने के लिए तैयार है। जैसा कि वित्तीय क्षेत्र तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग को अपना रहा है, एनबीएफसी को सतर्क रहना चाहिए और इन नए अवसरों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाकर साइबर चुनौतियों का सक्रिय रूप से समाधान करना चाहिए।

## संदर्भ

- FSB. (2024). Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation.
- Patra, M. D. (2022). Lost in Transmission? Financial Markets and Monetary Policy. *Speech by Dr Michael Debabrata Patra, Deputy Governor, Reserve Bank of India.*
- RBI. (2021). *Report on Currency and Finance.*
- RBIA. (2024). *Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting, December 4-6.*
- RBIB. (2024). *Report on Trend and Progress of Banking in India.*
- SIAM. (2025). *Performance of Indian Auto Industry in 2023-24.* Retrieved from <https://www.siam.in/statistics.aspx?mpgid=8&pgidtrail=9>

## नकदी मांग पर यूपीआई का प्रभाव - राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर से साक्ष्य

साक्षी अवस्थी और सुब्रत कुमार सीत द्वारा <sup>^</sup>

डिजिटल भुगतान की ओर व्यापक बदलाव भले ही सुस्थापित हो चुका हो, लेकिन एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) को क्षेत्रीय स्तर पर अपनाने और नकदी की माँग पर इसके प्रभाव का अभी तक पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है। एक दोहरी अनुभवजन्य रणनीति एक ऑटोरिग्रैसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग मॉडल और पैनेल क्वांटाइल रिग्रेशन का उपयोग करते हुए, इस अध्ययन में पाया गया है कि यूपीआई को अपनाने की दर में वृद्धि राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर कम नकदी की माँग से जुड़ी है, और राज्य-स्तरीय पैटर्न गैर-रैखिकता का संकेत देते हैं। अन्य राज्य-वार कारकों में, आय और एटीएम घनत्व नकदी की माँग से सकारात्मक रूप से जुड़े हैं, जबकि कार्यबल का औपचारिकीकरण और शैक्षिक उपलब्धि कम नकदी निर्भरता से जुड़ी हैं।

### परिचय

भुगतान सभी आर्थिक गतिविधियों का आधार है। एक प्रतिरोध रहित वातावरण में, भुगतान के तरीके के चुनाव का वास्तविक परिणामों पर कम प्रभाव पड़ सकता है; हालाँकि, व्यवहार में, लेन-देन की लागत और सूचना संबंधी विषमताएँ आर्थिक विकास को आकार देने में कुछ भुगतान विधियों को दूसरों की तुलना में अधिक कुशल बनाती हैं (दुबे और पूर्णानंदम, 2023)। नकदी से डिजिटल भुगतान, विशेष रूप से तेज़ भुगतान प्रणालियों में परिवर्तन कल्याण, वित्तीय समावेशन, ऋण पहुँच, आर्थिक औपचारिकता और वित्तीय सहनीयता में वृद्धि से जुड़ा

है (बाचास और अन्य., 2018; एगुइलर और अन्य., 2024; ऑराज़ो और फ्रेंको, 2024; कैंटू और अन्य., 2024)। साथ ही, मौजूदा साहित्य में नकदी और डिजिटल भुगतान में एक साथ वृद्धि के उदाहरण भी मौजूद हैं (बेच और अन्य., 2018; चेन और अन्य., 2020; कैसवेल और अन्य., 2020), जबकि नकदी लेन-देन संबंधी उपयोग कम हो रहा है, या जिसे अक्सर "बैंक नोटों का विरोधाभास" कहा जाता है (बेली, 2009)। इस प्रवृत्ति ने नकदी पर डिजिटल भुगतान के प्रभाव पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है, जिससे मुद्रा और चलनिधि प्रबंधन, अंतर्निहित आर्थिक घर्षण और व्यापक समष्टि आर्थिक नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहे हैं।

2016 में प्रारम्भ की गई भारत की तेज़ भुगतान प्रणाली, इकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई), तीन प्रमुख कारणों से नकदी और डिजिटल भुगतान के बीच विकसित हो रहे संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक अनूठा अनुभवजन्य ढांचा प्रदान करती है। सबसे पहले, अपनाने का पैमाना अभूतपूर्व रहा है। यूपीआई उपयोगकर्ता 2017 के लगभग 30 मिलियन से बढ़कर 2024 तक 420 मिलियन से अधिक हो गए हैं (आरबीआई, 2024; रेड्डी एट अल., 2024)। लेन-देन की मात्रा प्रति वर्ष 200 बिलियन के करीब है, जो कुल डिजिटल भुगतानों का 80 प्रतिशत से अधिक है (आरबीआई, 2025)। दूसरा, यूपीआई की शुरुआत के तुरंत बाद बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन अभियान यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई, जिससे सामाजिक-आर्थिक समूहों में व्यापक डिजिटल उपयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनीं। अंत में, डिजिटल भुगतान (विशेषकर यूपीआई) में वृद्धि के बावजूद, संचलन में मुद्रा में वृद्धि जारी रही है, हालाँकि हाल के वर्षों में धीमी गति से, नकदी और डिजिटल मोड के बीच एक गतिशील परस्पर-क्रिया दिखाई देती है।

यद्यपि डिजिटल भुगतान की ओर व्यापक बदलाव सुस्थापित है (नचाने और अन्य., 2013; चौधरी और अन्य., 2019; राज और अन्य., 2020; अवस्थी और अन्य., 2022; आरबीआई, 2023), यूपीआई को क्षेत्रीय रूप से अपनाया जाना और राज्य-स्तर पर नकदी की माँग पर इसका प्रभाव अभी भी कम ही माना जाता है। भारत की भौगोलिक और आय विविधता को देखते हुए, राष्ट्रीय समुच्चय क्षेत्रीय असमानताओं को छिपा

<sup>^</sup> लेखक आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग से हैं। पूर्व कार्यपालक निदेशक डॉ. राजीव रंजन, श्री एम.एम. रमैया और डॉ. राखे बालचंद्रन द्वारा की प्राप्त बहुमूल्य गहन विचारों के लिए हम कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। लेखक मुद्रा तिजोरी डेटा उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा प्रबंधन विभाग की टीम के प्रति आभारी हैं, जिसमें प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक श्री संजीव प्रकाश, प्रदीप भुयान और बसवराज पाटिल शामिल हैं। लेखक क्षेत्रवार यूपीआई डेटा तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक श्री गुणवीर सिंह के आभारी हैं। इस पत्र में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।



सकते हैं, क्योंकि डिजिटल उपयोग चुनिंदा आर्थिक समूहों तक ही सीमित रह सकता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में नकदी का प्रचलन बना रहेगा। अनुमानों के अनुसार, शीर्ष 20 प्रतिशत आय वर्ग के व्यक्तियों द्वारा डिजिटल भुगतान का उपयोग करने की संभावना निम्नतम 40 प्रतिशत आय वर्ग के व्यक्तियों की तुलना में दोगुनी है (एनपीसीआई, 2020)। हाल के आँकड़े एक तीव्र उतार-चढ़ाव दर्शाते हैं, जहाँ उपभोग व्यय के हिसाब से शीर्ष 10 प्रतिशत लोगों द्वारा यूपीआई का उपयोग करने की क्षमता की रिपोर्ट करने की संभावना निचले 25 प्रतिशत लोगों की तुलना में दोगुनी है, हालाँकि कुल क्षमता लगभग 50 प्रतिशत है (एनएसओ, 2025)। जैसे-जैसे डिजिटल भुगतान आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं, उन क्षेत्रों की पहचान करना महत्वपूर्ण है जो इससे वंचित हैं या पिछड़ रहे हैं - न केवल समावेशी पहुँच को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि बुनियादी ढाँचे की कमियों और उपभोक्ता संरक्षण के जोखिमों को दूर करने के लिए भी।

इस पृष्ठभूमि में, यह शोधपत्र राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नकदी की मांग का मॉडल बनाकर नकदी के उपयोग पर यूपीआई के प्रभाव की जांच करता है। विशेष रूप से, यह अध्ययन चार प्रमुख शोध प्रश्नों को संबोधित करता है: (ए) अखिल भारतीय समग्र स्तर पर नकदी की मांग पर यूपीआई का क्या प्रभाव है? (बी) यूपीआई और नकदी को अपनाने में कौन से क्षेत्रीय पैटर्न उभर कर आते हैं? (सी) यूपीआई राज्यों में नकदी की मांग को कैसे प्रभावित करता है? और (डी) क्या यह प्रभाव राज्य के आय स्तर के अनुसार अलग-अलग होता है? क्षेत्रीय रुझानों पर सीमित अनुभवजन्य फोकस को देखते हुए, यह अध्ययन भारत में नकदी से यूपीआई प्रतिस्थापन का पहला राज्य-स्तरीय आकलन प्रदान करता है।

शोधपत्र का शेष भाग इस प्रकार संरचित है: खंड II साहित्य की समीक्षा करता है, उसके बाद खंड III में वर्णनात्मक विश्लेषण किया गया है। खंड IV डेटा और कार्यप्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जबकि खंड V अनुभवजन्य परिणाम प्रस्तुत करता है। खंड VI समापन करता है। तकनीकी विवरण और अतिरिक्त अनुमान आउटपुट अनुलग्नक I-III में प्रस्तुत किए गए हैं।

## II. संबंधित साहित्य

नकदी की मांग के निर्धारकों पर सैद्धांतिक और अनुभवजन्य साहित्य का एक बड़ा भंडार उपलब्ध है (फ्रीडमैन, 1999;

अल्वारेज़ और लिप्पी, 2009)। नकदी की मांग को पारंपरिक रूप से तीन प्राथमिक उद्देश्यों से जोड़ा जाता है: आर्थिक गतिविधि से जुड़ा लेन-देन उद्देश्य (फिशर, 1911); एहतियाती उद्देश्य, जो अनिश्चित परिस्थितियों में तरलता की आवश्यकता को दर्शाता है; और सट्टा उद्देश्य, जो ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव की अपेक्षाओं से प्रेरित होता है (कीन्स, 1954)। इसके आधार पर, मुद्रा की मांग को संपत्ति के एक स्थिर कार्य के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाता है, जिसमें बांड, इक्विटी और टिकाऊ वस्तुओं जैसी वैकल्पिक आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल शामिल होता है (फ्रीडमैन, 1956)। मौलिक इन्वेंट्री (बॉमोल, 1952) और पोर्टफोलियो (टोबिन, 1956) सैद्धांतिक मॉडल ब्याज दरों और लेन-देन लागतों को शामिल करके मुद्रा की मांग के कार्य का विस्तार करते हैं। हाल के अध्ययनों ने भौतिक मुद्रा पर भुगतान नवाचारों के नकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया है (कोलंबा, 2009; ओयेलामी और यिनूसा, 2013; हुइन्ह और अन्य., 2014)। साथ ही, साहित्य का एक बढ़ता हुआ समूह नकदी और डिजिटल भुगतान के सह-अस्तित्व पर प्रकाश डालता है, जो एहतियाती उद्देश्यों और आर्थिक अनिश्चितताओं के लिए निरंतर नकदी उपयोग को जिम्मेदार ठहरता है (बेच और अन्य., 2018; कैसवेल और अन्य., 2020; चेन और अन्य., 2020; अर्दिजी और अन्य., 2020)।

भारतीय संदर्भ में, अध्ययनों में डिजिटल भुगतान और मुद्रा की मांग के बीच एक महत्वपूर्ण नकारात्मक संबंध पाया गया है, जो बढ़ते प्रतिस्थापन प्रभाव को दर्शाता है (नचाने और अन्य., 2013; भट्टाचार्य और सिंह, 2016; चौधरी और अन्य., 2019; राज और अन्य., 2020; और अवस्थी और अन्य., 2022; उडुपा और अन्य., 2025)। हालांकि, क्षेत्रीय स्तर पर, अनुभवजन्य शोध में प्रतिस्थापन गतिशीलता के बजाय बड़े पैमाने पर डिजिटल भुगतान अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। फोनपे से लेनदेन स्तर के डेटा का उपयोग करते हुए, दुबे और पूर्णानंदम (2023) ने पाया कि यूपीआई के बाद कैशलेस भुगतान के आधिक्य वाले जिलों में घरेलू आय में काफी अधिक वृद्धि हुई। उसी डेटासेट पर आधारित, आईसीआरआईआईआर की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि कोविड-19 ने डिजिटल अपनाने में तेजी लाई और राज्यों और जिलों में यूपीआई के उपयोगकर्ता प्रवेश में असमानताओं को कम कर दिया (रेड्डी और अन्य., 2024)। रिपोर्ट में डिजिटल अपनाने के प्रमुख कारकों जैसे आय स्तर, इंटरनेट

पहुंच, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय ढांचे की भी पहचान की गई है।

### III. भारत भुगतान कैसे करता है?

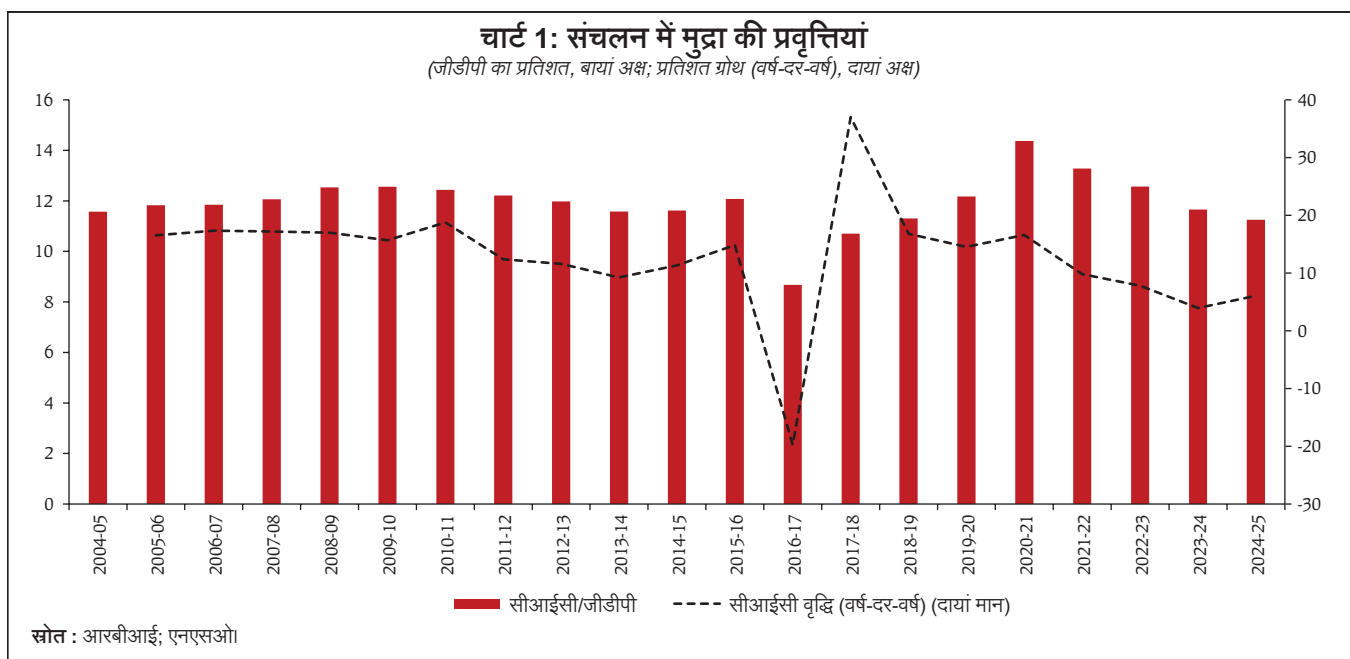
#### III.1. भुगतान विकल्पों पर समग्र-स्तरीय अंतर्दृष्टि

भारत में एक विविध भुगतान पारितंत्र है, जिसमें नकद और डिजिटल विकल्पों दोनों का एक विस्तृत समूह शामिल है। प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी)<sup>1</sup> 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 14.4 प्रतिशत के शिखर से 2023-24 में 11.7 प्रतिशत और 2024-25 में 11.2 प्रतिशत तक सामान्य हो गई है। हाल के वर्षों में सीआईसी की वृद्धि धीमी होकर 4-6 प्रतिशत हो गई है, जो डिजिटल भुगतान की ओर संरचनात्मक बदलाव, महामारी के बाद सामान्यीकरण, ₹2000 के नोटों की चरणबद्ध वापसी और अधिक औपचारिकता के कारण है (चार्ट 1)। 2024-25 में मामूली वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) उच्च ग्रामीण मांग और चुनाव-संबंधी खर्च को दर्शाती है। वास्तविक सीआईसी वृद्धि 2023-24 में ऋणात्मक हो गई और 2024-25 में मामूली रही, जो मुद्रास्फीति-समायोजित नकदी मांग में गिरावट का संकेत देती है।

इसके विपरीत, सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में डिजिटल भुगतान (मूल्य) तेजी से बढ़कर 800 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जिसमें महामारी ने मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में इसे अपनाने के लिए उत्प्रेरक का काम किया है (चार्ट 2ए)। कुल मिलाकर, कुल डिजिटल भुगतानों ने पिछले दशक (2015-2025) में मजबूत वृद्धि प्रदर्शित की है, जिसमें मात्रा के हिसाब से 48 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 12.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। मासिक रुझान सीआईसी वृद्धि में कमी के साथ व्यापक रूप से निरंतर डिजिटल गति दिखाते हैं (चार्ट 2बी)।

नकदी से दूर जाने की प्रवृत्ति मुद्रा-से-मांग जमा अनुपात में 2015-16<sup>2</sup> में 1.68 से घटकर 2024-25 में 1.31 रह जाने तथा 2018-19 से एटीएम से नकदी निकासी (जीडीपी के हिस्से के रूप में) में लगातार गिरावट से भी स्पष्ट है (चार्ट 3 ए और बी)।

नकदी की मांग में गिरावट के पीछे एक संभावित कारण यूपीआई का उदय रहा है। कोविड-19 के बाद इसमें उल्लेखनीय तेजी आई है और तेज भुगतान मोड के तहत लेनदेन की मात्रा

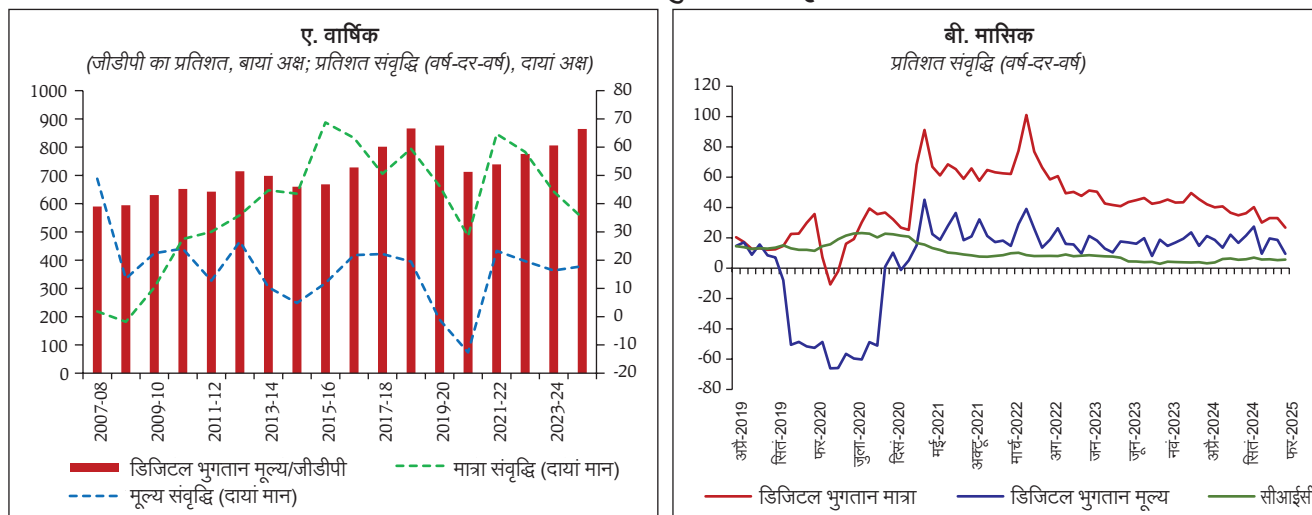


<sup>1</sup> नकदी आधारित आर्थिक लेनदेन से जुड़ी गुमनामी को देखते हुए, सीआईसी को पिछले आरबीआई अध्ययनों के अनुरूप नकदी की मांग के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में लिया जाता है (नचाने और अन्य., 2013; चौधरी और अन्य., 2019; राज और अन्य., 2020)

<sup>2</sup> चूंकि डिजिटल भुगतान बैंक जमाओं, मुख्यतः माँग जमाओं द्वारा समर्थित होते हैं, इसलिए सीआईसी-से-माँग जमा अनुपात में गिरावट अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए लेनदेन के डिजिटल तरीकों की ओर बदलाव का संकेत देती है, जबकि अनुपात में वृद्धि नकदी के प्रति बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाती है।



चार्ट 2: डिजिटल भुगतान में प्रवृत्तियां



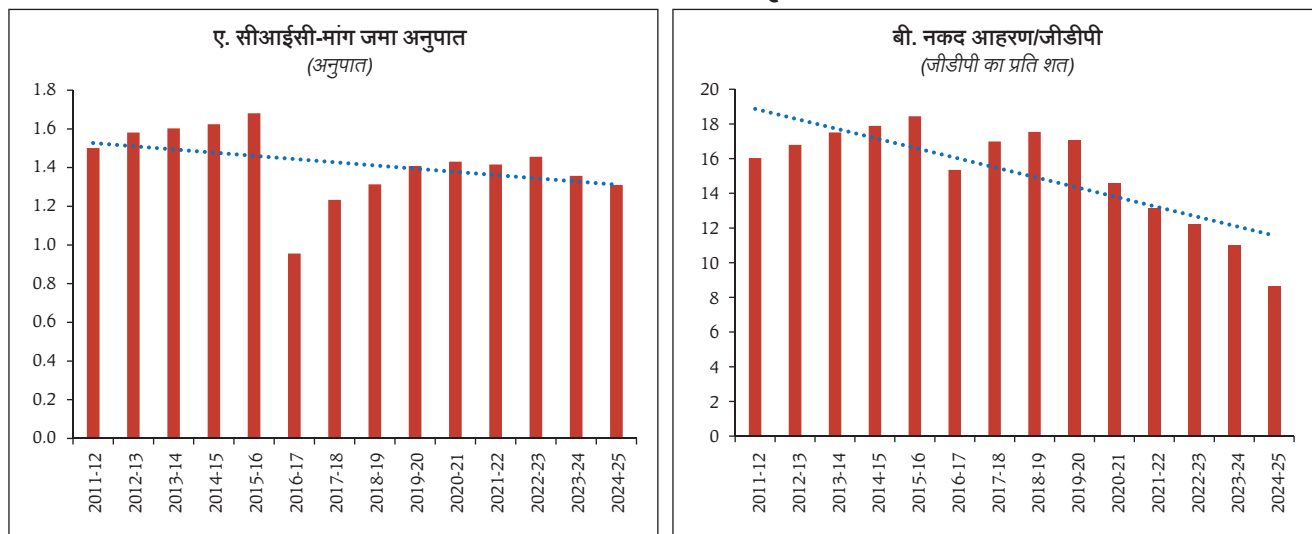
**नोट:** कुल डिजिटल भुगतान में, दूसरी बातों के साथ-साथ, वास्तविक समय सकल निपटान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, तत्काल भुगतान सेवा, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, भारत बिल भुगतान प्रणाली, कार्ड और प्रीपेड भुगतान उपकरण के तहत होने वाले लेन-देन शामिल हैं।

**स्रोत:** आरबीआई; एनएसओ।

2019-20 में 1,252 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 18,586 करोड़ हो गई। एक दशक से भी कम समय में, यूपीआई एक अग्रणी भुगतान प्रणाली बन गई है, जो प्रति माह 17 बिलियन से अधिक लेनदेन संसाधित करती है और कुल मिलाकर, 2024-25 में कुल डिजिटल भुगतान मात्रा और मूल्य का क्रमशः 84 प्रतिशत और 9 प्रतिशत हिस्सा है (सारणी 1)।

यूपीआई की मजबूत रैली इसकी खुली, तकनीक-निरपेक्ष संरचना पर आधारित है जो अनुप्रयोगों के विकास, उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल डिज़ाइन को सुगम बनाती है और डिजिटल जागरूकता बढ़ाती है (ऑराज़ो एट अल., 2024)। कम मूल्य के दैनिक लेन-देन के लिए यूपीआई का बढ़ता उपयोग पीयर-टू-मर्चेन्ट (पी2एम) भुगतानों की बढ़ती हिस्सेदारी, यूपीआई भुगतानों के टिकट आकार को कम करने (चार्ट 4ए) और पी2एम वॉल्यूम के

चार्ट 3: नकदी मांग में प्रवृत्तियां



**नोट:** 2024-25 के आंकड़े अनंतिम हैं। चार्ट बी में, डेटा में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से नकदी आहरण शामिल है। डॉटेड रेखा दोनों चार्ट में रेखिक प्रवृत्ति दिखाती है।

**स्रोत:** आरबीआई; एनएसओ।

सारणी 1: यूपीआई में वृद्धि

वर्ष	मात्रा (करोड़)	मूल्य (₹ लाख करोड़ रुपये)	औसत टिकट का आकार(₹)	कुल डिजिटल भुगतान मात्रा में हिस्सेदारी (प्रतिशत)	कुल डिजिटल भुगतान मूल्य में हिस्सेदारी (प्रतिशत)
2016-17	2	0.1	3867	0.2	0.0
2017-18	92	1.1	1200	6.3	0.1
2018-19	539	9	1627	23.2	0.5
2019-20	1,252	21	1703	36.8	1.3
2020-21	2,233	41	1838	51.1	2.9
2021-22	4,596	84	1831	63.8	4.8
2022-23	8,371	139	1662	73.5	6.7
2023-24	13,113	200	1525	79.7	8.2
2024-25	18,586	261	1404	84	9

नोट: औसत टिकट आकार (₹) की गणना = ((मूल्य/मात्रा)\*1,00,000) के रूप में की जाती है।

स्रोत: आरबीआई, एनपीसीएल।

बड़े हिस्से का 500 रुपये से कम मूल्य बैंड के भीतर आने से स्पष्ट है (चार्ट 4बी)।

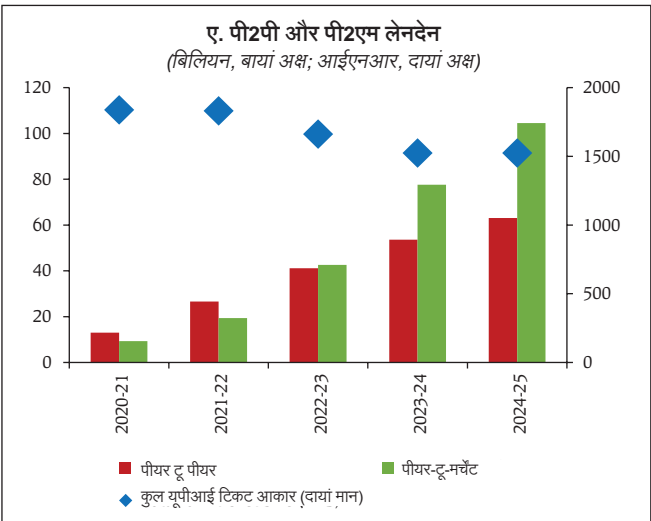
III.2. भुगतान विकल्प में राज्य-स्तरीय अंतर्दृष्टि

राज्य-स्तरीय विश्लेषण से आय और संरचनात्मक कारकों द्वारा आकार लेने वाले क्षेत्रीय विविधताओं का पता चलता है। एटीएम निकासी पर विस्तृत डेटा की अनुपलब्धता के कारण, नकदी का उपयोग मुद्रा तिजोरी से आहरण द्वारा किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रबंधित क्षेत्रीय भंडार हैं। चूँकि सभी नए जारी किए गए नोट इन तिजोरियों

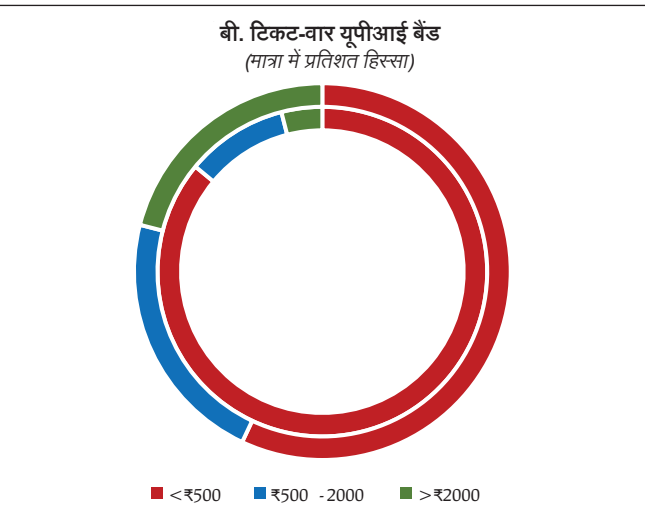
से होकर गुजरते हैं, इसलिए माना जाता है कि उनके आहरण का स्वरूप जनता की नकदी की माँग को दर्शाता है। औसतन, एटीएम से (डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से) वार्षिक नकद आहरण और मुद्रा तिजोरी से नकद आहरण का हिस्सा 2024-25 में 80 प्रतिशत है।

अलग-अलग यूपीआई डेटा के अभाव में, इस अध्ययन में फोनपे (पल्स) के डेटा का उपयोग किया है, जो एक भुगतान सेवा प्रदाता है तथा कुल यूपीआई लेनदेन मात्रा के 58 प्रतिशत और मूल्य के 53 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है (चार्ट 5 ए और बी)। इस ओपन-सोर्स डेटासेट का व्यापक रूप से राज्यों और

चार्ट 4: यूपीआई लेन-देनों का संयोजन



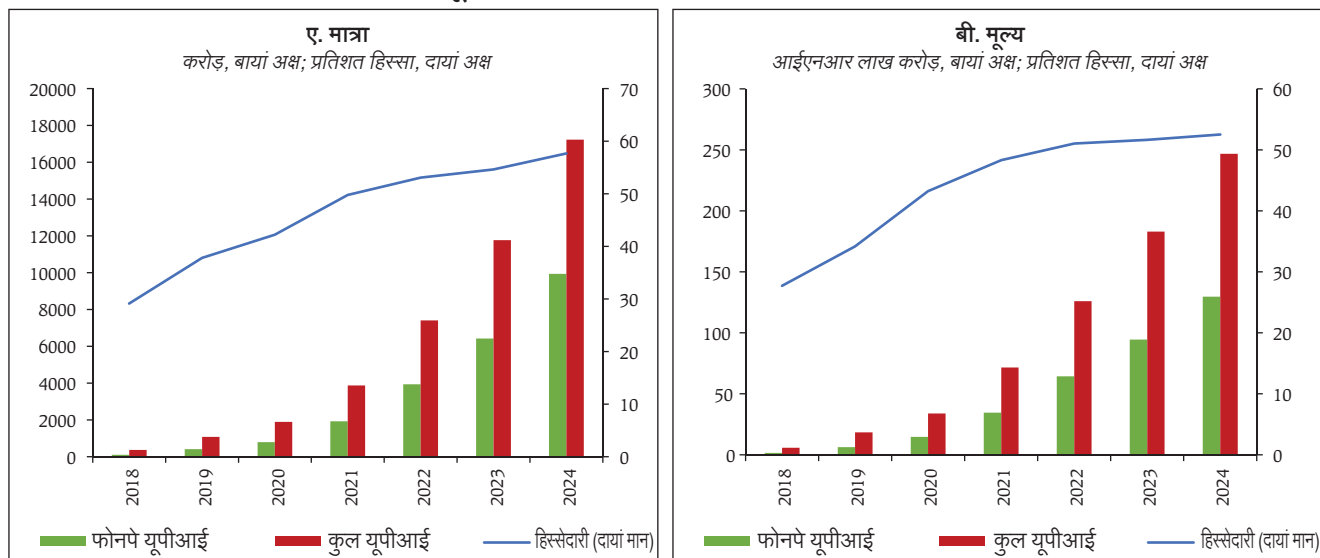
स्रोत: एनपीसीआई।



नोट: इनर और आउटर सर्कल क्रमशः पी2एम और पी2पी लेन-देनों से संबंधित हैं।

स्रोत: एनपीसीएल।

चार्ट 5: यूपीआई ओवर टाइम में फोनपे की हिस्सेदारी



स्रोत : फोनपे पल्स, एनपीसीआई, लेखकों की गणना।

जिलों में यूपीआई प्रसार की जांच करने वाले अध्ययनों में उपयोग किया गया है (दुबे और पूर्णानंदम, 2023; रेड्डी और अन्य., 2024)।

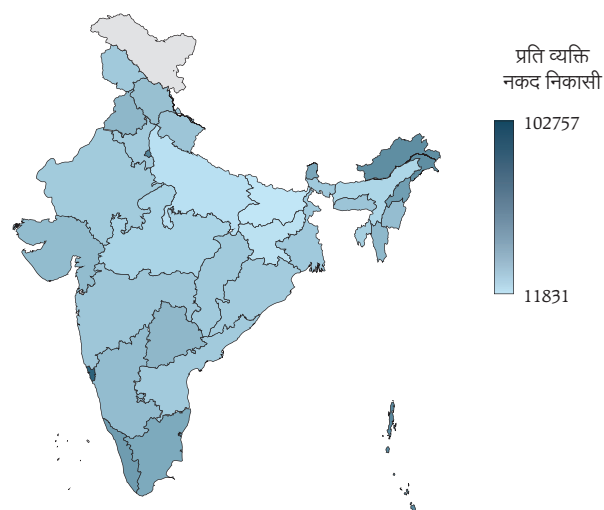
दो कारक समग्र यूपीआई गतिविधि के प्रॉक्सी के रूप में इस डेटासेट की सामान्यीकरण क्षमता का समर्थन करते हैं: सबसे पहले, फोनपे के विकास प्रक्षेपवक्र ने हाल के वर्षों में समग्र यूपीआई रुझानों को बारीकी से प्रतिबिंबित किया है, जिसमें मात्रा और मूल्य दोनों के लिए उनके वृद्धि के बीच सहसंबंध 0.99 है। दूसरा, फोनपे-आधारित राज्य-वार रैंकिंग 2024 में कुल राज्य-वार यूपीआई रैंकिंग के साथ एक मजबूत सहसंबंध प्रदर्शित करती है, जिसके लिए डेटा उपलब्ध था (आर = 0.97)। तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए, नकदी और यूपीआई दोनों संकेतक राज्य की आबादी द्वारा सामान्यीकृत किए जाते हैं, जिससे नकदी और यूपीआई तीव्रता के उपाय मिलते हैं।

नकदी लेन-देन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में व्यापक रूप से भिन्न होता है, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल और सिक्किम में प्रति व्यक्ति नकद निकासी सबसे अधिक दर्ज की गई है (चार्ट 6) जो पर्यटन और सेवा के नेतृत्व वाले नकदी उपयोग, प्रेषण प्रवाह, ग्रामीण क्षेत्रों की नकदी निर्भरता, सीमित डिजिटल बुनियादी ढांचे, पुरानी जनसांख्यिकी और सुरक्षा बाधाओं जैसे कारकों को दर्शाता है। हाल के रुझान

दर्शाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अधिकांश राज्यों में नकदी के उपयोग में व्यापक और निरंतर गिरावट आई है, जो अस्थायी बदलाव के बजाय संरचनात्मक बदलाव का संकेत देती हैं।

डिजिटल मोर्चे पर, फोनपे लेनदेन द्वारा प्रदर्शित यूपीआई तीव्रता, प्रति व्यक्ति मात्रा के संदर्भ में तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में उच्च बनी हुई है, जो शहरी केंद्रों, आर्थिक केंद्रों और उच्च रोजगार-संचालित प्रवासन वाले क्षेत्रों

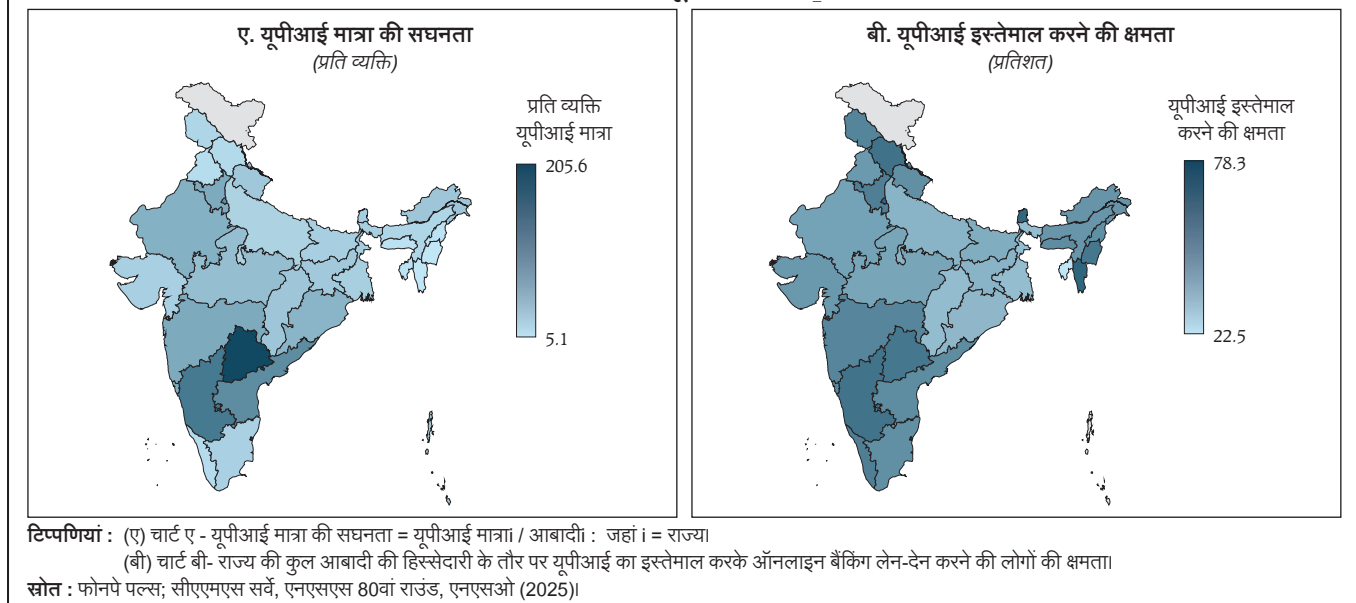
चार्ट 6: वित्तीय वर्ष 2024-25 में नकदी आहरण की सघनता (प्रति व्यक्ति)



नोट : नकदी सघनता = नकदी आहरण / आबादी। जहाँ i = राज्या

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट 7: वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूपीआई अपनाने में राज्य-वार अंतर

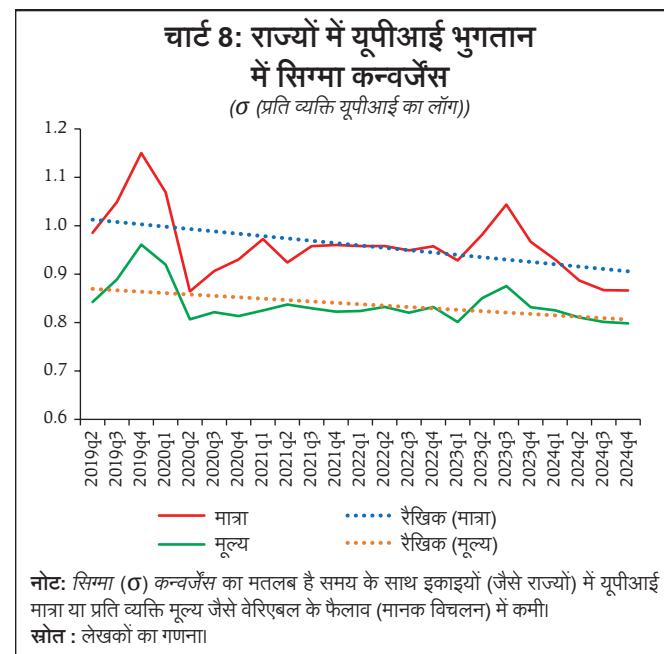


की मौजूदगी के साथ निकटता से जुड़ी हुई है (चार्ट 7ए)। इसके विपरीत, कई नकदी-निर्भर क्षेत्रों जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों (त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड) में यूपीआई का उपयोग मामूली बना हुआ है। एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन के लिए यूपीआई का उपयोग करने की क्षमता में अपेक्षाकृत कम अंतर-राज्यीय भिन्नता है, जिसमें दक्षिणी और उत्तरी राज्यों की ओर मामूली झुकाव है (एनएसओ, 2025)।<sup>3</sup> विशेष रूप से, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर और मिजोरम यूपीआई उपयोग संबंधी सबसे अधिक रिपोर्ट करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। (चार्ट 7बी)।

संवृद्धि के संदर्भ में, अधिकांश राज्यों ने महामारी के बाद (वित्त वर्ष: 2022) यूपीआई अपनाने में उछाल देखा है। यद्यपि यूपीआई भुगतान का समग्र प्रक्षेपवक्र राज्यों में सकारात्मक बना हुआ है, महामारी वर्ष के उच्च आधार प्रभाव और अधिक स्थिर, स्व-प्रेरित अधिग्रहण वक्र की ओर संक्रमण के कारण विकास की गति धीमी हो गई है।

<sup>3</sup> ये अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण के व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण - दूरसंचार, 29 मई, 2025 को जारी 80वें दौर के इकाई स्तर के आंकड़ों पर आधारित हैं। सर्वेक्षण प्रश्नावली में व्यक्तिगत उत्तरदाताओं से पूछा गया एक विशिष्ट प्रश्न शामिल है: "क्या कंप्यूटर या मोबाइल जैसे उपकरणों के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन करने में सक्षम हैं?" प्रतिक्रिया विकल्प हैं: (i) हाँ, केवल यूपीआई के माध्यम से; (ii) हाँ, केवल नेट बैंकिंग या अन्य माध्यमों (यूपीआई को छोड़कर) के माध्यम से; (iii) हाँ, यूपीआई और अन्य दोनों माध्यमों से; और (iv) नहीं।

हालाँकि, यूपीआई का उपयोग संकेंद्रित बना हुआ है, शीर्ष 10 राज्यों में कुल लेनदेन की मात्रा का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है एक ऐसा पैटर्न जो समय के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। फिर भी, राज्यों में यूपीआई अपनाने के विस्तार में गिरावट की प्रवृत्ति 2020 से सिग्मा ( $\sigma$ ) अभिसरण के मजबूत होने से स्पष्ट है, यद्यपि एक धीमी गति से (चार्ट 8)। यह धीमा अभिसरण डिजिटल बुनियादी ढांचे, औपचारिकता की सीमा, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, और राज्यों में व्यापारी स्वीकृति में विविधता को दर्शा सकता है।



#### IV. आँकड़े और कार्यप्रणाली

राष्ट्रीय स्तर पर, नाममात्र और वास्तविक रूप में नकदी माँग पर यूपीआई के प्रभाव का आकलन करने के लिए 2009 की दूसरी तिमाही से 2024 की चौथी तक के तिमाही आँकड़ों का उपयोग करके एक ऑटो-रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग (एआरडीएल) मॉडल का अनुमान लगाया जाता है।<sup>4</sup> प्रमुख निर्धारकों में जीडीपी, जमा दरें (प्रमुख बैंकों की एक वर्ष की निचली सीमा द्वारा प्रॉक्सी), प्रचलन में उच्च-मूल्य वाले नोटों का हिस्सा<sup>5</sup> (स्टोर-ऑफ-वैल्यू प्रॉक्सी), और यूपीआई लेनदेन की मात्रा (प्रतिस्थापन प्रभाव)<sup>6</sup> शामिल हैं, जिससे लेनदेन, एहतियाती और सट्टा उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। उच्च मूल्य वाले नोटों के हिस्से को नियंत्रित करने से सीआईसी पर यूपीआई के प्रभाव को अलग करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि उच्च-मूल्य वाले लेनदेन मुख्य रूप से छोटे-मूल्य वाले यूपीआई भुगतानों द्वारा संचालित रुझानों को बिगाड़ सकते हैं। चुनी गई नमूना अवधि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (2007) के बाद संरचनात्मक बदलाव को दर्शाती है और वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव को कम करती है। ब्याज दरों को छोड़कर, सभी चर मौसमी रूप से समायोजित और लॉग-रूपांतरित हैं। ओगमेंटेड डिकी-फुलर (एडीएफ) परीक्षण का उपयोग करके स्थिरता जाँच से पुष्टि होती है कि सभी श्रृंखलाएँ  $I(0)$  या  $I(1)$  हैं, जो एआरडीएल ढाँचे को मान्य करती हैं। 2016 में निर्दिष्ट बैंक नोटों की वापसी और कोविड-19 लॉकडाउन सहित प्रमुख झटकों को त्रैमासिक डमी के माध्यम से दर्ज किया गया है।<sup>7</sup>

समष्टि-स्तरीय अंतर्दृष्टि के आधार पर, राज्य स्तर पर नकदी निर्धारकों का विश्लेषण निश्चित-प्रभाव<sup>8</sup> पैरल क्वांटाइल रिग्रेशन का उपयोग करके 31 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2019 की दूसरी तिमाही से 2025 की पहली तिमाही की

अवधि में नकदी वितरण के 25वें, 50वें और 75वें प्रतिशतक पर किया है। मॉडल अप्रत्याशित राज्य-विशिष्ट विविधता और समय प्रभावों के लिए जिम्मेदार है। 2019 से शुरू होने वाली नमूना अवधि, उस चरण को पकड़ती है जिसके दौरान यूपीआई ने गति प्राप्त की। आय समूहों में विविधता की जांच करने के लिए, निम्न, मध्यम और उच्च आय वाले राज्यों के लिए अलग-अलग पैरल प्रतिगमन का अनुमान लगाया जाता है, जो निवल राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान मूल्य) के 25वें, 50वें और 75वें प्रतिशत पर स्तरीकृत हैं।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नकद मांग को त्रैमासिक मुद्रा तिजोरी आहरण और फोनपे लेनदेन डेटा द्वारा यूपीआई अपनाने से मापा जाता है। त्रैमासिक उप-राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अभाव में, आर्थिक गतिविधि को VIIRS VNP46A2 नाइट टाइम लाइट्स का उपयोग करके प्रदर्शित किया जाता है, जो 1~500-मीटर स्थानिक रिज़ॉल्यूशन पर कृत्रिम (मानव-जनित) रोशनी के दैनिक माप प्रदान करता है। त्रैमासिक राज्य-स्तरीय समुच्चयों की गणना "गैप फिल्ड डीएनबी बीआरडीएफ करेक्टेड नाइटटाइम लाइट्स" बैंड के योग के रूप में की जाती है, जिसमें राज्य की सीमाओं पर क्षेत्रीय सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है, जिससे किसी भी उच्च-आवृत्ति अस्थिरता को समाप्त किया जाता है। इस डेटा का उपयोग व्यापक रूप से उत्पादन और विकास का अनुमान लगाने के लिए किया गया है, विशेष रूप से डेटा-दुर्लभ भौगोलिक स्तरों में, और अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधि को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए (लाहिड़ी, 2020; बेयर एट अल., 2022; माथेन एट अल., 2024)। अन्य नियंत्रण चर में एटीएम घनत्व (वित्तीय अवसंरचना), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) शुद्ध पेट्रोल परिवर्धन (औपचारिकीकरण), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की उच्च-माध्यमिक स्तर (साक्षरता) से नीचे की शैक्षिक प्राप्ति, और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की इंटरनेट सदस्यता (डिजिटल अवसंरचना) शामिल हैं। इंटरनेट ग्राहकों और शिक्षा प्राप्ति के स्तर को छोड़कर सभी चर राज्य की जनसंख्या द्वारा सामान्यीकृत और लॉग-रूपांतरित हैं। वर्ष के निश्चित प्रभाव व्यापक समष्टि आर्थिक रुझानों को नियंत्रित करते

<sup>4</sup> निम्नलिखित दीर्घकालीन समीकरण का अनुमान लगाया गया है:  $\ln(CIC_t) = \psi_0 + \psi_1 \ln(GDP_t) + \psi_2 INT_t + \psi_3 HDN_t + \psi_4 \ln(1 + UPI_t) + \mu_t$ , where  $\psi_k$ , जहाँ  $\psi_k$  दीर्घकालीन गुणांक हैं।

<sup>5</sup> उच्च मूल्यवर्ग के नोटों में ₹500, ₹1000 (उनके बंद होने से पहले) और ₹2000 के नोट शामिल हैं।

<sup>6</sup> चूंकि 2016 से पहले की अवधि के लिए यूपीआई डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए लॉग (1 + वास्तविक यूपीआई लेनदेन) का उपयोग चर के रूप में किया जाता है। यह चर 2016 से पहले की तिमाहियों के लिए स्थिर रहता है, जिससे अनुमान प्रभावित नहीं होता है।

<sup>7</sup> मई 2023 में ₹2000 के नोटों की वापसी के लिए एक डमी मॉडल को शुरू में शामिल किया गया था, लेकिन यह महत्वहीन पाया गया और इसलिए इसे अंतिम मॉडल से बाहर रखा गया। यह प्रभाव संभवतः उच्च-मूल्य वाले नोटों के हिस्से के चर द्वारा समाहित हो गया होगा, जो संभवतः मुख्य प्रतिगमन में इसकी व्याख्यात्मक शक्ति का कारण है।

<sup>8</sup> हॉसमैन परीक्षण यादृच्छिक प्रभावों की तुलना में स्थिर प्रभाव मॉडल के उपयोग को मान्य करता है।



हैं<sup>१०</sup> जबकि त्योहारों, राज्य चुनावों और कोविड-19 जैसे अंतर-वर्षीय आघात तिमाही डमी के माध्यम से शामिल किए जाते हैं। हालांकि ये प्रतिगमन अनुमान जरूरी नहीं कि कार्य-कारण का संकेत दें, वे इन कारकों की भयावहता पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अंतर्राज्यीय सारांश आँकड़े और सहसंबंध हीटमैप अनुबंध I में दिए गए हैं।

## V. नकदी माँग पर यूपीआई का प्रभाव: अनुभवजन्य साक्ष्य

### V.1. राष्ट्रीय स्तर की अंतर्दृष्टि

यूपीआई मात्रा, नाममात्र और वास्तविक दोनों ही रूपों में, सभी मॉडलों में नकदी की मांग के साथ ऋणात्मक रूप से संबद्ध है, जो नकदी के विकल्प के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करती है (सारणी 2)। आय (जीडीपी) 0.79 से 0.86 तक की लोच के साथ नकदी की मांग के प्राथमिक निर्धारक के रूप में उभरती है, जो आर्थिक गतिविधि और नकदी उपयोग के बीच एक सकारात्मक संबंध को दर्शाती है। जमा ब्याज दरें एक ऋणात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, जो नकदी रखने की अवसर लागत को दर्शाती है। इसके विपरीत, उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का हिस्सा एक छोटा लेकिन सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है, जो इसके स्टोर-ऑफ-वैल्यू (मॉडल 2) के अनुरूप है। अनुमान-पश्चात निदान 5 प्रतिशत के स्तर पर क्रमिक स्व-सहसंबंध और विषमता (हेटेरोस्केडैस्टिसिटी) के अभाव की पुष्टि करता है। त्रुटि सुधार गुणांक, जो उस गति को दर्शाता है जिस पर अल्पकालिक विचलन दीर्घकालिक संतुलन में समायोजित होते हैं, वह यह दर्शाता है कि 24-30 प्रतिशत विचलन एक ही तिमाही के भीतर ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा, सीमा परीक्षण एफ-स्टैटिस्टिक महत्वपूर्ण मूल्यों की ऊपरी सीमा को पार कर जाता है, जो इन चरों के बीच दीर्घकालिक संबंध के अस्तित्व की पुष्टि करता है।

निर्दिष्ट बैंक नोट आहरण के कारण, 2016 की चौथी तिमाही और 2017 की पहली तिमाही के लिए डमी गुणांक ऋणात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है (अनुलग्नक II)। इसके अलावा, महामारी की पहली और दूसरी दोनों लहरों के लिए डमी चर सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि लॉकडाउन के दौरान मुद्रा की मांग में वृद्धि एहतियाती और स्टोर-ऑफ-वैल्यू उद्देश्यों से प्रेरित थी, जो पिछले निष्कर्षों

**सारणी 2: एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस का प्रचलन में मुद्रा पर प्रभाव**  
आश्रित चर: प्रचलन में मुद्रा का लॉग

चर	नाममात्र		वास्तविक	
	(1)	(2)	(1)	(2)
मॉडल प्रकार	एआरडीएल (3,2,0)	एआरडीएल (3,2,0,0,0)	एआरडीएल (3,2,0)	एआरडीएल (3,3,0,0,0)
आय	0.86*** (0.03)	0.83*** (0.04)	0.84*** (0.06)	0.79*** (0.10)
ब्याज दर	-0.05*** (0.01)	-0.05*** (0.01)	-0.04*** (0.01)	-0.03** (0.01)
यूपीआई मात्रा		-0.016*** (0.01)		-0.013*** (0.01)
एचडीएन शेयर		0.005*** (0.01)		0.005** (0.01)
अन्तःखंड	1.80*** (0.60)	1.96*** (0.60)	1.95* (1.03)	2.36 (1.50)
<i>सह-एकीकरण परीक्षण</i>				
सीमा परीक्षण: एफ सांख्यिकी #	89.6	134.7	283.37	318.3
त्रुटि सुधार गुणांक	-0.26*** (0.01)	-0.24*** (0.01)	-0.30*** (0.01)	-0.28*** (0.01)
<i>मॉडल टेस्ट</i>				
समायोजित आर वर्ग	0.99	0.99	0.99	0.99
एसआईसी और एआईसी	-4.73 और -5.13	-4.74 और 5.21	-4.52 और 4.91	-4.48 और 4.98
<i>अनुमान के बाद के परीक्षण</i>				
एलएम ऑटो सहसंबंध का परीक्षण: संभाव्यता	0.63	0.08	0.49	0.05
बीपीजी हेटेरोस्केडैस्टिसिटी टेस्ट: संभावना	0.91	0.85	0.73	0.79
सीयूएसयूएम और सीयूएसयूएम वर्ग स्थिरता परीक्षण	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर

**टिप्पणियाँ:** (ए) मानक त्रुटियाँ कोष्ठक में हैं। \*\*\*, \*\* और \* क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के महत्व स्तरों को दर्शाती हैं।  
(बी) सीआईसी, आय और यूपीआई प्राकृतिक लघुगणक रूपांतरित हैं। वास्तविक सीआईसी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मूल्य स्तरों के समायोजन और मुद्रा की क्रय शक्ति को दर्शाने के लिए अपस्फीतिकृत सीआईसी को संदर्भित करता है।  
(सी) मॉडल 1, यूपीआई और एचडीएन शेयर के बिना आधारभूत मॉडल है। मॉडल 2 में यूपीआई मात्रा और एचडीएन शेयर शामिल हैं।  
(डी) सभी मॉडलों में निर्दिष्ट बैंक नोटों का आहरण, कोविड-19 की पहली लहर और दूसरी लहर के लिए प्रासंगिक डमी चर हैं।  
(ई) मजबूती की जाँच के लिए, कुल डिजिटल लेनदेन में यूपीआई की हिस्सेदारी पर भी विचार किया गया, जिसका मान 2016 से पहले की अवधि के लिए शून्य है। परिणाम यूपीआई शेयर और नकदी मांग के बीच ऋणात्मक संबंध की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा, कोविड-19 रिट्रेंजेंसी सूचकांक को शामिल करने से सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव सामने आया।  
(एफ) # 5 प्रतिशत स्तर पर एफ सांख्यिकी के लिए महत्वपूर्ण मान I(0) और I(1) मान्यताओं के लिए क्रमशः लगभग 3.0 और 6.0 हैं।  
(जी) आकलन-पश्चात जाँच में, शून्य परिकल्पना एलएम परीक्षण के लिए कोई क्रमिक सहसंबंध नहीं है, और बीपीजी परीक्षण के लिए समरूपता है।

**स्रोत:** लेखकों की गणना।

के अनुरूप है (कैसवेल और अन्य., 2020; चेन और अन्य., 2020; अवस्थी और अन्य., 2022; आरबीआई, 2023।

## V.2. राज्य स्तरीय अंतर्दृष्टि

### V.2.1. कैश क्वांटाइल्स द्वारा

समग्र प्रतिगमन के अनुरूप, नाईटटाइम लाइट्स द्वारा प्रदर्शित आर्थिक गतिविधि सभी राज्यों में नकदी उपयोग के साथ एक मजबूत और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध प्रदर्शित करती है (सारणी 3, मॉडल 1)। यद्यपि नकदी मांग के सशर्त वितरण में इसका प्रभाव लगातार सकारात्मक बना रहता है, यह नकदी उपयोग के निम्न से उच्च परिमाणों में मामूली रूप से कम होता जाता है (मॉडल 2 - 4)।

प्रति व्यक्ति यूपीआई मात्रा एक ऋणात्मक और गैर-रैखिक संबंध प्रदर्शित करती है, जिसमें ऋणात्मक रैखिक अवधि के साथ एक धनात्मक वर्ग अवधि दी गई है। यह इंगित करता है कि यूपीआई उपयोग में वृद्धि, हालांकि, एक अनुमानित सीमा (प्रति व्यक्ति लॉग यूपीआई = 2.18) से परे नकदी का स्थान ले लेती है और जैसे-जैसे डिजिटल अपनाने की प्रक्रिया परिपक्व होती है, प्रतिस्थापन प्रभाव कम होता जाता है, जो संभवतः संतृप्ति या व्यवहारिक जड़ता को दर्शाता है। विभिन्न नकद क्वांटाइल्स में यूपीआई गुणांक का आरेखण ऊपरी क्वांटाइल्स में एक मजबूत प्रतिस्थापन प्रभाव दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि नकदी-प्रधान राज्यों में, डिजिटल अपनाने से नकदी के उपयोग पर एक मजबूत ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है (चार्ट 9)। यह पैटर्न उच्च प्रारंभिक नकदी निर्भरता, नीति और बाज़ार प्रयासों, और डिजिटल अपनाने में शुरुआती चरण के तेजी से सीखने के वक्रों के संयोजन को दर्शा सकता है। प्रति व्यक्ति यूपीआई मूल्य के लिए भी इसी तरह की गैर-रेखीय गतिशीलता देखी गई है (सारणी 1: अनुबंध III)।

डिजिटल अवसंरचना के प्रतिनिधि के रूप में इंटरनेट ग्राहक आधार, केवल एक कमजोर प्रभाव डालता है, जिसका औसत क्वांटाइल पर सीमावर्ती महत्व है। औपचारिकता की डिग्री नकदी की मांग के साथ एक अवतल संबंध प्रदर्शित करती है। प्रारंभिक औपचारिकता कम नकदी निर्भरता से जुड़ी है, संभवतः बैंकिंग और डिजिटल वेतन भुगतान तक बेहतर पहुंच के कारण, जो बाद

### सारणी 3: नकदी माँग पर यूपीआई मात्रा का राज्यवार प्रभाव - नकदी मात्राओं के अनुसार आश्रित चर: प्रति व्यक्ति मुद्रा तिजोरी आहरण का लॉग

चर	(1) पूर्ण नमूना	(2) 25वीं क्वांटाइल (कम नकदी)	(3) 50वीं क्वांटाइल (मध्यम नकदी)	(4) 75वीं क्वांटाइल (उच्च नकदी)
आर्थिक गतिविधि <sup>a</sup>	0.25*** (0.05)	0.29*** (0.06)	0.26*** (0.05)	0.21*** (0.06)
यूपीआई मात्रा <sup>a</sup>	-0.13** (0.05)	-0.12*** (0.03)	-0.13*** (0.03)	-0.15*** (0.04)
यूपीआई मात्रा वर्ग <sup>a</sup>	0.03*** (0.01)	0.03*** (0.00)	0.03*** (0.00)	0.03*** (0.01)
एटीएम घनत्व <sup>a</sup>	0.77** (0.29)	0.52*** (0.19)	0.76*** (0.15)	1.04*** (0.21)
औपचारिकता की डिग्री <sup>a</sup>	-0.11*** (0.03)	-0.12*** (0.03)	-0.11*** (0.03)	-0.10*** (0.04)
औपचारिकता की डिग्री का वर्ग <sup>a</sup>	0.01*** (0.00)	0.01*** (0.00)	0.01*** (0.00)	0.01*** (0.00)
शिक्षा प्राप्ति स्तर	-0.01 (0.00)	-0.00 (0.00)	-0.01** (0.00)	-0.01** (0.00)
इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस <sup>a</sup>	0.05 (0.04)	0.05 (0.04)	0.05 (0.03)	0.06 (0.05)
कोविड डमी	0.04*** (0.01)	0.05* (0.03)	0.04** (0.02)	0.04 (0.03)
राज्य चुनाव डमी	0.05*** (0.01)	0.05** (0.02)	0.05*** (0.02)	0.04* (0.02)
त्योहार डमी	0.05**	0.05***	0.05***	0.05**
अपरिवर्तनीय	17.27*** (2.40)			
वर्ष निश्चित प्रभाव	Yes	Yes	Yes	Yes
अवलोकन	688	688	688	688
आर-स्क्वेयर्ड	0.43			
एफ सांख्यिकी प्रोब > एफ	66.07			
राज्यों की संख्या	31			

**टिप्पणियाँ:** ए) कोष्ठकों में दी गई मानक त्रुटियाँ राज्यवार समूहीकृत हैं। \*\*\*, \*\* और \* क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के महत्व स्तरों को दर्शाते हैं।

बी) # चर प्रति व्यक्ति के संदर्भ में हैं और लॉग रूपांतरित हैं।

सी) @ चर तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि के संदर्भ में हैं।

डी) लद्दाख, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, सिक्किम और पुदुचेरी के लिए डेटा अनुपलब्धता के कारण, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या का नमूना आकार घटकर 31 रह गया है।

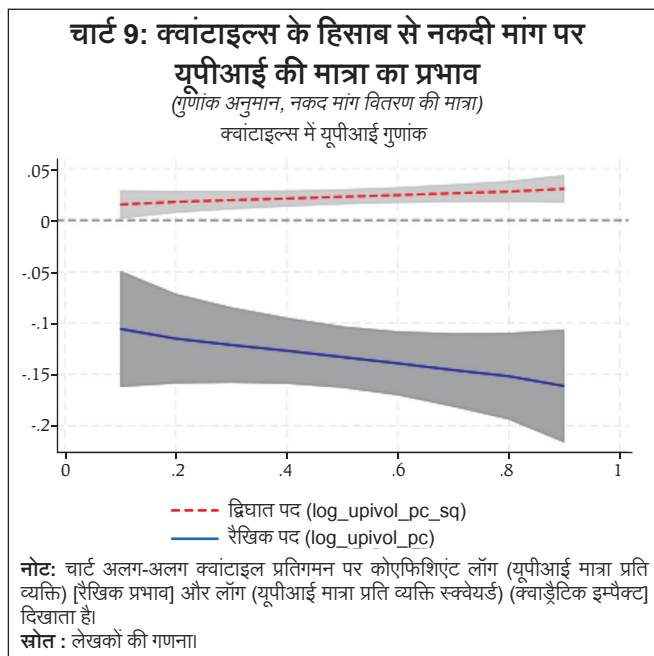
ई) ये परिणाम वर्ष के निश्चित प्रभावों को नियंत्रित करते हैं।

एफ) राज्यवार औपचारिकता की मात्रा की गणना जनसंख्या के लिए समायोजित ईपीएफओ के अंतर्गत निवल वेतन वृद्धि के लॉग के रूप में की जाती है।

जी) यद्यपि राज्यवार सीपीआई को नियंत्रण के रूप में शामिल किया गया था, यह सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन पाया गया, संभवतः इसके प्रभाव को आर्थिक गतिविधि और समग्र रूप से सीमित अंतर-राज्य भिन्नता के कारण अवशोषित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या प्रॉक्सी पर भी विचार किया गया; हालाँकि, चूंकि ये 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें निश्चित-प्रभाव पैनल प्रतिगमन से बाहर रखा गया।

**स्रोत:** लेखकों की गणना।





में कम हो जाती है (औपचारिकता की डिग्री का लॉग = 5.8)। यह पैटर्न बताता है कि अनौपचारिक क्षेत्र अधिक नकदी-प्रधान बना हुआ है, जिसमें डिजिटल भुगतान अपनाने की इच्छा कम है (लिगॉन और अन्य., 2019), संभवतः यह औपचारिक वित्तीय नेटवर्क के साथ सीमित एकीकरण के कारण है (लाहिड़ी, 2020)। इसके अलावा, कम से कम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त जनसंख्या के उच्च अनुपात वाले राज्य मध्य और ऊपरी क्वांटाइल पर कम नकदी मांग दिखाते हैं, जो शिक्षा और डिजिटल विकल्पों के बीच सकारात्मक संबंध को दर्शाते हैं। संरचनात्मक झटके, कोविड-19, राज्य चुनाव, त्यौहार और शादी का मौसम जैसी नीतिगत और मौसमी घटनाएं सभी सकारात्मक और महत्वपूर्ण रूप से वितरण में नकदी की मांग में वृद्धि के साथ जुड़ी हुई हैं, जो राज और अन्य., (2020) के अनुसार इसकी प्रासंगिक और एहतियाती प्रकृति की पुष्टि करती हैं।

#### V.2.2. आय समूहों के द्वारा

यद्यपि यूपीआई अपनाने में आय समूहों के बीच एक गैर-रैखिक संबंध प्रदर्शित होता है, मध्यम-आय वाले राज्य सबसे प्रबल प्रतिस्थापन लोच प्रदर्शित करते हैं, जो दर्शाता है कि विद्यमान डिजिटल परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण विभक्ति बिन्दु पर हैं (सारणी 4)। सभी आय समूहों में आर्थिक गतिविधि नकदी की मांग

से सकारात्मक रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन उच्च-आय वाले राज्यों में इसका परिमाण अधिक है। एटीएम घनत्व अधिक समृद्ध राज्यों की तुलना में केवल निम्न-आय वाले राज्यों में अधिक नकदी

**सारणी 4: नकदी मांग पर यूपीआई मात्रा का राज्यवार प्रभाव - आय समूहों के अनुसार**  
आश्रित चर: प्रति व्यक्ति मुद्रा तिजोरी आहरण का लॉग

	(1)	(2)	(3)
चर	निम्न आय वाले राज्य	मध्यम आय वाले राज्य	उच्च आय वाले राज्य
आर्थिक गतिविधि <sup>#</sup>	0.26*** (0.07)	0.22** (0.09)	0.41*** (0.10)
यूपीआई मात्रा <sup>#</sup>	-0.15* (0.08)	-0.22*** (0.06)	-0.08* (0.05)
यूपीआई मात्रा वर्ग <sup>#</sup>	0.05** (0.02)	0.04*** (0.01)	0.01* (0.01)
एटीएम घनत्व <sup>#</sup>	1.22** (0.54)	0.45 (0.31)	0.58 (0.43)
औपचारिकता की डिग्री <sup>#</sup>	-0.06 (0.08)	-0.09*** (0.02)	-0.16 (0.13)
औपचारिकता की डिग्री का वर्ग <sup>#</sup>	0.01 (0.01)	0.01*** (0.00)	0.01 (0.01)
शिक्षा प्राप्ति स्तर	-0.01* (0.01)	0.01 (0.01)	-0.01** (0.00)
इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस <sup>@</sup>	0.07 (0.06)	0.01 (0.02)	0.05 (0.21)
कोविड डमी	0.04* (0.02)	0.03 (0.03)	0.02 (0.02)
राज्य चुनाव डमी	0.03 (0.03)	0.06** (0.03)	0.01 (0.02)
त्योहार डमी	0.03 (0.02)	0.08 (0.05)	0.08** (0.03)
अपरिवर्तनीय	21.50*** (4.88)	13.47*** (2.10)	16.52*** (3.46)
वर्ष निश्चित प्रभाव	Yes	Yes	Yes
अवलोकन	244	235	209
आर-स्क्वेयर्ड	0.50	0.54	0.50
राज्यों की संख्या	14	15	11

**टिप्पणियाँ:** (ए) निम्न, मध्यम और उच्च आय वाले राज्य निचले राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान मूल्य) के क्रमशः 25वें, 50वें और 75वें प्रतिशतक से संबंधित हैं।

(बी) कोष्ठकों में मानक त्रुटियाँ राज्यवार समूहीकृत हैं। \*\*\*, \*\* और \* क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के महत्व स्तरों को दर्शाती हैं।

(सी) # चर प्रति व्यक्ति और लॉग रूपांतरित हैं।

(डी) @ चर तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि के संदर्भ में हैं।

(ई) लद्दाख, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, सिक्किम और पुदुचेरी के लिए डेटा अनुपलब्धता के कारण, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नमूना आकार घटाकर 31 कर दिया गया है।

(एफ) ये परिणाम वर्ष के स्थिर प्रभावों को नियंत्रित करते हैं।

**स्रोत:** लेखकों की गणना।

उपयोग से जुड़ी है, जो पारंपरिक पहुँच बिंदुओं पर उनकी निरंतर निर्भरता को रेखांकित करता है। कार्यबल का औपचारिकीकरण केवल मध्यम-आय वाले राज्यों में और वह भी एक सीमा तक नकदी उपयोग से ऋणात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा स्तर निम्न और उच्च आय वाले राज्यों में कम नकदी मांग से जुड़ा हुआ है। प्रति व्यक्ति यूपीआई मूल्यों के लिए भी इसी तरह के परिणाम सामने आते हैं (अनुलग्नक III, सारणी 2)।

## VI. निष्कर्ष

यह अध्ययन भारत में नकदी की मांग पर यूपीआई के प्रभाव की जांच करता है। ऑटोरिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग मॉडल और पैनल क्वांटाइल रीग्रेशन की दोहरी अनुभवजन्य रणनीति का उपयोग करते हुए, आलेख में पाया गया है कि राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर यूपीआई का अधिक उपयोग कम नकदी की मांग से जुड़ा है। समग्र स्तर पर, वर्णनात्मक रुझान भारत के भुगतान परिदृश्य में एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत देते हैं, जो महामारी के स्तर से धीमी हुई मुद्रा वृद्धि और कम होते टिकट आकार के साथ यूपीआई के निरंतर विस्तार से स्पष्ट है। अनुभवजन्य रूप से, जीडीपी द्वारा प्रदर्शित आय, नकदी की मांग से सकारात्मक रूप से जुड़ी है, जबकि यूपीआई और ब्याज दरें ऋणात्मक प्रभाव प्रदर्शित करती हैं।

राज्य-स्तर पर, फ़ोनपे लेनदेन द्वारा प्रदर्शित नकदी और यूपीआई के बीच प्राथमिकताएँ क्षेत्रीय भिन्नता दर्शाती हैं। यूपीआई को जल्दी अपनाने वाले राज्यों ने कुल यूपीआई भुगतानों में एक प्रमुख हिस्सेदारी बरकरार रखी है, हालाँकि, महामारी के बाद से राज्यों में नकदी की मांग में आई व्यापक गिरावट और यूपीआई अपनाने में अंतर-राज्यीय असमानताओं में कमी, अभिसरण के शुरुआती संकेतों की ओर इशारा करती है। अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि यूपीआई अपनाने और नकदी की माँग के बीच एक ऋणात्मक और गैर-रेखीय संबंध है। हालाँकि यूपीआई काफी हद तक नकदी का विकल्प है, लेकिन संभवतः संतृप्ति या व्यवहारिक जड़ता के कारण डिजिटल अपनाने के परिपक्व होने के साथ इसका प्रभाव कम होता जाता है, नाईटटाइम से लाइट्स प्रदर्शित आय और एटीएम घनत्व नकदी की मांग से सकारात्मक

रूप से जुड़े हैं, जबकि कार्यबल का औपचारिकीकरण और उच्च शिक्षा प्राप्ति कम नकदी निर्भरता से जुड़ी हैं। आय-समूह-वार पृथक्करण दर्शाता है कि मध्यम-आय वाले राज्य सबसे मजबूत प्रतिस्थापन लोच प्रदर्शित करते हैं, जबकि निम्न-आय वाले राज्य बेहतर साक्षरता और अधिक कार्यबल औपचारिकीकरण के माध्यम से अप्रयुक्त प्रतिस्थापन क्षमता को उजागर कर सकते हैं।

ये निष्कर्ष बताते हैं कि सभी के लिए एक जैसा दृष्टिकोण यूपीआई को अपनाने और निरंतर उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। प्रत्येक राज्य के जनसांख्यिकीय, अवसंरचनात्मक और व्यवहारिक संदर्भ के साथ संरेखित क्षेत्र-विशिष्ट लक्षित हस्तक्षेप प्रभावी होने की संभावना है। डिजिटल अवसंरचना और वित्तीय साक्षरता हस्तक्षेपों का विस्तार, डिजिटल वेतन अंतरण को प्रोत्साहित करना और डिजिटल माध्यमों में विश्वास का निर्माण, पूरे स्पेक्ट्रम में नकदी-से-यूपीआई संक्रमण को तेज कर सकता है।

## संदर्भ:

- Aguilar, A., Frost, J., Guerra, R., Kamin, S., and Tombini, A. (2024). Digital Payments, Informality and Economic Growth. *BIS Working Papers No. 1196*.
- Alvarez, F., and Lippi, F. (2009). Financial Innovation and the Transactions Demand For Cash. *Econometrica*, 77(2), 363-402.
- Ardizzi, G., Nobili, A., and Rocco, G. (2020). A Game Changer in Payment Habits: Evidence from Daily Data during a Pandemic. *Bank of Italy Occasional Paper*, 591.
- Aurazo, J., and Franco, C. (2024). Fast Payment Systems and Financial Inclusion. *BIS Quarterly Review*, p 41.
- Awasthy, S., Misra, R., and Dhal, S. (2022). Cash versus Digital Payment Transactions in India: Decoding the Currency Demand Paradox. *Reserve Bank of India Occasional Papers*, 43(2), 1-45.

- Bachas, P., Gertler, P., Higgins, S., and Seira, E. (2018). Digital Financial Services Go a Long Way: Transaction Costs and Financial Inclusion. *AEA Papers and Proceedings* Vol. 108, pp. 444-448.
- Bailey, A. (2009). Banknotes in Circulation—Still Rising. What Does this Mean for the Future of Cash?. In *Speech at the Banknote 2009 Conference, Washington DC* (Vol. 6).
- Baumol, W. J. (1952). The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach. *The Quarterly Journal of Economics*, 66 (4), 545–556.
- Bech, M. L., Faruqui, U., Ougaard, F., and Picillo, C. (2018). Payments are a-changin' But Cash Still Rules. *BIS Quarterly Review, March*, 67–80.
- Beyer, R. C., Hu, Y., and Yao, J. (2022). Measuring Quarterly Economic Growth from Outer Space. *IMF Working Paper 22/109*.
- Bhattacharya, K., and Singh, S. K. (2016). Impact of Payment Technology on Seasonality of Currency in Circulation: Evidence from the USA and India. *Journal of Quantitative Economics* 14, 117–36.
- Cantú, C., Frost, J., Goel, T., and Prenio J. (2024). From Financial Inclusion to Financial Health. *BIS Bulletin* no. 85.
- Caswell, E., Smith, H., Learmonth, D., and Pearce, G. (2020). Cash in the Time of Covid. *Bank of England Quarterly Bulletin, Q4*.
- Chaudhari, Dipak R, Sarat Dhal, and Sonali M Adki (2019). Payment Systems Innovation and Currency Demand in India: Some Applied Perspectives. *Reserve Bank of India Occasional Papers*, 40 (2): 33–63.
- Chen, H., Engert, W., Huynh, K., Nicholls, G., Nicholson, M., and Zhu, J. (2020). Cash and COVID-19: The Impact of the Pandemic on the Demand for and Use of Cash. *Bank of Canada Staff Discussion Paper 2020-6*.
- Columba, F. (2009). Narrow Money and Transaction Technology: New Disaggregated Evidence. *Journal of Economics and Business*, 61(4), 312-325.
- Dubey, T. S., and Purnanandam, A. (2023). Can Cashless Payments spur Economic Growth?. *Available at SSRN, 4373602*.
- Fisher, I. (1911). The Purchasing Power of Money, its Determination and Relation to Credit, Interest and the Crises. *Macmillan*.
- Friedman, M. (1956). The Quantity Theory of Money: A Restatement. *Ch. 1 in Studies in the Quantity Theory of Money, ed. by Milton Friedman (Chicago University Press, 1956)*, 3-21.
- Friedman, B. M. (1999). The Future of Monetary Policy: The Central Bank as an Army with only a Signal Corps?. *International Finance*, 2(3), 321-338.
- Huynh, K. P., Schmidt-Dengler, P., and Stix, H. (2014). The Role of Card Acceptance in the Transaction Demand For Money. *Bank of Canada Working Paper No. 14-44*.
- Keynes, J. M. (1954). The General Theory of Employment, Interest, and Money: By John Maynard Keynes. *Macmillan*.
- Lahiri, A. (2020). The Great Indian Demonetization. *Journal of Economic Perspectives*, 34(1), 55-74.
- Ligon, E., Malick, B., Sheth, K., and Trachtman, C. (2019). What Explains Low Adoption Of Digital Payment Technologies? Evidence From Small-Scale Merchants in Jaipur, India. *PloS one*, 14(7), e0219450.
- Mathen, C. K., Chattopadhyay, S., Sahu, S., and Mukherjee, A. (2024). Which Nighttime Lights Data Better Represent India's Economic Activities and Regional Inequality?. *Asian Development Review*, 41(02), 193-217.
- Nachane, DM, AB Chakraborty, AK Mitra, and S Bordoloi (2013). Modelling Currency Demand in

India: An Empirical Study. *Reserve Bank of India Discussion Paper* 39.

National Payments Corporation of India (2020). Digital Payments Adoption in India, 2020. *NPCI-PRICE Report*.

National Statistics Office. (2025). Comprehensive Modular Survey – Telcom, NSS 80<sup>th</sup> Round. May 29, 2025.

Oyelami, L. O., and Yinusa, D. O. (2013). Alternative Payment Systems Implication for Currency Demand and Monetary Policy in Developing Economy: A Case Study of Nigeria. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(20), 253–260.

Raj, J., Bhattacharyya, I., Behera S.R., John, J., and Talwar, B.A. (2020). Modelling and Forecasting Currency Demand in India: A Heterodox Approach. *Reserve Bank of India Occasional Papers* 41 (1), 1–45.

Reddy, A., Kedia, M., and Shukla, S. Diffusion of Digital Payments in India - Insights based on Data from PhonePe Pulse. *Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER) Working Paper*. March 2024.

Reserve Bank of India (RBI). (2023). Annual Report 2022-23.

Reserve Bank of India (RBI). (2024). Report on Currency and Finance – India's Digital Revolution.

Reserve Bank of India (RBI). (2025). Payments Systems Data. Accessed June 2025.

Tobin, James (1956). "The Interest Elasticity of the Transactions Demand for Cash". *Review of Economics and Statistics*. 38 (3), 241–247.

Udupa, G., Bhuyan P., Verma D.K., and Kulkarni N. (2025). Economic Activity and Banknotes: New Approaches. *RBI May 2025 Bulletin*.

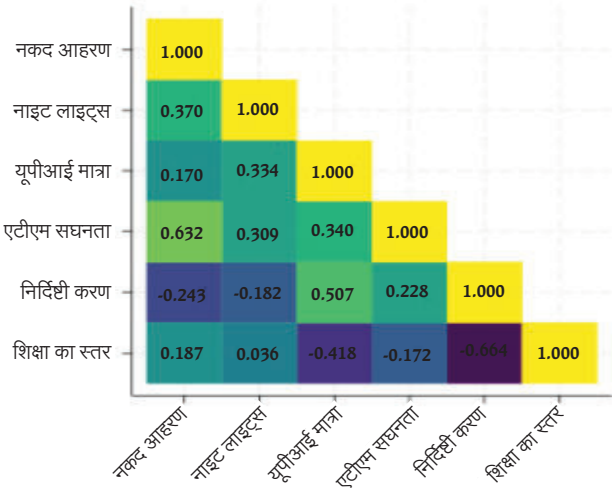
अनुलग्नक I

सारणी 1: चुनिंदा चरों की राज्यवार सारांश सांख्यिकी

चर	प्रकार	औसत	मानक विचलन	न्यूनतम	अधिकतम	अवलोकन
नकद आहरण	कुल मिलाकर	9.06	0.66	5.34	10.56	792
	के बीच		0.54	7.85	10.19	33
	भीतर		0.38	6.56	10.31	24
नाइट टाइम लाइट्स (आर्थिक गतिविधि)	कुल मिलाकर	-4.38	0.49	-5.68	-2.40	792
	के बीच		0.44	-5.25	-2.98	33
	भीतर		0.23	-5.13	-3.80	24
यूपीआई	कुल मिलाकर	1.04	1.48	-3.30	4.45	792
	के बीच		0.92	-0.75	3.00	33
	भीतर		1.17	-2.39	3.48	24
एटीएम	कुल मिलाकर	-8.49	0.52	-9.64	-7.30	792
	के बीच		0.52	-9.55	-7.33	33
	भीतर		0.06	-8.72	-8.30	24
औपचारिकता	कुल मिलाकर	9.85	2.52	1.39	13.78	718
	के बीच		2.48	4.53	13.35	31
	भीतर		0.62	3.66	12.41	24
शिक्षा का स्तर	कुल मिलाकर	66.88	8.37	49.70	87.10	792
	के बीच		8.24	53.70	85.34	33
	भीतर		2.05	57.47	73.26	24
इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस ग्रोथ	कुल मिलाकर	0.02	0.12	-0.68	2.14	759
	के बीच		0.01	-0.01	0.07	33
			0.12	-0.73	2.09	23

टिप्पणी: शिक्षा और इंटरनेट ग्राहकों को छोड़कर, सभी चर प्रति व्यक्ति के संदर्भ में हैं और लॉग रूपांतरित हैं।  
स्रोत: लेखकों की गणना।

चार्ट 1: चुनिंदा चरों का सह-संबंध हीट मैप



नोट : शिक्षा को छोड़कर, ये सभी चर आबादी और लॉग परिवर्तन द्वारा सामान्यीकृत किए गए हैं।  
स्रोत : लेखकों की गणना।

## अनुलग्नक II

**सारणी 1: भारत में मुद्रा की मांग के अल्पकालिक चालक**  
 आश्रित चर: एलसीआईसी (संचलन में मुद्रा का लॉग)

	नाममात्र		वास्तविक	
	(1)	(2)	(1)	(2)
<b>मॉडल प्रकार</b>	एआरडीएल (3,2,0)	एआरडीएल (3,2,0,0,0)	एआरडीएल (3,2,0)	एआरडीएल (3,2,0,0,0)
	(a)	(b)	(a)	(b)
डी (एलसीआईसी) (-1)	-0.23*** (0.02)	-0.26*** (0.02)	-0.20*** (0.03)	-0.25*** (0.02)
डी (एलसीआईसी) (-2)	-0.15*** (0.02)	-0.14*** (0.02)	-0.13*** (0.03)	-0.12*** (0.03)
डी (आय)	0.08* (0.04)	0.07* (0.04)	0.14*** (0.04)	0.18*** (0.03)
डी (आय) (-1)	0.11*** (0.03)	0.12*** (0.03)	0.21*** (0.04)	0.26*** (0.04)
डमी: एसबीएन आहरण	-0.31*** (0.01)	-0.33*** (0.01)		0.09*** (0.03)
डमी: कोवडि की पहली लहर	0.10*** (0.01)	0.10*** (0.01)	-0.30*** (0.01)	-0.32*** (0.01)
डमी: कोवडि की दूसरी लहर	0.03*** (0.01)	0.03*** (0.01)	0.12*** (0.01)	0.13*** (0.01)

**टिप्पणियाँ:** (ए) मानक त्रुटियाँ कोष्ठक में हैं।, \*\* और \* क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर महत्व स्तरों को संदर्भित करते हैं।

(बी) सीआईसी, आय और यूपीआई प्राकृतिक लॉग रूपांतरित हैं।

(सी) मॉडल 1 यूपीआई और एचडीएन शेयर के बिना बेसलाइन मॉडल है। मॉडल 2 में यूपीआई मात्रा और एचडीएन शेयर शामिल हैं।

**स्रोत:** लेखकों की गणना।

अनुलग्नक III

सारणी 1: नकदी की मांग पर यूपीआई मूल्य का राज्यवार प्रभाव – नकद मात्रा के आधार पर  
निर्भर चर: प्रति व्यक्ति मुद्रा तिजोरी आहरण का लॉग

	(1)	(2)	(3)	(4)
चर	पूर्ण नमूना	25 वीं क्वांटाइल (कम नकद)	50वीं क्वांटाइल (मध्यम केश)	75 वीं क्वांटाइल (उच्च नकद)
आर्थिक गतिविधि #	0.27*** (0.05)	0.31*** (0.06)	0.28*** (0.05)	0.23*** (0.07)
यूपीआई मात्रा #	-0.65*** (0.21)	-0.62*** (0.11)	-0.65*** (0.09)	-0.69*** (0.13)
यूपीआई मात्रा स्क्वेअर्ड #	0.04*** (0.01)	0.03*** (0.01)	0.04*** (0.00)	0.04*** (0.01)
एटीएम घनत्व #	0.68** (0.29)	0.45** (0.19)	0.66*** (0.15)	0.93*** (0.22)
औपचारिकता की डिग्री #	-0.12*** (0.03)	-0.13*** (0.04)	-0.12*** (0.03)	-0.12*** (0.04)
औपचारिकता का डिग्री वर्ग #	0.01*** (0.00)	0.01*** (0.00)	0.01*** (0.00)	0.01*** (0.00)
शिक्षा प्राप्ति स्तर	-0.01 (0.01)	-0.01 (0.00)	-0.01*** (0.00)	-0.01*** (0.00)
इंटरनेट सब्सक्राइबर की वृद्धि @	0.06 (0.04)	0.04 (0.05)	0.06 (0.04)	0.07 (0.05)
कोविड डमी	0.06*** (0.01)	0.06** (0.03)	0.06** (0.02)	0.05 (0.03)
राज्य चुनाव डमी	0.04*** (0.01)	0.04** (0.02)	0.04** (0.02)	0.04 (0.02)
त्योहार डमी	0.04* (0.02)	0.04** (0.02)	0.04*** (0.02)	0.03 (0.02)
अपरिवर्तनीय	19.59*** (3.12)			
वर्ष निश्चित प्रभाव	हां	हां	हां	हां
अवलोकन	688	688	688	688
आर-स्क्वेयर्ड	0.39			
एफ- सांख्यिकी	74.11			
प्रोब > एफ	0.00			
राज्यों की संख्या	31			

टिप्पणियाँ: ए) कोष्ठकों में दी गई मानक त्रुटियाँ राज्यवार समूहीकृत हैं। \*\*\*, \*\* और \* क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के महत्व स्तरों को दर्शाती हैं।  
बी) # चर प्रति व्यक्ति के संदर्भ में हैं और लॉग रूपांतरित हैं।  
सी) @ चर तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि के संदर्भ में हैं।  
डी) लद्दाख, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, सिक्किम और पुदुचेरी के लिए डेटा अनुपलब्धता के कारण, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या का नमूना आकार घटकर 31 रह गया है।  
ई) ये परिणाम वर्ष के निश्चित प्रभावों को नियंत्रित करते हैं।  
स्रोत: लेखकों की गणना।



**सारणी 2: नकदी की मांग पर यूपीआई मूल्य का राज्यवार प्रभाव - आय समूहों के अनुसार**  
आश्रित चर: प्रति व्यक्ति मुद्रा तिजोरी आहरण लॉग

	(1)	(2)	(3)
चर	कम आय वाले राज्य	मध्यम आय वाले राज्य	उच्च आय वाले राज्य
आर्थिक गतिविधि #	0.33*** (0.07)	0.21** (0.09)	0.41*** (0.10)
यूपीआई मात्रा#	-1.13** (0.52)	-0.90*** (0.08)	-0.35* (0.17)
यूपीआई मात्रा स्क्वेअर्ड #	0.07** (0.03)	0.05*** (0.01)	0.02 (0.01)
एटीएम घनत्व #	1.13* (0.62)	0.33 (0.32)	0.55 (0.45)
औपचारिकता की डिग्री #	-0.08 (0.08)	-0.10*** (0.02)	-0.17 (0.13)
औपचारिकता का डिग्री वर्ग #	0.01 (0.01)	0.01*** (0.00)	0.01* (0.01)
शिक्षा प्राप्ति स्तर	-0.01* (0.01)	0.00 (0.02)	-0.01** (0.00)
इंटरनेट सब्सक्राइबर की वृद्धि @	0.07 (0.06)	0.01 (0.02)	0.05 (0.21)
कोविड डमी	0.07*** (0.02)	0.05 (0.03)	0.03 (0.02)
राज्य चुनाव डमी	0.03 (0.03)	0.06** (0.02)	0.01 (0.02)
त्योहार डमी	0.00 (0.02)	0.07 (0.06)	0.07** (0.03)
अपरिवर्तनीय	25.70*** (7.66)	16.84*** (2.34)	18.04*** (4.04)
वर्ष निश्चित प्रभाव	Yes	Yes	Yes
अवलोकन	244	235	209
आर-स्क्वेयर्ड	0.44	0.50	0.48
राज्यों की संख्या	14	15	11

**टिप्पणियाँ:** (ए) निम्न, मध्यम और उच्च आय वाले राज्य एनएसडीपी (वर्तमान मूल्य) के क्रमशः 25वें, 50वें और 75वें प्रतिशतक से संबंधित हैं।  
 (बी) कोष्ठकों में मानक त्रुटियाँ राज्यवार समूहीकृत हैं। \*\*\*, \*\* और \* क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के महत्व स्तरों को दर्शाती हैं।  
 (सी) # चर प्रति व्यक्ति और लॉग रूपांतरित हैं।  
 (डी) @ चर तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि के संदर्भ में हैं।  
 (ई) लद्दाख, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, सिक्किम और पुदुचेरी के लिए डेटा अनुपलब्धता के कारण, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या का नमूना आकार घटकर 31 रह गया है।  
 (एफ) ये परिणाम वर्ष के निश्चित प्रभावों को नियंत्रित करते हैं।

**स्रोत:** लेखकों की गणना।

## क्या उपभोग असमानता घट रही है? - 2022-23 का एनएसएसओ सर्वेक्षण हमें क्या बताता है

कौस्तुभ, सतद्रु दास,  
पवन गोपालकृष्णन, और  
देबोज्योति मजूमदार ^

यह आलेख विभिन्न समूहों के बीच घरेलू उपभोग व्यय में अभिसरण या विचलन का विश्लेषण करके भारत में उपभोग असमानता का आकलन करता है। इसके अलावा, लेख रंगराजन समिति की गरीबी रेखा को अद्यतन करते हुए राज्यों में गरीबी की घटनाओं का अनुमान लगाता है। अध्ययन में पाया गया है कि परिवारों के बीच उपभोग व्यय में अभिसरण की एक व्यापक प्रवृत्ति है, लेकिन कुछ उल्लेखनीय अपवाद भी हैं। भारत के राज्यों में गरीबी की घटनाओं में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।

### परिचय

हाल के वर्षों में, भारत ने उपभोग वृद्धि में मंदी का अनुभव किया है, जो आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थों वाला एक रुझान है। उपभोग जो आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक है न केवल समग्र मांग को दर्शाता है, बल्कि परिवारों के जीवन स्तर और कल्याण को भी दर्शाता है। उपभोग असमानता और क्षेत्रीय अभिसरण का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां उपभोग में असमानताएँ आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कायम रख सकती हैं, वहां अभिसरण अधिक समावेशी विकास की दिशा में प्रगति का संकेत दे सकता है। जबकि वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के रुझान पिछले एक दशक में राज्यों के बीच बढ़ती असमानता दर्शाते हैं (कौस्तुभ और घोष, 2023; 2025), यह जांचना आवश्यक हो जाता है कि यह उपभोग के संदर्भ में कैसे साकार हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण

प्रश्न को उठाता है: क्या बढ़ती स्थानिक आय असमानता उपभोग असमानता में भी इसी अनुपात में वृद्धि का कारण बन रही है? पिछले दशक में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन और कोविड-19 महामारी की तरह के अप्रत्याशित झटकों जैसे कई महत्वपूर्ण कारकों का असमानता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। जहाँ कुछ विश्लेषकों ने अन्य स्रोतों से प्राप्त वास्तविक साक्ष्यों और आंकड़ों का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि इन घटनाओं ने बढ़ती असमानता में योगदान दिया (हिमांशु, 2017; झा और लाहोटी, 2022; घोष, 2024), वहीं अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि इन घटनाओं के प्रभाव या तो अस्थायी थे या असमानता के कारण बने (चंदा और कुक, 2022; गुप्ता और अन्य., 2021)। राज्यों में श्रम गतिशीलता में वृद्धि और सु-लक्षित नीतिगत उपाय उपभोग पर बढ़ती आय असमानता के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं।

विपरीत निष्कर्षों और परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 2022-23 का घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण इन मुद्दों की विस्तार से जांच करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। यह सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा ग्यारह वर्षों के अंतराल के बाद, जुलाई 2024 में जारी किया गया था। 2.6 लाख परिवारों को शामिल करते हुए, यह डेटासेट आय समूहों, राज्यों और ग्रामीण-शहरी विभाजनों में उपभोग व्यवहारों की गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे असमानता के चालकों और क्षेत्रीय अभिसरण की सीमा का व्यापक विश्लेषण संभव हो पाता है। इन रुझानों को समझना भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और समान आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए उपभोग असमानताओं को दूर करना आवश्यक है। इन गतिशीलताओं की जांच करके, इस अध्ययन का उद्देश्य नीतिगत हस्तक्षेपों को सूचित करना है जो संतुलित विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकास के लाभ आबादी में अधिक समान रूप से वितरित किए जाएं।

एचसीईएस 2022-23 के संबंध में मीडिया और अकादमिक अनुसंधान में अधिकांश चर्चा सर्वेक्षण से प्राप्त समग्र आंकड़ों

^ लेखक आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग से हैं। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

पर केंद्रित रही है। इन लेखों ने 2011-12 और 2022-23 के सर्वेक्षणों की तुलना करके भारतीय अर्थव्यवस्था के उपभोग पैटर्न में उभरते प्रमुख रुझानों का विश्लेषण किया है। इन लेखों के निष्कर्षों को मोटे तौर पर संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: 2011-12 और 2022-23 के बीच ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) में वृद्धि हुई है; उपभोग में ग्रामीण और शहरी अंतर में कमी आई है; कुल उपभोग व्यय में भोजन की हिस्सेदारी में गिरावट आई है; और अंत में, आय के विभिन्न दशमलवों में उपभोग असमानता में कमी आई है (रामपाल, 2024; अय्यर, 2024; नागेश्वरन और अन्य., 2024)।

पिछले अध्ययनों में खाद्य पदार्थों की तुलना में गैर-खाद्य पदार्थों के उपभोग में अधिक स्थानिक असमानता पाई गई है और एचसीईएस 2022-23 के आधार पर एमपीसीई के संदर्भ में राज्यों के बीच ग्रामीण एमपीसीई में स्थानिक असमानता शहरी एमपीसीई से अधिक है (मित्रा और श्रीवास्तव, 2024)। इसी तरह, बोन्नू, 2024 ने सामाजिक समूहों के बीच उपभोग असमानता का विश्लेषण किया। यह पाया गया कि ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियाँ उपभोग पिरामिड में सबसे निचले पायदान पर हैं। मोटे तौर पर, उन्होंने इस बात के प्रमाण दिए कि अनुसूचित जनजातियाँ उपभोक्ता पिरामिड में सबसे निचले पायदान पर हैं और उसके बाद लगभग सभी राज्यों में अनुसूचित जातियाँ हैं। इन अध्ययनों ने उपभोग असमानताओं के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करने के लिए केवल एचसीईएस 2022-23 पर ध्यान केंद्रित किया।

वर्तमान लेख एचसीईएस 2022-23 के माइक्रो-डेटा का विश्लेषण करके और एनएसएसओ उपभोग सर्वेक्षणों के पिछले दौर के साथ उनकी तुलना करके उपभोग व्यय में स्थानिक और अस्थायी भिन्नता के रुझानों का विश्लेषण करके इस चर्चा में योगदान देता है।

एनएसएसओ सर्वेक्षण दौर 2011-12 और 2022-23 के तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से, अध्ययन में शहरी और ग्रामीण

परिवारों के बीच, उच्च उपभोग और निम्न उपभोग वाले परिवारों के बीच, और राज्यों में कई आयामों में व्यय असमानता में कमी पाई गई है। उपभोग असमानता में यह कमी गरीबी के स्तर पर भी प्रभाव डाल सकती है। इसका पता लगाने के लिए, वर्ष 2014 में रंगराजन समिति द्वारा अनुशंसित उपभोग व्यय आधारित गरीबी रेखा को वर्तमान कीमतों के अनुसार उचित रूप से समायोजित करके गरीबी के भार का अनुमान लगाया गया है। इन अनुमानों के परिणाम राज्यों में गरीबी की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाते हैं।

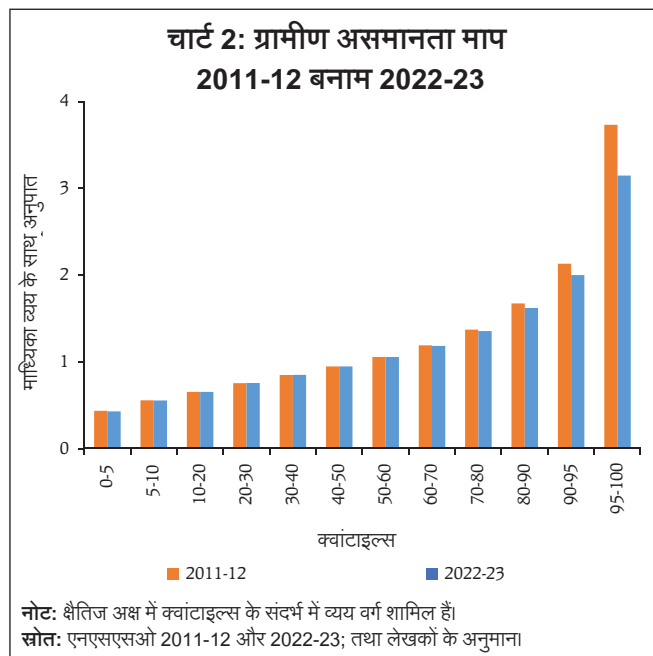
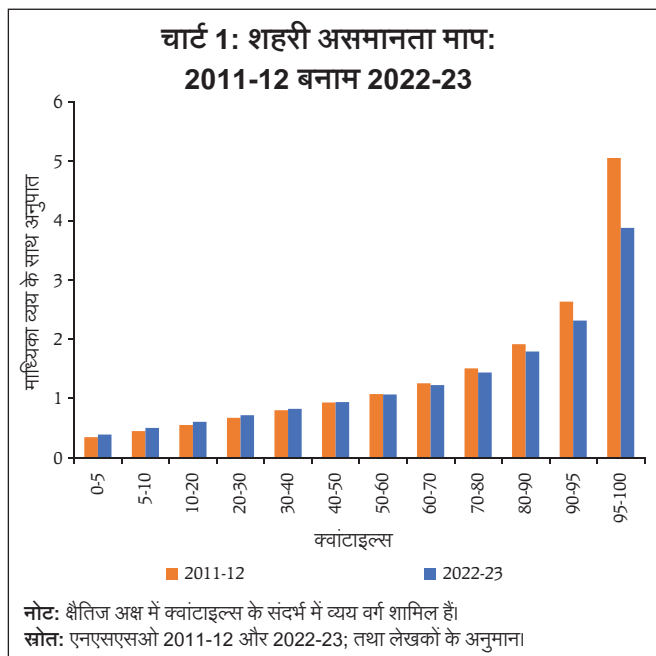
लेख का शेष भाग इस प्रकार व्यवस्थित है: खंड II व्यय वर्गों में उपभोग व्यय में भिन्नता का विश्लेषण करता है, खंड III शहरी और ग्रामीण परिवारों के बीच भिन्नता प्रस्तुत करता है, जबकि खंड IV राज्यों में भिन्नता की जांच करता है। खंड V बड़े राज्यों के लिए रंगराजन समिति की गरीबी रेखा को अद्यतन करता है और गरीबी की घटनाओं की गणना करता है। अंत में, खंड VI कुछ नीति अंतर्दृष्टि प्रदान करके समाप्त होता है।

## II. व्यय वर्गों में अभिसरण

व्यय वर्गों में असमानता का विश्लेषण करने के लिए, प्रत्येक व्यय वर्ग के औसत व्यय और संपूर्ण नमूने के माध्यिका व्यय के बीच के अनुपात की गणना की जाती है। यह अभ्यास शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए अलग-अलग किया जाता है<sup>1</sup>। अभिसरण के लिए, 2011-12 और 2022-23 के बीच माध्यिका से नीचे के फ्रैक्टाइल के लिए अनुपात में वृद्धि और माध्यिका से ऊपर के फ्रैक्टाइल के लिए कमी होनी चाहिए।

यह देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में, माध्यिका से नीचे के अधिकांश फ्रैक्टाइल के लिए अनुपात में वृद्धि हुई और माध्यिका से ऊपर के अधिकांश फ्रैक्टाइल के लिए कमी आई (चार्ट 1)।

<sup>1</sup> असमानता को शीर्ष फ्रैक्टाइल और निचले फ्रैक्टाइल के औसत एमपीसीई के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। चार्ट में, प्रत्येक क्वांटाइल के औसत एमपीसीई और माध्यिका एमपीसीई के बीच के अनुपात को बार के रूप में दर्शाया गया है। यह अनुपात 50 से नीचे के क्वांटाइल के लिए 1 से कम और 50 से ऊपर के क्वांटाइल के लिए 1 से अधिक होगा। 50 से नीचे के फ्रैक्टाइल के अनुपात में वृद्धि का अर्थ माध्यिका की ओर गति होगा और 50 से ऊपर के फ्रैक्टाइल के अनुपात में गिरावट का अर्थ भी माध्यिका की ओर गति होगा, इसलिए, असमानता में कमी का संकेत होगा।



ग्रामीण क्षेत्रों में, माध्यिका से नीचे के अधिकांश फ्रैक्टाइल के लिए अनुपात अपरिवर्तित रहा है, लेकिन शीर्ष चार अंशों के लिए इसमें कमी आई है (चार्ट 2)। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 2011-12 की तुलना में शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों के लिए व्यय वर्गों में असमानता में कमी आई है, हालाँकि शहरी क्षेत्रों में गिरावट अधिक रही है।

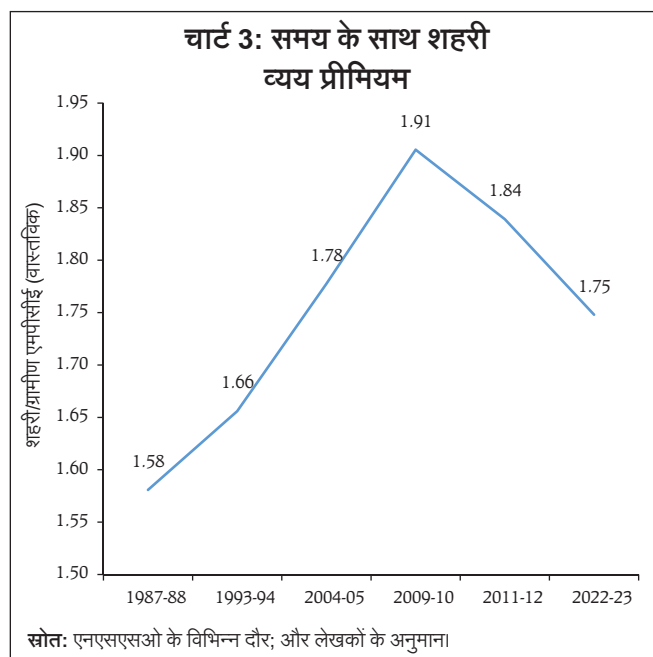
### III. शहरी और ग्रामीण परिवारों के बीच अभिसरण

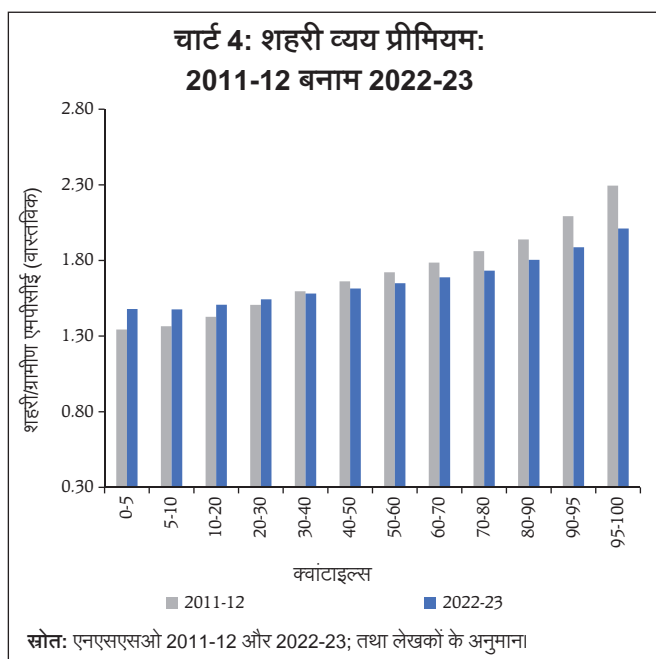
शहरी-ग्रामीण अंतर को शहरी प्रीमियम का उपयोग करके मापा जाता है, जिसे वास्तविक शहरी एमपीसीई और वास्तविक ग्रामीण एमपीसीई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। वास्तविक मूल्यों की गणना शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए उनके संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (सीपीआई) के साथ नाममात्र एमपीसीई को घटाकर की जाती है ताकि सभी मूल्यों को 2011-12 की कीमतों के संदर्भ में व्यक्त किया जा सके। 2009-10 में अपने चरम पर पहुँचने के बाद से इस अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, जो दर्शाती है कि उपभोग के संदर्भ में शहरी-ग्रामीण अंतर 2009-10 से लगातार घट रहा है (चार्ट 3)।

हालाँकि, आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि शहरी प्रीमियम में गिरावट व्यय वर्गों में एक समान नहीं है। विशेष रूप से,

शहरी प्रीमियम निचले 30 प्रतिशत में बढ़ा है और उपभोग के शीर्ष 70 प्रतिशत वर्गों में घटा है (चार्ट 4)। इसका अर्थ है कि बेहतर स्थिति वाले परिवारों के लिए शहरी-ग्रामीण अंतर कम हुआ है, लेकिन गरीब परिवारों के लिए बढ़ा है।

इसके बाद, अनुमानित शहरी प्रीमियम की तुलना राज्यों के बीच की जाती है ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या यह अमीर राज्यों (उच्च औसत एमपीसीई वाले राज्य) में गरीब राज्यों





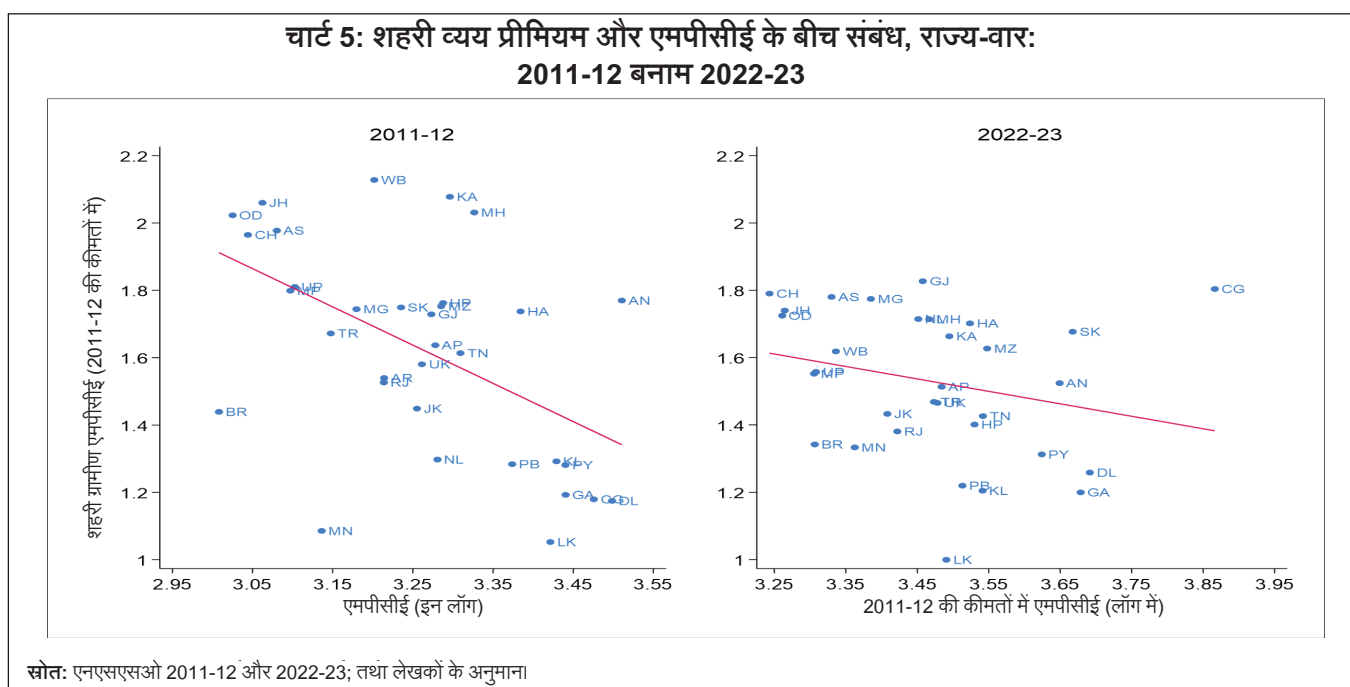
की तुलना में कम है और क्या यह संबंध समय के साथ समान बना हुआ है। राज्यवार औसत एमपीसीई की गणना 2010-11 की जनगणना (सर्वेक्षण के लिए एनएसएसओ द्वारा इसी का उपयोग किया गया) से संबंधित शहरी और ग्रामीण आबादी के आधार पर किसी राज्य में औसत शहरी और ग्रामीण एमपीसीई को भारत

करके की जाती है। 2011-12 और 2022-23 के लिए राज्यवार शहरी प्रीमियम और एमपीसीई के बीच संबंध की अलग-अलग जाँच की जाती है।

शहरी प्रीमियम का राज्यों के औसत एमपीसीई के साथ नकारात्मक संबंध है। इसका अर्थ है कि उच्च एमपीसीई वाले राज्यों में शहरी-ग्रामीण अंतर कम है (चार्ट 5)। हालाँकि, 2011-12 और 2022-23 के दौरान यह संबंध बदल गया है। स्कैटर प्लॉट में फिट की गई रेखाओं के ढलानों की तुलना करने पर, यह देखा गया है कि यह संबंध कमजोर हो गया है। ढलान में गिरावट मुख्य रूप से उन राज्यों में शहरी प्रीमियम में गिरावट के कारण है जिनका एमपीसीई राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। यह दर्शाता है कि 2011-12 और 2022-23 के बीच कम एमपीसीई वाले राज्यों में शहरी-ग्रामीण अंतर में काफी कमी आई है।

#### IV. राज्यों में अभिसरण

भारतीय संदर्भ में आर्थिक परिणामों में अंतर-राज्यीय असमानता और इसकी गतिशीलता पर साहित्य मुख्यतः भारतीय राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति आय<sup>2</sup> में बढ़ते विचलन पर केंद्रित रहा है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानिक आर्थिक असमानता बढ़ रही



<sup>2</sup> राज्य स्तरीय प्रति व्यक्ति आय को राज्य स्तरीय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का उपयोग करके मापा जाता है।

है। मोटे तौर पर, इन अध्ययनों से पता चला है कि हाल के दशकों में भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में बीटा-विचलन मौजूद है (घोष और कौस्तुभ, 2023; 2025)। भारतीय राज्यों के बीच एमपीसीई की गतिशीलता के संबंध में, आचार्य और अन्य., 2021 ने एनएसएसओ उपभोग व्यय सर्वेक्षणों के पहले के दौरों पर आधारित एक विस्तृत अध्ययन किया था और 1993-94 से 2011-12 के बीच की अवधि में राज्यों के बीच एमपीसीई में समग्र विचलन के प्रमाण पाए थे, और राज्यों को उनके जीवन स्तर के आधार पर समूहीकृत करने पर सशर्त अभिसरण के कुछ प्रमाण भी मिले थे। समाचार मीडिया में कुछ लेख नमूने (जैसे महाम्बारे और ज्योति, 2024) ने 2022-23 के घरेलू उपभोग सर्वेक्षण दौर के संदर्भ में कुछ राज्यों में अलग-अलग प्रति व्यक्ति जीएसडीपी/एनएसडीपी और अभिसरण एमपीसीई के बीच विरोधाभास के वास्तविक सबूत की ओर इशारा किया है। उदाहरण के लिए, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र में राजस्थान की तुलना में प्रति व्यक्ति एनएसडीपी अधिक है, ग्रामीण राजस्थान में एमपीसीई ग्रामीण गुजरात और महाराष्ट्र की तुलना में अधिक है। वे अनुमान लगाते हैं कि इस तरह के विरोधाभास को कई कारकों जैसे उच्च श्रम गतिशीलता जो श्रम-निर्यातक राज्यों में उनके जीएसडीपी स्तरों की तुलना में अधिक आय उत्पन्न करती है, और लोगों के जीवन स्तर पर बढ़ती स्थानिक आर्थिक असमानता के प्रभाव को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई सरकारी नीतियां और योजनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

इस संदर्भ को देखते हुए, वर्तमान अध्ययन 2011-12 से 2022-23 की अवधि के बीच एमपीसीई की अंतर-राज्यीय गतिशीलता की जांच करता है। 2011-12 से 2022-23 की अवधि के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग, एक राज्य-स्तरीय बीटा-अभिसरण विश्लेषण किया जाता है। विशेष रूप से, बीटा-अभिसरण तब होता है जब कम प्रारंभिक मूल्यों वाले क्षेत्र अपने समृद्ध समकक्षों की तुलना में तेजी से विकास का अनुभव करते हैं। जैसा कि समीकरण 1 में दिखाया गया है, इस संबंध की जांच 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2011-12 में अपने एमपीसीई (लॉग(एमपीसीई)<sub>i,2011-12</sub>) के लघुगणक पर  $i$  राज्य के 2011-12 और 2022-23 ( $\Delta$  वास्तविक एमपीसीई) के बीच शहरी और ग्रामीण वास्तविक एमपीसीई में वृद्धि को प्रतिगमन

करके की जाती है। मानक त्रुटियों ( $e_i$ ) को हेटेरोस्केडैस्टिसिटी के लिए मजबूत बनाया गया है। 2011-12 में एमपीसीई के लॉग का सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण ऋणात्मक गुणांक ( $\beta$ ) बिना शर्त बीटा-अभिसरण को दर्शाएगा और गुणांक का उच्च परिमाण अभिसरण की उच्च गति को दर्शाएगा (बैरो और साला-आई-मार्टिन, 1992; 1995)।

$$\Delta \text{ Real MPCE}_i = \alpha + \beta * \text{Log}(\text{MPCE})_{i,2011-12} + e_i \quad (1)$$

उपरोक्त प्रतिगमन का परीक्षण करने पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए 2011-12 में एमपीसीई में वृद्धि और एमपीसीई के लॉग के बीच एक महत्वपूर्ण ऋणात्मक संबंध प्राप्त होता है, जो राज्यों में प्रति व्यक्ति उपभोग में बीटा-अभिसरण को दर्शाता है (सारणी 1)। इसका तात्पर्य यह है कि 2011-12 में कम एमपीसीई वाले राज्यों ने तेजी से उपभोग वृद्धि का अनुभव किया, जिसके परिणामस्वरूप 2011-12 और 2022-23 के बीच उपभोग में अंतर-राज्यीय असमानता में कमी आई। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण की गति शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, जैसा कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए  $\beta$  के उच्च परिमाण से परिलक्षित होता है।

राज्यों में एमपीसीई में बीटा अभिसरण को बेहतर ढंग से देखने के लिए, 2011-12 के राज्यवार नाममात्र एमपीसीई (लॉग में) और 2011-12 से 2022-23 तक वास्तविक एमपीसीई में संबंधित वृद्धि के बीच एक स्कैटर आरेख ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए प्लॉट किया गया है (चार्ट 6)। बीटा अभिसरण के लिए, स्कैटर प्लॉट की फिट की गई रेखा का ढलान ऋणात्मक होना चाहिए, जैसा कि देखा गया है। काली ऊर्ध्वाधर धराशायी रेखा 2011-12 में राष्ट्रीय औसत एमपीसीई है। ऊर्ध्वाधर रेखा के बाईं ओर के राज्यों का एमपीसीई 2011-12 में राष्ट्रीय औसत से कम था।

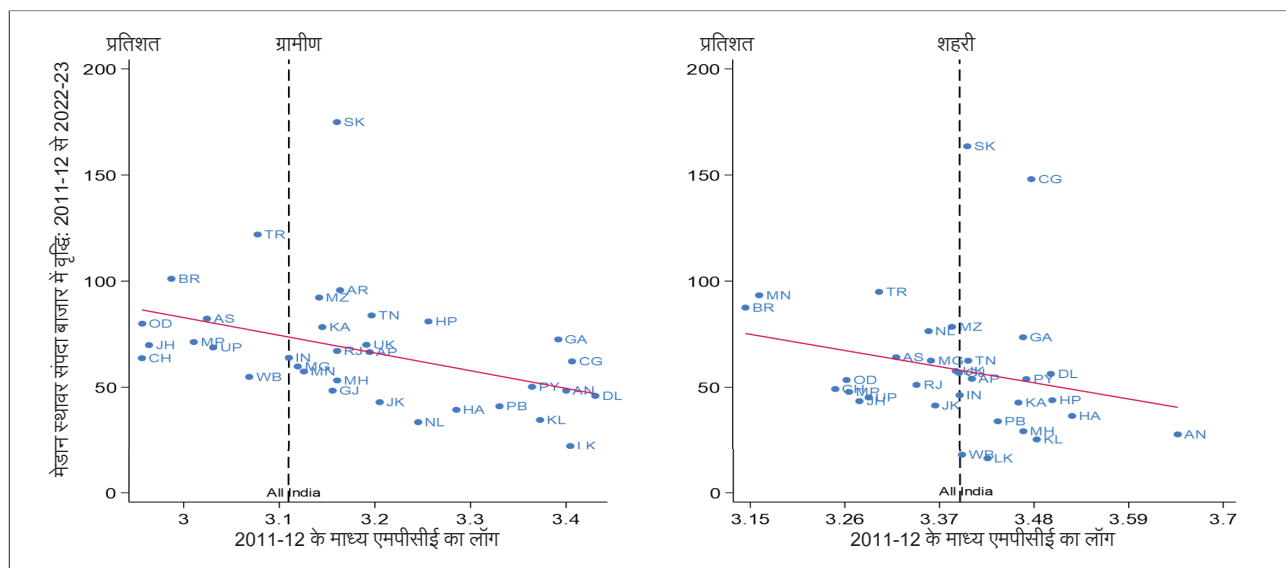
सारणी 1: बीटा-अभिसरण परीक्षण

चर	ग्रामीण	शहरी
$\beta$	-83.8***	-72.3*
$\alpha$	333.6***	302.1**

नोट: \*\*\* 1 प्रतिशत महत्व स्तर को दर्शाता है, \*\* 5 प्रतिशत महत्व स्तर को दर्शाता है और \* 10 प्रतिशत महत्व स्तर को दर्शाता है।

स्रोत: एचसीएस 2011-12 और 2022-23 पर लेखक की गणना आधारित है।



**चार्ट 6: राज्यों में वास्तविक एमपीसीई में अभिसरण**

स्रोत: एनएसएसओ 2011-12 और 2022-23; तथा लेखकों के अनुमान।

ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का एमपीसीई राष्ट्रीय औसत से कम था और वे निर्धारित वक्र (लाल रेखा) से नीचे थे, जिसका अर्थ है कि इन राज्यों को अखिल भारतीय औसत एमपीसीई तक पहुँचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगेगा क्योंकि उनकी वास्तविक एमपीसीई वृद्धि 2011-12 में उनके एमपीसीई के संबंध में अभिसरण अनुमान द्वारा सुझाए गए स्तर से नीचे थी। दूसरी ओर, अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित) का एमपीसीई 2011-12 में राष्ट्रीय औसत से अधिक और निर्धारित रेखा से ऊपर था, जो यह दर्शाता है कि उनकी वास्तविक एमपीसीई वृद्धि अभिसरण अनुमान द्वारा सुझाए गए स्तर से ऊपर थी।

इस प्रकार, डेटा 2011-12 से 2023-24 की अवधि के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए राज्यों में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में बिना शर्त बीटा-अभिसरण का प्रमाण दिखाता है। यह 1993-94 से 2011-12 के बीच की अवधि के लिए आचार्य और अन्य 2021 द्वारा प्राप्त परिणामों के विपरीत है। हालांकि, पहले के अध्ययन के निष्कर्षों के समान, ग्रामीण और शहरी

क्षेत्रों और राज्यों के बीच अभिसरण की गति में विविधताएं हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां भारतीय राज्यों की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में विचलन हो रहा है (घोष और कौस्तुभ, 2023; 2025), वहीं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एमपीसीई अभिसरण के संकेत दिखा रहा है। इससे पता चलता है कि इन क्षेत्रों में जीवन स्तर अधिक समान होता जा रहा है, भले ही उनका प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादन अलग-अलग हो रहा है।

## V. गरीबी रेखा का अनुमान लगाना

यह लेख गरीबी पर रंगराजन विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित पद्धति का अनुसरण करता है, जिसका गठन योजना आयोग ने 2011 में गरीबी के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए किया था। उपभोग-आधारित गरीबी रेखाएँ एक परिवार के लिए आवश्यक वस्तुओं की एक बास्केट खरीदने के लिए आवश्यक धन की मात्रा निर्धारित करती हैं। घरेलू उपभोग व्यय पर सूक्ष्म-स्तरीय डेटा से गरीबी रेखा द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक खर्च करने वाले परिवारों का प्रतिशत पता चल सकता है। बढ़ती अर्थव्यवस्था में असमानता में कमी का अर्थ होगा कि गरीब परिवारों का खर्च अमीर परिवारों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। उपभोग व्यय के



अभिसरण में स्थानिक भिन्नता की सीमा तक, राज्यों में गरीबी में कमी में अंतर हो सकता है।

कुछ हालिया आलेखों ने एचसीईएस 2022-23 के उपभोग आंकड़ों के आधार पर भारत में गरीबी के राज्यवार प्रभाव की गणना की है (भसीन और भल्ला, 2024; सेतु और अन्य., 2024)। उन्होंने कीमतों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए या तो विश्व बैंक की क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) गरीबी रेखाओं \$1.9 और \$3.2 का उपयोग किया है या घरेलू गरीबी रेखाओं (तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति द्वारा सुझाई गई) को सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के साथ बढ़ाकर दर्शाया है। हालाँकि, इन दृष्टिकोणों के साथ समस्याएँ हैं। विश्व बैंक की गरीबी रेखाओं, जिन्हें डॉलर में परिभाषित किया गया है, को रुपये में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक पीपीपी परिवर्तन कारक के संबंध में आम सहमति का अभाव है। रंगराजन या तेंदुलकर गरीबी रेखा को मुख्य सीपीआई मुद्रास्फीति के साथ बढ़ाने के लिए, सीपीआई बास्केट में उपभोग वस्तुओं का भार गरीबी रेखा बास्केट (पीएलबी) में उन वस्तुओं के भार से बहुत भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रंगराजन पीएलबी में खाद्य पदार्थों का भार 57 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण सीपीआई उपभोग बास्केट में इसका भार 54 प्रतिशत है। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों के लिए रंगराजन पीएलबी में खाद्य पदार्थों का भार 47 प्रतिशत है, जबकि शहरी सीपीआई उपभोग बास्केट में इसका भार 36 प्रतिशत है। इस प्रकार, पीएलबी में मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य सीपीआई मुद्रास्फीति उपयुक्त मीट्रिक नहीं हो सकती है।

इससे निपटने के लिए, सीपीआई बास्केट से आइटम भार का उपयोग करने के बजाय, रंगराजन पीएलबी में प्रत्येक आइटम के भार के आधार पर एक मूल्य सूचकांक विकसित किया गया है। इस अवधि के दौरान पीएलबी के लिए मुद्रास्फीति निर्धारित करने के लिए पीएलबी में संबंधित आइटम के भार द्वारा इन परिवर्तनों को समायोजित करते हुए, 2011-12 और 2022-23 के बीच प्रत्येक आइटम के मूल्य परिवर्तनों की गणना की जाती है। यह विश्लेषण प्रत्येक राज्य में शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए अलग-अलग किया गया था। इसके बाद, रंगराजन समिति की नाममात्र गरीबी रेखाओं को, 2012 की गरीबी रेखा से पिछले चरण में की गई चर्चा के अनुसार मुद्रास्फीति दरों के साथ समायोजित करके अद्यतन

किया गया। अंत में, एचसीईएस 2022-23 के सूक्ष्म-आँकड़ों का उपयोग करके प्रत्येक राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अद्यतन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का प्रतिशत प्राप्त किया गया।

2014 में योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनेवाली रंगराजन समिति, द्वारा सुझाई गई पद्धति में तेंदुलकर समिति द्वारा निर्मित पिछली आधिकारिक गरीबी रेखा की तुलना में कुछ विशिष्ट लाभ थे। पहला, रंगराजन समिति की कार्यप्रणाली शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए दोनों समूहों के बीच उपभोग पैटर्न में अंतर के आधार पर अलग-अलग पीएलबी परिभाषित करती है। दूसरा, तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली द्वारा गरीबी रेखा को न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं से अलग करने के बाद, कार्यप्रणाली उन्हें फिर से जोड़ती है। तीसरा, रंगराजन समिति की रिपोर्ट शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पीएलबी में प्रत्येक मद का भारांक देती है, जिससे प्रत्येक राज्य के लिए 2022-23 की कीमतों में इन श्रेणियों के नाममात्र मूल्य की गणना करना संभव हो जाता है।<sup>3</sup>

सारणी 2 में रंगराजन समिति की रिपोर्ट में बताई गई 2011-12 की राज्यवार गरीबी रेखा और 2022-23 की गरीबी रेखा शामिल है, जिसका अनुमान बड़े भारतीय राज्यों के लिए ऊपर वर्णित कार्यप्रणाली का उपयोग करके लगाया गया है।

एचसीईएस 2022-23 के सूक्ष्म-आँकड़ों का उपयोग करके, 2022-23 में प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के प्रतिशत की गणना की गई। इन्हें 2014 की रंगराजन रिपोर्ट से क्रमशः 2009-10 और 2011-12 में राज्यों के गरीबी प्रतिशत के साथ सारणी 3 में दर्शाया गया है। एचसीईएस 2011-12 की तुलना में एचसीईएस 2022-23 में प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी की घटनाओं में पर्याप्त कमी देखी गई है। एचसीईएस 2022-23 का उपयोग करने वाले अन्य अध्ययनों ने भी इस अवधि के दौरान गरीबी में पर्याप्त गिरावट पाई है,

<sup>3</sup> यह ध्यान देने योग्य है कि इस आलेख में अनुमानित गरीबी रेखा 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट में प्रस्तावित पद्धति पर आधारित है। रिपोर्ट जारी हुए दस साल बीत चुके हैं, और उपभोग के पैटर्न में बदलाव आया है और उपभोग की बास्केट में नई वस्तुएँ अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसके लिए एक नई गरीबी रेखा का निर्माण आवश्यक हो सकता है जो वर्तमान वास्तविकता को बेहतर ढंग से दर्शा सके (भसीन और भल्ला, 2024; देव और अन्य., 2024)।

## सारणी 2: रंगराजन पद्धति का उपयोग करते हुए राज्यवार गरीबी रेखा 2011-12 और 2022-23

(रुपये में)

राज्य	ग्रामीण 2011-12	शहरी 2011-12	ग्रामीण 2022-23	शहरी 2022-23
आंध्र प्रदेश	1032	1371	1903	2588
असम	1067	1420	1968	2586
बिहार	971	1229	1724	2277
छत्तीसगढ़	912	1230	1586	2149
दिल्ली	1492	1538	2577	2592
गुजरात	1103	1507	2014	2664
हरियाणा	1128	1528	2083	2696
हिमाचल प्रदेश	1067	1412	1895	2547
जम्मू और कश्मीर	1044	1403	1980	2653
झारखंड	904	1272	1621	2356
कर्नाटक	975	1373	1784	2599
केरल	1054	1354	1982	2563
मध्य प्रदेश	942	1340	1707	2521
महाराष्ट्र	1078	1560	2006	2791
ओडिशा	876	1205	1608	2182
पंजाब	1127	1479	2048	2622
राजस्थान	1036	1406	1887	2561
तमिलनाडु	1082	1380	2041	2608
उत्तर प्रदेश	890	1330	1622	2429
पश्चिम बंगाल	934	1373	1755	2572

नोट: तेलंगाना आंध्र प्रदेश में शामिल है; लद्दाख जम्मू और कश्मीर में शामिल है।

स्रोत: एचसीईएस 2022-23; उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एमओएसपीआई; और लेखकों की गणना।

हालांकि उनके द्वारा गणना की गई गरीबी दर इस अध्ययन के अनुमानों से अलग है, यह कार्यप्रणाली में अंतर के कारण है। भसीन और भल्ला, 2024 के पेपर ने 2022-23 में कुल गरीबी हेडकाउंट अनुपात दर 2.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था जो 2011-12 में 12.2 था। उनके द्वारा अनुमानित गरीबी रेखा विश्व बैंक के 1.99 अमरीकी डॉलर प्रति दिन के उपभोग व्यय के माप पर आधारित है जिसे वे क्रय शक्ति समता माप का उपयोग करके रुपये में परिवर्तित करते हैं। सेतु और अन्य., 2024 ने भी एचसीईएस 2022-23 का उपयोग करते हुए गरीबी के प्रभाव का अनुमान लगाया और पाया कि पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 23 प्रतिशत और 27.4 प्रतिशत गरीबी दर है। उनकी गरीबी दर उनके द्वारा निर्मित गरीबी रेखा पर आधारित है, जिसमें परिवार के सदस्यों के व्यवसाय और आयु के आधार

## सारणी 3: चुनिंदा भारतीय राज्यों में 2009-10, 2010-11 और 2022-23 में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत

राज्य	ग्रामीण 2009-10	शहरी 2009-10	ग्रामीण 2011-12	शहरी 2011-12	ग्रामीण 2022-23	शहरी 2022-23
आंध्र प्रदेश	27.0	30.5	12.7	15.6	1.2	2.2
असम	42.9	40.2	42.0	34.2	8.7	5.5
बिहार	65.1	55.0	40.1	50.8	5.9	9.1
छत्तीसगढ़	58.9	36.5	49.2	43.7	25.1	13.3
दिल्ली	4.9	24.7	11.9	15.7	0.9	2.6
गुजरात	37.0	35.6	31.4	22.2	5.9	4.1
हरियाणा	19.2	24.8	11.0	15.3	4.1	4.3
हिमाचल प्रदेश	11.2	22.5	11.1	8.8	0.4	2.0
जम्मू और कश्मीर	14.4	32.4	12.6	21.6	4.2	4.1
झारखंड	55.3	42.1	45.9	31.3	16.6	12.6
कर्नाटक	24.3	26.7	19.8	25.1	0.9	3.3
केरल	9.7	23.7	7.3	15.3	1.4	4.3
मध्य प्रदेश	51.3	45.0	45.2	42.1	9.6	11.6
महाराष्ट्र	27.6	30.3	22.5	17.0	11.3	8.6
ओडिशा	50.0	41.2	47.8	36.3	8.6	10.2
पंजाब	14.8	28.6	7.4	17.6	0.6	2.6
राजस्थान	31.9	38.5	21.4	22.5	6.8	6.7
तमिलनाडु	25.9	29.7	24.3	20.3	2.1	1.9
उत्तर प्रदेश	46.3	49.6	38.1	45.7	5.7	9.9
पश्चिम बंगाल	37.8	36.6	30.1	29.0	7.5	12.4

नोट: आंध्र प्रदेश में तेलंगाना शामिल है; जम्मू और कश्मीर में लद्दाख शामिल है।

स्रोत: एचसीईएस 2022-23, और लेखकों की गणना।

पर उनकी अद्यतन कैलोरी संबंधी ज़रूरतें शामिल हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान अध्ययन किसी गरीबी रेखा का निर्माण नहीं करता है, बल्कि मद-वार मूल्य सूचकांकों का उपयोग करके रंगराजन गरीबी रेखा को अद्यतन करता है।

## निष्कर्ष

यह अध्ययन एनएसएसओ द्वारा 2022-23 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के उपभोग व्यय आंकड़ों की तुलना 2011-12 में किए गए सर्वेक्षण से करता है, जो व्यय वर्गों, शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों और राज्यों जैसे विभिन्न आयामों में अभिसरण पर केंद्रित है। परिणाम दर्शाते हैं कि एमपीसीआई में अभिसरण की एक व्यापक प्रवृत्ति है। गहन विश्लेषण से पता चलता है कि व्यापक प्रवृत्ति के कुछ अपवाद भी हैं। व्यय दशमलवों और क्षेत्रों में उपभोग

व्यय में असमानता में कमी को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा समझाया जा सकता है। साथ ही, अध्ययन ने रंगराजन समिति की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इन आंकड़ों के साथ प्रत्येक राज्य के लिए गरीबी रेखा का पुनर्मूल्यांकन किया। गरीबी की अनुमानित घटना भारत के राज्यों में गरीबी में समग्र कमी दर्शाती है।

## संदर्भ

Acharya, D., Rath, B.N., Parida, T.K. (2021). Convergence in Monthly Per Capita Expenditure and the Rural–Urban Dichotomy: Evidence from Major Indian States. In: Batabyal, A.A., Higano, Y., Nijkamp, P. (eds) Rural–Urban Dichotomies and Spatial Development in Asia. New Frontiers in Regional Science: Asian Perspectives, vol 48. Springer, Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-16-1232-9\\_10](https://doi.org/10.1007/978-981-16-1232-9_10)

Barro, R. J. and Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. *Journal of Political Economy*, 100(2), 223-251.

Barro, R. J. and Sala-i-Martin, X. (1995). *Economic Growth*. London. McGraw-Hill.

Bhasin, Karan and Bhalla, Surjit (2024). Poverty in India over the last decade. *Economic and Political Weekly*.

Bonu, S. (2024, August 22). Consumption Expenditure by Social Groups: Findings from India's Household Consumption Expenditure Survey, 2022-23. Isaac Centre for Public Policy, Ashoka University.

Chanda, A., and Cook, J. C. (2022). Was India's demonetization redistributive? Insights from satellites and surveys. *Journal of Macroeconomics*.

Dev, M. and Rangarajan, C. (2024, March 12). With new consumption survey, the need for new indices. *Indian Express*.

Ghosh, S. (2024, January 15). India's K-shaped recovery debate has economists divided. *Mint*.

Ghosh, T. and Kaustubh. (2023). Growth decomposition of the Indian states using panel data techniques. *Applied Economics*, 56(39), 4664–4684.

Ghosh, T., and Kaustubh. (2025). Growth Divergence between Indian States. *Economic and Political Weekly*, 60(6)

Gupta, A., Malani, A., and Woda, B. (2021). Inequality in India declined during covid. *NBER Working Paper*.

Himanshu. (2017, November 6). Demonetisation, inequality and informal sector. *Mint*.

Iyer, Vaidyanathan P. (2024, February 26). Five questions the Household Consumption Expenditure Survey 2022-23 answers. *The Indian Express*.

Jha, M., and Lahoti, R. (2022). Who was impacted and how? COVID-19 pandemic and the long uneven recovery in India. *WIDER Working Paper*.

Mahambare, Vidya and Jyoti, Amar. (2024, March 19) What tells us more about prosperity: Consumption or GDP per head? *Mint*.

Mitra, A., & Shrivastav, P. K. (2024). Interstate inequality in consumption: Emerging evidence from HCES 2022–23. *Economic & Political Weekly*, 59(28), 17–20.

Nageswaran, V. A., Guru, Anuradha and Bisht, D. S. (2024, March 6). India's consumption numbers fit into our big picture of progress. *Mint*.

Rampal, Nikhil (2024, February 27). Here are 5 key takeaways from Household Consumption Expenditure Survey 2022-2023. *The Print*.

Sethu, C. A., Abhinav Surya, L. T. and Ruthu, C. A. (2024). Poverty in India: The Rangarajan Method and the 2022–23 Household Consumption and Expenditure Survey. *Review of Agrarian Studies*, 14(2).



## अवसंरचना - भारत की विकास एक्सप्रेस का एक इंजन

आशुतोष राराविकर एवं अभिषेक रंजन<sup>^</sup>

पिछले दशक के दौरान भारत ने एक एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण के साथ अवसंरचना के विकास पर नीतिगत जोर दिया है। इस संदर्भ में, यह अध्ययन विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अवसंरचना के सूचकांक बनाकर अवसंरचना और आर्थिक विकास के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है। परिणाम बताते हैं कि अवसंरचना ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को सकारात्मक और महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इसलिए व्यापक आधार वाले अवसंरचना के विस्तार पर नीति का ध्यान विकास की कहानी को आगे ले जाएगा। इसके अलावा, अवसंरचना में निवेश की बड़ी आवश्यकता को देखते हुए, उपयुक्त वित्तपोषण विकल्पों और रणनीतियों की खोज करने से अवसंरचना की कमी को तेजी से खत्म करने में मदद मिलेगी।

### भूमिका

भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य और आकांक्षा रखता है। यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। हाल ही में, अवसंरचना के विस्तार पर नीतिगत जोर दिया गया है। व्यापक और तीव्र विकास के लिए अवसंरचना एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि यह आपूर्ति और माँग दोनों पक्षों से सुविधाजनक ढाँचा तैयार करता है। अवसंरचना एक ऐसा इंजन है जो भारतीय विकास को और आगे बढ़ा सकता है। यह आलेख अवसंरचना के विभिन्न आयामों पर गहराई से विचार करता है और भारत में अवसंरचना और आर्थिक विकास के बीच अनुभवजन्य संबंधों का पता लगाने और उन्हें स्थापित करने का प्रयास करता है। यह अवसंरचना के वित्तपोषण के विभिन्न तरीकों का भी विश्लेषण करता है। खंड II वैश्विक और भारतीय दोनों संदर्भों में

इस विषय पर उपलब्ध साहित्य का अवलोकन प्रस्तुत करता है। खंड III अवसंरचना और विकास तथा कल्याण के बीच के तंत्र की व्याख्या करता है और वैश्विक अनुभवों का हवाला देता है। खंड IV भारत में अवसंरचना के विकास, विशेष रूप से इसके तीव्र विकास के हालिया चरण को एक पुनर्निर्देशित दृष्टिकोण के साथ संक्षेपित करता है। भारत में अवसंरचना और विकास पर हमारे अनुभवजन्य कार्य के परिणामों की व्याख्या की गई है। खंड V अवसंरचना के वित्तपोषण के दृष्टिकोणों पर चर्चा करता है। खंड VI में निष्कर्ष है।

### II. साहित्य की समीक्षा

दुनिया भर में कई शोध अध्ययनों में अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास के लिए अवसंरचना के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इन शोधों ने सार्वजनिक निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका और उत्पादकता एवं राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर इसके सकारात्मक प्रभाव को उजागर किया है। मुनेल (1992) ने दर्शाया कि 1970 के दशक में अमेरिका में आई मंदी सरकारी पूँजीगत व्यय में कमी से जुड़ी थी। एजेनोर (2010) ने प्रतिपादित किया कि भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश ने किसी देश को दीर्घकाल में स्थिर आर्थिक विकास प्राप्त करने में सक्षम बनाया। बोघेस और अन्य लोगों के शोध कार्यों ने भी अवसंरचना और विकास के बीच सकारात्मक संबंध पर तर्क दिया है। डेविड एस्चाउर (1993) ने सार्वजनिक व्यय के माध्यम से बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए राजकोषीय नीति को एक साधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता की वकालत की। पॉल और श्वार्ट्ज (1996) ने तर्क दिया कि अवसंरचना में निवेश ने उत्पादकता में वृद्धि को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। हालाँकि, कुछ अध्ययनों में दोनों के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया, या अनिर्णायक या कमजोर पाया गया। उदाहरण के लिए, एल्बर्ज एवं अन्य (2017) ने अवसंरचना पर निवेश और उत्पादन के बीच कोई संबंध नहीं पाया।

भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित शोध अध्ययन दोनों के बीच सकारात्मक संबंध का संकेत देते हैं। दाश और साहू (2010) ने तर्क दिया कि बुनियादी ढाँचे के निर्माण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन वृद्धि पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण

<sup>^</sup> लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। राजीव दास के इनपुट के हम आभारी हैं। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।



रूप से प्रभाव डाला है। कुमारी और शर्मा (2017) ने प्रतिपादित किया कि भारत के मामले में, बुनियादी ढांचे के विकास ने 1-2 साल के अंतराल के साथ आर्थिक विकास को अनुकूल रूप से प्रभावित किया। रथ एवं अन्य, (2022) ने भारत में राज्यों के पूंजीगत परिव्यय और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के बीच एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक संबंध दिखाया और यह कि वर्तमान वर्ष का निर्णय पूंजीगत परिव्यय के पिछले मूल्यों से प्रभावित था। मिश्रा एवं अन्य, (2017) ने आर्थिक विकास और पूंजीगत परिव्यय के बीच महत्वपूर्ण संबंध पाया। इस प्रकार, बुनियादी ढांचे में निवेश पर व्यय, विशेष रूप से सरकारी व्यय, के महत्व की वकालत जीडीपी वृद्धि के लिए की गई थी।

### III. अवसंरचना, विकास और कल्याण

अवसंरचना भौतिक संरचनाओं का एक समूह है जो आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाती है और आर्थिक संचालन की क्षमता को सहारा देती है। इसमें "भौतिक सुविधाएँ, संस्थान और संगठनात्मक संरचनाएँ या समाज के संचालन के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार" शामिल हैं (अंकटाड, 2008)। अवसंरचना सामाजिक पूँजी भी है जिसमें उत्पादक गतिविधियों के संचालन हेतु बुनियादी सेवाएँ शामिल हैं। इसके दो घटक हैं - आर्थिक या भौतिक और सामाजिक। पहले में मुख्य रूप से परिवहन और संचार के साधन शामिल हैं जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, और दूसरे में शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ आदि शामिल हैं, जो लोगों के कल्याण को प्रभावित करते हैं। पर्याप्त परिवहन नेटवर्क के अभाव में कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता होती है और तैयार उत्पादों को बाजारों तक पहुँचाने में बाधा आती है। किसानों को कम कीमत मिलती है जिससे ग्रामीण आय में कमी आती है और परिणामस्वरूप विकास में बाधा आती है। भौतिक अवसंरचना उत्पादन लागत को कम करती है और साधन उत्पादकता को बढ़ाती है। अवसंरचना के विकास में आवास, परिवहन, दूरसंचार, स्वच्छता और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों सहित देश के लिए आवश्यक परिसंपत्तियों का निर्माण शामिल है।

प्रौद्योगिकी एक क्रांतिकारी माध्यम रही है जो सरकारी लाभकारी योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुँच और लक्षित

लाभार्थियों तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। डिजिटल अवसंरचना में भौतिक और सॉफ्टवेयर-आधारित व्यवस्थाएँ शामिल हैं जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, दूरस्थ कार्यों और अन्य आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हैं। इनमें डेटा सेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कर्मचारी, फाइबर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि शामिल हैं। डिजिटल अवसंरचना एक प्रमुख उपयोगिता है जो आर्थिक विकास और वृद्धि में योगदान देती है।

मानव जीवन की गुणवत्ता बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और एक मैत्रीपूर्ण एवं सुखद वातावरण में रहने पर निर्भर करती है। यह सामाजिक अवसंरचना द्वारा संभव होता है। सामाजिक अवसंरचना में मानव विकास और कल्याण हेतु सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था और सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव शामिल है। इनमें वृद्धजनों, असंगठित श्रमिकों और आकांक्षी क्षेत्रों जैसे विभिन्न वर्गों के लिए तैयार की गई शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ शामिल हैं। सामाजिक अवसंरचना मानव दक्षता और कौशल को बढ़ाती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है।

अवसंरचना पर व्यय अपने गुणक प्रभावों के माध्यम से आर्थिक विकास को लाभान्वित करता है (विश्व बैंक, 2023)। बुनियादी ढांचे में विस्तार उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ समग्र मांग के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाता है। यह कनेक्टिविटी में वृद्धि, माल और लोगों की आवाजाही में तेजी लाने, लागत में कमी, व्यापार करने में आसानी को सुविधाजनक बनाने और विभिन्न सुविधाओं और वित्तीय सेवाओं तक लोगों की पहुँच बढ़ाने के माध्यम से होता है। बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश निजी खर्च की तुलना में बड़े गुणक पैदा करता है क्योंकि पूर्व में समग्र मांग पर इसके सकारात्मक प्रभाव के अलावा, निजी निवेश में भीड़ के माध्यम से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने की क्षमता है। इसके अलावा, यह अल्प और दीर्घकालिक दोनों में उत्पादन बढ़ाता है और सरकारी ऋण को जीडीपी अनुपात में घटाता है (आईएमएफ, 2014)।

वैश्विक अनुभव ने बुनियादी ढाँचे और आर्थिक विकास एवं वृद्धि के स्तर के बीच एक मज़बूत सहसंबंध और जुड़ाव दिखाया है। दुनिया भर के विभिन्न देश अपनी अवसंरचना-आधारित रणनीतियों से लाभान्वित हुए हैं। अमेरिका, जर्मनी, इटली, इथियोपिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, जापान, चीन और उप-सहारा अफ्रीका के अनुभव बताते हैं कि अवसंरचना में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश ने विभिन्न माध्यमों, जैसे कि उत्पादकता में वृद्धि और संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार, के माध्यम से सकारात्मक और तेज़ विकास में मदद की है। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई और वृद्धि समान रही। इस प्रकार, विभिन्न देशों का अंतरराष्ट्रीय अनुभव विकास और कल्याण पर सरकार द्वारा संचालित अवसंरचना के विकास के महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि करता है।

## IV. भारत में अवसंरचना विकास

### IV.1 ऐतिहासिक विकास

स्वतंत्रता के बाद, भारत में अवसंरचना के निर्माण सहित नियोजित विकास का युग शुरू हुआ। पहले दो दशकों के दौरान, बचत और ऋण के संस्थागतकरण और विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) की स्थापना ने अवसंरचना के वित्तपोषण को सुगम बनाया। बैंकिंग पर सामाजिक नियंत्रण के अगले युग में देश भर में वित्तीय अवसंरचना में परिवर्तन देखा गया जिसने अवसंरचना के निर्माण में सहायता की। 1990 का दशक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के साथ देश के आर्थिक प्रबंधन में आमूल-चूल परिवर्तन के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद संस्थागत, संरचनात्मक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुए, जिसने बाजार-उन्मुख समाधानों के माध्यम से अवसंरचना के विकास को गति दी। अवसंरचना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाया गया। राकेश मोहन की अध्यक्षता में अवसंरचना परियोजनाओं के व्यावसायीकरण पर विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों ने आगे के अवसंरचना विकास का खाका तैयार किया। 2006 में,

आर्थिक या सामाजिक रूप से लाभकारी लेकिन वित्तीय रूप से अव्यवहारिक परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना (वीजीएफएस) शुरू की गई थी। इसके तहत, पूंजीगत व्यय का 40 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान किया गया था। पिछले दशक में अवसंरचना विकास में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 2009 में, घर-घर सेवा वितरण के एक माध्यम के रूप में आधार की शुरुआत के साथ, भारत में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का उदय हुआ। कोविड के बाद के परिदृश्य में, जब भौतिक संपर्क अव्यवहारिक हो गए, डिजिटल अवसंरचना का महत्व और भी स्पष्ट हो गया।

### IV.2 उच्चतर सतहों की उड़ान

भारत आर्थिक विकास प्राप्त करने हेतु एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की आकांक्षा रखता है जो सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दे और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे, जो वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कौशल द्वारा सक्षम हो। ये सभी मिलकर सभी लोगों के कल्याण हेतु समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। पिछले दशक के दौरान इस दिशा में प्रयास शुरू किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संख्या 9 का उद्देश्य "सभी के लिए किफायती और समान पहुँच पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक विकास और मानव कल्याण को समर्थन देने हेतु क्षेत्रीय और सीमा-पार अवसंरचना सहित गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और आघातसहनीय अवसंरचना विकसित करना" है।<sup>1</sup> बुनियादी ढाँचे पर ध्यान "भारतीय विकास मॉडल" का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य "निरंतर, तेज़, समावेशी विकास" है (नीति आयोग, 2023)। "सामाजिक परिव्यय पूँजी" के माध्यम से देश के सुदूरतम भागों तक आर्थिक विकास को पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं। इसके महत्व को समझते हुए और अवसंरचना के पूर्ण गुणक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने 2019 में "अग्रेषित कार्यक्रम-आत्मक दृष्टिकोण" अपनाया। इनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (एनएमपी), राष्ट्रीय

<sup>1</sup> आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (खंड 2), भारत सरकार



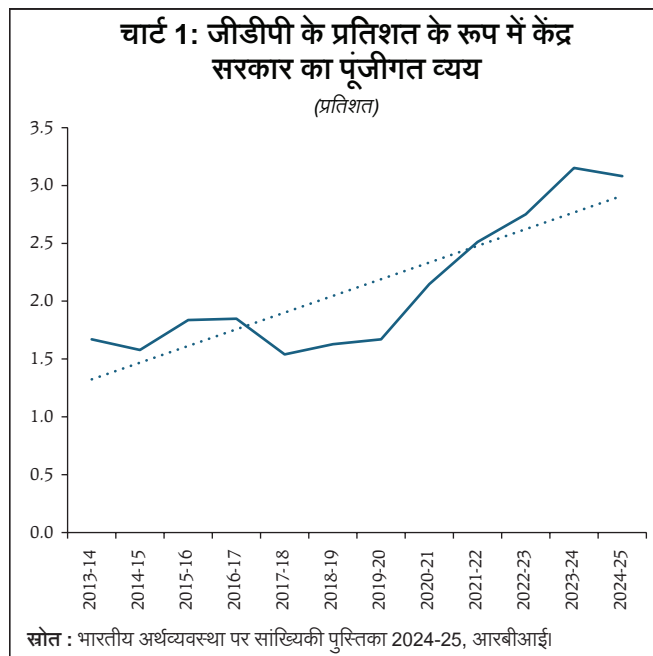
अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), भौतिक अवसंरचना के विस्तार हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), राजकोषीय सुधार, वित्तपोषण कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था को हरित बनाने के उपाय और डिजिटल एवं सामाजिक अवसंरचना को बढ़ावा देना शामिल हैं। सरकार द्वारा हाल ही में अपनाए गए व्यापक कार्यक्रम का विवरण अनुबंध 'ए' में दिया गया है।

पिछले दशक के दौरान, केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2013-14 में ₹1.9 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹10.2 लाख करोड़ हो गई है, जिसमें 2018-19 से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (चार्ट 1)। इस अवधि के दौरान अवसंरचना में तेज़ वृद्धि हुई (चार्ट 2)। पूंजीगत व्यय और अवसंरचना में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि से जुड़ी हुई थी (चार्ट 3 और 4)।

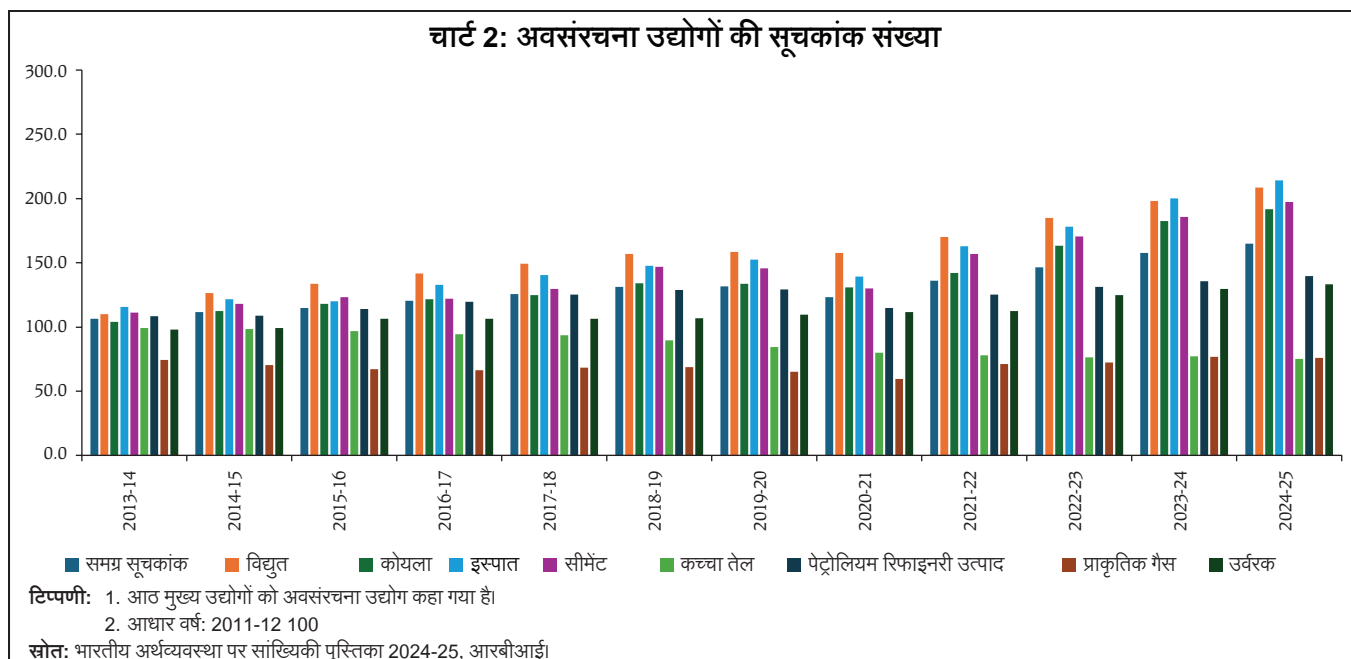
### IV.3 अनुभवजन्य अनुसंधान

#### IV.3.1 विभिन्न अनुमान

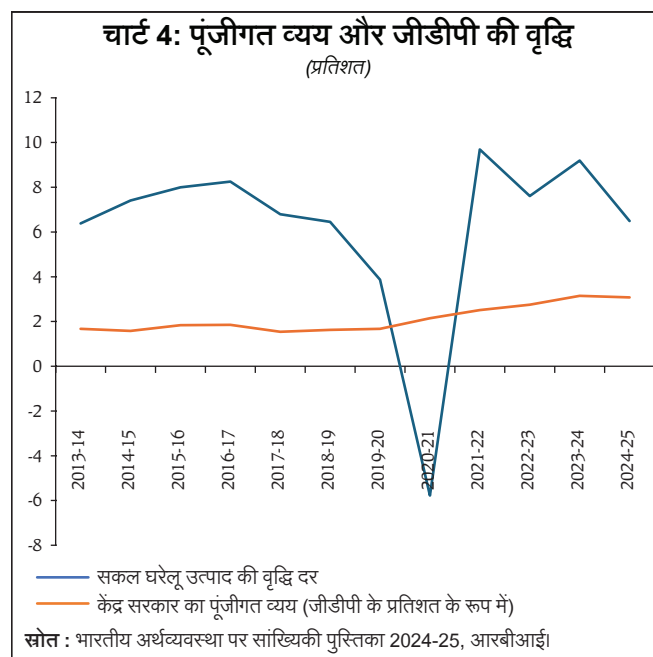
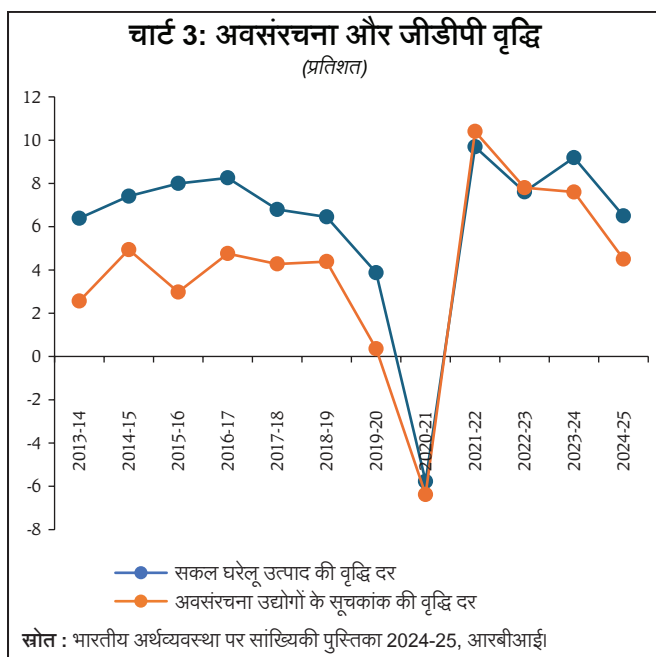
विभिन्न शोध अध्ययनों ने अवसंरचना पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। वर्ष 2019 में



भारत सहित दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों के 54 देशों के लिए प्रति व्यक्ति अवसंरचना के निवेश और प्रति व्यक्ति जीडीपी के बीच सहसंबंध गुणांक 0.75 पर महत्वपूर्ण था। वर्ष 2018 में भारत सहित 154 देशों के लिए समग्र अवसंरचना की गुणवत्ता और प्रति व्यक्ति जीडीपी के बीच सहसंबंध गुणांक 0.76 था।



<sup>2</sup> आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, भारत सरकार



भारत के लिए जीडीपी के साथ रेल, सड़क, हवाई अड्डे और अंतर्देशीय मोड से संबंधित अवसंरचना में निवेश के सहसंबंध 0.90 (भारत सरकार, 2019) से अधिक मूल्यों के साथ काफी अधिक थे। विभिन्न अनुभवजन्य कार्यों ने अवसंरचना आउटपुट का अनुमान लगाया है (1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक के प्रारंभ में) 0.38 - 0.56 (खान, 2015) के बीच था। भारत के लिए, साहू (2011) ने इसे 0.5 तक पाया है। सार्वजनिक अवसंरचना का उत्पादन आउटपुट 8 प्रतिशत रहा (बॉम और लाइटहार्ट, 2013)। अवसंरचना में निवेश के लाभ पर्याप्त थे और अवसंरचना पर सार्वजनिक निवेश के गुणकों (निजी खपत के संदर्भ में) का उत्पादन और कल्याण का मूल्य क्रमशः 1-1.4 और 0.8 पर गणना किया गया था (आईएमएफ, 2016), जब अवसंरचना पर्याप्त रूप से प्रभावी थी। अवसंरचना ने जीवन की गुणवत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा (बाल्डविन, डिकसन, 2008), पर्यावरण और कल्याण (ब्रिस्टो और नेल्थोर्प, 2000), उत्पादन और रोजगार (गु, मैकडोनाल्ड, 2009), क्षेत्रीय विकास (निजकैंप, 1986) को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया।

अवसंरचना ने विनिर्माण फर्मों की उत्पादकता और दक्षता को अनुकूल रूप से प्रभावित किया (मित्रा एवं अन्य, 2002)। इसने गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (दत्त और रैवेलियन, 1998)

अवसंरचना के निवेश के लिए राजकोषीय गुणक प्रभाव का अनुमान विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगाया गया था। यह 2 वर्ष तक 0.8, 2-5 वर्ष के लिए 1.5 और मंदी में 1.6 की सीमा में था। अवसंरचना के निवेश गुणक का मूल्य समग्र सार्वजनिक व्यय के गुणक से बड़ा था। भारत में, गुणक के अनुमानित मूल्य 2.5-3.5 के बीच काम करते थे (केपीएमजी, 2024)। इसका मतलब है कि अवसंरचना के निर्माण के लिए व्यय किए गए प्रत्येक रुपये के लिए, जीडीपी में वृद्धि ₹2.50 से ₹3.50 होगी। विस्तारवादी अवधि की तुलना में अर्थव्यवस्था के संकुचन चरण के दौरान गुणक मूल्य अधिक था, जिससे जरूरत पड़ने पर अधिक लाभ हुआ। इसके अलावा, इसका प्रभाव राजस्व व्यय की तुलना में लंबी अवधि तक रहा। तदनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के रूप में अवसंरचना के निर्माण या पूंजीगत व्यय के लिए व्यय की वृद्धि विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई।

<sup>3</sup> प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा उद्धृत एस एंड पी ग्लोबल द्वारा अनुमान लगाया गया है।

### IV.3.2 अनुभवजन्य अभ्यास

हम अवसंरचना और जीडीपी के बीच संबंधों को देखते हैं। इसका अध्ययन करने के लिए, हम एक अवसंरचना सूचकांक बनाते हैं और जीडीपी के साथ संबंध देखते हैं। हमारे अध्ययन में उपयोग किए गए डेटा में 2006 से 2021 तक की अवधि शामिल है और यह वार्षिक आवृत्ति पर है। वास्तविक जीडीपी, प्रति व्यक्ति जीडीपी और सड़क नेटवर्क के आंकड़े सीईआईसी<sup>4</sup> से प्राप्त किए गए हैं। शेष सभी अवसंरचना संकेतक वर्ल्ड बैंक के वैश्विक विकास संकेतक<sup>5</sup> से लिए गए हैं। प्रत्येक संकेतक के लिए वर्ष-दर-वर्ष विकास दर की गणना की गई है। हम अवसंरचना चर की वृद्धि दर के आधार पर तीन अलग-अलग सूचकांक बनाते हैं। पहली विधि में, हम वृद्धि दरों का सरल औसत लेते हैं। दूसरी विधि में, हम वृद्धि दरों का मुख्य घटक लेते हैं, और तीसरे में, हम गतिशील कारक मॉडल (डीएफएम) के आधार पर एक सूचकांक बनाते हैं। पहले दो रैखिक विधियाँ हैं और उनके भार सारणी 1 में दिए गए हैं।

सरल औसत में, हम मानते हैं कि प्रत्येक चर समान रूप से कार्य करता है। हम पाते हैं कि बिजली, स्वच्छ ईंधन और खाना पकाने की तकनीकों तक पहुँच, सड़कों की लंबाई और टेलीफोन का मुख्य घटक विश्लेषण (पीसीए) सूचकांक में महत्वपूर्ण भार है, और इन चरों में कोई भी वृद्धि सूचकांक में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगी। समीकरण 1 प्रतिगमन मॉडल को दर्शाता है। प्रतिगमन के परिणाम सारणी 2 में दिए गए हैं।

$$GDP = a + b \text{ Infrastructure Index} + \epsilon \quad (1)$$

#### सारणी 1: अवसंरचना चर और भार

अवसंरचना चर	पीसीए भार	समान भार
खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकियों तक पहुँच (आबादी का प्रतिशत)	0.58	0.2
बिजली तक पहुँच (जनसंख्या का प्रतिशत)	0.62	0.2
फिक्स्ड टेलीफोन सब्सक्रिप्शन (प्रति सौ लोग)	0.32	0.2
हवाई परिवहन, माल ढुलाई (मिलियन टन-किमी)	0.18	0.2
सड़कों की लंबाई: राजमार्ग: लोक निर्माण विभाग: राष्ट्रीय	0.38	0.2

<sup>4</sup> <https://www.ceicdata.com/en>

<sup>5</sup> <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>

#### सारणी 2: प्रतिगमन अनुमान

	मॉडल 1 (औसत)	मॉडल 2 (पीसीए)	मॉडल 3 (डीएफएम)
अंतरोधन	6.25*** 0.97	6.76*** 0.91	6.77*** 0.91
अवसंरचना सूचकांक	0.22** 0.19	0.17* 0.74	0.16* 0.74
समायोजित आर-वर्ग	0.18	0.11	0.11

महत्वपूर्ण कोड: \*\*\*\* 0.001 \*\*\* 0.01 \*\* 0.1

डेटा स्रोत: हमारे अध्ययन में प्रयुक्त डेटा 2006 से 2021 की अवधि को वार्षिक आवृत्ति के साथ कवर करता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और सड़क नेटवर्क के आंकड़े सीईआईसी से हैं। शेष सभी अवसंरचना संकेतक वर्ल्ड बैंक के वैश्विक विकास संकेतकों से हैं।

नतीजे साफ़ तौर पर दर्शाते हैं कि अवसंरचना सूचकांक जीडीपी वृद्धि के एक हिस्से की व्याख्या करता है। अवसंरचना सूचकांक महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि अवसंरचना ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अध्ययन को राज्य स्तर तक विस्तारित किया गया है ताकि एक पैनल डेटा तैयार किया जा सके जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को आश्रित चर और स्वतंत्र चरों के रूप में दर्शाया गया है: 1) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), 2) प्रस्तावित निवेश, 3) कृषि उपज, 4) पंजीकृत वाहन, 5) सड़क की लंबाई, 6) दूरसंचार ग्राहक और 7) प्रत्येक राज्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक निर्यात यह एक असंतुलित पैनल है जिसमें 2012-2025 तक के कुल 431 अवलोकनों के डेटा शामिल हैं। हॉसमैन परीक्षण का उपयोग किया गया है और परिणाम यादृच्छिक प्रभाव के बजाय स्थिर प्रभाव के पक्ष में पाए गए हैं (p-मान < 0.001 के साथ)। प्रतिगमन को समीकरण 2 द्वारा दर्शाया गया है और अनुमान सारणी 3 में दिए गए हैं।

$$\begin{aligned} \text{Log(GSDP)} \sim & \text{Log(FDI)} + \text{Log(Proposed\_} \\ & \text{Investment)} + \text{Agricultural\_Yield} + \text{Registered\_} \\ & \text{Vehicles} + \text{Log(Roads\_Length)} + \text{Log(Telecom\_} \\ & \text{Subscribers)} + \text{Log(Electronics\_Exports)} \end{aligned} \quad (2)$$

**सारणी 3: निर्धारित प्रभाव पैनेल प्रतिगमन अनुमान**

गुणांक	अनुमान	मानक त्रुटि	टी-वैल्यू	पीआर(> t )
लॉग_एफडीआई	0.013	0.0028	4.425	1.25e-05 ***
लॉग_प्रस्तावित निवेश	0.118	0.0140	8.457	< 2e-16 ***
कृषि प्रतिफल	0.000	0.0001	3.906	1.12e-04 ***
पंजीकृत वाहन	0.000	0.0001	-3.508	5.04e-04 ***
लॉग_सड़क_लंबाई	0.000	0.0000	2.857	4.49e-03 ***
लॉग_संचार_अभिदाता	0.145	0.0033	4.436	1.19e-05 ***
लॉग_इलेक्ट्रॉनिक निर्यात	0.008	0.0027	3.063	2.35e-03 **

समायोजित आर-वर्ग: 0.15238,

महत्वपूर्ण कोड: '\*\*\*' 0.001 '\*\*' 0.01

उपरोक्त परिणाम हमारी इस परिकल्पना की पुष्टि करते हैं कि अवसंरचना जीडीपी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम एक निश्चित प्रभाव प्रतिगमन मॉडल के लिए समूह-प्रबल मानक त्रुटियों की गणना करते हैं, जिसमें विषम-प्रसंभाव्य और समूह के भीतर सहसंबंध जैसे मुद्दों का समाधान किया जाता है (होचले, डी., 2007)। यह "स्थिति" के आधार पर क्लस्टर किए गए प्रबल मानक त्रुटियों की गणना करता है, समान और स्वतंत्र वितरण मान्यताओं को शिथिल करता है, जो साधारण न्यूनतम वर्ग (ओएलएस) में प्रयुक्त एक मान्यता है। लघु-नमूना सुधार विधि परिमित क्लस्टरों के लिए समायोजन करती है। पुनर्गणित गुणांक महत्व परीक्षण सांख्यिकी (टी-सांख्यिकी, पी-मान) (एसएआरएनआई 4) के साथ गुणांक सार्थक बने रहते हैं।

परिणाम दर्शाते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 1 प्रतिशत की वृद्धि जीएसडीपी में 0.013 प्रतिशत की

**सारणी 4: मजबूत निर्धारित प्रभाव पैनेल प्रतिगमन अनुमान**

गुणांक	अनुमान लगाना	मानक त्रुटि	टी-वैल्यू	पीआर (> t )
लॉग_एफडीआई	0.013	0.0030	4.178	3.59e-05 ***
लॉग_प्रस्तावित निवेश	0.118	0.0161	7.375	8.77e-13 ***
कृषि प्रतिफल	0.000	0.0001	3.458	6.02e-04 ***
पंजीकृत वाहन	0.000	0.0001	-3.027	2.61e-03 **
लॉग_सड़क_लंबाई	0.000	0.0000	2.101	3.62e-02 **
लॉग_संचार_अभिदाता	0.145	0.0036	4.038	6.26e-05 ***
लॉग_इलेक्ट्रॉनिक निर्यात	0.008	0.0030	2.744	6.31e-03 **

महत्वपूर्ण कोड: '\*\*\*' 0.001 '\*\*' 0.01

वृद्धि से जुड़ी है और निवेश में 1 प्रतिशत की वृद्धि जीएसडीपी में 0.118 प्रतिशत की वृद्धि से जुड़ी है। दूरसंचार ग्राहकों की संख्या में 1 प्रतिशत की वृद्धि से जीएसडीपी में 0.15 प्रतिशत की वृद्धि होती है, और इलेक्ट्रॉनिक निर्यात वृद्धि में 1 प्रतिशत की वृद्धि से जीएसडीपी में 0.008 प्रतिशत की वृद्धि होती है। शेष चरों का जीएसडीपी पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। परिणामों का महत्व हमारी परिकल्पना की और पुष्टि करता है।

## V. अवसंरचना का वित्तपोषण

भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनने के लिए, वार्षिक वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.6 प्रतिशत की आवश्यकता होगी (बेहरा एवं अन्य., 2023)। 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अवसंरचना में निवेश अगले पांच वर्षों के लिए 8-10 प्रतिशत की वार्षिक दर से किया जाना चाहिए (एनबीएफआईडी, 2022)। इसके लिए, अवसंरचना पर आवश्यक वार्षिक व्यय जीडीपी का 7-8 प्रतिशत यानी लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। इस संदर्भ में, अवसंरचना में निवेश का वित्तपोषण महत्व रखता है। अवसंरचना के वित्तपोषण में कई चुनौतियाँ शामिल हैं। इनमें उच्च विफल लागत और लंबी उत्पादन-पूर्व अवधि से उत्पन्न आस्ति-देयता बेमेल, अनुमोदन में देरी के कारण लागत में वृद्धि, करारों का उल्लंघन, भूमि अधिग्रहण में समस्या परियोजनाओं की परस्पर निर्भरता और पूरक इकाइयों की अनुपलब्धता के कारण समस्याएँ और भी बढ़ जाती हैं, जिससे समग्र योजना के अभाव में समय की अधिकता और व्यापक प्रभाव पड़ता है। विकसित ऋण जुटाने वाले बाजार और वित्तीय प्रणाली के अभाव के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण न चुकाने और पिछले दशक में बैंकों की उच्च अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के कारण अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

<sup>6</sup> आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, भारत सरकार।

पिछले कुछ वर्षों में, रिज़र्व बैंक और सरकार ने अवसंरचना के वित्तपोषण को सुगम बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनका विवरण अनुबंध 'बी' में दिया गया है। निजी संस्थानों द्वारा लंबी परिपक्वता अवधि और जोखिम लेने से बचने के कारण, विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) को बाज़ार की विफलता को दूर करने और राष्ट्र के व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। भारत में, अवसंरचना के वित्तपोषण हेतु एक प्रमुख विकास वित्त संस्थान के रूप में, संसद के एक अधिनियम (एनएबीएफआईडी अधिनियम, 2021) द्वारा 2022 में राष्ट्रीय अवसंरचना विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) की स्थापना की गई थी। इसने अवसंरचना के लिए स्थिर वित्त प्रदान करने, चलनिधि और गहराई के साथ डेरिवेटिव और बॉण्ड बाजारों का विकास करने और अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए नए वित्तपोषण साधनों की खोज पर काम शुरू कर दिया है। एनएबीएफआईडी अवसंरचना के लिए ऋण प्रदान करता है, निजी क्षेत्र और विदेशों सहित संस्थानों से निवेश प्राप्त करता है, मौजूदा ऋणों का पुनर्वित्त करता है, विवादों के समाधान में सहायता करता है, और अवसंरचना के वित्तपोषण में विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है। यह सावधि ऋण, डिबेंचर, बॉण्ड, गारंटी और लेटर ऑफ कम्फर्ट सहित कई सेवाएँ प्रदान करता है। ये सेवाएँ उन अवसंरचना परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन में भी सहायक होंगी जो अव्यवहारिक लागत और देरी की समस्याओं का सामना कर रही हैं। इसकी गतिविधियों में दीर्घकालिक अवसंरचना के विकास हेतु संस्था निर्माण को सुगम बनाने हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करना शामिल है। एनएबीएफआईडी ने वर्ष 2023-24 तक ₹1 लाख करोड़ से अधिक की मंजूरी दी है और संवितरण राशि भी बढ़ाई है (राव, 2024)। बहुपक्षीय संस्थागत साझेदारी के एक भाग के रूप में, इसने निजी वित्त जुटाकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा जैसे जलवायु जोखिम न्यूनीकरण के लिए, के विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और

विदेशी राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय के साथ एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह शहरी निकायों के वित्तपोषण और वित्तीय साधनों के विकास में सहायता करेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के साथ इसके समझौता ज्ञापन से तकनीकी विशेषज्ञता, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा (एनएबीएफआईडी, 2025)।

आगे देखें तो, एनएबीएफआईडी द्वारा की जाने वाली अन्य पहलों से इसके मिशन में और अधिक योगदान मिल सकता है। भविष्य निधि और बीमा कंपनियों जैसे बड़े दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों के पैमाने में विस्तार के साथ, यह उनसे धन प्राप्त कर सकता है। यह वित्त के वैश्विक और घरेलू स्रोतों का उपयोग करने के लिए एक उच्च क्रेडिट रेटिंग भी प्राप्त कर सकता है। यह सरकारी संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए अपना स्वयं का स्थायी वित्तपोषण मॉडल विकसित कर सकता है। यह ज्ञान-आधार और विशेषज्ञता के साथ एक मजबूत शासन और आश्वासन तंत्र विकसित कर सकता है। यह सर्वेक्षण आदि के माध्यम से अपनी वित्तपोषित परियोजनाओं के मूल्यांकन और गतिशील निगरानी में अपने कौशल को निखार सकता है। संकटग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए प्रणालियाँ स्थापित की जा सकती हैं। यह सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जलवायु प्रतिरोधी निम्न कार्बन अवसंरचना और प्रौद्योगिकी के लिए धन उपलब्ध करा सकता है। यह अवसंरचना परियोजनाओं और बॉण्ड बाज़ार के विकास के लिए तकनीकी सलाहकार सेवाएँ प्रदान कर सकता है। क्रेडिट चूक स्वैप (सीडीएस) जैसे उत्पादों का प्रावधान और ऋण समूहन को सुविधाजनक बनाना इस संबंध में एक अच्छा प्रयास होगा (राव, 2024)।

यह वांछनीय होगा कि वित्त पोषण संस्था अवसंरचना परियोजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में वित्त पोषित संस्थाओं के प्रदर्शन पर नियंत्रण रखे। इस तरह के 'अनुशासन' की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। "पारस्परिक नियंत्रण तंत्र" (एम्सडेन, 2001) पर आधारित "आवंटन अनुशासन" के सिद्धांत का पालन किया जा सकता है (कुमार, 2022)। प्रदर्शन ट्रेकिंग और हस्तक्षेप वित्तपोषण संस्था को नियंत्रण रखने में सक्षम बनाएंगे, और लाभार्थी संस्थाएं परियोजनाओं

<sup>7</sup> <https://www.nabfid.org>



के लक्ष्यों को प्राप्त करके पारस्परिक व्यवहार करेंगी। वित्तदाता को परियोजनाओं की व्यवहार्यता और उद्देश्यों की पूर्ति का आकलन करने के लिए वित्त प्रस्तावों की जांच के लिए कठोर प्रक्रियाओं को लागू करने की आवश्यकता होगी। कार्य की प्रगति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से वित्त पोषण का प्रावधान वांछनीय होगा। सुदृढ़ एवं प्रभावी निगरानी सहायक होगी। विफलता या चूक की स्थिति में, पुनर्गठन या परिसमापन की एक प्रणाली लागू करना आवश्यक होगा। इसमें प्रतिभूतिकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रतिभूतिकरण अवसंरचना के वित्तपोषण में एक महत्वपूर्ण साधन है। यह ऋण बाजार को विविधीकृत बनाता है। बैंकों को अपनी पूँजी और आस्ति देयता प्रबंधन जारी करने में लाभ होता है। छोटे और मध्यम आकार के बैंकों को ऋण मूल्यांकन की अपनी क्षमता में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रतिभूतिकरण उन्हें परियोजना के शुरू होने के बाद बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण में सक्षम बनाता है। इस संदर्भ में, प्रतिभूतिकरण के लिए बाजार विकसित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए, विभिन्न बाधाओं का समाधान करना और पर्याप्त प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने, लंबी अवधि के लिए प्राप्य राशियों की मांग बढ़ाने, दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों की भागीदारी, निवेशक आधार का विस्तार, द्वितीयक बाजार का विकास, और फौजदारी कानूनों सहित कर-संबंधी और कानूनी मुद्दों के समाधान जैसी पहल करना अनिवार्य होगा।

भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाने और व्यक्तियों और शहरों में निवेश को आकर्षित करने के लिए, शहरी अवसंरचना का विकास महत्वपूर्ण होगा। स्मार्ट शहरों के निर्माण की दिशा में तेजी से प्रगति और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सक्रिय पहल इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान देगी। नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए बॉण्ड और भूमि के आधार पर उपयुक्त और नए वित्त पोषण तंत्र की खोज करके अपने पूँजीगत व्यय को बढ़ा सकते हैं। हरित बॉण्ड सहित नगरपालिका बॉण्ड जारी करने से नगर निगमों द्वारा स्थायी आधार पर वित्त जुटाने में मदद मिलेगी (आरबीआई, 2024)। स्थानीय शहरी अवसंरचना

के वित्तपोषण के लिए 1990 के दशक के मध्य से भारत में नगरपालिका बॉण्ड जारी करना शुरू हुआ। इसकी वृद्धि को एक अमेरिकी एजेंसी, नगरपालिका बॉण्ड पर सेबी के विनियामक ढांचे, अमृत योजना के तहत अनुदान, और सेबी के सूचना डेटाबेस और नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए नगरपालिका बॉण्ड पर रिपॉजिटरी के तहत मार्गदर्शन के माध्यम से सुगम बनाया गया था। हाल ही में नगरपालिका बॉण्ड वित्तपोषण में वृद्धि हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा हाल ही में नगरपालिका बॉण्ड सूचकांक लॉन्च किया गया था, जो निवेश ग्रेड रेटिंग वाले निगमों द्वारा जारी किए गए बॉण्ड के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। इससे नगरपालिका बॉण्ड बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और निवेशक आधार का विस्तार होगा। नगरपालिका बॉण्ड जारी करना और उनका बाजार वर्तमान में प्रारंभिक चरण में है। 31 मार्च 2024 तक बकाया नगरपालिका बॉण्ड जारी करने की राशि 4,204 करोड़ रुपये थी, जो बकाया कॉर्पोरेट बॉण्ड का 0.09 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद का 0.01 प्रतिशत थी। निवेशक आधार बॉण्ड जारी करने के बड़े हिस्से के निजी स्थानों तक सीमित है। अवसंरचना में विस्तार को सक्षम करने के लिए, नगरपालिका बॉण्ड बाजार को तेजी से विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए नगर निगमों के वित्तीय प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग में सुधार जरूरी होगा। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और बाजार की भागीदारी को व्यापक बनाया जाएगा। कुछ स्थानीय निकायों ने हाल ही में सकारात्मक पारिस्थितिक प्रभाव वाली परियोजनाओं के लिए हरित बॉण्ड जारी करना शुरू किया है। इससे सतत शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। जारी करने में अतिरिक्त लागत शामिल है। हालांकि, जैसे-जैसे बाजार विकसित होगा, लागत में गिरावट आएगी। चौदहवें वित्त आयोग ने बॉण्ड बाजारों तक पहुंचने वाले स्थानीय निकायों की मदद करने के लिए एक मध्यस्थ के गठन की सिफारिश की। इसके अलावा, स्थानीय कर सुधार, कर और गैर-कर राजस्व बढ़ाने के लिए अभिनव रणनीतियां, नगरपालिका सेवाओं और करों के लिए उपयोगकर्ता शुल्क में संशोधन और प्रदर्शन से जुड़े नगरपालिका अनुदान बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण की व्यापकता को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे।



बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए एक और प्रभावी अवसर है। यह संस्थाओं को ब्याज दरों और विनिमय दरों जैसे कारकों के आधार पर कम लागत और/या आसान पहुंच पर विदेशी धन उधार लेने में सक्षम बनाता है। इससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत कम हो जाती है। दूसरी ओर, अत्यधिक विदेशी ऋण और प्रतिकूल विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ हेजिंग लागत ऋण जाल के जोखिम के साथ उनकी ऋणग्रस्तता को बढ़ाते हैं और सामान्य रूप से देश की बाह्य क्षेत्र की स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं। ईसीबी नीति का प्रगतिशील उदारीकरण, रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई नियम-आधारित गतिशील सीमा, भारत के विदेशी ऋण का छोटा हिस्सा और विदेशी क्षेत्र की मजबूती ईसीबी के माध्यम से अवसंरचना वित्तपोषण में अंतर को पाटने में सक्षम होगी। व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सरकारी गारंटी के साथ ईसीबी का समर्थन करना मददगार हो सकता है।

बैंकों द्वारा सतत अवसंरचना का वित्तपोषण ऐसी आस्तियों की स्थिति पर निर्भर करेगा। बैंकिंग प्रणाली के साथ अवसंरचना में उच्च स्तर की दबावग्रस्त आस्तियों के निर्माण को रोकने के लिए, कुछ उपाय उपयोगी होंगे। सबसे पहले, परियोजना के पूरा होने के समय कार्यक्रम का यथार्थवादी मूल्यांकन और इक्विटी और ऋण के साथ उनके वित्तपोषण की उचित संरचना लागत को निम्नतम स्तर पर रखेगा और वित्त पोषण में व्यवहार्यता में वृद्धि करेगा। दूसरा, दबाव से बचने के लिए परियोजनाओं के नकदी प्रवाह के अनुसार पुनर्भुगतान की अनुसूची तय की जा सकती है। तीसरा, परियोजना मूल्यांकन वित्त द्वारा वास्तविक रूप से इसके डिजाइनों, अनुमानों, जोखिमों की पहचान और वित्तपोषकों की जोखिम उठाने की क्षमता वाले लोगों के संबंध में किया जाना चाहिए। चौथा, परियोजना वित्तपोषण कॉर्पोरेट बॉण्ड सहित स्रोतों और साधनों के विविध मिश्रण के माध्यम से किया जा सकता है। पांचवां, ऋणदाताओं द्वारा ऋण मूल्य निर्धारण को जोखिमों को प्रतिबिंबित करना चाहिए और बदलते जोखिम प्रोफाइल के साथ समायोजित करने के लिए गतिशील होना चाहिए। छठा, संस्थागत सुधारों में दीर्घकालिक निवेशक आधार का विस्तार करना, पूंजी बाजार और अवसंरचना कोष की क्षमता का दोहन करना, विविध वित्तीय साधनों का विकास

करना और ऋणों के प्रतिभूतिकरण का विस्तार करना शामिल होगा।

अवसंरचना के वित्तपोषण के मामले में बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली आस्ति देयता बेमेल के मुद्दे को हल किया जा सकता है यदि वे अस्थिर दरों पर एक बड़ा हिस्सा उधार देते हैं। इसके अलावा, बैंकिंग प्रणाली की आस्तियों में किसी भी दबाव से उत्पन्न होने वाले वित्तीय स्थिरता जोखिमों से बचने के लिए अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने की आवश्यकता है। निवेश बैंकर वित्त पोषण के अभिनव तरीकों के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और सरकार और निजी क्षेत्र के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर सकते हैं। अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए एक बॉण्ड बाजार विकसित करने की आवश्यकता है। यह ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल को बढ़ाएगा, ऋणदाताओं की बुक में परिपक्वता बेमेल को कम करेगा, वित्तपोषण आधार को व्यापक बनाएगा, जोखिम प्रबंधन साधनों का विस्तार करेगा, मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन को सक्षम करेगा और वित्तपोषकों पर उधारकर्ताओं के प्रभाव को कम करेगा (खान, 2015)। सॉवरेन हरित बॉण्ड के लिए बाजार को विकसित करने को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि उनके पास कम पुनर्वित्त जोखिम के साथ एक लंबा कार्यकाल है, जिसमें ग्रीनियम (सादे बॉण्ड पर प्रीमियम) शामिल है, जलवायु से संबंधित अवसंरचना के लिए सरकार को स्थिर वित्त पोषण स्रोत प्रदान करता है और हरित परिवर्तन को वित्तपोषित करता है।

अंत में, चूंकि घरेलू बचत आवश्यक संसाधनों से कम हो जाती है, इसलिए रियायती बहुपक्षीय संस्थागत वित्त और संप्रभु गारंटी के साथ बाह्य वाणिज्यिक उधार जैसे स्थिर बाह्य स्रोतों के माध्यम से अवसंरचना के वित्तपोषण के तरीकों की खोज करना महत्वपूर्ण होगा। यह संसाधन अंतर को पूरा कर सकता है और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से परियोजनाओं को व्यवहार्यता और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान कर सकता है। यह प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित करते हुए और निधियों के बिना बचाव हिस्से से जोखिमों को कवर करते हुए किया जाना चाहिए। नीतिगत दृष्टिकोण से, क्षेत्र-वार विवरण के साथ देश में विभिन्न प्रकार

की अवसंरचना की मौजूदा आपूर्ति के वृहद आथक मात्रात्मक मूल्यांकन और अवसंरचना की आवश्यकता की सीमा की आवश्यकता है। यह अंतर निजी क्षेत्र से निवेश की आवश्यकता का अनुमान प्रदान करेगा। तदनुसार, विभिन्न तरीकों का दोहन करके अंतर का वित्तपोषण किया जा सकता है।

## VI. निष्कर्ष

अवसंरचना में निवेश अपने गुणक प्रभावों के माध्यम से और एक मिलनसार मानव जीवन को सुविधाजनक बनाकर सतत आर्थिक विकास, विकास और कल्याण को अनुकूल रूप से प्रभावित करता है। एक एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण, लागत दक्षता, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, हरित पहलुओं, उच्च पूंजीगत व्यय और विस्तारित वित्तपोषण तंत्र के साथ भौतिक, डिजिटल और सामाजिक अवसंरचना पर भारत की हालिया नीति जोर देश को एक स्थायी तरीके से उच्च विकास में ले जाने में प्रभावी साबित हो रही है। हमारे अनुभवजन्य अभ्यास से पता चलता है कि बुनियादी ढांचे के विकास ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को सकारात्मक और महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। अवसंरचना सूचकांक जीडीपी वृद्धि की एक महत्वपूर्ण मात्रा बताता है। तदनुसार, भविष्य की नीतिगत पहल देश भर में व्यापक आधार वाले अवसंरचना के निर्माण के लिए बढ़े हुए निवेश और परिचालन पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। अवसंरचना में निवेश की बड़ी आवश्यकता को देखते हुए, अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के रास्ते और तरीकों की खोज करना महत्वपूर्ण है। यह एनएबीएफआईडी द्वारा टिकाऊ और अभिनव वित्तपोषण मॉड्यूल तैयार करने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के विविध तरीकों की खोज करने, कॉर्पोरेट, नगरपालिका और हरित बॉण्ड बाजारों के विकास, प्रतिभूतीकरण, उचित परियोजना मूल्यांकन और ऋण मूल्य निर्धारण, अनुशासन के साथ परियोजना आवंटन और वित्तपोषण के वैकल्पिक और अभिनव आंतरिक और बाह्य स्रोतों के विकास के माध्यम से किया जा सकता है। अवसंरचना की आवश्यकताओं का व्यापक आर्थिक मूल्यांकन और आपूर्ति अंतराल की पहचान नीतियों के लिए आगे की दिशाएं प्रदान कर सकती है। ये विकास, समृद्धि और सभी के कल्याण के साथ इकोसिस्टम को विकसित करने की गति को बनाए रखने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे।

## संदर्भ

- Abiad A, Furceri D. and Topalova P. (2014). The Time is Right for an Infrastructure Push. *IMF Survey*, September 30. Retrieved from <https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sores093014a>
- Agenor, P. R. (2010). A Theory of Infrastructure-led Development. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 14 (5), 932-950.
- Alice, H. and Amsden (2003). The Rise of 'The Rest': Challenges to the West from Late Industrialising Economies. *Journal of Development Economics*, 71(2), 625-630.
- Ankrah, N., Mante, J. And Ndekugri, I. (2015). Challenges of Infrastructure Procurement in Emerging Economies and Implications for Economic Development: A Case Study of Ghana. In Abdulai, R.T., Obeng-Odoom, F., Ochieng, E. and Maliene, V. (eds.) *Real Estate, Construction and Economic Development in Emerging Market Economies*, Abingdon: Routledge [online], 9 (174-201). Retrieved from <https://rgu-repository.worktribe.com/output/246673/challenges-of-infrastructure-procurement-in-emerging-economies-and-implications-for-economic-development-a-case-study-of-ghana>
- Aschauer, D. A. (1993). Genuine Economic Returns to Infrastructure Investment. *Policy Studies Journal*, 21(2), 380-390.
- Babu, M. S. (2022). We Should Keep Close Track our Infrastructure Push. *Mint*, June.
- Baldwin J. R. and Dixon J. (2008). Infrastructure Capital: What is it? Where is it? How Much of it is There? *Canadian Productivity Review Research Paper* (No. 16). Retrieved from [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1507883](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1507883)

- Behera, H., Dhanya V., Priyadarshi K. and Goel S. (2023). India @100. *RBI Bulletin*, July.
- Bingswanger H., Khandker S. and Sosenzveig M. (1993). How Infrastructure and Financial Institutions Affect Agricultural Output and Investment in India. *Journal of Development Economics*, 41(2), 337-366. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/030438789390062R>
- Bom P. R. D. and Ligthart J. E. (2013). What Have We Learned from Three Decades of Research on the Productivity of Public Capital? *Journal of Economic Surveys*, 10 July. Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joes.12037>
- Bougheas S, Demetriades P and Mamuneas T (2001). Infrastructure, Specialisation and Economic Growth. *Canadian Journal of Economics*. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/2384551\\_Infrastructure\\_Specialization\\_And\\_Economic\\_Growth](https://www.researchgate.net/publication/2384551_Infrastructure_Specialization_And_Economic_Growth)
- Bristow A. L. and Nelthorp J. (2000). Transport Project Appraisal in the European Union. *Transport Policy*, 7(1), 51-60. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0967070X0000010X>
- Calderon C. and Serven L. (2010). Infrastructure and Economic Development in Sub-Saharan Africa. *Journal of African Economies*, 19(1), i13-i87. Retrieved from <https://doi.org/10.1093/jae/ejp022>
- Dash, R. and Sahoo, P. (2010). Economic Growth in India: The Role of Physical and Social Infrastructure. *Journal of Economic Policy Reform*, 13(4), 373-385.
- Datt G. and Ravallion M (1998). Why Have Some Indian States Done Better than Others at Reducing Rural Poverty? *Economica*, London School of Economics and Political Science, 65(257), 17-38.
- Diamond, J. (1989). Government Expenditure and Economic Growth: An Empirical Investigation. *IMF Working Paper*, May.
- Enimola, S. S. (2011). Infrastructure and Economic Growth: The Nigeria Experience, 1980–2006. *Journal of Infrastructure Development*, 2 (2).
- Fan S., Hazell T and Thorat S. (2000). Government Spending, Growth and Poverty in Rural India. *American Journal of Agricultural Economics*, 82(4), 1038-1051.
- Ganelli G. and Trevala, J. (2015). The Welfare Multiplier of Public Infrastructure Investment. *IMF Working Paper* (WP/16/40).
- Ghosh P. K. (2020). Nexus between Infrastructure and Economic Growth: An Empirical Study in the Post-Reform Period in India. *MPRA Munich Personal RePEc Archive*.
- Government of India (2019). *Economic Survey 2018-19*.
- Government of India (2022). *Frameworks for Sovereign Green Bonds*.
- Government of India, Ministry of Finance (2017-18 to 2022-23). *Economic Survey*.
- Gu W and Macdonald R. (2009). The Impact of Public Infrastructure on Canadian Multifactor Productivity Estimates. *The Canadian Productivity Review* (No. 1).
- Hoechle, D. (2007). Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross-sectional Dependence. *The Stata Journal*, 7(3), 281-312.
- Kant, Amitabh (2021). *Speeding Up with Gati Shakti*. Niti Aayog.
- Khan, H. R. (2015). Financing for Infrastructure: Current Issues and Emerging Challenges. Keynote Address at Infrastructure Group Conclave of the SBICAP at Amby Valley. *RBI Bulletin* (September).
- KPMG (2024). Transforming India's Infrastructure: A Futuristic Roadmap through Budget 2024-25.

- Kumar, Mausam (2022). *National Bank for Financing Infrastructure and Development, A Vehicle of Infrastructure Financing: Challenges and Opportunities*. EAC-PM Working Paper Series (December).
- Kumari A. and Sharma A. K. (2017). Physical and Social Infrastructure in India and its Relationship with Economic Development. *World Development Perspectives*, 5(3), 30-33.
- Mishra S., Behera A. R. and Behera S. R. (2017). Capital Outlay and Economic Growth in Indian States: An Empirical Study. *IUP Journal of Applied Economics*, 16(2), 39-57.
- Mitra A., Varoudakis A. and Varoudakis M. (2002). Productivity and Technical Efficiency in Indian States' Manufacturing: the Role of Infrastructure. *Economic Development and Cultural Change*, 50 (2).
- Moller L. C. and Walker K. M. (2017). Explaining Ethiopia's Growth Acceleration—The Role of Infrastructure and Macroeconomic Policy. *Elsevier*, 96(8), 198-215.
- Munnell, A. H. (1992). Policy Watch: Infrastructure Investment and Economic Growth. *The Journal of Economic Perspectives*, 6(4), 189–198.
- National Bank for Financing Infrastructure and Development (2024).
- Nijkamp P. (1986). Infrastructure and Regional Development: A Multidimensional Policy Analysis. *Empirical Economics*, 11(3), 1–21.
- Paley T. (2015). Assessing the Impact of Infrastructure on Economic Growth and Global Competitiveness. *Procedia Economics and Finance*.
- Papagni E, Lepore A., Felice E., Baraldi A. and Alfano M. R. (2021). Public Investment and Growth: Lessons learned from 60-years' Experience in Southern Italy. *Elsevier Journal of Policy Modelling*, 43(2), 376-393.
- Patra, M. D. (2022). India@75. Speech delivered by Dr. Michael Debabrata Patra, Deputy Governor, Reserve Bank of India in an event to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav organised by Reserve Bank of India, Bhubaneswar on August 13, 2022.
- Paul, C. M. and Schwartz A. (1996). State Infrastructure and Productive Performance. *American Economic Review*, 86(5), 1095-1111.
- Prescott Edward C. (1988). Robert M. Solow's Neoclassical Growth Model : An Influential Contribution to Economics. *The Scandinavian Journal of Economics*, 90(1), 7-12.
- Raphael Espinoza, R, Gamboa-Arbelaes J and Sy M (2014). The Fiscal Multiplier of Public Investment: The Role of Corporate Balance Sheet. *IMF Working Paper* (WP/20/199).
- Rath D. P., Seth B., Behera S. R. and Suresh A. K. (2023). Capital Outlay of Indian States: An Empirical Assessment of its Role and Determinants. *RBI Bulletin* (April), 163-171.
- Rao, Rajeshwar (2024). Managing the Challenges in Financing Infrastructure - the Road Ahead for NaBFID. Keynote Address by Shri Rajeshwar Rao, Deputy Governor, Reserve Bank of India, at the Infrastructure Conclave, organised by the National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID), Mumbai on September 12, 2024.
- Reserve Bank of India (2023). RBI Press Release: *Issuance Calendar for Marketable Sovereign Green Bonds: FY 2022-23* (January 6, 2023).
- Reserve Bank of India (2022). *Report on Municipal Finances*.
- Reserve Bank of India (2024). *Report on Municipal Finances*.
- Reserve Bank of India (2023). *Report on Currency and Finance*.
- Reserve Bank of India (2024). State of the Economy. *RBI Bulletin* (No. 5).

Reserve Bank of India (2023). Review of Regulatory Framework for IDf-NBFCs. *RBI Press Release*. 18 August.

Sahoo, Pravakar (2011) Transport Infrastructure in India: Development, Challenges and Lessons from Japan.

Shi Y., Guo S. and Sun P. (2017). The Role of Infrastructure in China's Regional Economic Growth. *Journal of Asian Economics*, 49(4), 26-41.

Snieska V. and Simkunaite I. (2009). Socio-economic Impact of Infrastructure Investments. *Economics of Engineering Decisions*, 63(3).

Straub S. and Terada-Hagiwara A. (2010). Infrastructure and Growth in Developing Asia. *ADB Economics Working Paper Series*, Asian Development Bank (No. 231).

Timilsina G., Stern D. and Das D. (2023). Physical Infrastructure and Economic Growth. *Applied Economics*.

Vagliasindi M. and Gorgulu N. (2023). Beyond brick and mortar: Key lessons learned on the impact of infrastructure on economic development. *World Bank Blogs*, World Bank.

Virmani Arvind (2023). *Bhartiya Model of Inclusive Development*. Niti Policy Paper, NITI Aayog.

Vishwanathan, N. S. (2016). Issues in Infrastructure Financing in India. Address delivered at 6<sup>th</sup> National Summit by ASSOCHAM, *RBI Bulletin*, Reserve Bank of India (December).



## अनुबंध ए: भारत का अवसंरचना कार्यक्रम

### व्यापक-आधारित संस्थागत सेट-अप

अवसंरचना परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (एनएमपी), राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) शुरू की। एनआईपी देश में अवसंरचना के विकास पर पूरी नजर रखता है। यह निवेशकों को अवसंरचना में अपने निवेश की योजना बनाने में सक्षम बनाता है। एनआईपी की परिकल्पना वर्ष 2020-2025 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ की गई है, जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। वर्तमान में इसमें 108 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाली 8,964 परियोजनाएं हैं। एनआईपी इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड (आईआईजी) के प्लेटफॉर्म पर काम करता है जो एक केंद्रीय पोर्टल है जो सभी अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति का समन्वय और ट्रैक करता है। अवसंरचना के सृजन के अलावा, हवाई अड्डों और पत्तनों सहित मौजूदा सेट-अप के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) और एनआईपी पोर्टलों के एनआईपी के साथ डेटा दर्ज करने और पीएमजी द्वारा डेटा का उपयोग करने के लिए प्रस्तावित एकीकरण के साथ, समय की पर्याप्त बचत होगी। अवसंरचना के लिए वित्तपोषण निजी, सरकारी और बहुपक्षीय संस्थाओं से प्राप्त होता है। एनएमपी के माध्यम से आस्तियों के मुद्राकरण से भी वित्त पोषण प्राप्त होता है, जिसे निजी क्षेत्र से निवेश का दोहन करके मुद्राकरण के माध्यम से आस्तियों के निर्माण के लिए वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। इसमें आस्तियों को प्रतिफल के आधार पर निश्चित अवधि के लिए रखरखाव और परिचालन के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को पट्टे पर या लाइसेंस दिया जाता है। सरकार द्वारा अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रतिफल राशि का निवेश किया जाता है।

अवसंरचना के विकास के लिए सरकार द्वारा की गई कई अन्य नई पहलों में भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे (आईसीईगेट), व्यापार के लिए विंडो इंटरफेस (स्विफ्ट), राष्ट्रीय रेल योजना, उड़े देश का आम

नागरिक (उड़ान), पर्वतमाला, भारतमाला, सागरमाला, ई-संचित, विभिन्न प्रक्रियाओं में सुधार और जीएसटी सुधार शामिल हैं। सरकार ने राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय से जुड़ी अतिरिक्त उधार सुविधाओं और दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण जैसे कई उपायों की घोषणा की ताकि उनके पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जा सके। जोखिम मूल्यांकन के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के लिए क्रेडिट रेटिंग के लिए एक प्रणाली शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, अवसंरचना वित्तपोषण के लिए एक संस्था की स्थापना जैसे राष्ट्रीय वित्तपोषण अवसंरचना एवं विकास बैंक (एनएबीएफआईडी), मॉडल रियायत करारों के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी, अवसंरचना निवेश न्यासों (आईएनवीआईटी) और स्थावर संपदा निवेश न्यासों (आरईआईटी) के वित्तपोषण विकल्पों, विकास वित्तीय संस्थाओं (डीएफआई) के पुनर्पूँजीकरण और सामाजिक अवसंरचना का विकास सहित कुछ पूरक सुधार किए गए हैं। पीपीपी परियोजनाओं के विकासात्मक व्यय के वित्तपोषण के लिए, भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) योजना 2022 में शुरू हुई। जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय को एक बड़ा सहयोग मिला क्योंकि यह वर्ष 2024-25 में औसत 1.7 प्रतिशत (2009-2020) से बढ़कर 3.1 प्रतिशत हो गया।

लागत संरचनाओं को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए, गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति (एनएलपी) शुरू की गई थी। पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क में एक संपूर्ण डेटाबेस के साथ सभी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एक एकछत्र प्लेटफॉर्म बनाने की परिकल्पना की गई है। एनआईपी में जन परिवहन, बंदरगाह, लॉजिस्टिक अवसंरचना, रेलवे, सड़क, हवाई अड्डे और जलमार्ग जैसे "सात इंजन" को पीएम गति शक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय रसद नीति (एनएलपी) को 2022 में सभी सरकारी संस्थाओं की अवसंरचना की गतिविधियों के समन्वय और अभिसरण के लिए शुरू किया गया था और एक एकीकृत रसद ढांचा है। इसके दृष्टिकोण में प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित एकीकृत, लागत प्रभावी और लचीले लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का विकास शामिल है।



इसे एक व्यापक लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान (सीएलएपी) के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। यह जनशक्ति कौशल, डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देगा और सेवाओं को बढ़ाएगा। इसके तहत लक्ष्यों में 2030 तक अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क से मेल खाने के लिए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और 2030 तक शीर्ष 25 देशों में स्थान हासिल करने के लिए लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार शामिल है। अब तक, इसने लागत को लगभग 50 प्रतिशत तक कम कर दिया है (विरमानी, 2023)। परिवहन के विभिन्न साधनों को जोड़ने के लिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी की शुरुआत से विभिन्न प्रकार के परिवहन के बीच लोगों और माल की आवाजाही में सुविधा होगी। यह कनेक्टिविटी की पहुंच का विस्तार करेगा, लागत और यात्रा के समय को कम करेगा।

### अर्थव्यवस्था का हरितकरण

पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता पर संविधान के अनुच्छेद 48-ए के अनुसार और वैश्विक जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों को देखते हुए सरकार ने कई उपाय किए हैं। 2008 में, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) को टिकाऊ आवासों के विकास, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने और वनों के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए शुरू किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) की स्थापना 2015 में जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील वर्गों और क्षेत्रों के लिए की गई थी। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) की स्थापना आपदा प्रबंधन प्रणाली की दिशा में एक पहल के रूप में की गई थी। हरित वृद्धि इक्विटी फंड (जीजीईएफ) को 2018 में हरित अवसंरचना व्यय के लिए लॉन्च किया गया था। हरित अवसंरचना के लिए धन जुटाने के लिए, जनवरी 2023 में अनिवासी निवेशकों को पूरी तरह से सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत सॉवरेन हरित बॉण्ड सहित सहित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ श्रेणियों तक अप्रतिबंधित पहुंच प्रदान की गई थी। वर्ष 2022 में, सरकार ने सॉवरेन हरित बॉण्ड के लिए फ्रेमवर्क जारी किया और तदनुसार रिजर्व बैंक ने वर्ष 2023 में हरित अवसंरचना के लिए वित्त जुटाने के लिए विपणन योग्य सॉवरेन हरित बॉण्ड (एसजीबी) के लिए जारी कैलेंडर को

अधिसूचित किया। आय का उपयोग अर्थव्यवस्था में कार्बन की तीव्रता को कम करने के लिए किया जाएगा।

### डिजिटल अवसंरचना

वर्ष 2015 में, सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (डीआईपी) शुरू किया जो सेवा वितरण के लिए हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल भंडारण और दस्तावेजों को साझा करने के लिए सार्वजनिक क्लाउड पर निजी स्थान और नागरिकों को विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करता है। व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी), राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना (एनएफएपी) और ब्रॉडबैंड सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के साथ कनेक्टिविटी और वहनीय सेवाओं के प्रावधान के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ई-मार्केटप्लेस 'माईस्कीम' से लोग उपयुक्त सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल (एनएआईपी) को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। गतिशील डिजिटल परिदृश्य के साथ, इंटरनेट उपयोग के लिए मानक जैसे ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (ओसीईएन) उधार लेने और उधार देने के तौर-तरीकों के लिए विकसित किए गए हैं। डिजिटलीकरण को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक बनाया गया है। जनधन आधार मोबाइल (जेएम) ट्रिनिटी द्वारा सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस 'ई-श्रम' पोर्टल, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), डिजिलॉकर, माईगव, को-विन, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क (एएएफ) के साथ वित्तीय डेटा साझाकरण, कर प्रशासन का डिजिटलीकरण, मिशन ड्रोन शक्ति, ई-रुपया और ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीएस) जैसी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास की यात्रा में प्रमुख उपलब्धि का संकेत देती है।

डिजिटल और संचार अवसंरचना के विकास पर जोर देने के साथ, पहुंच, उपयोग और अंतरसंचालनीयता के मामले में विस्तार देखा गया। मोबाइल फोन के माध्यम से किए गए कई कार्यों, लाभ प्रदान करने के लिए आधार-आधारित पहचान और

वंचित वर्गों तक वित्तीय, शैक्षिक सेवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के कारण विकास पर डिजिटल अवसंरचना का गुणक प्रभाव बहुत बड़ा रहा है। ई-गवर्नेंस पर आधारित सेवाओं के प्रावधान की दिशा में प्रगति हुई है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के माध्यम से डिजिटल व्यापार से संबंधित नवाचारों और एएफ के साथ उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करने जैसी नई पहलों से निकट भविष्य में डिजिटल अवसंरचना के परिदृश्य को और मजबूत करने की उम्मीद है।

### सामाजिक अवसंरचना

भारत द्वारा अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के तहत एजेंडा गरीबी, असमानता के उन्मूलन और सतत और

समावेशी विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण पर केंद्रित है। इन तर्ज पर हाल ही में की गई पहलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), स्कूल सुविधाओं में सुधार, शिक्षकों की संख्या में वृद्धि, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय के अनुपात में वृद्धि, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में वृद्धि, आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य बीमा के कवरेज में विस्तार, टेलीमेडिसिन के लिए ई-संजीवनी, पर्याप्त पेयजल का प्रावधान, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के लिए स्वामित्व जैसे उपायों के माध्यम से बिजली, महिलाओं का सशक्तिकरण और ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण शामिल है।

### अनुबंध बी: अवसंरचना के वित्तपोषण पर नीतिगत उपाय

- विभिन्न कारणों से अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब को ध्यान में रखते हुए, समय और लागत में वृद्धि की अनुमति दी गई है, जो शर्तों के अधीन है।
- बैंकों को बुनियादी अवसंरचना के लिए अन्य ऋणदाताओं को गारंटी जारी करने की अनुमति दी गई है, यदि बैंक परियोजनाओं की लागत का कम से कम 5 प्रतिशत वहन करते हैं और ऋण का मूल्यांकन और निगरानी करते हैं।
- बैंकों को भारत में अवसंरचना परियोजना को निष्पादित करने वाली कंपनी में शेयर प्राप्त करने के मामले में प्रवर्तकों की इक्विटी को निधि देने की अनुमति दी गई है।
- पुनर्भुगतान के साथ नकदी प्रवाह को संरेखित करने के लिए बैंकों को ऋण की लचीली संरचना की अनुमति दी गई है।
- बैंकों द्वारा अवसंरचना बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी गई है और आस्तियों को आरक्षित आवश्यकताओं से निधियों के लिए दी गई छूट के अलावा स्वामित्व क्षेत्र ऋण मानदंडों से छूट दी गई है। बैंकों द्वारा विदेशी पूंजी बाजारों (मसाला बॉण्ड) में रुपये के मूल्यवर्ग के बॉण्ड को भी जुटाने की अनुमति दी गई है।
- चूंकि अवसंरचना के लिए निधियां जुटाने के लिए एक विकसित बॉण्ड बाजार की आवश्यकता होगी और चूंकि इससे बैंकों के लिए जोखिम कम होगा, इसलिए रिजर्व बैंक ने कारपोरेट बॉण्ड बाजार के विकास के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें बैंकों द्वारा दीर्घकालिक बॉण्ड जारी करने की अनुमति देना, उनके द्वारा प्राथमिक निर्गम के अनुपात की क्रॉस होल्डिंग के साथ-साथ उन्हें बॉण्ड जारी करने की 50 प्रतिशत तक ऋण वृद्धि प्रदान करने की अनुमति देना, कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण, बाजार सम्मेलनों का मानकीकरण, बाजार चलनिधि बढ़ाने के लिए कारपोरेट बॉण्ड को फिर से जारी करने की अनुमति देना, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए सीमा बढ़ाना, विदहोल्डिंग टैक्स में कमी, ऑफशोर रुपया बॉण्ड बाजार को गहन करने के उपाय, पारदर्शिता के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना, जोखिम को रोकने के लिए ओवर काउंटर (ओटीसी) लेनदेन के वितरण बनाम भुगतान (डीवीपी) निपटान का संचालन, कारपोरेट बॉण्ड में रेपो की अनुमति देना, बैंकों द्वारा अवसंरचना के लिए कारपोरेट बॉण्ड के क्रेडिट में वृद्धि की अनुमति देना और जोखिम प्रबंधन के लिए कारपोरेट बॉण्ड में क्रेडिट चूक स्वैप (सीडीएस) की अनुमति देना, इन उपायों के कारण कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- चूंकि वित्त प्रदाताओं को पूर्व चरण में निर्माण के जोखिम के लिए प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित होती है, इसलिए बैंकों से निर्माणोपरान्त आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए म्यूचुअल फंड (एमएफ) के रूप में अवसंरचना विकास निधि (आईडीएफ) और गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को स्थापित करने की अनुमति और वित्तपोषण को ले जाने जैसे उपाय किए गए हैं। आईडीएफ और इनविट की बढ़ी हुई भूमिका से अवसंरचना के वित्तपोषण को बढ़ावा मिलेगा।
- पीपीपी परियोजनाओं के ऋणदाताओं को प्रतिभूति के रूप में देय ऋण के प्रतिफल को कुछ हद तक अनुमति दी गई है।
- चूंकि एस्करो खातों जैसे अवसंरचना वित्तपोषण के लिए सुरक्षा उपाय हैं, इसलिए अवसंरचना में उप-मानक अप्रतिभूतित ऋण खातों पर प्रावधान को घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है, बशर्ते बैंकों के पास नकदी प्रवाह को कम करने की व्यवस्था हो और उन पर पहला दावा हो।
- चूंकि अवसंरचना क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से और संभावित रूप से बड़ी संख्या में दबावग्रस्त आस्तियों का संचयन होता है, इसलिए बैंकों को दबावग्रस्त आस्तियों से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए कई साधन प्रदान किए गए हैं जैसे कि निर्माण, परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और सुधारात्मक कार्य योजना जैसे अवसंरचना क्षेत्रों को शामिल करने के साथ लचीली पुनर्संरचना योजना।

11. बैंकों को अवसंरचना ऋणों के लिए लंबी पुनर्भुगतान अवधि निर्धारित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन प्रारंभिक वर्षों या छोटी अवधि के लिए वित्त पोषण प्रदान करते हैं और अन्य बैंकों या साधनों के माध्यम से आवधिक पुनर्वित्त प्रदान करते हैं, जिसे 5/25 योजना कहा जाता है। हालांकि, ऋणदाताओं द्वारा आस्ति दबाव को छिपाए बिना इस तरह के लचीलेपन का विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है, ।
12. वर्ष 2014 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जिसमें बैंकों को नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) जैसे न्यूनतम विनियामक पूर्व-रिक्ति के साथ अवसंरचना को ऋण देने के लिए दीर्घकालिक वित्त जुटाने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 2023 में आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा रिज़र्व बैंक द्वारा की गई थी ताकि उनकी बड़ी भूमिका को सुविधाजनक बनाया जा सके और नियमों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके।
13. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (आरईआईटी) और इनविट की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी गई थी।
14. टेकआउट फाइनेंसिंग की अवसंरचना के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह बैंकों को उनके एक्सपोजर में कमी और उनकी आस्तियों और देयताओं के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से मध्यम अवधि के वित्त के साथ लंबी अवधि की परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में सक्षम बनाता है। तदनुसार, बैंकों को अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ पूर्व समझौते के बिना आंशिक टेकआउट फंडिंग के माध्यम से परियोजना ऋण का पुनर्वित्त करने और मोचन के लिए एक लंबी अवधि निर्धारित करने की अनुमति दी गई है।
15. ₹10,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण में कमी का उपयोग करके एक शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना की गई है।



# वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
मुद्रा और बैंकिंग  
मूल्य और उत्पादन  
सरकारी खाते और खज़ाना बिल  
वित्तीय बाजार  
बाह्य क्षेत्र  
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ  
आवसरिक शृंखलाएं





## विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	129
	<b>भारतीय रिज़र्व बैंक</b>	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	130
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	131
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	132
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का परिपक्वता विश्लेषण (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	133
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	133
	<b>मुद्रा और बैंकिंग</b>	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	134
7	मुद्रा स्टॉक (एम <sub>3</sub> ) के स्रोत	135
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	136
9	कुल चलनिधि राशियाँ	137
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	138
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	138
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	139
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	139
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	140
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	141
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	142
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	143
	<b>मूल्य और उत्पादन</b>	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	144
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	144
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	144
21	थोक मूल्य सूचकांक	145
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	149
	<b>सरकारी खाते और खज़ाना बिल</b>	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	149
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	150
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	150
	<b>वित्तीय बाजार</b>	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	151
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	152
28	वाणिज्यिक पत्र	152
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	152
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	153

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	<b>बाह्य क्षेत्र</b>	
31	विदेशी व्यापार	154
32	विदेशी मुद्रा भंडार	154
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ	154
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	155
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण	155
36	भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक	156
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण	157
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	158
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (₹ करोड़)	159
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	160
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (₹ करोड़)	161
42	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	162
	<b>भुगतान और निपटान प्रणालियाँ</b>	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	163
	<b>आवसरिक शृंखलाएं</b>	
44	लघु बचत	165
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	166
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण	167
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	168
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	169
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियाँ	170
50 (ए)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह-लिखत-वार	171
50 (बी)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक-चुनिंदा संकेतक	174

टिप्पणियाँ: .. = उपलब्ध नहीं।

– = शून्य/नगण्य।

प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम।

आंसं = आंशिक रूप से संशोधित।

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2024-25	2023-24	2024-25		2025-26
		ति4	ति1	ति4	ति1
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.4	7.3	6.5	6.8	7.6
1.1.1 कृषि	4.6	0.9	1.5	5.4	3.7
1.1.2 उद्योग	4.5	9.9	7.8	4.7	5.8
1.1.3 सेवाएं	7.5	8.0	7.2	7.9	9.0
1.1ए अंतिम खपत व्यय	6.5	6.3	7.0	4.7	7.1
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	7.1	6.0	6.7	9.4	7.8
	2024-25	2024		2025	
		जून	जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	4.0	4.9	5.0	1.5	3.5
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियाँ	10.3	11.1	10.6	10.1	10.2
2.1.2 ऋण#	11.0	17.4	13.7	9.5	10.0
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण#	11.0	17.4	13.7	9.3	9.9
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	9.7	8.6	8.1	8.8	6.6
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	4.3	7.4	7.2	4.9	4.7
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	9.4	10.1	9.7	9.5	9.6
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.50	4.50	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.3	5.1	5.1	4.4	4.3
3.4 ऋण-जमा अनुपात	80.8	79.3	79.3	78.9	79.2
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात#	86.1	56.0	53.1	28.7	33.5
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.7	28.9	29.8	28.6	28.8
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	28.1	6.4	28.8	-0.1	3.8
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रेपो दर	6.25	6.50	6.50	5.50	5.50
4.2 स्थायी रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर*	6.00	6.25	6.25	5.25	5.25
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	6.50	6.75	6.75	5.75	5.75
4.5 बैंक दर	6.50	6.75	6.75	5.75	5.75
4.6 आधार दर	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.30	8.50/10.30
4.7 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.15/8.45	8.10/8.60	8.10/8.60	7.95/8.25	7.95/8.20
4.8 मीयादी जमा दर >1 वर्ष	6.00/7.25	6.00/7.30	6.00/7.30	5.85/6.70	5.85/6.70
4.9 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.50/2.75	2.50/2.50
4.10 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.35	6.67	6.59	5.29	5.55
4.11 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	6.52	6.80	6.67	5.41	5.40
4.12 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	6.52	6.92	6.79	5.54	5.52
4.13 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	6.47	6.96	6.80	5.57	5.57
4.14 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियां सममूल्य प्रतिफल (एफबीआईएल)	6.62	7.04	6.97	6.34	6.41
5 संदर्भ दर और वायदा प्रीमियम					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	85.58	83.45	83.73	85.56	86.52
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	92.32	89.25	90.86	100.20	101.73
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमियम	1-माह (%)	1.10	1.11	1.65	1.81
	3-माह (%)	2.56	1.14	1.66	1.76
	6-माह (%)	2.28	1.26	1.43	1.85
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.6	5.1	3.6	2.1	1.6
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.39	3.7	2.1	2.5	2.7
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	2.3	3.4	2.1	-0.2	-0.6
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	5.2	9.2	3.2	-3.2	-5.0
6.3.2 ईंधन और उर्जा	-1.3	0.5	1.9	-3.1	-2.4
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	1.7	1.5	1.6	1.9	2.0
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	6.2	4.6	11.2	-3.7	8.6
7.2 निर्यात	0.1	2.4	0.6	-0.1	7.3

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार 31 मार्च 2018 से जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।  
#: 3 दिसंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक सभी पखवाड़ों के लिए चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है।  
कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।  
\*: दिनांक 8 अप्रैल 2022 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2022-2023/41 के अनुसार।

# भारतीय रिज़र्व बैंक

## सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां\*

(₹ करोड़)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2024-25	2024	2025				
		अग.	अग.01	अग.08	अग.15	अग.22	अग.29
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1 निर्गम विभाग</b>							
<b>1.1 देयताएं</b>							
1.1.1 संचलन में नोट	3683836	3458493	3753870	3779110	3788176	3773434	3763879
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	14	17	17	16	14	13
<b>1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां</b>	<b>3683847</b>	<b>3458507</b>	<b>3753886</b>	<b>3779127</b>	<b>3788192</b>	<b>3773448</b>	<b>3763892</b>
<b>1.2 आस्तियां</b>							
1.2.1 स्वर्ण	235379	188699	260533	267638	265785	263628	271256
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	3448129	3269461	3492976	3511227	3522214	3509319	3492206
1.2.3 रुपया सिक्का	340	347	378	261	194	501	429
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 बैंकिंग विभाग</b>							
<b>2.1 देयताएं</b>							
2.1.1 जमाराशियाँ	1709285	1702744	1797387	1748116	1732715	1739682	1737992
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	100	100	101	100	100	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	43	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	943060	1019456	1001761	926802	954551	932900	959655
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7776	8019	8011	8472	8122	8011	8031
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	5963	5186	5256	5333	5188	5022	5120
2.1.1.7 अन्य बैंक	46963	49701	47560	47715	47538	47994	48027
2.1.1.8 अन्य	593085	479121	635149	649765	601228	630623	583536
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	112296	141119	99508	109887	115944	114989	133480
2.1.2 अन्य देयताएं	2150508	1917383	2257657	2347314	2349220	2303451	2399650
<b>2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां</b>	<b>3859793</b>	<b>3620127</b>	<b>4055044</b>	<b>4095429</b>	<b>4081935</b>	<b>4043133</b>	<b>4137642</b>
<b>2.2 आस्तियां</b>							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	14	17	17	16	14	13
2.2.2 विदेशों में धारित राशियाँ	1413591	1790736	1631246	1639427	1639085	1618220	1691216
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	26284	13381	32232	42792	34130	27463	19623
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	251984	6968	1100	4352	1187	1818	1950
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	36426	8547	10320	10361	11106	11006	10975
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	111768	141402	99465	109553	115461	114364	132802
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1560630	1317280	1786267	1781635	1776673	1769940	1767243
2.2.6 अन्य आस्तियां	459101	341800	494397	507292	504276	500308	513821
2.2.6.1 स्वर्ण	429510	330135	474804	487753	484376	480446	494347

\* डेटा अनंतिम हैं।

## सं. 3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6 -8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तन- शील रेपो दर	परिवर्तन- शील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जुला. 1, 2025	-	-	-	-	1233	255381	-	-	-	-254148
जुला. 2, 2025	-	-	-	-	3410	299291	-1030	-	-	-296911
जुला. 3, 2025	-	-	-	-	1111	326770	-	-	-	-325659
जुला. 4, 2025	-	-	-	100010	1282	332158	-	-	-	-430886
जुला. 5, 2025	-	-	-	-	216	285155	-	-	-	-284939
जुला. 6, 2025	-	-	-	-	339	250650	-	-	-	-250311
जुला. 7, 2025	-	-	-	-	1051	250865	-230	-	-	-250044
जुला. 8, 2025	-	-	-	-	1072	214021	-240	-	-	-213189
जुला. 9, 2025	-	-	-	97315	1081	136036	-186	-	-	-232456
जुला. 10, 2025	-	-	-	-	1078	124621	-45	-	-	-123588
जुला. 11, 2025	-	-	-	151633	1223	187091	365	-	-	-337136
जुला. 12, 2025	-	-	-	-	85	127893	-	-	-	-127808
जुला. 13, 2025	-	-	-	-	81	132452	-	-	-	-132371
जुला. 14, 2025	-	-	-	-	838	116037	-	-	-	-115199
जुला. 15, 2025	-	-	-	57450	869	97432	-	-	-	-154013
जुला. 16, 2025	-	-	-	-	879	109064	-18	-	-	-108203
जुला. 17, 2025	-	-	-	-	808	106279	-5	-	-	-105476
जुला. 18, 2025	-	-	-	200027	951	116590	293	-	-	-315373
जुला. 19, 2025	-	-	-	-	819	111162	-	-	-	-110343
जुला. 20, 2025	-	-	-	-	1179	103669	-	-	-	-102490
जुला. 21, 2025	-	-	-	-	10750	56852	361	-	-	-45741
जुला. 22, 2025	-	-	-	-	13273	63745	2063	-	-	-48409
जुला. 23, 2025	-	-	50001	-	820	78428	1829	-	-	-25778
जुला. 24, 2025	-	-	1421	-	362	117991	-	-	-	-116208
जुला. 25, 2025	-	-	-	125008	1906	174961	-104	-	-	-298167
जुला. 26, 2025	-	-	-	-	484	119530	-	-	-	-119046
जुला. 27, 2025	-	-	-	-	484	121441	-	-	-	-120957
जुला. 28, 2025	-	-	-	-	938	109847	-	-	-	-108909
जुला. 29, 2025	-	-	-	46058	1584	108957	-	-	-	-153431
जुला. 30, 2025	-	-	-	-	1408	94716	-	-	-	-93308
जुला. 31, 2025	-	-	-	13075	1649	114195	-	-	-	-125621



सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय

i) तटीय/ अपतटीय ओटीसी खंड में परिचालन

मद	2024-25	2024	2025	
		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	-34511	6934	-3661	-2540
1.1 क्रय (+)	364200	23569	1164	0
1.2 विक्रय (-)	398711	16635	4825	2540
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (₹ करोड़)	-291233	57887	-31808	-22267
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-34511	5402	-3557	-6097
(₹ करोड़)	-291233	44872	-31881	-54148
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-84345	-9100	-60390	-57850

ii) मुद्रा वायदा खंड में परिचालन

मद	2024-25	2024	2025	
		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	31415	2144	0	0
1.2 विक्रय (-)	31415	2144	0	0
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	0	-340	0	0

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का  
परिपक्वता विश्लेषण (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	31 जुलाई 2025 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	0	7695	-7695
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	0	10835	-10835
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	0	19220	-19220
4. 1 वर्ष से अधिक	0	20100	-20100
<b>कुल (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>57850</b>	<b>-57850</b>

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति							
	2024-25	2024	2025					
			अग. 23	मार्च 21	अप्रै. 21	मई 21	जून 27	जुला. 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	9961	1818	9961	2003	1540	1065	1906	1818
2 अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	9900	9900	9900	14900	14900	14900	14900	14900
3.2 बकाया	9517	8541	9517	7999	8595	7010	10299	10985
4 अन्य								
4.1 सीमा	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	19478	10359	19478	10002	10135	8075	12205	12803

# मुद्रा और बैंकिंग

## सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2024-25	2024	2025		
		जुला. 26	जून 27	जुला. 11	जुला. 25
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3630751	3426089	3722652	3729016	3707458
1.1 संचलन में नोट	3687816	3502874	3783575	3787633	3763742
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	35889	33563	36909	36909	37314
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	93696	111091	98575	96269	94341
2 जनता की जमाराशियाँ	2953329	2678638	3324072	3054960	3126308
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियाँ	2840023	2587413	3215375	2944828	3018666
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	113307	91225	108697	110133	107642
3 एम1 (1+2)	6584081	6104726	7046725	6783976	6833766
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियाँ	212331	199017	212331	212331	212331
5 एम2 (3+4)	6796412	6303743	7259056	6996307	7046097
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियाँ	20702508	19568786	21183731	21357280	21306108
7 एम3 (3+6)	27286589	25673513	28230456	28141256	28139873
8 कुल डाकघर जमाराशियाँ	1443555	1361211	1443555	1443555	1443555
9 एम4 (7+8)	28730144	27034724	29674011	29584811	29583428

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम<sub>3</sub>) के स्रोत

(₹ करोड़)

स्रोत	मार्च 31 / माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2024-25	2024	2025		
		जुला. 26	जून 27	जुला. 11	जुला. 25
	1	2	3	4	5
<b>1 सरकार को निवल बैंक ऋण</b>	<b>8510825</b>	<b>7678213</b>	<b>8520033</b>	<b>8614205</b>	<b>8541317</b>
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1508105	1060910	1513361	1586327	1502150
1.1.1 सरकार पर दावे	1591591	1341836	1806229	1808369	1810116
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1558903	1320596	1786164	1787938	1786091
1.1.1.2 राज्य सरकारें	32688	21239	20066	20431	24026
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियाँ	83485	280926	292869	222042	307966
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	83443	280883	292826	221999	307924
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	43
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	7002720	6617302	7006672	7027878	7039167
<b>2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण</b>	<b>19068129</b>	<b>17577818</b>	<b>19283371</b>	<b>19266495</b>	<b>19300981</b>
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	38246	10935	9029	7965	12383
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	19029883	17566883	19274342	19258530	19288597
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	18243972	16813935	18486200	18469893	18501377
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	766659	733892	769075	767978	767165
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	19252	19056	19067	20660	20056
<b>3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)</b>	<b>6148527</b>	<b>5800754</b>	<b>6437976</b>	<b>6406286</b>	<b>6467260</b>
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	5550947	5434047	5840396	5808706	5869680
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	5550956	5434044	5840398	5808708	5869677
3.1.2 विदेशी देयताएं	9	-2	2	2	-3
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	597580	366707	597580	597580	597580
<b>4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं</b>	<b>36632</b>	<b>34306</b>	<b>37652</b>	<b>37652</b>	<b>38057</b>
<b>5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं</b>	<b>6477524</b>	<b>5417577</b>	<b>6048576</b>	<b>6183381</b>	<b>6207741</b>
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	2147427	1718640	2168644	2176784	2235868
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	4330098	3698937	3879932	4006598	3971873
<b>एम<sub>3</sub> (1+2+3+4-5)</b>	<b>27286589</b>	<b>25673513</b>	<b>28230456</b>	<b>28141256</b>	<b>28139873</b>

## सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

स्रोत	मार्च 31 / माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2024-25	2024	2025		
		जुला. 28	जून 27	जुला. 11	जुला. 25
	1	2	3	4	5
<b>समग्र मौद्रिक राशियाँ</b>					
एनएम <sub>1</sub> (1.1 + 1.2.1+1.3)	6584081	6104726	7046725	6783976	6833766
एनएम <sub>2</sub> (एनएम <sub>1</sub> + 1.2.2.1)	15768688	14799222	16446990	16262123	16288486
एनएम <sub>3</sub> (एनएम <sub>2</sub> + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	27909568	26361016	28786422	28701812	28681808
<b>1 घटक</b>					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3426089	3722652	3729016	3707458
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ	23250261	21908513	24104854	24007378	24029154
1.2.1 मांग जमाराशियाँ	2840023	2587413	3215375	2944828	3018666
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	20410239	19321100	20889478	21062550	21010489
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	9184607	8694495	9400265	9478148	9454720
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	527375	420069	516691	528946	507798
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	11225631	10626605	11489213	11584403	11555769
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	113307	91225	108697	110133	107642
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधियन	915248	935190	850218	855286	837554
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 देशी ऋण	28802443	26384962	29048840	29141826	29125727
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	7678213	8520033	8614205	8541317
2.1.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1508105	1060910	1513361	1586327	1502150
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	7002720	6617302	7006672	7027878	7039167
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	20291618	18706750	20528808	20527622	20584410
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण	38246	10935	9029	7965	12383
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	20253372	18695815	20519778	20519657	20572027
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियाँ)	1208294	1112229	1208081	1241827	1243910
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	36632	34306	37652	37652	38057
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5605462	5304425	5954722	5880727	5943463
2.3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5434047	5840396	5808706	5869680
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	54514	-129622	114326	72021	73784
2.4 पूंजी खाता	4481192	4317778	5040017	5048368	5127183
2.5 अन्य मदें (निवल)	2053777	1044899	1214776	1310026	1298257

## सं. 9: चलनिधि समग्र राशियाँ

(₹ करोड़)

समग्र राशियाँ	2024-25	2024	2025		
		जुला.	मई	जून	जुला.
	1	2	3	4	5
<b>1 एनएम<sub>3</sub></b>	<b>27896780</b>	<b>26361016</b>	<b>28594932</b>	<b>28786422</b>	<b>28681808</b>
2 डाकघर जमाराशियाँ	756786	720419	756786	756786	756786
<b>3 एल<sub>1</sub> (1 + 2)</b>	<b>28653566</b>	<b>27081435</b>	<b>29351718</b>	<b>29543208</b>	<b>29438594</b>
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	95148	68324	116492	113786	113786
4.1 सावधि मुद्रा उधार	10	748	4	5	5
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	80810	54670	101755	98755	98755
4.3 सावधि जमाराशियाँ	14328	12905	14733	15026	15027
<b>5 एल<sub>2</sub> (3 + 4)</b>	<b>28748714</b>	<b>27149759</b>	<b>29468210</b>	<b>29656993</b>	<b>29552381</b>
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियाँ	121178	..	..	129567	..
<b>7 एल<sub>3</sub> (5 + 6)</b>	<b>28869892</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>29786560</b>	<b>..</b>

टिप्पणी : संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।



सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2024-25	2024	2025		
		जुला. 26	जून 27	जुला. 11	जुला. 25
	1	2	3	4	5
<b>1 घटक</b>					
1.1 संचलन में मुद्रा	3724448	3537180	3821227	3825285	3801799
1.2 आरबीआई के पास बैंकों की जमाराशियाँ	991488	1039059	994142	990947	978898
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	926001	976073	933483	930199	918229
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	113307	91225	108697	110133	107642
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	4829243	4667464	4924066	4926365	4888339
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 आरबीआई के देशी ऋण	1389090	917751	1214662	1256791	1216470
2.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1508105	1060910	1513361	1586327	1502150
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल आरबीआई ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1475460	1039713	1493338	1565939	1478167
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1558574	1320373	1785715	1787655	1785639
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	1558574	1320373	1785715	1787655	1785639
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	329	223	449	282	451
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियाँ	83443	280883	292826	221999	307924
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल आरबीआई ऋण	32646	21197	20023	20388	23983
2.1.2 बैंकों पर आरबीआई के दावे	-157261	-154094	-307728	-337501	-298063
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-157261	-154094	-307728	-337501	-298063
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई के ऋण	38246	10935	9029	7965	12383
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	9182	9062	7010	5881	10299
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	36632	34306	37652	37652	38057
2.3 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5434047	5840396	5808706	5869680
2.3.1 स्वर्ण	668162	483062	722374	723791	741528
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4882794	4950982	5118023	5084916	5128149
2.4 पूंजी खाता	1875114	1774642	2127550	2127699	2179408
2.5 अन्य मदें (निवल)	272313	-56002	41094	49084	56460

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	2024-25	मार्च 31/माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2024	2025				
		जुला. 26	जून 27	जुला. 4	जुला. 11	जुला. 18	जुला. 25
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	4829243	4667464	4924066	4923222	4926365	4964256	4888339
<b>1 घटक</b>							
1.1 संचलन में मुद्रा	3724448	3537180	3821227	3821421	3825285	3811252	3801799
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियाँ	991488	1039059	994142	992989	990947	1045162	978898
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	113307	91225	108697	108812	110133	107843	107642
<b>2 स्रोत</b>							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1508105	1060910	1513361	1673148	1586327	1603965	1502150
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-157261	-154094	-307728	-430882	-337501	-315666	-298063
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	38246	10935	9029	8297	7965	8235	12383
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5434047	5840396	5806062	5808706	5823240	5869680
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	36632	34306	37652	37652	37652	37652	38057
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	2147427	1718640	2168644	2171055	2176784	2193169	2235868

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार / माह के रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2024-25	2024	2025		
		जुला. 26	जून 27	जुला. 11	जुला. 25
	1	2	3	4	5
<b>1 घटक</b>					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियाँ	22288331	20945882	23131393	23030976	23054208
1.1.1 मांग जमाराशियाँ	2698049	2444220	3072874	2802034	2876368
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	19590283	18501662	20058519	20228941	20177840
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	8788876	8288307	9002651	9079791	9057108
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	527375	420069	516691	528946	507798
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	10741960	10130153	11003241	11097523	11069799
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	915248	935190	850218	855286	837554
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 देशी ऋण	26156690	24247935	26419739	26438568	26502935
2.1.1 सरकार को ऋण	6697298	6312657	6696348	6715694	6726284
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	19459392	17935278	19723391	19722874	19776651
2.1.2.1 बैंक ऋण	18243972	16813935	18486200	18469893	18501377
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	18207441	16785745	18421811	18410900	18444703
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	15458	16966	37618	19563	39782
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	630	1111	454	554	544
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1199332	1103267	1199119	1232864	1234948
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	54514	-129622	114326	72021	73784
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	529621	284197	577466	524521	526520
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियाँ	292270	247686	294252	294730	295619
2.2.3 ओवरसीज़ विदेशी मुद्रा उधार	182837	166133	168887	157771	157117
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	791777	1229518	1327882	1352241	1298767
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	882415	976073	933483	930199	918229
2.3.2 उपलब्ध नकदी	81874	99350	86671	84541	82475
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	172512	-154094	-307728	-337501	-298063
2.4 पूंजी खाता	2581908	2518965	2888296	2896498	2923604
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	807812	472008	603594	698238	685360
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	878795	732752	877929	814152	832554
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	118268	149498	135597	105815	140516

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(₹ करोड़)

मद	21 मार्च, 2025 की स्थिति	2024	2025		
		जुला. 26	जून 27	जुला. 11	जुला. 25
		1	2	3	4
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	6697928	6313767	6696802	6716248	6726828
2 अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ (गैर-एसएलआर)	165500	157537	160012	160009	160190
3 वाणिज्यिक पत्र	63163	52091	63802	61337	63539
4 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	13874	12950	13835	15651	14823
4.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	95984	93831	98318	96026	97826
4.3 अन्य	7664	7367	7764	8017	7715
5 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
5.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	130308	121092	145962	139677	132293
5.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	248138	242161	260094	241944	245757
5.3 अन्य	150000	138806	152384	159471	157888
6 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
6.1 म्यूचुअल फंड	119867	96391	91749	131978	138862
6.2 वित्तीय संस्थाएं	204865	181041	205220	218755	216055

टिप्पणी: 1. कॉलम सं. (1), (2) व (3) में दिया गया डेटा अंतिम है और कॉलम सं.(4) व (5) में दिया गया डेटा अनंतिम है।

2. 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में, एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2024-25	2024	2025		2024-25	2024	2025	
		जुला.	जून	जुला.		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5	6	7	8
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	208	208	194	195	135	135	120	121
<b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>	<b>458011</b>	<b>500022</b>	<b>502739</b>	<b>476008</b>	<b>451305</b>	<b>495646</b>	<b>496493</b>	<b>469955</b>
1.1 बैंकों से माँग और मीयादी जमाराशियाँ	315675	285475	376910	347964	309414	281386	371106	342422
1.2 बैंकों से उधार राशि	112027	138779	100647	105216	111976	138752	100641	105206
1.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	30310	75768	25182	22828	29916	75507	24746	22327
<b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>	<b>25053097</b>	<b>23505340</b>	<b>25831875</b>	<b>25688230</b>	<b>24557481</b>	<b>23027726</b>	<b>25322680</b>	<b>25177053</b>
2.1 कुल जमाराशियाँ	23055487	21654100	23916476	23843715	22580601	21193568	23425645	23349827
2.1.1 माँग	2748263	2493596	3121710	2925734	2698049	2444220	3072874	2876368
2.1.2 मीयादी	20307224	19160504	20794766	20917980	19882552	18749348	20352771	20473459
2.2 उधार	920568	939516	854691	841980	915248	935190	850218	837554
2.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	1077042	911725	1060708	1002536	1061632	898968	1046816	989672
<b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>	<b>311466</b>	<b>7161</b>	<b>1065</b>	<b>1906</b>	<b>311466</b>	<b>7161</b>	<b>1065</b>	<b>1906</b>
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	311466	7161	1065	1906	311466	7161	1065	1906
<b>4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि</b>	<b>985044</b>	<b>1097637</b>	<b>1041975</b>	<b>1022191</b>	<b>964289</b>	<b>1075424</b>	<b>1020154</b>	<b>1000704</b>
4.1 उपलब्ध नकदी	84399	101799	89278	85044	81874	99350	86671	82475
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	900645	995838	952697	937147	882415	976073	933483	918229
<b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>	<b>432645</b>	<b>432441</b>	<b>490913</b>	<b>458151</b>	<b>348496</b>	<b>363113</b>	<b>398514</b>	<b>369221</b>
5.1 अन्य बैंकों के पास शेषराशि	273720	242359	340579	327705	215801	193127	273831	264197
5.1.1 चालू खाते में	13239	12352	25103	15890	10619	9487	22785	13780
5.1.2 अन्य खातों में	260481	230007	315476	311815	205182	183640	251046	250417
5.2 माँग और अल्पसूचना पर मुद्रा	44772	29827	42285	36664	25838	13930	24041	17911
5.3 बैंकों को अग्रिम	43856	42711	33677	28849	39504	41613	31558	27214
5.4 अन्य आस्तियां	70296	117544	74373	64933	67353	114443	69084	59900
<b>6 निवेश</b>	<b>6850574</b>	<b>6466548</b>	<b>6854341</b>	<b>6887824</b>	<b>6697928</b>	<b>6313767</b>	<b>6696802</b>	<b>6726828</b>
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	6842024	6458194	6845977	6878471	6697298	6312657	6696348	6726284
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	8550	8354	8365	9353	630	1111	454	544
<b>7 बैंक ऋण</b>	<b>18708286</b>	<b>17254613</b>	<b>18956024</b>	<b>18968340</b>	<b>18243972</b>	<b>16813935</b>	<b>18486200</b>	<b>18501377</b>
7ए खाद्यान्न ऋण	87145	78811	116363	108648	36531	28190	64389	56674
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	18370704	16938015	18613283	18627704	17909851	16500433	18146380	18163165
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	76523	68987	80511	77657	74963	67638	79560	77094
7.3 देशी बिल - भुनाए गए	222320	208216	225234	226698	221059	207073	223845	225406
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	15357	16061	14007	13538	15122	15852	13787	13316
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	23382	23334	22988	22743	22977	22940	22627	22395

टिप्पणी: कॉलम सं. (4) व (8) में दिया गया डेटा अनंतिम है।  
1, जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 21, 2025	2024	2025		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			जुला. 26	जून 27		
			जुला. 25	जुला. 25	2025-26	2025
	1	2	3	4	%	%
I. बैंक ऋण (II+III)	18243936	16814792	18483098	18501872	1.4	10.0
II. खाद्यान्न ऋण	36531	28190	64389	56674	55.1	101.0
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	18207404	16786602	18418709	18445197	1.3	9.9
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	2287071	2156320	2305993	2313845	1.2	7.3
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	3937149	3724547	3947139	3947778	0.3	6.0
2.1 सूक्ष्म और लघु	791721	729948	872577	883101	11.5	21.0
2.2 मध्यम	360475	317323	357618	363994	1.0	14.7
2.3 बड़े	2784953	2677277	2716943	2700683	-3.0	0.9
3. सेवाएं	5161462	4623910	5140226	5113966	-0.9	10.6
3.1 परिवहन परिचालक	258409	244262	266029	265924	2.9	8.9
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	32915	27356	36232	36579	11.1	33.7
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	83091	79202	84781	85458	2.8	7.9
3.4 शिपिंग	7305	7076	8042	8727	19.5	23.3
3.5 विमानन	46026	44637	50750	45213	-1.8	1.3
3.6 पेशेवर सेवाएं	195956	171393	196406	194935	-0.5	13.7
3.7 व्यापार	1186787	1043753	1174129	1179121	-0.6	13.0
3.7.1 थोक व्यापार <sup>1</sup>	648619	545170	629888	637065	-1.8	16.9
3.7.2 खुदरा व्यापार	538168	498582	544241	542056	0.7	8.7
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	532757	484531	555519	560514	5.2	15.7
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) <sup>2</sup> जिसमें से	1636098	1528856	1596490	1568925	-4.1	2.6
3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	323146	322052	331346	315767	-2.3	-2.0
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)	228678	202991	211702	198406	-13.2	-2.3
3.10 अन्य सेवाएं <sup>3</sup>	1182118	992845	1171848	1168570	-1.1	17.7
4. व्यक्तिगत ऋण	5952299	5507740	6126535	6161047	3.5	11.9
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23402	24606	23376	23114	-1.2	-6.1
4.2 आवास	3010477	2810108	3067120	3081152	2.3	9.6
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	141101	120373	145540	140433	-0.5	16.7
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	10080	9422	9886	9730	-3.5	3.3
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	284366	275601	292602	291088	2.4	5.6
4.6 शिक्षा	137456	123066	139587	141537	3.0	15.0
4.7 वाहन ऋण	622794	590981	642866	643654	3.3	8.9
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण <sup>4</sup>	208735	132535	277025	294166	40.9	122.0
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1513889	1421047	1528534	1536172	1.5	8.1
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां <sup>5</sup>	2287804	2196939	2274259	2288548	0.0	4.2
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम <sup>6</sup>	2240503	1998597	2460012	2489085	11.1	24.5
(iii) मध्यम उद्यम <sup>7</sup>	601451	511874	591992	596343	-0.8	16.5
(iv) आवास	746651	748840	856626	940427	26.0	25.6
(v) शिक्षा ऋण	62825	61523	64355	68839	9.6	11.9
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	10325	7075	12563	12160	17.8	71.9
(vii) सामाजिक अवसंरचना	1316	2937	828	943	-28.4	-67.9
(viii) निर्यात ऋण	12479	12298	13047	12875	3.2	4.7
(ix) अन्य	47900	58548	46467	44331	-7.5	-24.3
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1820904	1743686	1825579	1842667	1.2	5.7

**टिप्पणियाँ:** (1) आंकड़े अंतिम हैं। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण आंकड़े धारा-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को कवर करते हैं, जबकि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण आंकड़े क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं, जो महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित, सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा देने वाले चुनिंदा बैंकों को कवर करते हैं।

(2) 28 जुलाई, 2023 से आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

1 थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर खाद्य खरीद ऋण शामिल हैं।

2 एनबीएफसी में एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई), स्वर्ण ऋण देने वाली एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।

3 "अन्य सेवाओं" में म्यूचुअल फंड (एमएफ), एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग और वित्त, और अन्य सेवाएँ शामिल हैं जो सेवाओं के अंतर्गत कहीं और इंगित नहीं की गई हैं।

4 एक बैंक ने मई 2024 से, खुदरा खंड के तहत कृषि ऋण की एक श्रेणी के वर्गीकरण को "स्वर्ण के आभूषणों पर ऋण" में बदल दिया है।

5 प्राथमिकता क्षेत्र के तहत "कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।

6 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।

7 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 21, 2025	2024	2025		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जुला. 26	जून 27	जुला. 25	2025-26	2025
	1	2	3	4	%	%
2 उद्योग (2.1 से 2.19)	3937149	3724547	3947139	3947778	0.3	6.0
2.1 खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	56756	54719	56945	54751	-3.5	0.1
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	219527	205744	223136	216389	-1.4	5.2
2.2.1 चीनी	28522	22622	22862	20158	-29.3	-10.9
2.2.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति तेल	20927	18179	21342	21048	0.6	15.8
2.2.3 चाय	5084	6058	4950	4925	-3.1	-18.7
2.2.4 अन्य	164994	158886	173983	170258	3.2	7.2
2.3 पेय पदार्थ एवं तंबाकू	35513	30470	34636	34731	-2.2	14.0
2.4 वस्त्र	277267	255111	277281	270465	-2.5	6.0
2.4.1 सूती वस्त्र	107227	94890	105615	98267	-8.4	3.6
2.4.2 जूट वस्त्र	4288	4125	4411	4329	1.0	4.9
2.4.3 मानव निर्मित वस्त्र	49091	45754	49102	48545	-1.1	6.1
2.4.4 अन्य वस्त्र	116661	110341	118153	119324	2.3	8.1
2.5 चमड़ा एवं चमड़े से बने उत्पाद	12980	12548	13207	13385	3.1	6.7
2.6 लकड़ी एवं लकड़ी से बने उत्पाद	27826	24458	28303	28053	0.8	14.7
2.7 कागज एवं कागज से बने उत्पाद	52848	47826	52731	52961	0.2	10.7
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं आपिक् ईंधन	154178	136958	154602	157907	2.4	15.3
2.9 रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	267814	254881	271055	268991	0.4	5.5
2.9.1 उर्वरक	32011	34891	31958	29718	-7.2	-14.8
2.9.2 औषधी और दवाइयाँ	88738	82308	86613	86835	-2.1	5.5
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	26892	27879	31955	30494	13.4	9.4
2.9.4 अन्य	120172	109803	120529	121944	1.5	11.1
2.10 रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	103464	89581	102610	102513	-0.9	14.4
2.11 कांच और कांच के बर्तन	13443	12431	13243	12920	-3.9	3.9
2.12 सीमेंट और सीमेंट से बने उत्पाद	59752	60728	59183	59668	-0.1	-1.7
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	433502	402716	442055	440996	1.7	9.5
2.13.1 लोहा और स्टील	300156	285055	301600	298486	-0.6	4.7
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	133345	117661	140455	142509	6.9	21.1
2.14 सभी इंजीनियरिंग	240135	204685	248780	252030	5.0	23.1
2.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	52862	45156	55370	57446	8.7	27.2
2.14.2 अन्य	187272	159529	193411	194585	3.9	22.0
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरण	119057	109189	121183	121116	1.7	10.9
2.16 रत्न और आभूषण	85734	82940	88818	91482	6.7	10.3
2.17 निर्माण	150701	141194	150855	146725	-2.6	3.9
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1322831	1301135	1316796	1325756	0.2	1.9
2.18.1 ऊर्जा	682953	636926	695401	704850	3.2	10.7
2.18.2 दूरसंचार	118940	129614	104278	106891	-10.1	-17.5
2.18.3 सड़क	311219	327581	316840	316260	1.6	-3.5
2.18.4 हवाई अड्डा	9156	8004	9355	8296	-9.4	3.7
2.18.5 बंदरगाह	5916	6331	5530	5505	-6.9	-13.0
2.18.6 रेलवे	13595	11835	11510	11457	-15.7	-3.2
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	181052	180844	173882	172498	-4.7	-4.6
2.19 अन्य उद्योग	303822	297232	291720	296940	-2.3	-0.1

टिप्पणी : 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति							
	2024-25	2024	2025					
		जुला. 28	अप्रै. 18	अप्रै. 25	मई 02	मई 16	मई 30	जून 13
		1	2	3	4	5	6	7
		2	3	4	5	6	7	8
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	34	33	34	34	34	34	34	34
1 कुल जमाराशियाँ (2.1.1.2+2.2.1.2)	146871.0	133938.0	145054.5	147251.7	147608.7	147866.9	145985.2	147828.9
2 मांग और मीयादी देयताएं								
2.1 मांग देयताएं	29215.6	27801.7	27277.2	26936.5	28452.9	27298.2	26758.2	26529.6
2.1.1 जमाराशियाँ								
2.1.1.1 अंतर-बैंक	9022.9	7904.7	8714.1	8298.2	8119.3	8033.8	7428.2	7289.6
2.1.1.2 अन्य	14063.9	14567.8	13668.7	14069.6	14316.8	13861.7	11836.7	13791.0
2.1.2 बैंकों से उधार	700.0		350.0		1289.0	824.2	2912.2	721.2
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	5428.9	5329.2	4544.4	4568.8	4727.9	4578.4	4581.2	4727.8
2.2 मीयादी देयताएं	201100.7	185708.9	199471.9	199412.2	199704.6	200375.1	199917.5	199176.8
2.2.1 जमाराशियाँ								
2.2.1.1 अंतर-बैंक	66874.3	64501.4	66627.7	64779.7	64977.2	64945.2	64334.4	63644.4
2.2.1.2 अन्य	132807.1	119370.2	131385.8	133182.1	133291.9	134005.2	134148.5	134037.9
2.2.2 बैंकों से उधार	643.9	653.2	615.5	615.5	615.5	615.5	615.5	615.5
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	775.4	1184.1	842.9	834.9	820.0	809.2	819.0	878.9
3 रिज़र्व बैंक से उधार	699.5		499.9	499.8	499.8	499.8	499.8	499.8
4 अधिसूचित बैंक/ सरकार से उधार	126928.5	85281.4	120340.2	117224.0	113687.2	112391.9	113039.0	113368.7
4.1 मांग	53459.8	23887.4	50684.0	50291.4	48334.5	47731.0	47805.0	48429.0
4.2 मीयादी	73468.7	61394.0	69656.2	66932.6	65352.6	64660.9	65234.0	64939.6
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	13390.9	13323.7	15967.2	19115.8	12935.0	15919.7	16813.3	14110.1
5.1 उपलब्ध नकदी	1052.1	759.4	813.7	741.3	970.1	756.2	772.5	824.3
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	12338.8	12564.3	15153.5	18374.6	11964.9	15163.5	16040.7	13285.8
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेषराशि	1656.3	1631.9	1856.2	1487.3	1306.3	1197.9	1102.6	1230.4
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	77220.1	75500.4	79265.3	78742.6	78309.8	79425.0	79798.1	80061.3
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	26531.1	20740.5	22162.6	20185.1	22926.3	53472.9	21442.9	18248.3
9 बैंक ऋण (10.1+11)	174828.8	134324.1	174573.0	185733.8	173379.6	173468.6	173065.3	173173.8
10 अग्रिम								
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	174590.4	134111.9	174312.5	185468.1	173105.4	173203.9	172775.8	172882.6
10.2 बैंकों से प्राप्त राशि	124607.6	135046.8	119426.7	118050.3	116990.1	116484.5	116407.6	116476.4
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	238.4	212.2	260.5	265.6	274.2	264.7	289.5	291.2

कीमत और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2024-25			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	अग.24	जुला.25	अग.25(अ)	अग.24	जुला.25	अग.25(अ)	अग.24	जुला.25	अग.25(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	198.6	205.3	201.1	200.2	198.4	199.9	207.1	207.0	207.8	202.7	201.6	202.8
1.1 अनाज और उत्पाद	195.0	193.7	194.6	192.6	197.0	197.5	191.9	197.3	197.8	192.4	197.1	197.6
1.2 मांस और मछली	222.3	231.9	225.7	220.1	225.5	222.8	229.2	236.3	233.7	223.3	229.3	226.6
1.3 अंडा	192.8	197.5	194.6	188.0	196.3	193.3	190.7	202.3	197.4	189.0	198.6	194.9
1.4 दूध और उत्पाद	186.3	187.0	186.6	186.2	190.4	190.8	187.1	192.1	192.4	186.5	191.0	191.4
1.5 तेल और चर्बी	175.4	165.5	171.8	164.1	197.9	202.3	157.1	182.1	184.5	161.5	192.1	195.8
1.6 फल	188.3	194.2	191.0	186.1	210.2	211.7	197.5	217.2	215.9	191.4	213.5	213.7
1.7 सब्जी	222.1	269.6	238.2	245.0	196.4	203.9	291.2	242.6	249.1	260.7	212.1	219.2
1.8 दाल और उत्पाद	208.0	213.5	209.8	212.5	182.8	182.0	219.0	187.2	186.4	214.7	184.3	183.5
1.9 चीनी और उत्पाद	130.4	132.6	131.2	130.7	134.7	135.7	132.8	136.4	137.4	131.4	135.3	136.3
1.10 मसाले	228.5	223.9	227.0	229.6	221.6	221.6	225.0	219.2	218.9	228.1	220.8	220.7
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	185.2	173.9	180.5	183.8	190.9	191.4	172.8	180.5	180.6	179.2	186.6	186.9
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	199.4	209.7	204.2	198.5	205.3	206.1	208.3	217.5	217.8	203.0	211.0	211.5
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	207.3	212.6	208.7	206.8	211.6	212.1	213.1	217.9	218.2	208.5	213.3	213.7
3 कपड़ा और जूते	197.9	186.7	193.5	197.2	201.3	201.4	186.0	190.7	191.0	192.8	197.1	197.3
3.1 कपड़ा	198.8	188.8	194.9	198.0	202.2	202.4	188.1	193.0	193.3	194.1	198.6	198.8
3.2 जूते	192.7	174.7	185.2	192.3	195.5	195.7	174.2	178.2	178.4	184.8	188.3	188.5
4 आवास	--	181.5	181.5	--	--	--	181.1	185.7	186.7	181.1	185.7	186.7
5 ईंधन और प्रकाश	181.2	169.7	176.9	180.9	184.0	184.5	169.8	175.3	175.2	176.7	180.7	181.0
6 विविध	189.3	180.7	185.1	188.3	197.4	198.2	180.1	188.1	188.8	184.3	192.9	193.6
6.1 घरेलू सामान और सेवा	185.7	177.1	181.6	184.9	188.4	188.8	176.4	181.0	181.9	180.9	184.9	185.5
6.2 स्वास्थ्य	198.4	193.2	196.4	197.3	205.4	206.0	192.2	200.3	200.7	195.4	203.5	204.0
6.3 परिवहन और संचार	175.5	164.8	169.9	176.1	179.4	179.8	165.3	168.1	168.2	170.4	173.5	173.7
6.4 मनोरंजन	180.1	175.5	177.5	179.6	182.8	183.1	174.9	178.7	179.2	177.0	180.5	180.9
6.5 शिक्षा	190.8	186.2	188.1	191.7	196.8	197.3	186.5	193.7	194.2	188.7	195.0	195.5
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और संबंधित सामन	204.3	206.2	205.1	199.1	229.8	232.3	201.0	232.0	234.3	199.9	230.7	233.1
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	194.9	190.0	192.6	195.4	197.6	198.7	190.3	194.3	195.0	193.0	196.1	197.0

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2024-25	2024	2025	
				जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	142.6	142.7	145.0	146.5
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2019	9.69	-	134.3	134.1	135.3
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2019	9.78	-	134.3	134.4	135.7

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में स्वर्ण और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2024-25	2024	2025	
		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	75842	71189	97176	97581
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	89131	88058	105444	110958

स्रोत: मुंबई में स्वर्ण और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।



सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक  
(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2024-25	2024	2025		
			अग.	जून	जुला.(अ)	अग.(अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	154.9	154.4	153.7	154.4	155.2
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	192.5	195.1	186.1	188.0	191.0
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	205.3	209.0	198.0	199.7	202.6
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	210.1	210.0	203.0	204.1	205.3
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	241.4	259.2	212.4	220.9	231.4
1.1.1.3 दूध	4.440	185.8	185.9	190.2	190.1	190.7
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	173.4	173.1	174.0	171.8	173.2
1.1.1.5 मसाले	0.529	232.7	236.8	199.5	200.0	199.6
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	213.6	205.7	222.8	221.0	218.6
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	161.7	160.2	160.7	164.3	169.1
1.1.2.1 फाइबर	0.839	161.4	161.2	162.7	165.0	168.0
1.1.2.2 तिलहन	1.115	181.5	178.6	190.6	197.8	203.5
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	138.7	140.0	137.8	137.7	139.5
1.1.2.4 पुष्पोत्पादन	0.204	277.4	248.6	210.5	234.5	269.4
1.1.3 खनिज	0.833	229.0	227.6	228.8	229.0	235.1
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	219.2	217.4	219.4	219.6	227.3
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	263.4	263.6	261.9	261.7	262.4
1.1.4 कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस	2.410	151.3	155.0	139.2	140.3	139.7
1.2 ईंधन और ऊर्जा	13.152	150.0	148.3	142.3	144.6	143.6
1.2.1 कोयला	2.138	135.6	135.6	136.7	136.3	136.3
1.2.1.1 कुकिंग कोयला	0.647	143.4	143.4	146.4	146.4	146.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोयला	1.401	125.8	125.8	126.6	126.6	126.6
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	232.4	232.0	224.5	215.0	215.0
1.2.2 खनिज तेल	7.950	156.2	156.9	146.7	149.6	149.5
1.2.3 बिजली	3.064	144.1	134.8	134.5	137.3	133.3
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	142.6	141.3	144.7	144.6	144.9
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	172.0	166.5	177.3	177.3	178.4
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	155.7	153.0	158.2	158.4	158.3
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	144.9	143.8	147.4	146.6	149.3
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	132.6	131.6	135.7	135.9	135.8
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	168.5	150.5	181.5	182.2	185.0
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	180.8	178.5	183.9	183.8	184.0
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	186.9	184.0	185.2	185.7	186.6
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	167.0	173.3	154.7	152.8	150.7
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	170.5	168.4	176.8	176.6	176.5
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	139.1	139.5	143.2	143.0	144.1
1.3.1.10 कोकोआ, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	160.6	157.1	178.7	177.3	177.0
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	156.7	150.8	159.7	160.6	160.1
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	190.7	202.8	203.8	198.9	194.5
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	192.6	191.9	189.7	190.6	190.1
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	152.7	151.9	156.4	156.6	157.3
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	185.1	185.9	188.8	187.8	187.8
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	204.1	208.6	199.9	200.8	203.8
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	134.1	134.0	135.4	135.2	135.6
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	136.0	135.6	138.8	138.3	138.8
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	138.7	138.3	139.9	140.1	140.7
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी का उत्पादन	0.275	127.5	128.1	126.7	126.4	126.7
1.3.3 तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण	0.514	177.8	176.0	179.8	179.9	179.9
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	177.8	176.0	179.8	179.9	179.9

**सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)**  
(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2024-25	2024	2025		
			अग.	जून	जुला.(अ)	अग.(अ)
	1	2	3	4	5	6
<b>1.3.4 वस्त्र विनिर्माण</b>	<b>4.881</b>	<b>136.3</b>	<b>135.9</b>	<b>136.4</b>	<b>136.6</b>	<b>137.8</b>
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	121.4	122.3	120.2	119.9	120.7
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	158.3	155.7	160.1	161.0	163.0
1.3.4.3 बुने हुए और क्रोशिए से बना कपड़ा	0.193	124.0	123.7	125.1	125.3	127.3
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	160.4	160.5	161.0	161.1	160.8
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	142.7	141.1	151.8	155.3	158.9
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	134.9	135.4	132.7	133.1	133.0
<b>1.3.5 तैयार वस्त्र का विनिर्माण</b>	<b>0.814</b>	<b>153.4</b>	<b>152.9</b>	<b>155.5</b>	<b>156.0</b>	<b>155.9</b>
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर, तैयार वस्त्र (बुने हुए) का विनिर्माण	0.593	150.9	150.3	153.8	154.1	154.1
1.3.5.2 बुने हुए और क्रोशिए से बने वस्त्र	0.221	160.1	159.8	160.1	161.0	160.7
<b>1.3.6 चमड़ा और संबंधित उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>0.535</b>	<b>125.3</b>	<b>124.9</b>	<b>127.5</b>	<b>127.6</b>	<b>127.9</b>
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगाई	0.142	106.1	104.1	112.2	112.1	110.7
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और हार्नेस	0.075	142.5	143.1	141.1	141.0	141.9
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	129.7	129.8	131.1	131.3	132.3
<b>1.3.7 लकड़ी व लकड़ी और कॉर्क के उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>0.772</b>	<b>149.2</b>	<b>149.5</b>	<b>150.4</b>	<b>150.1</b>	<b>150.0</b>
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	141.1	140.3	142.2	141.6	142.7
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड, लैमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड का विनिर्माण	0.493	148.6	149.1	149.4	149.3	148.7
1.3.7.3 बिल्डरों की बढईगरी	0.036	215.3	216.4	216.1	215.3	215.3
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	140.6	141.1	143.3	142.7	143.3
<b>1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>1.113</b>	<b>139.2</b>	<b>139.8</b>	<b>140.0</b>	<b>139.8</b>	<b>139.8</b>
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और पेपर बोर्ड	0.493	144.6	145.5	143.9	143.8	143.9
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	147.3	146.1	150.9	151.1	150.9
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	122.4	124.0	122.6	121.9	121.9
<b>1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन</b>	<b>0.676</b>	<b>187.3</b>	<b>187.0</b>	<b>189.6</b>	<b>190.3</b>	<b>191.4</b>
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	187.3	187.0	189.6	190.3	191.4
<b>1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>6.465</b>	<b>136.5</b>	<b>136.7</b>	<b>137.1</b>	<b>137.0</b>	<b>137.1</b>
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	138.6	137.9	141.7	141.2	140.9
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	143.1	143.2	143.0	142.9	142.9
1.3.10.3 प्लास्टिक और प्राथमिक रूप में सिंथेटिक रबड़	1.001	133.6	134.1	134.0	134.6	135.1
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	128.8	129.8	131.6	131.2	131.6
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	139.5	140.7	136.8	136.3	137.1
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	139.7	139.0	142.4	142.6	142.7
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	135.4	136.2	133.5	133.1	132.8
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	104.9	106.9	103.1	103.5	102.9
<b>1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>1.993</b>	<b>144.3</b>	<b>144.8</b>	<b>145.7</b>	<b>146.0</b>	<b>146.0</b>
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	144.3	144.8	145.7	146.0	146.0
<b>1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>2.299</b>	<b>129.0</b>	<b>129.1</b>	<b>129.5</b>	<b>129.1</b>	<b>129.5</b>
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रिट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	115.6	114.8	115.7	115.2	114.9
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	112.1	113.6	113.3	114.3	113.8
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	138.1	138.2	138.5	137.9	138.7
<b>1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>3.202</b>	<b>131.5</b>	<b>129.8</b>	<b>133.4</b>	<b>133.5</b>	<b>133.7</b>
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	163.2	163.5	163.5	163.5	162.9
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	121.6	119.6	123.2	123.7	124.0
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	124.4	121.6	131.0	129.3	133.4
1.3.13.4 चीनी मिट्टी और चीनी मिट्टी के उत्पाद	0.222	124.6	124.6	125.8	125.6	125.6
1.3.13.5 सीमेंट, चूना और प्लास्टर	1.645	130.4	127.7	132.8	133.1	133.1

## सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2024-25	2024	2025		
			अग.	जून	जुला.(अ)	अग.(अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	139.2	138.4	140.1	139.5	140.2
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	134.4	133.7	138.3	138.0	138.2
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	95.2	96.8	93.6	94.9	94.0
<b>1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण</b>	<b>9.646</b>	<b>139.7</b>	<b>138.3</b>	<b>138.6</b>	<b>137.5</b>	<b>137.4</b>
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	133.6	131.2	131.4	131.2	129.8
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	141.8	145.4	129.5	128.6	128.3
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	117.9	114.4	117.1	116.2	115.9
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	140.4	138.6	137.2	135.4	135.8
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	134.2	136.4	134.4	133.0	132.2
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	135.4	134.6	133.2	130.8	128.8
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील - अर्ध निर्मित	0.924	131.1	128.6	128.7	122.6	123.0
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	164.7	165.2	166.7	163.2	161.3
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	157.4	154.6	161.4	162.7	164.1
1.3.14.10 कार्स्टिंग	0.925	144.9	144.0	143.4	143.4	143.6
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	172.2	170.7	177.9	173.9	174.3
<b>1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>3.155</b>	<b>136.0</b>	<b>136.6</b>	<b>137.0</b>	<b>136.6</b>	<b>136.9</b>
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	130.8	131.5	131.4	131.5	132.1
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	149.5	151.2	151.6	149.7	149.2
1.3.15.3 वाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स को छोड़कर	0.145	109.8	111.5	112.1	112.5	113.2
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैम्पिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	138.0	138.4	135.0	133.8	135.7
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	102.0	101.9	104.7	104.8	105.5
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	144.9	144.7	146.8	147.2	146.8
<b>1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>2.009</b>	<b>121.5</b>	<b>121.6</b>	<b>122.1</b>	<b>122.5</b>	<b>122.1</b>
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	117.9	117.4	120.3	120.8	120.1
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	134.2	136.2	131.4	131.4	130.4
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	146.0	145.4	146.9	147.0	147.2
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	101.1	101.1	100.2	100.6	100.0
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	119.9	118.1	126.6	126.6	126.6
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	167.9	166.3	173.7	173.3	175.0
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	114.4	119.7	109.9	115.4	115.4
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	107.4	106.9	118.1	118.1	117.9
<b>1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण</b>	<b>2.930</b>	<b>133.7</b>	<b>133.5</b>	<b>134.8</b>	<b>134.6</b>	<b>135.0</b>
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	132.3	131.7	133.3	132.7	133.2
1.3.17.2 बैटरी और एक्यूमुलेटर	0.236	141.3	141.8	144.1	144.8	144.9
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	118.6	120.7	115.9	115.7	115.9
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	154.4	153.3	158.3	158.6	159.2
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	118.4	118.9	118.5	118.2	118.2
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	131.8	132.4	130.3	130.4	130.8
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	123.4	122.6	125.6	125.5	125.5
<b>1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण</b>	<b>4.789</b>	<b>130.8</b>	<b>130.6</b>	<b>132.5</b>	<b>132.3</b>	<b>132.5</b>
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	132.8	132.4	136.6	136.6	137.1
1.3.18.2 तरल ऊर्जा उपकरण	0.162	134.5	134.0	134.9	134.8	135.0
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	118.5	118.5	119.9	120.2	120.0
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	128.5	126.4	131.9	130.0	129.9
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	86.6	86.7	87.9	88.2	86.6
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने – उतारने वाले उपकरण	0.285	130.0	129.5	130.8	131.0	131.2

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)  
(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2024-25	2024	2025		
			अग.	जून	जुला.(अ)	अग.(अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उप करण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उप करण	0.437	145.3	149.2	143.8	141.8	142.4
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	145.5	144.3	146.8	146.4	146.2
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	123.2	122.8	127.3	127.4	127.4
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	89.8	88.8	92.7	93.0	92.9
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	126.1	126.2	127.8	128.0	127.0
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	141.4	141.9	139.9	139.6	144.9
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	144.9	144.8	147.1	147.5	147.9
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	69.2	69.1	69.4	69.4	69.4
<b>1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण</b>	<b>4.969</b>	<b>129.9</b>	<b>129.8</b>	<b>130.6</b>	<b>130.7</b>	<b>130.7</b>
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	130.6	130.3	131.1	131.2	131.2
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	129.1	129.3	130.1	130.1	130.1
<b>1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण</b>	<b>1.648</b>	<b>145.2</b>	<b>144.6</b>	<b>150.4</b>	<b>151.1</b>	<b>151.8</b>
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली – वस्तुओं का निर्माण	0.117	180.5	177.9	190.7	190.7	190.7
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	108.9	110.0	109.8	110.0	111.0
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	146.0	145.4	151.4	152.1	152.9
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	134.9	134.6	137.1	138.2	138.2
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	163.2	162.4	165.8	165.9	165.6
<b>1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण</b>	<b>0.727</b>	<b>160.3</b>	<b>159.0</b>	<b>164.6</b>	<b>164.8</b>	<b>164.7</b>
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	160.3	159.0	164.6	164.8	164.7
<b>1.3.22 अन्य विनिर्माण</b>	<b>1.064</b>	<b>183.8</b>	<b>174.1</b>	<b>224.5</b>	<b>226.8</b>	<b>227.7</b>
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	185.4	175.0	228.6	231.1	232.0
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	201.9	201.4	204.3	204.3	203.5
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	164.9	163.6	171.4	171.9	172.4
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	163.1	163.6	164.7	160.2	162.6
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और संबंधित सामग्री	0.049	158.6	159.7	162.1	162.1	160.9
<b>2 खाद्य सूचकांक</b>	<b>24.378</b>	<b>192.9</b>	<b>193.1</b>	<b>190.2</b>	<b>191.3</b>	<b>193.5</b>

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भार	2023-24	2024-25	अप्रै.-जून		जुला.	
				2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	146.7	152.6	150.9	154.4	149.8	155.0
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	128.9	132.8	129.6	124.5	116.1	107.7
1.2 विनिर्माण	77.63	144.7	150.6	147.6	153.3	148.8	156.9
1.3 बिजली	7.99	198.3	208.6	221.1	219.0	220.2	221.5
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	147.7	153.5	154.8	152.6	150.1	147.6
2.2 पूंजीगत माल	8.22	106.6	112.6	106.4	115.5	114.0	119.7
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	157.3	164.0	161.0	169.4	164.6	174.1
2.4 इन्फ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं	12.34	176.3	188.2	183.8	197.5	179.7	201.0
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	118.6	128.0	125.9	130.7	126.6	136.3
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	153.7	151.4	149.3	147.8	147.1	147.8

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खजाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(₹ करोड़)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - जुला.			
	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (वास्तविक आंकड़े)	2024-25 (वास्तविक आंकड़े)	बजट अनुमान का प्रतिशत	
	1	2	3	2025-26	2024-25
1 राजस्व प्राप्ति	3420409	1065420	1017020	31.1	32.5
1.1 कर राजस्व (निवल)	2837409	661812	715224	23.3	27.7
1.2 करेतर राजस्व	583000	403608	301796	69.2	55.3
2 गैर कर्ज पूंजीगत प्राप्ति	76000	29789	6386	39.2	8.2
2.1 ऋण की वसूली	29000	7138	6381	24.6	22.8
2.2 अन्य प्राप्ति	47000	22651	5	48.2	0.0
3 कुल प्राप्ति (लिए गए उधार को छोड़कर) (1+2)	3496409	1095209	1023406	31.3	31.9
4 राजस्व व्यय जिसमें से :	3944255	1216699	1039091	30.8	28.0
4.1 ब्याज भुगतान	1276338	446690	327887	35.0	28.2
5 पूंजी व्यय	1121090	346926	261260	30.9	23.5
6 कुल व्यय (4+5)	5065345	1563625	1300351	30.9	27.0
7 राजस्व घाटा (4-1)	523846	151279	22071	28.9	3.8
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	1568936	468416	276945	29.9	17.2
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	292598	21726	-50942	7.4	-11.3

स्रोत: महालेखा नियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और अंतरिम केंद्रीय बजट 2025-26।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2024-25	2024	2025					
		जुला. 26	जून. 20	जून. 27	जुला. 4	जुला. 11	जुला. 18	जुला. 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 91-दिवसीय</b>								
1.1 बैंक	26554	2466	18639	18898	17315	16732	16088	15002
1.2 प्राथमिक व्यापारी	25258	9749	21671	18582	17761	16823	16781	17505
1.3 राज्य सरकारें	40315	46140	71291	80904	81477	87277	92777	71677
1.4 अन्य	115688	95885	96090	95120	97524	97045	97731	98093
<b>2 182-दिवसीय</b>								
2.1 बैंक	44887	51248	51017	49943	48673	50941	51612	54296
2.2 प्राथमिक व्यापारी	62218	57730	55998	57055	54535	52998	51354	56692
2.3 राज्य सरकारें	11078	14922	18888	16888	16888	17888	17419	17460
2.4 अन्य	104994	119522	93886	92901	94692	91961	90934	80911
<b>3 364-दिवसीय</b>								
3.1 बैंक	72304	90700	71580	71571	73723	74980	75410	74597
3.2 प्राथमिक व्यापारी	86939	137182	74466	76439	78576	76859	74963	74963
3.3 राज्य सरकारें	37389	38525	44898	45967	46328	46459	46563	47732
3.4 अन्य	162757	164118	160754	159789	154500	155860	157527	157340
<b>4 14-दिवसीय मध्यवर्ती</b>								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	188072	175531	156490	155018	85981	142202	138198	184745
4.4 अन्य	572	1008	1297	428	229	2607	1638	1026
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	790381	828188	779176	784059	781993	785823	789158	766268

# 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं हैं, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।  
**टिप्पणी:** प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियाँ			कुल निर्गम (6+7)	निर्दिष्ट मूल्य ( ₹ )	निर्दिष्ट मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2025-26										
जुला. 2	9000	129	38698	1202	34	8975	1202	10177	98.68	5.3699
जुला. 9	9000	151	40780	5814	41	8986	5814	14800	98.67	5.3872
जुला. 16	9000	140	36181	7429	40	8971	7429	16400	98.68	5.3851
जुला. 23	9000	161	37548	5127	35	8973	5127	14100	98.67	5.3872
जुला. 30	10000	102	25879	16274	60	9976	16274	26250	98.67	5.3970
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2025-26										
जुला. 2	6000	100	28293	23	25	5977	23	6000	97.33	5.5001
जुला. 9	6000	103	22512	2311	50	5989	2311	8300	97.31	5.5371
जुला. 16	6000	171	36447	300	28	5980	300	6280	97.31	5.5399
जुला. 23	6000	145	33760	1009	28	5991	1009	7000	97.32	5.5291
जुला. 30	6000	122	30192	1007	29	5993	1007	7000	97.32	5.5206
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2025-26										
जुला. 2	5000	97	18105	471	58	4989	471	5460	94.76	5.5494
जुला. 9	5000	81	21498	2492	36	4950	2492	7442	94.73	5.5787
जुला. 16	5000	113	24851	1332	47	4986	1332	6318	94.72	5.5924
जुला. 23	5000	122	29165	1254	26	4987	1254	6240	94.74	5.5701
जुला. 30	5000	103	26370	164	35	4989	164	5153	94.74	5.5673

# वित्तीय बाजार

## सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

की स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा	भारित औसत दरें
	उधार लेना / उधार देना	उधार लेना / उधार देना
	1	2
जुला. 01 ,2025	4.75-5.40	5.31
जुला. 02 ,2025	4.70-5.35	5.27
जुला. 03 ,2025	4.75-5.35	5.26
जुला. 04 ,2025	4.75-5.35	5.26
जुला. 05 ,2025	4.70-5.30	4.91
जुला. 07 ,2025	4.75-5.35	5.26
जुला. 08 ,2025	4.50-5.35	5.26
जुला. 09 ,2025	4.80-5.45	5.32
जुला. 10 ,2025	4.75-5.45	5.35
जुला. 11 ,2025	4.75-5.55	5.45
जुला. 14 ,2025	4.75-5.40	5.31
जुला. 15 ,2025	4.75-5.50	5.38
जुला. 16 ,2025	4.75-5.45	5.36
जुला. 17 ,2025	4.75-5.50	5.35
जुला. 18 ,2025	4.75-5.45	5.33
जुला. 19 ,2025	4.75-5.40	5.00
जुला. 21 ,2025	4.75-5.70	5.48
जुला. 22 ,2025	4.75-5.80	5.62
जुला. 23 ,2025	4.75-5.85	5.73
जुला. 24 ,2025	4.75-5.65	5.54
जुला. 25 ,2025	4.75-5.50	5.39
जुला. 28 ,2025	4.75-5.40	5.34
जुला. 29 ,2025	4.75-5.45	5.38
जुला. 30 ,2025	4.75-5.42	5.37
जुला. 31 ,2025	4.75-5.55	5.48
अगस्त 01 ,2025	4.75-5.55	5.44
अगस्त 02 ,2025	4.75-5.24	4.95
अगस्त 04 ,2025	4.75-5.45	5.37
अगस्त 05 ,2025	4.75-5.45	5.36
अगस्त 06 ,2025	4.75-5.50	5.33
अगस्त 07 ,2025	4.75-6.00	5.44
अगस्त 08 ,2025	4.75-5.70	5.55
अगस्त 11 ,2025	4.75-5.45	5.36
अगस्त 12 ,2025	4.85-5.55	5.45
अगस्त 13 ,2025	4.75-5.55	5.46
अगस्त 14 ,2025	4.85-5.68	5.46

टिप्पणी : नोटिस मुद्रा शामिल है।



**सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र**

मद	2024	2025			
	अग. 23	जुला. 11	जुला. 25	अग. 8	अग. 22
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	446580.44	525253.75	508451.73	511313.00	494942.79
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (₹ करोड़)	46185.89	18575.50	18550.54	27981.81	36879.16
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	7.03-7.68	5.67-6.49	5.59-6.63	5.64-6.24	5.66-6.27

**सं. 28: वाणिज्यिक पत्र**

मद	2024	2025					
	जुला. 31	जून 15	जून 30	जुला. 15	जुला. 31	अग. 15	अग. 31
	1	2	3	4	5	6	7
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	458911.05	549258.30	500000.60	534009.15	547229.30	554479.70	543870.10
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (₹ करोड़)	67966.95	102447.00	58021.75	79530.05	73858.50	56758.35	60807.60
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.89-12.07	5.67-11.63	5.71-13.84	5.51-12.67	5.57-13.84	5.68-12.67	5.72-13.83

**सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार**

(₹ करोड़)

मद	2024-25	2024	2025					
		जुला. 26	जून 20	जून 27	जुला. 4	जुला. 11	जुला. 18	जुला. 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	18990	17812	24157	28538	25874	29963	28444	29057
2 नोटिस मुद्रा	2506	228	6749	307	6276	535	6323	380
3 मीयादी मुद्रा	941	618	903	990	1098	1679	1361	1240
4 त्रिपक्षीय रेपो	692068	693314	802836	702250	858204	663802	788486	682533
5 बाजार रेपो	578912	566606	763218	632175	789565	633563	750243	610007
6 कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो	5212	3283	9639	8409	8251	9481	9722	9721
7 विदेशी मुद्रा (यूएस मिलियन डॉलर)	131877	103577	118707	165416	137181	122259	127800	123941
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	56065	139737	132864	121551	114628	82402	89891	82508
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	3971	6747	5182	4910	6521	4755	8566	7952
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	2514	3301	6647	3997	4351	4625	3984	4981
10.2 182-दिवसीय	2218	4933	4672	3436	3339	2508	4595	3470
10.3 364-दिवसीय	1854	4467	3093	1967	3392	2562	3923	2395
10.4 नकदी प्रबंधन बिल		0	0	0	0	0	0	0
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	66622	159184	152459	135862	132231	96851	110959	101306
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	1715	2077	816	596	33	176	811	627

सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2024-25		2024-25 (अप्रै.-जुला.)		2025-26 (अप्रै.-जुला.) *		जुला. 2024		जुला. 2025 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	464	210190	154	50281	132	51219	42	9001	59	28160
1.1 पब्लिक	322	190478	106	42592	90	41596	31	6210	45	26132
1.2 राइट्स	142	19712	48	7690	42	9623	11	2791	14	2029
2 बॉन्ड और डिबेंचर्स के सार्वजनिक निर्गम	43	8149	12	2716	17	4086	2	262	6	2000
3 कुल (1+2)	507	218339	166	52997	149	55305	44	9263	65	30161
3.1 पब्लिक	365	198627	118	45307	107	45682	33	6472	51	28132
3.2 राइट्स	142	19712	48	7690	42	9623	11	2791	14	2029

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।  
2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़े कुल में न जुड़ पाने की संभावना है।  
3. सारणी में केवल इक्विटी और ऋण के पब्लिक और राइट्स निर्गम शामिल हैं। इसमें ऋण के निजी प्लेसमेंट, पात्र संस्थागत प्लेसमेंट और अधिमान्य आवंटन के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

\* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31 : विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2024-25		2024	2025			
				जुला.	मार्च	अप्रै	मई	जून
		1	2	3	4	5	6	जुला.
1 निर्यात	₹ करोड़	3701070	290134	363598	328021	327855	301901	320672
	यूएस \$ मिलियन	437416	34707	41968	38338	38485	35144	37238
1.1 तेल	₹ करोड़	534917	48417	42467	61423	47820	39650	37385
	यूएस \$ मिलियन	63341	5792	4902	7179	5613	4616	4341
1.2 तेल से इतर	₹ करोड़	3166153	241716	321131	266598	280035	262251	283287
	यूएस \$ मिलियन	374075	28915	37066	31159	32872	30529	32897
2 आयात	₹ करोड़	6089909	497180	550211	555329	516260	463159	556189
	यूएस \$ मिलियन	720241	59475	63507	64904	60601	53916	64587
2.1 तेल	₹ करोड़	1570226	121162	164684	177212	125635	118534	134126
	यूएस \$ मिलियन	185779	14494	19008	20712	14748	13799	15575
2.2 तेल से इतर	₹ करोड़	4519683	376018	385527	378117	390624	344624	422063
	यूएस \$ मिलियन	534462	44981	44499	44193	45853	40118	49012
3 व्यापार शेष	₹ करोड़	-2388839	-207046	-186613	-227308	-188405	-161257	-235517
	यूएस \$ मिलियन	-282825	-24768	-21539	-26567	-22116	-18772	-27349
3.1 तेल	₹ करोड़	-1035309	-72744	-122217	-115789	-77815	-78884	-96741
	यूएस \$ मिलियन	-122438	-8702	-14107	-13533	-9134	-9183	-11234
3.2 तेल से इतर	₹ करोड़	-1353530	-134302	-64395	-111519	-110590	-82373	-138776
	यूएस \$ मिलियन	-160387	-16066	-7433	-13034	-12982	-9589	-16115

टिप्पणी: सारणी में डेटा अनंतिम हैं।  
स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

मद	इकाई	2024	2025					
		सितं. 06	जुला. 25	अग. 01	अग. 08	अग. 15	अग. 22	अग. 29
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल आरक्षित निधियां	₹ करोड़	5785515	6040880	6030417	6081131	6086782	6046195	6125356
	यूएस \$ मिलियन	689235	698192	688871	693618	695106	690720	694230
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	₹ करोड़	5071259	5095487	5091494	5119915	5130564	5096748	5152367
	यूएस \$ मिलियन	604144	588926	581607	583979	585903	582251	583937
1.2 स्वर्ण	₹ करोड़	520331	741528	735336	755391	750161	744074	765603
	यूएस \$ मिलियन	61988	85704	83998	86160	85667	85003	86769
	मात्रा (मीट्रिक टन)	853.64	879.98	879.98	879.98	879.98	879.98	879.98
1.3 एसडीआर	एसडीआर मिलियन	13702	13707	13707	13707	13707	13709	13709
	₹ करोड़	155056	162741	162582	164304	164467	164003	165665
	यूएस \$ मिलियन	18472	18809	18572	18741	18782	18736	18775
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	₹ करोड़	38869	41125	41005	41521	41591	41371	41721
	यूएस \$ मिलियन	4631	4753	4694	4739	4754	4731	4749

\* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन की वजह से है।  
टिप्पणी : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा एवं नेक्सस ग्लोबल पेमेंट्स को निधियन के रूप में आरबीआई के अंशदान शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों को रिजर्व में रखी गैर-यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2024-25	2024	2025		2024-25	2025-26
		जुला.	जून	जुला. (अ)	अप्रै-जुला.	अप्रै-जुला.(अ)
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियाँ	164677	157157	168327	167862	5820	4657
1.1 एफसीएनआर (बी)	32809	28572	33583	33581	2839	772
1.2 एनआर (ई) आरए	100733	99981	102750	102029	1780	2418
1.3 एनआरओ	31135	28603	31993	32251	1201	1468

अ: अनंतिम ।

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2024-25	2024-25	2025-26 (अ)	2024 (अ)	2025 (अ)	
		अप्रै.-जुला.	अप्रै.-जुला.	जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	959	3536	10751	-2688	2507	5046
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.1.2)	29130	10937	21435	331	5413	7304
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह / सकल निवेश	80615	28316	37712	5539	9571	11105
1.1.1.1.1 इक्विटी	50993	19693	28178	3291	7175	8760
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	2208	321	1371	112	1004	11
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	34686	13863	19894	2099	5337	6366
1.1.1.1.1.3 शेयरों का अधिग्रहण	13124	5207	6046	1002	571	2306
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	975	302	867	78	263	78
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	22759	7037	7688	1812	1959	1812
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	6863	1587	1846	436	438	533
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	51486	17379	16277	5207	4159	3801
1.1.1.2.1 इक्विटी	49525	16679	15743	5005	4026	3666
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	1960	700	534	202	133	135
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	28171	7402	10684	3019	2905	2258
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	16945	5100	6201	2372	2038	1449
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	6846	2282	2454	571	628	571
1.1.2.3 अन्य पूंजी	7955	1350	2966	260	445	561
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	3575	1330	938	183	205	323
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	3564	6785	-1116	5840	2435	-2724
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	3283	6725	-2	5828	2726	-2483
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	-281	-59	1113	-12	291	241
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	4523	10320	9635	3152	4943	2322

अ: अनंतिमा

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2024-25	2024	2025		
		जुला.	मई	जून	जुला.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	29563.12	2754.05	2313.16	2127.39	2452.93
1.1 जमाराशियाँ	705.26	41.68	54.65	42.12	46.24
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	322.82	24.54	41.69	37.75	39.48
1.3 इक्विटी / कर्ज में निवेश	1698.94	120.86	104.94	206.12	156.19
1.4 उपहार	2938.69	275.26	233.30	190.51	223.53
1.5 दान	11.81	0.68	1.98	1.26	0.73
1.6 यात्रा	16964.57	1662.13	1389.23	1235.17	1445.34
1.7 निकट संबंधियों से संबंधित खर्चे	3722.03	337.40	322.54	262.97	298.11
1.8 चिकित्सा उपचार	81.19	8.62	6.72	5.59	6.26
1.9 विदेश में शिक्षा	2918.91	272.16	149.78	138.76	229.25
1.10 अन्य	198.90	10.72	8.32	7.15	7.80

सं. 36: भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और  
वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक

मद	2023-24	2024-25	2024	2025	
			अग.	जुला.	अग.
	1	2	3	4	5
<b>40- मुद्रा समूह (आधार: 2015-16 = 100 )</b>					
1 व्यापार-आधारित भारांक					
1.1 नीर	90.75	91.03	90.80	86.57	85.40
1.2 रीर	103.71	105.26	105.50	100.19	98.79
2 निर्यात-आधारित भारांक					
2.1 नीर	93.13	93.52	93.46	88.62	87.35
2. 2 रीर	101.22	102.34	102.85	97.45	95.97
<b>6- मुद्रा समूह (व्यापार-भारित)</b>					
1 आधार : 2015-16 =100					
1.1 नीर	83.62	82.38	82.02	78.58	77.47
1.2 रीर	101.66	102.72	102.50	98.15	97.14
2 आधार : 2022-23 = 100					
2.1 नीर	97.31	95.87	95.46	91.44	90.16
2.2 रीर	99.86	100.90	100.69	96.41	95.42

टिप्पणी : 2024-25 और 2025-26 के लिए अब तक का डेटा अनंतिम है।

## सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि मिलियन यूएस\$ में)

मद	2024-25	2024	2025	
		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1328	119	112	126
1.2 राशि	47800	3581	2733	3220
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	51	0	1	1
2.2 राशि	13384	0	750	101
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1379	119	113	127
3.2 राशि	61184	3581	3483	3321
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.05	5.20	4.90	5.30
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 अस्थिर दर के ऋणों@ के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) पर भारत औसत मार्जिन	1.48	1.45	1.70	1.61
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-11.67	0.00-10.00	0.00-10.50	0.00-10.80

## उधारकर्ता श्रेणियाँ

I. कॉरपोरेट विनिर्माण	13900	626	954	299
II. कॉरपोरेट - बुनियादी संरचना	15462	1393	1819	1260
ए) परिवहन	614	0	5	0
बी) ऊर्जा	6900	559	155	724
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	28	0	0	0
डी) संचार	13	0	0	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	184	0	7	0
एफ) अन्वेषण, खनन और रिफाइनरी	5356	800	0	160
जी) अन्य उप-क्षेत्र	2367	34	1652	376
III. कॉरपोरेट सेवा क्षेत्र	3226	349	19	379
IV. अन्य संस्थाएं	1026	4	0	0
ए) एसईजेड में इकाइयां	26	4	0	0
बी) सिडबी	0	0	0	0
सी) एक्विजिशन बैंक	1000	0	0	0
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी के अलावा)	0	0	0	0
VII. एनबीएफसी	26318	1195	682	1372
ए) एनबीएफसी - आईएफसी / एएफसी	12389	0	97	121
बी) एनबीएफसी - एमएफआई	459	16	18	15
सी) एनबीएफसी - अन्य	13470	1179	567	1236
VIII. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)	0	0	0	0
	1252	14	9	11

टिप्पणी: ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों के आधार पर जिन्हें निर्धारित अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या आबंटित की गई है।

@ 01 जुलाई, 2023 से लागू, बेचमार्क दर को बदलकर वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) कर दिया गया है।

## सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	अप्रै-जून 2024			अप्रै-जून 2025 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
<b>समग्र भुगतान शेष (1+2+3)</b>	<b>507129</b>	<b>501903</b>	<b>5226</b>	<b>545826</b>	<b>541318</b>	<b>4508</b>
<b>1 चालू खाता (1.1+1.2)</b>	<b>241832</b>	<b>250508</b>	<b>-8676</b>	<b>256736</b>	<b>259106</b>	<b>-2370</b>
<b>1.1 पण्य</b>	<b>111158</b>	<b>174963</b>	<b>-63805</b>	<b>113087</b>	<b>181551</b>	<b>-68464</b>
<b>1.2 अप्रत्यक्ष मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)</b>	<b>130674</b>	<b>75545</b>	<b>55129</b>	<b>143649</b>	<b>77555</b>	<b>66094</b>
1.2.1 सेवाएं	88465	48784	39681	97428	49507	47920
1.2.1.1 यात्रा	7352	9171	-1819	5855	9085	-3230
1.2.1.2 परिवहन	8506	8609	-103	7708	8395	-687
1.2.1.3 बीमा	903	593	310	926	613	313
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	161	309	-147	134	323	-188
1.2.1.5 विविध	71542	30102	41440	82805	31092	51712
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	41926	4479	37447	47324	5853	41471
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	23000	16625	6375	29511	15868	13643
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	2215	1267	948	1945	703	1242
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	519	444	75	503	380	123
1.2.2 अंतरण	29520	3215	26304	34048	3029	31019
1.2.2.1 आधिकारिक	18	312	-293	20	217	-197
1.2.2.2 निजी	29502	2904	26598	34028	2812	31216
1.2.3 आय	12689	23546	-10857	12174	25019	-12845
1.2.3.1 निवेश आय	10552	22568	-12016	10044	23992	-13948
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	2137	978	1159	2130	1027	1103
<b>2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>264502</b>	<b>251395</b>	<b>13107</b>	<b>289090</b>	<b>281389</b>	<b>7700</b>
<b>2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)</b>	<b>183768</b>	<b>176600</b>	<b>7168</b>	<b>173561</b>	<b>166248</b>	<b>7313</b>
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	23925	17701	6224	27222	21517	5705
2.1.1.1 भारत में	22777	12171	10606	26607	12476	14131
2.1.1.1.1 इक्विटी	16402	11673	4728	19418	12078	7340
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	5225		5225	5876		5876
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1151	498	653	1313	398	914
2.1.1.2 विदेश में	1147	5529	-4382	615	9041	-8426
2.1.1.2.1 इक्विटी	1147	2728	-1580	615	4752	-4137
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	1712	-1712	0	1884	-1884
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1090	-1090	0	2405	-2405
2.1.2 संविभाग निवेश	159844	158899	945	146339	144731	1608
2.1.2.1 भारत में	159240	158343	897	145201	142720	2481
2.1.2.1.1 एफआईआई	159240	158343	897	145201	142720	2481
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	139824	140833	-1009	123636	118245	5391
2.1.2.1.1.2 ऋण	19416	17510	1906	21565	24475	-2910
2.1.2.1.2 एडीआर / जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	604	556	48	1138	2011	-872
<b>2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)</b>	<b>31815</b>	<b>26686</b>	<b>5129</b>	<b>65326</b>	<b>59337</b>	<b>5989</b>
2.2.1 बाह्य सहायता	3640	2267	1373	3120	2398	722
2.2.1.1 भारत द्वारा	6	26	-20	6	11	-5
2.2.1.2 भारत को	3634	2241	1393	3114	2387	727
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	12627	11098	1529	46754	42206	4548
2.2.2.1 भारत द्वारा	4138	4255	-117	36024	35153	871
2.2.2.2 भारत को	8489	6843	1646	10730	7053	3677
2.2.3 भारत को अल्पावधि	15548	13321	2228	15453	14734	719
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	13729	13321	408	15453	13689	1764
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	1820	0	1820	0	1045	-1045
<b>2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)</b>	<b>36380</b>	<b>33511</b>	<b>2870</b>	<b>33634</b>	<b>35189</b>	<b>-1555</b>
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	36259	33511	2749	33625	35189	-1564
2.3.1.1 आस्तियां	10705	13570	-2865	8579	13083	-4504
2.3.1.2 देयताएं	25554	19941	5614	25046	22106	2939
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	23426	19401	4025	23778	20164	3614
2.3.2 अन्य	121	0	121	10	0	10
<b>2.4 रुपया कर्ज चुकौती</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>-61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>-61</b>
<b>2.5 अन्य पूंजी</b>	<b>12538</b>	<b>14537</b>	<b>-1999</b>	<b>16568</b>	<b>20554</b>	<b>-3986</b>
<b>3 भूल-चूक</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>823</b>	<b>-823</b>
<b>4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)</b>	<b>0</b>	<b>5226</b>	<b>-5226</b>	<b>0</b>	<b>4508</b>	<b>-4508</b>
4.1 आई.एम.एफ.	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)		5226	-5226		4508	-4508

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक



सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	अप्रै-जून 2024			अप्रै-जून 2025 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	4230634	4187037	43597	4669620	4631057	38563
1 चालू खाता (1.1+1.2)	2017438	2089818	-72379	2196416	2216691	-20275
1.1 पण्य	927317	1459598	-532281	967474	1553197	-585723
1.2 अप्रत्यक्ष मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	1090122	630220	459902	1228942	663494	565447
1.2.1 सेवाएं	738001	406971	331030	833507	423543	409964
1.2.1.1 यात्रा	61335	76511	-15177	50087	77720	-27633
1.2.1.2 परिवहन	70959	71816	-856	65943	71818	-5876
1.2.1.3 बीमा	7534	4950	2584	7924	5245	2679
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	1346	2575	-1229	1148	2761	-1612
1.2.1.5 विविध	596827	251118	345709	708405	265999	442406
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	349760	37363	312397	404862	50070	354792
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	191873	138694	53178	252469	135754	116715
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	18478	10572	7906	16636	6012	10624
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4331	3702	629	4305	3251	1053
1.2.2 अंतरण	246264	26824	219440	291287	25911	265375
1.2.2.1 आधिकारिक	153	2599	-2446	172	1858	-1686
1.2.2.2 निजी	246112	24225	221887	291114	24053	267061
1.2.3 आय	105857	196425	-90569	104148	214040	-109892
1.2.3.1 निवेश आय	88028	188267	-100239	85926	205255	-119329
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	17829	8158	9670	18222	8785	9437
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2206565	2097219	109346	2473204	2407326	65878
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	1533057	1473256	59801	1484840	1422274	62567
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	199586	147666	51920	232886	184078	48808
2.1.1.1 भारत में	190016	101538	88478	227624	106733	120892
2.1.1.1.1 इक्विटी	136827	97382	39445	166121	103325	62795
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	43588	0	43588	50274	0	50274
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	9600	4156	5444	11230	3407	7822
2.1.1.2 विदेश में	9570	46128	-36558	5262	77345	-72084
2.1.1.2.1 इक्विटी	9570	22755	-13184	5262	40654	-35392
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	14278	-14278	0	16116	-16116
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	9095	-9095	0	20575	-20575
2.1.2 संविभाग निवेश	1333471	1325590	7881	1251954	1238196	13759
2.1.2.1 भारत में	1328434	1320949	7485	1242216	1220994	21223
2.1.2.1.1 एफआईआई	1328434	1320949	7485	1242216	1220994	21223
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	1166461	1174878	-8416	1057724	1011603	46121
2.1.2.1.1.2 ऋण	161973	146071	15901	184493	209391	-24898
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	5037	4641	396	9738	17202	-7464
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	265411	222623	42788	558876	507639	51237
2.2.1 बाह्य सहायता	30365	18913	11451	26690	20513	6177
2.2.1.1 भारत द्वारा	52	217	-166	52	94	-42
2.2.1.2 भारत को	30313	18696	11617	26638	20419	6219
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	105337	92583	12753	399987	361074	38913
2.2.2.1 भारत द्वारा	34517	35497	-980	308187	300735	7452
2.2.2.2 भारत को	70820	57087	13733	91800	60339	31461
2.2.3 भारत को अल्पावधि	129710	111126	18583	132199	126052	6147
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	114529	111126	3402	132199	117110	15089
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	15181	0	15181	0	8942	-8942
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	303498	279556	23942	287747	301047	-13300
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	302487	279556	22931	287664	301047	-13384
2.3.1.1 आस्तियां	89303	113205	-23902	73395	111925	-38530
2.3.1.2 देयताएं	213184	166351	46833	214268	189122	25147
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	195426	161851	33575	203422	172503	30920
2.3.2 अन्य	1011	0	1011	84	0	84
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	508	-508	0	524	-524
2.5 अन्य पूंजी	104599	121277	-16677	141740	175841	-34101
3 भूल-चूक	6630	0	6630	0	7040	-7040
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	43597	-43597	0	38563	-38563
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	43597	-43597	0	38563	-38563

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन यूएस \$)

मद	अप्रै-जून 2024			अप्रै-जून 2025 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	241831	250477	-8646	256736	259087	-2351
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	199623	223747	-24124	210514	231059	-20544
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	111158	174963	-63805	113087	181551	-68464
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	111119	166616	-55497	112707	174065	-61359
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	39	0	39	380	0	380
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		8347	-8347		7486	-7486
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	88465	48784	39681	97428	49507	47920
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	268	22	246	253	40	213
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	81	238	-157	76	267	-191
1.अ.ख.3 परिवहन	8506	8609	-103	7708	8395	-687
1.अ.ख.4 यात्रा	7352	9171	-1819	5855	9085	-3230
1.अ.ख.5 निर्माण	1478	563	915	1098	891	207
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	903	593	310	926	613	313
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	2215	1267	948	1945	703	1242
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	341	4448	-4107	446	5352	-4906
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	42541	5215	37326	47932	6470	41462
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	23000	16625	6375	29511	15868	13643
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	1175	1249	-74	1210	1157	54
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	161	309	-147	134	323	-188
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	444	475	-31	334	345	-11
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	12689	23546	-10857	12174	25019	-12845
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	2137	978	1159	2130	1027	1103
1.आ.2 निवेश आय	8660	21944	-13284	8498	23345	-14846
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	3384	12672	-9288	3156	14533	-11377
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	70	2411	-2341	113	1815	-1702
1.आ.2.3 अन्य निवेश	1110	6641	-5531	1001	6826	-5825
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	4095	220	3876	4228	170	4058
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1892	624	1268	1545	647	898
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	29520	3185	26335	34048	3010	31038
1.इ.1 वित्तीय निगम, विरतैतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएस	29502	2904	26598	34028	2812	31216
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	28644	1989	26655	33162	2061	31101
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	857	914	-57	866	750	115
1.इ.2 सामान्य सरकार	18	281	-263	20	198	-178
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	185	150	35	177	577	-400
2.1 अनुत्पादित विरतैतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	4	45	-41	23	398	-374
2.2 पूंजी अंतरण	182	105	76	154	179	-26
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	264317	256501	7816	288913	285339	3574
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	23925	17701	6224	27222	21517	5705
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	22777	12171	10606	26607	12476	14131
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	21627	11673	9953	25294	12078	13217
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	16402	11673	4728	19418	12078	7340
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	5225		5225	5876		5876
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1151	498	653	1313	398	914
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1151	498	653	1313	398	914
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1147	5529	-4382	615	9041	-8426
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1147	4439	-3292	615	6636	-6021
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	1147	2728	-1580	615	4752	-4137
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		1712	-1712		1884	-1884
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1090	-1090	0	2405	-2405
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1090	-1090		2405	-2405
3.2 संविभाग निवेश	159844	158899	945	146339	144731	1608
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	159240	158343	897	145201	142720	2481
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	139824	140833	-1009	123636	118245	5391
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	19416	17510	1906	21565	24475	-2910
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	604	556	48	1138	2011	-872
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	6053	9666	-3613	5501	10588	-5087
3.4 अन्य निवेश	74496	65009	9487	109851	103996	5855
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	23547	19401	4146	23788	20164	3624
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रुपी कर्ज मूवमेंट, एनआरजी)	121	0	121	10	0	10
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	23426	19401	4025	23778	20164	3614
3.4.2.3 सामान्य सरकार			0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	29100	27475	1626	59721	59629	92
3.4.3अ भारत को ऋण	24956	23193	1763	23691	24465	-774
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	4144	4281	-137	36030	35163	866
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	47	133	-86	43	92	-49
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	15548	13321	2228	15453	14734	719
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	6253	4680	1574	10848	9378	1470
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0			0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	5226	-5226	0	4508	-4508
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए			0			0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए			0			0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	5226	-5226	0	4508	-4508
4. कुल आस्तियां / देयताएं	264317	256501	7816	288913	285339	3574
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	169302	167301	2001	156227	149648	6579
4.2 ऋण लिखत	88762	79295	9467	121838	121805	33
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	6253	9906	-3652	10848	13886	-3038
5. निवल भूल-घटक	795	0	795	0	823	-823

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिका

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़)

मद	अप्रै-जून 2024			अप्रै-जून 2025 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	2017436	2089564	-72128	2196412	2216528	-20117
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	1665317	1866568	-201251	1800981	1976740	-175759
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	927317	1459598	-532281	967474	1553197	-585723
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	926993	1389964	-462971	964221	1489154	-524933
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	324	0	324	3253	0	3253
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	69634	-69634	0	64043	-64043
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	738001	406970	331030	833507	423543	409964
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इन्पुट पर विनिर्माण सेवाएं	2234	183	2051	2162	341	1821
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	676	1983	-1307	654	2286	-1632
1.अ.ख.3 परिवहन	70959	71816	-856	65943	71818	-5876
1.अ.ख.4 यात्रा	61335	76511	-15177	50087	77720	-27633
1.अ.ख.5 निर्माण	12327	4693	7635	9390	7619	1771
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	7534	4950	2584	7924	5245	2679
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	18478	10572	7906	16636	6012	10624
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	2843	37103	-34261	3818	45787	-41969
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	354891	43507	311384	410065	55353	354712
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	191873	138694	53178	252469	135754	116715
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	9803	10418	-615	10353	9894	459
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	1346	2575	-1229	1148	2761	-1612
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	3703	3965	-262	2858	2953	-95
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	105857	196425	-90569	104148	214040	-109892
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	17829	8158	9670	18222	8785	9437
1.आ.2 निवेश आय	72241	183061	-110820	72705	199717	-127012
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	28232	105711	-77480	27000	124332	-97331
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	582	20112	-19530	969	15529	-14560
1.आ.2.3 अन्य निवेश	9262	55405	-46143	8563	58401	-49838
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	34166	1833	32333	36172	1455	34717
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	15787	5206	10581	13221	5537	7683
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	246262	26570	219692	291283	25749	265534
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	246112	24225	221887	291114	24053	267061
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	238960	16597	222364	283709	17634	266075
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	7151	7628	-477	7405	6419	986
1.इ.2 सामान्य सरकार	150	2345	-2195	168	1695	-1527
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	1547	1253	295	1515	4936	-3421
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तरण (जमा)	32	375	-343	199	3401	-3202
2.2 पूँजी अंतरण	1515	878	637	1316	1535	-219
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	2205020	2139817	65203	2471694	2441116	30578
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	199586	147666	51920	232886	184078	48808
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	190016	101538	88478	227624	106733	120892
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	180416	97382	83034	216395	103325	113069
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	136827	97382	39445	166121	103325	62795
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	43588	0	43588	50274	0	50274
3.1.अ.2 ऋण लिखत	9600	4156	5444	11230	3407	7822
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	9600	4156	5444	11230	3407	7822
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	9570	46128	-36558	5262	77345	-72084
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	9570	37033	-27463	5262	56770	-51509
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	9570	22755	-13184	5262	40654	-35392
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	14278	-14278	0	16116	-16116
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	9095	-9095	0	20575	-20575
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	9095	-9095	0	20575	-20575
3.2 संविभाग निवेश	1333471	1325590	7881	1251954	1238196	13759
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	1328434	1320949	7485	1242216	1220994	21223
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1166461	1174878	-8416	1057724	1011603	46121
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	161973	146071	15901	184493	209391	-24898
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	5037	4641	396	9738	17202	-7464
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	50493	80637	-30144	47060	90579	-43519
3.4 अन्य निवेश	621470	542327	79143	939793	889701	50093
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशिया	196437	161851	34586	203506	172503	31003
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रुपी कर्ज मूवमेंट, एनआरजी)	1011	0	1011	84	0	84
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	195426	161851	33575	203422	172503	30920
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	242762	229201	13561	510918	510131	787
3.4.3अ भारत को ऋण	208194	193487	14707	202679	209303	-6624
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	34569	35714	-1146	308239	300829	7410
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	396	1109	-714	366	783	-417
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	129710	111126	18583	132199	126052	6147
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	52166	39039	13127	92803	80231	12572
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	43597	-43597	0	38563	-38563
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	43597	-43597	0	38563	-38563
4. कुल आस्तियां / देयताएं	2205020	2139817	65203	2471694	2441116	30578
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	1412373	1395681	16693	1336545	1280262	56282
4.2 ऋण लिखत	740481	661501	78980	1042346	1042060	286
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	52166	82636	-30470	92803	118794	-25990
5. निवल भूल-शुद्ध	6630	0	6630	0	7040	-7040

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक।

सं. 42: भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन यूएस \$)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2024-25		2024				2025	
			मार्च		दिसं.		मार्च	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	270441	556812	242271	542952	260755	547104	270441	556812
1.1 इक्विटी पूंजी*	173559	521931	153343	511142	166493	512997	173559	521931
1.2 अन्य पूंजी	96882	34881	88927	31810	94262	34107	96882	34881
2. संविभाग निवेश	13763	272061	12469	277239	12173	276521	13763	272061
2.1 इक्विटी	8727	141938	10942	162061	9356	155573	8727	141938
2.2 ऋण	5036	130123	1527	115178	2817	120948	5036	130123
3. अन्य निवेश	186700	640384	132617	574786	170526	619693	186700	640384
3.1 व्यापार ऋण	33422	131203	33413	123722	33213	135606	33422	131203
3.2 ऋण	25891	250551	17547	221396	22523	240588	25891	250551
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	79332	167598	53519	154787	68630	165713	79332	167598
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	48055	91032	28138	74880	46160	77785	48055	91032
4. आरक्षित निधियाँ	668326		646419		635701		668326	
5. कुल आस्तियां/देयताएं	1139230	1469257	1033776	1394977	1079156	1443318	1139230	1469257
6. निवल आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)	-330027		-361201		-364162		-330027	

टिप्पणी: \* इक्विटी पूंजी में निवेश निधि और पुनर्निवेशित अर्जन का शेयर शामिल है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2024	2025		वि.व. 2024-25	2024	2025	
		जुला.	जून	जुला.		जुला.	जून	जुला.
		1	2	3	4	5	6	7
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	47.40	4.54	5.30	5.21	296218030	25280807	30959727	32781616
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.10.1 से 1.1.3)	17.87	1.71	1.77	1.63	185733719	17139102	17946468	19293299
1.1.1 आउटराइट	10.56	1.03	1.05	0.84	16056018	1524120	1611829	1274228
1.1.2 रेपो	4.72	0.44	0.51	0.55	77286611	7150905	7894091	8664018
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.58	0.23	0.21	0.24	92391091	8464077	8440549	9355053
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	28.06	2.71	3.39	3.48	100639565	7417106	11968143	12739681
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.46	0.12	0.14	0.10	9844746	724598	1045117	748636
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	3024.55	246.68	254.88	277.67	201387682	15970680	19012360	18863902
1.1 ग्राहक लेनदेन	3010.32	245.48	253.73	276.46	181153129	14531533	16983278	16624624
१.२ अंतरबैंक लेनदेन	14.23	1.19	1.15	1.21	20234553	1439147	2029082	2239279
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	2061014.91	161225.51	200519.84	212335.07	79781976	6480748	6957478	7319321
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.64	0.31	0.30	0.31	190	13	16	16
2.2 एपीबीएस \$	32964.43	2481.39	2841.94	2705.04	554034	28605	48247	42355
2.3 आईएमपीएस	56249.68	4902.84	4481.05	4821.90	7139110	593177	606356	631411
2.4 एनएसीएच जमा \$	16938.86	1479.29	1325.97	1628.20	1670223	132397	134188	143081
2.5 एनईएफटी	96198.05	8006.14	7920.52	8500.14	44361464	3662264	3764742	3993960
2.6 यूपीआई @	1858660.25	144355.54	183950.06	194679.48	26056955	2064292	2403931	2508498
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	17.24	1.40	1.18	1.59	185	15	21	31
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	21659.95	1734.76	1891.36	1912.72	2208583	175789	210754	217899
3.1 भीम आधार पे @	230.08	19.25	18.27	19.95	6907	575	615	619
3.2 एनएसीएच नामे \$	19762.28	1588.11	1728.39	1753.66	2199327	175014	209956	217102
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा ) @	1667.59	127.40	144.70	139.11	2349	200	183	179
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	63861.15	5294.35	5672.82	5982.42	2605110	217435	218552	231987
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	47740.76	3837.80	4587.10	4861.81	2109197	172670	183088	193849
4.1.1 पीओएस आधारित \$	24571.10	1970.94	2338.70	2432.75	795022	62284	67468	70380
4.1.2 अन्य \$	23169.66	1866.86	2248.41	2429.06	1314175	110386	115620	123469
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	16120.39	1456.56	1085.72	1120.61	495914	44765	35463	38138
4.2.1 पीओएस आधारित \$	11980.33	1068.58	812.90	832.19	332556	28600	23079	23921
4.2.2 अन्य \$	4140.06	387.98	272.82	288.42	163358	16165	12384	14216
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	70254.08	5356.71	6868.39	7124.06	216751	16327	20740	20758
5.1 वालेट	52898.40	4009.69	5338.82	5431.45	154066	11386	17308	16915
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	17355.68	1347.01	1529.57	1692.61	62686	4941	3432	3842
5.2.1 पीओएस आधारित \$	8240.14	713.97	595.05	660.66	11512	940	888	908
5.2.2 अन्य \$	9115.54	633.05	934.51	1031.95	51174	4001	2544	2935
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6095.38	531.00	447.43	494.59	7113350	610685	550176	607504
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6095.38	531.00	447.43	494.59	7113350	610685	550176	607504
6.2 अन्य	0.00	—	—	—	—	—	—	—
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2222885.46	174142.33	215399.84	227848.86	91925771	7500984	7957700	8397469
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2225910.01	174389.01	215654.72	228126.54	293313453	23471665	26970060	27261371
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2219814.63	173858.01	215207.29	227631.95	286200103	22860979	26419884	26653867

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2024	2025		वि.व. 2024-25	2024	2025	
		जुला.	जून	जुला.		जुला.	जून	जुला.
		1	2	3		6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)		1756976.91	138523.69	170640.11	180368.04	39206221	3141241	3467488
1.1 इंस्टाबैंक \$		110801.96	8897.45	9560.57	10205.70	7207439	584669	611428
1.2 अंतर-बैंक \$		1646174.95	129626.24	161079.54	170162.34	31998782	2556572	2856060
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)		47478.09	4305.75	3635.82	3987.57	131858133	10958678	12824960
2.1 अंतर्बैंक @		13056.37	1227.41	839.90	935.66	69086996	5820942	6918867
2.2 अंतर-बैंक @		34421.72	3078.34	2795.92	3051.90	62771136	5137737	5906093
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी \$ (3.1 से 3.3)		60308.11	5069.38	4382.08	4472.41	3063077	250318	229907
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$		97.25	8.54	6.28	6.63	5084	433	345
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$		59965.70	5040.14	4358.58	4447.66	3046987	248968	228735
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$		245.16	20.70	17.22	18.13	11005	917	827
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)		3.58	0.29	0.14	0.13	37	3	1
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$		3.33	0.27	0.11	0.11	35	3	1
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$		0.25	0.02	0.02	0.02	3	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @		11640.55	944.29	944.62	996.95	296622	23498	25646
1 एईपीएस @		11640.55	944.29	944.62	996.95	296622	23498	25646

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2025 तक	2024	2025	
		जुला.	जून	जुला.
		1	2	3
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)		11006.97	10677.71	11163.78
1.1 क्रेडिट कार्ड		1098.85	1045.68	1111.97
1.2 डेबिट कार्ड		9908.12	9632.02	10051.80
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)		13401.35	15211.55	13520.65
2.1 वॉलेट @		8678.44	11419.62	8681.92
2.2 कार्ड @		4722.91	3791.93	4838.73
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)		2.56	2.55	2.51
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम s		2.20	2.21	2.15
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम s		0.36	0.34	0.36
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @		14.82	14.78	14.59
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या		110.98	89.72	117.91
6 भारत क्यूआर @		67.18	61.87	67.21
7 यूपीआई क्यूआर *		6579.30	5851.14	6782.51

@: नवंबर 2019 से नया समावेश  
#: सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।  
\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।  
\* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल हैं।  
टिप्पणियाँ: 1. डेटा अंतिम हैं।  
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।  
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्यूलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।  
4. केवल पररेल वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन, फास्ट टैग लेनदेन, डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सचेंज कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।  
भाग I-ए. निपटान प्रणाली  
1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।  
भाग I-बी. भुगतान प्रणाली  
4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।  
4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।  
5. दिसंबर 2010 से उपलब्ध।  
5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल हैं।  
5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।  
6.1: तीन छिड़ों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।  
6.2: 'अन्य' में गैर-एनआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।  
भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल  
1: मोबाइल भुगतान -  
बैंकों के मोबाइल ऐस और यूपीआई ऐस के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।  
जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।  
2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।  
भाग II-बी. एटीएम  
3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।  
भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना  
3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

आवसरिक शृंखला

सं. 44 लघु बचत

(₹ करोड़)

प्रणाली		2023-24	2024		2025	
			फर.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	232460	14570	11133	12581	11379
	बकाया	1865029	1819758	1982465	1994553	2005585
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	161344	10025	8734	9178	8077
	बकाया	1298795	1268920	1395484	1404661	1412738
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	17229	1520	1090	2702	814
	बकाया	191692	218498	201999	204701	205515
1.1.2 सुकन्या समृद्धि योजना	प्राप्तियां	35174	2233	2244	2347	2282
	बकाया	157611	109222	177007	179354	181636
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	26696	1927	827	1279	1045
	बकाया	269007	267205	282142	283421	284466
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	38167	2153	1531	1922	1952
	बकाया	175472	173476	194605	196527	198479
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25341	2632	2125	2853	2108
	बकाया	305776	303000	330912	333764	335872
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	140423	138552	159174	161578	163358
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	11967	11730	14299	14476	14637
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	8932	8782	10308	10487	10645
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	144454	143936	147131	147223	147232
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	18713	-420	1025	-1831	-25
	बकाया	197134	195727	207269	205438	205413
1.1.9 डाक घर संचयी मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	8	-20	-108	-95	-100
	बकाया	1754	1444	1195	1100	1000
1.1.11 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन	प्राप्तियां	16	0	0	1	1
	बकाया	349	348	355	356	357
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	56069	3940	2226	3019	2858
	बकाया	418021	414597	438074	440601	443112
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	16853	1446	430	796	762
	बकाया	183905	180181	192621	193417	194179
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	20939	1428	1113	1376	1247
	बकाया	220560	219498	228707	230083	231330
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.7 एम.एस. प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	18277	1066	683	847	849
	बकाया	18277	17235	25303	26150	26999
1.2.8 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	-4721	-2317	-8557	-9049	-9396
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	15047	605	173	384	444
	बकाया	148213	136241	148907	149291	149735

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं, अर्थात सकल प्राप्तियों से सकल भुगतान को घटाने पर प्राप्त  
स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ



सं. 45 केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2024			2025	
	जून	सित.	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	10946860	11271589	11422728	11642652	11854200
1. वाणिज्यिक बैंक	37.52	37.55	37.98	36.18	35.28
2. सहकारी बैंक	1.42	1.35	1.36	1.29	1.29
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.70	0.77	0.65	0.76	0.59
4. बीमाकृत कंपनियां	26.11	25.95	26.14	25.81	25.95
5. म्यूच्युअल फंड	2.87	3.14	3.11	2.68	2.46
6. भविष्य निधियां	4.41	4.25	4.25	4.24	4.35
7. पेंशन निधि	4.74	4.86	5.05	4.91	4.96
8. वित्तीय संस्थाएं	0.57	0.63	0.64	0.71	0.74
9. कॉरपोरेट	1.44	1.60	1.45	1.49	1.26
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	2.34	2.80	2.81	3.12	2.80
11. भारतीय रिजर्व बैंक	11.92	11.16	10.55	12.78	14.21
12. अन्य	5.97	5.92	6.01	6.01	6.13
12.1 राज्य सरकार	2.13	2.19	2.21	2.25	2.29

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2024			2025	
	जून	सित.	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	5727482	5909490	6055711	6399564	6524417
1. वाणिज्यिक बैंक	33.85	34.39	35.11	35.40	35.54
2. सहकारी बैंक	3.38	3.29	3.22	3.08	3.02
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.59	0.60	0.53	0.61	0.60
4. बीमाकृत कंपनियां	25.85	25.56	25.16	24.07	24.12
5. म्यूच्युअल फंड	2.08	1.93	1.89	1.93	1.84
6. भविष्य निधियां	22.94	23.02	22.90	23.60	23.72
7. पेंशन निधि	4.87	4.87	4.82	5.07	4.96
8. वित्तीय संस्थाएं	1.58	1.57	1.58	1.48	1.59
9. कॉरपोरेट	2.03	1.95	1.97	2.05	1.93
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.05	0.04	0.03	0.05	0.02
11. भारतीय रिजर्व बैंक	0.62	0.60	0.58	0.55	0.54
12. अन्य	2.17	2.18	2.19	2.10	2.12
12.1 राज्य सरकार	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25

खजाना बिल					
श्रेणी	2024			2025	
	जून	सित.	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	858193	747242	760045	790381	784059
1. वाणिज्यिक बैंक	47.79	44.74	40.45	46.58	42.87
2. सहकारी बैंक	1.49	1.58	1.22	2.17	1.80
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	2.69	2.28	1.41	2.09	1.10
4. बीमाकृत कंपनियां	5.78	5.26	4.73	4.23	4.07
5. म्यूच्युअल फंड	14.50	15.06	15.41	16.15	15.72
6. भविष्य निधियां	0.60	0.26	0.04	0.20	0.09
7. पेंशन निधि	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
8. वित्तीय संस्थाएं	6.56	6.36	6.77	7.73	6.31
9. कॉरपोरेट	4.79	4.66	4.56	4.50	3.77
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.20	0.15	0.12	0.09	0.02
11. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. अन्य	15.59	19.65	25.29	16.23	24.26
12.1 राज्य सरकार	11.55	14.95	20.11	11.23	18.34

**टिप्पणियाँ :** (1) बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फार्मेट संशोधित किया है।  
(2) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों में विशेष प्रतिभूतियां और सॉवरेन गोल्ड बांड शामिल हैं।  
(3) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।  
(4) वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है।  
(5) अन्य श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।  
(6) सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (सं.अ.)	2024-25 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	5410887	6353359	7098451	7880522	9110725	9800798
1.1 विकास संबंधी	3074492	3823423	4189146	4701611	5514584	5862996
1.1.1 राजस्व	2446605	3150221	3255207	3574503	3965270	4195108
1.1.2 पूंजी	588233	550358	861777	1042159	1453849	1526993
1.1.3 ऋण	39654	122844	72163	84949	95464	140895
1.2 गैर-विकास संबंधी	2253027	2442941	2810388	3069896	3467270	3800321
1.2.1 राजस्व	2109629	2271637	2602750	2895864	3266628	3537378
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	955801	1060602	1226672	1377807	1562660	1711972
1.2.2 पूंजी	141457	169155	175519	171131	196073	259346
1.2.3 ऋण	1941	2148	32119	2902	4569	3597
1.3 अन्य	83368	86995	98916	109015	128871	137481
2. कुल प्राप्तियां	5734166	6397162	7156342	7855370	9054999	9650488
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3851563	3688030	4823821	5447913	6379349	7209647
2.1.1 कर प्राप्तियां	3231582	3193390	4160414	4809044	5456913	6142276
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	2012578	2076013	2626553	2865550	3248450	3631569
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	1216203	1114805	1530636	1939550	2204462	2506181
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	2800	2572	3225	3943	4001	4526
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	619981	494640	663407	638870	922436	1067371
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	31137	33448	35250	42975	49552	57273
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	110094	64994	44077	62716	86733	118239
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	59515	16951	27665	15970	55895	45125
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	50578	48044	16412	46746	30839	73114
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	1449230	2600335	2230553	2369892	2644642	2472912
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1440548	2530155	2194406	2332768	2619811	2456959
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	571872	890012	627255	687904	346483	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	190241	107493	350911	529	-257913	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	868676	1640143	1567151	1644864	2273328	...
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	8682	70180	36147	37124	24832	15952
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1440548	2530155	2194406	2332768	2619811	2456959
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	971378	1696012	1213169	1651076	1962969	1983757
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	209232	458801	526693	358764	434151	447511
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	38280	41273	28100	13880	21386	19857
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	10411	4545	42153	68803	52385	-33653
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	-14227	25682	42203	51989	35819	-10138
3ख.1.6 नकद शेष	-323279	-43802	-57891	25152	55726	150310
3ख.1.7 अन्य	548753	347643	399980	163104	57374	-100684
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	8682	70180	36147	37124	24832	15952
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल वितरण	26.9	32.0	30.1	29.2	30.8	30.0
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियां	28.5	32.2	30.3	29.1	30.7	29.6
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां	19.2	18.6	20.4	20.2	21.6	22.1
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियां	16.1	16.1	17.6	17.8	18.5	18.8
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल वित्तीय घाटा	7.2	13.1	9.5	8.8	9.0	7.6

... : उपलब्ध नहीं। सं.अ. संशोधित अनुमान, ब.अ. बजट अनुमान।

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।

टिप्पणियाँ : जीडीपी डेटा 2011-12 के आधार पर है। 2024-25 के लिए जीडीपी केन्द्रीय बजट 2024-25 से है।

डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

1 और 2: डेटा केंद्र सरकार (एनएसएसएफ को पुनर्भुगतान सहित) और राज्य सरकारों के निवल पुनर्भुगतान का है।

1.3: राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर और समनुदेशन का प्रतिनिधित्व करता है।

2: डेटा केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में निवल भिन्नता को दर्शाता है और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियां शामिल हैं।

3ए.1.1: आरबीआई रिकॉर्ड के अनुसार डेटा।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार।

3बी.1.2: राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवल निवेश को दर्शाता है।

नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण यह डेटा पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

3बी.1.7: ट्रेजरी बिल, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकद शेष निवेश खाता शामिल हैं।

**सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता**

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जुला. 2025 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	6012.90	31	765.83	13	701.57	1
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	474.28	7	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	313.77	1	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	411.89	21	140.27	5
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	37.45	7	74.81	7	-	-
11	झारखंड	677.06	9	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	1262.45	31	407.81	12	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	96.68	17	88.49	8	-	-
17	मेघालय	279.30	26	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	263.53	16	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	4774.33	31	1140.12	28	833.11	2
23	राजस्थान	2877.15	26	1313.80	3	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	5046.19	31	1750.66	28	1933.57	11
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	1022.48	23	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

**टिप्पणीयां:** 1) राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेष तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।  
2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्पकालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।  
3) राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।  
4) प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।  
5) -: नगण्य।

**स्रोत :** भारतीय रिज़र्व बैंक।

## सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जुला. 2025 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	11966	1181	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	3040	8	0	5350
3	असम	7730	94	0	0
4	बिहार	13890	-	0	19000
5	छत्तीसगढ़	8508	987	0	8268
6	गोवा	1164	473	0	0
7	गुजरात	15863	688	0	2000
8	हरियाणा	2706	1756	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	37	36	0	0
11	झारखंड	3094	-	0	780
12	कर्नाटक	20953	776	0	65925
13	केरल	3342	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1320	0	1500
15	महाराष्ट्र	73889	2221	0	0
16	मणिपुर	72	145	0	0
17	मेघालय	1320	112	0	0
18	मिज़ोरम	522	83	0	0
19	नगालैंड	1959	48	0	0
20	उड़ीसा	18946	2120	0	15636
21	पुदुचेरी	599	-	0	2050
22	पंजाब	10400	948	0	0
23	राजस्थान	2884	375	0	5750
24	तमिलनाडु	3567	-	0	968
25	तेलंगाना	8167	1790	0	0
26	त्रिपुरा	1361	31	0	0
27	उत्तराखंड	5865	315	0	0
28	उत्तरप्रदेश	16554	2914	0	15000
29	पश्चिम बंगाल	14311	1067	0	10000
	<b>कुल</b>	<b>252706</b>	<b>19487</b>	<b>0</b>	<b>152227</b>

**टिप्पणियाँ:** 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।  
2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।  
3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।

सं. 49: राज्य सरकारों की बाजार उधारियाँ

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य	2023-24		2024-25		2025-26						2025-26 में में अब तक ली गई कुल राशि	
		ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	मई		जून		जुला.		सकल	निवल
						ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	68400	55330	78205	57123	6822	4322	14000	13000	5600	3300	32172	25372
2	अरुणाचल प्रदेश	902	672	1010	704	-	-	-	-	-	-	-	-130
3	असम	18500	16000	19000	13850	2600	2600	-	-	1400	1400	4900	3950
4	बिहार	47612	29910	47546	30890	-	-	-	-	6000	6000	6000	6000
5	छत्तीसगढ़	32000	26213	24500	16913	1000	1000	1000	1000	-	-700	3970	3270
6	गोवा	2550	1560	1050	250	100	-50	100	100	100	-	300	-100
7	गुजरात	30500	11947	38200	16280	8500	4500	1500	300	3000	3000	13000	5240
8	हरियाणा	47500	28364	49500	31710	5000	3100	3000	425	3000	945	13000	6470
9	हिमाचल प्रदेश	8072	5856	7359	4725	-	-	800	800	1919	1919	4919	4269
10	जम्मू और कश्मीर	16337	13904	13170	11416	800	300	705	705	1100	600	3605	2605
11	झारखंड	1000	-2505	3500	-2005	-	-	-	-	-	-1000	-	-1000
12	कर्नाटक	81000	63003	92025	71525	-	-	-	-1000	-	-	-	-1000
13	केरल	42438	26638	53666	37966	5000	3500	5000	4000	5000	2500	17000	10000
14	मध्य प्रदेश	38500	26264	63400	47206	5000	5000	3277	2277	6800	5300	15077	12577
15	महाराष्ट्र	110000	79738	123000	90917	-	-3500	8000	6500	24000	21000	45500	37500
16	मणिपुर	1426	1076	1500	1037	750	750	-	-	250	100	1000	650
17	मेघालय	1364	912	1882	997	-	-	500	430	-	-50	850	630
18	मिज़ोरम	901	641	1169	939	-	-	125	50	100	100	225	150
19	नगालैंड	2551	2016	1550	950	-	-100	-	-100	-	-	-	-200
20	उड़ीसा	0	-4658	20780	17780	-	-	-	-	3000	3000	3000	3000
21	पुदुचेरी	1100	475	1600	880	-	-	200	200	-	-200	200	-
22	पंजाब	42386	29517	40828	32466	5500	4600	4500	2858	5000	4400	20800	16058
23	राजस्थान	73624	49718	75185	49479	8600	6600	9500	4938	5500	4000	29100	19038
24	सिक्किम	1916	1701	1951	1621	-	-	-	-	-	-	-	-
25	तमिलनाडु	113001	75970	123625	89894	7300	1300	13000	9750	7000	5500	31300	17550
26	तेलंगाना	49618	39385	56209	42199	4500	1152	8500	7200	8500	6000	25900	17752
27	त्रिपुरा	0	-550	0	-150	300	300	-	-	-	-200	800	600
28	उत्तरप्रदेश	97650	85335	45000	23185	3000	1000	-	-3233	3000	1000	9000	-2233
29	उत्तराखंड	6300	3800	10400	8000	-	-	1000	250	1000	1000	3000	2250
30	पश्चिम बंगाल	69910	48910	76500	54600	-	-1500	7500	6000	5500	4000	13000	7500
	कुल	1007058	717140	1073310	753345	64772	34874	82207	56449	96769	72914	297618	197767

- : शून्य।

टिप्पणी: 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देयताएं जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देयताओं के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

## सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2022-23				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	287802.7	297217.6	293954.9	451660.3	1330635.4
जीडीपी का प्रतिशत	4.4	4.6	4.3	6.4	4.9
I. वित्तीय आस्तियां	577822.4	632335.6	748109.7	968986.1	2927253.7
जीडीपी का प्रतिशत	8.9	9.8	11.0	13.6	10.9
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	185429.1	317361.2	280233.1	325852.7	1108876.2
(ए) बैंक जमाराशियां	163172.4	299532.7	256399.7	307866.8	1026971.5
i. वाणिज्यिक बैंक	158613.3	300565.0	248459.8	284968.0	992606.2
ii. सहकारी बैंक	4559.0	-1032.4	7939.8	22898.9	34365.3
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22256.8	17828.6	23833.5	17985.9	81904.7
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	6504.8	2076.7	8081.6	2234.0	18897.1
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	4230.6	3267.2	3246.9	3945.8	14690.4
ii. आवास वित्त कंपनियां	2274.2	-1190.5	4834.7	-1711.8	4206.6
2. जीवन बीमा निधियाँ	73357.5	151737.1	167581.7	156268.5	548944.9
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ सहित)	146719.1	118171.9	136388.4	216513.6	617793.1
4. मुद्रा	66438.9	-54579.3	76760.1	148990.1	237609.7
5. निवेश	51502.6	48530.1	49778.6	64150.6	213961.9
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	35443.5	44484.0	40205.9	58954.5	179087.8
(बी) इक्विटी	13560.9	1378.2	6434.1	1664.9	23038.1
6. अल्प बचत (पीपीएफ छोड़ कर)	54375.1	51114.5	37367.7	57210.6	200068.0
II. वित्तीय देयताएँ	290019.7	335118.0	454154.8	517325.8	1596618.3
जीडीपी का प्रतिशत	4.5	5.2	6.7	7.3	5.9
ऋण/उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	289781.5	334879.7	453916.6	517087.5	1595665.3
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	234235.0	263450.2	370782.9	383843.2	1252311.4
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	230283.8	261265.3	368304.6	331291.0	1191144.8
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	55546.4	71429.5	83133.7	133244.3	343353.9
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	30531.7	36650.3	55791.7	94565.3	217539.1
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	22336.7	33031.2	24903.3	36745.8	117017.0
iii. बीमा कंपनियाँ	2678.0	1747.9	2438.7	1933.2	8797.8
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	33.7	33.7	33.7	33.7	135.0
3. सामान्य सरकार	204.5	204.5	204.5	204.5	818.0

## सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2023-24				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	349607.1	283994.4	294431.6	666547.4	1594580.4
जीडीपी का प्रतिशत	4.8	3.9	3.8	8.4	5.3
I. वित्तीय आस्तियां	671244.1	810128.8	805066.2	1187279.1	3473718.2
जीडीपी का प्रतिशत	9.3	11.2	10.4	14.9	11.5
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	266680.3	407948.0	296931.3	406706.9	1378266.4
(ए) बैंक जमाराशियां	253004.1	501768.5	277432.0	390720.4	1422924.9
i. वाणिज्यिक बैंक	243833.9	502260.7	280096.7	383460.6	1409651.9
ii. सहकारी बैंक	9170.2	-492.2	-2664.7	7259.8	13273.0
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	13676.2	-93820.5	19499.4	15986.5	-44658.5
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	-485.4	-107982.1	5337.7	1824.9	-101304.9
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	6119.3	4782.3	4895.8	1942.9	17740.3
ii. आवास वित्त कंपनियां	-6604.7	-112764.4	441.9	-118.0	-119045.2
2. जीवन बीमा निधियाँ	157301.9	140356.8	160135.2	189267.6	647061.4
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ सहित)	163686.0	148356.1	153435.1	253882.9	719360.2
4. मुद्रा	-48636.2	-36700.8	56719.0	146643.8	118025.7
5. निवेश	41014.3	72664.6	79238.2	108336.6	301253.8
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	32085.6	55768.8	60134.6	90973.0	238962.1
(बी) इक्विटी	3756.7	7146.3	9941.1	8236.1	29080.1
6. अल्प बचत (पीपीएफ छोड़ कर)	91197.8	77504.1	58607.4	82441.4	309750.7
II. वित्तीय देयताएँ	321637.1	526134.4	510634.6	520731.7	1879137.8
जीडीपी का प्रतिशत	4.5	7.3	6.6	6.5	6.2
ऋण/उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	321519.8	526016.2	510516.4	520613.5	1878665.8
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	213606.3	868873.9	402647.1	392330.5	1877457.7
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	208026.5	875654.0	389898.0	382557.9	1856136.4
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	107913.6	-342857.7	107869.2	128283.0	1208.0
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	81448.8	59683.7	85031.8	100836.5	327000.7
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	23784.0	-404294.0	21233.4	25852.9	-333423.7
iii. बीमा कंपनियाँ	2680.7	1752.6	1604.0	1593.6	7631.0
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	33.7	34.7	34.7	34.7	138.0
3. सामान्य सरकार	83.5	83.5	83.5	83.5	334.0



सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2024-25				वार्षिक
	ति1	ति2	ति3	ति4	
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	551994.2	496676.1	271043.1	674489.0	1994202.4
जीडीपी का प्रतिशत	7.0	6.3	3.2	7.6	6.0
I. वित्तीय आस्तियां	840665.3	901135.4	689663.5	1129381.1	3560845.4
जीडीपी का प्रतिशत	10.6	11.5	8.1	12.8	10.8
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	274567.9	403591.4	158320.8	418183.6	1254663.6
(ए) बैंक जमाराशियां	254885.4	388328.6	141290.0	401577.5	1186081.4
i. वाणिज्यिक बैंक	251171.1	389734.0	147864.7	395337.4	1184107.2
ii. सहकारी बैंक	3714.3	-1405.4	-6574.7	6240.0	1974.2
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	19682.4	15262.8	17030.8	16606.1	68582.2
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	7461.4	3041.8	4809.8	4385.1	19698.2
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	6289.7	3230.0	4444.5	4220.0	18184.2
ii. आवास वित्त कंपनियां	1171.7	-188.2	365.4	165.1	1514.0
2. जीवन बीमा निधियाँ	175427.0	178835.2	90159.4	90393.0	534814.6
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	170218.2	170219.6	170758.3	281332.6	792528.6
4. मुद्रा	34212.5	-57615.2	70840.8	162236.1	209674.1
5. निवेश	120638.2	152637.1	159255.2	103720.8	536251.4
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	106987.0	137618.0	124132.0	97193.0	465930.0
(बी) इक्विटी	14448.0	15645.0	36063.1	7410.3	73566.5
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	65601.6	53467.4	40329.0	73515.0	232913.0
II. वित्तीय देयताएँ	288671.1	404459.3	418620.4	454892.1	1566642.9
जीडीपी का प्रतिशत	3.7	5.2	4.9	5.2	4.7
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	288492.4	404280.6	418441.7	454713.3	1565928.0
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	205040.4	322147.7	319626.6	387045.6	1233860.3
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	208525.3	321241.4	302569.3	379856.5	1212192.4
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	83452.0	82132.9	98815.0	67667.7	332067.7
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	65813.7	65488.7	75764.5	39833.9	246900.8
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	15125.2	14233.6	20561.4	25756.8	75677.0
iii. बीमा कंपनियाँ	2513.1	2410.7	2489.1	2077.1	9489.9
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	34.7	34.7	34.7	34.7	139.0
3. सामान्य सरकार	144.0	144.0	144.0	144.0	576.0

टिप्पणियां: 1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत से तात्पर्य निवल वित्तीय आस्तियों से है, जिन्हें वित्तीय आस्ति और देयताओं के प्रवाह के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है।  
2. 2024-25 के लिए प्रारंभिक अनुमान और 2022-23 और 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान।  
3. एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, 2024-25 के पहले संशोधित अनुमान जारी होने के साथ 2024-25 के प्रारंभिक अनुमानों में संशोधन किया जाएगा।  
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ, सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं।  
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

## 50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2022	सितं-2022	दिसं-2022	मार्च-2023
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	25621348.1	26423992.1	27187715.6	27844981.1
जीडीपी का प्रतिशत	102.8	102.6	103.3	103.5
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	11843527.1	12143059.7	12399459.4	12707326.2
i. वाणिज्यिक बैंक	10987692.1	11288257.2	11536717.0	11821685.0
ii. सहकारी बैंक	855834.9	854802.6	862742.4	885641.2
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	216170.0	218246.7	226328.2	228562.2
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	74794.2	78061.4	81308.3	85254.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	141375.8	140185.3	145020.0	143308.2
(सी) जीवन बीमा निधि	5325967.3	5559681.9	5786592.6	5795430.6
(डी) मुद्रा	2950343.2	2895763.9	2972524.0	3121514.1
(ई) म्यूचुअल फंड	2048097.3	2260209.7	2355315.8	2367792.5
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	851913.4	858591.1	864730.6	939449.0
(जी) पेंशन निधि	744459.2	796454.0	853412.0	898343.0
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	1640870.6	1691985.1	1729352.9	1786563.5
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	8911860.9	9246740.6	9700657.2	10217744.7
जीडीपी का प्रतिशत	35.8	35.9	36.9	38.0
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	7095467.7	7358918.0	7729700.9	8113544.1
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	6620073.1	6881338.5	7249643.0	7580934.1
ii. सहकारी बैंक	473897.0	476024.8	478486.9	530915.0
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1816393.1	1887822.6	1970956.3	2104200.7
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	869174.9	905825.3	961617.0	1056182.3
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	835181.3	868212.5	893115.8	929861.7
iii. बीमा निगम	112036.9	113784.8	116223.5	118156.7

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

	जून-2023	सितं-2023	दिसं-2023	मार्च-2024
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	28754605.9	29637615.0	30737884.8	32025210.0
जीडीपी का प्रतिशत	104.2	104.4	105.0	106.3
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	12960330.3	13462098.8	13739530.7	14130251.1
i. वाणिज्यिक बैंक	12065518.9	12567779.6	12847876.2	13231336.9
ii. सहकारी बैंक	894811.4	894319.2	891654.5	898914.3
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	228076.8	120094.7	125432.4	127257.3
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	91373.3	96155.6	101051.4	102994.3
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	136703.5	23939.1	24381.0	24263.0
(सी) जीवन बीमा निधि	6064436.9	6255801.1	6553726.0	6820611.8
(डी) मुद्रा	3072877.9	3036177.0	3092896.0	3239539.8
(ई) म्यूचुअल फंड	2626046.1	2829859.3	3156299.3	3387208.3
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	955060.6	960343.6	964851.5	1051376.5
(जी) पेंशन निधि	970016.0	1017975.0	1091276.0	1172651.0
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	1877761.2	1955265.4	2013872.8	2096314.2
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	10539264.5	11065280.7	11575797.1	12096410.5
जीडीपी का प्रतिशत	38.2	39.0	39.6	40.2
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	8327150.3	9196024.2	9598671.3	9991001.8
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	7788960.6	8664614.6	9054512.6	9437070.5
ii. सहकारी बैंक	536409.2	529527.7	542240.6	551852.1
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	2212114.2	1869256.5	1977125.7	2105408.7
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1137631.1	1197314.8	1282346.6	1383183.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	953645.7	549351.7	570585.1	596438.0
iii. बीमा निगम	120837.4	122590.0	124194.0	125787.7

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2024	सितं-2024	दिसं-2024	मार्च-2025
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	33253098.6	34421189.5	34532805.6	35264710.9
जीडीपी का प्रतिशत	107.9	109.6	107.2	106.6
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	14385136.5	14773465.1	14914755.1	15316332.6
i. वाणिज्यिक बैंक	13482508.0	13872242.0	14020106.6	14415444.1
ii. सहकारी बैंक	902628.6	901223.2	894648.5	900888.5
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	134718.7	137760.5	142570.3	146955.5
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	109284.0	112514.0	116958.5	121178.5
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	25434.7	25246.5	25611.9	25777.0
(सी) जीवन बीमा निधि	7123527.6	7385938.1	7272871.3	7293099.1
(डी) मुद्रा	3273752.3	3216137.1	3286977.8	3449213.9
(ई) म्यूचुअल फंड	3866386.1	4291914.4	4224091.7	4128924.5
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	1059829.5	1063056.1	1064212.0	1157449.2
(जी) पेंशन निधि	1247832.0	1337535.0	1371615.0	1443509.0
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	2161915.8	2215383.2	2255712.2	2329227.2
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	12384902.9	12789183.5	13207625.1	13662338.5
जीडीपी का प्रतिशत	40.2	40.7	41.0	41.3
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	10196042.2	10518189.9	10837816.5	11224862.1
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	9645595.7	9966837.1	10269406.4	10649262.8
ii. सहकारी बैंक	548284.4	549069.4	566104.4	573131.8
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	2188860.7	2270993.6	2369808.7	2437476.4
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1448996.8	1514485.5	1590250.0	1630083.9
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	611563.2	625796.8	646358.2	672115.0
iii. बीमा निगम	128300.7	130711.4	133200.5	135277.5

टिप्पणियाँ: 1. जीडीपी के अनुपात के रूप में डेटा की गणना एनएसओ द्वारा 30 मई 2025 को जारी राष्ट्रीय आय 2024-25 के अनंतिम अनुमान के आधार पर की गई है।  
2. पेंशन निधि में राष्ट्रीय पेंशन योजना की निधि शामिल है।  
3. लघु बचत के साथ बकाया जमा राशि भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक से प्राप्त की जाती है।  
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं। बकाया जमाराशियों के लिए आंकड़े केवल अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध हैं।  
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

## वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

### सारणी सं. 1

- 1.2 और 6 : वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।  
 3.5 और 3.7 : वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।  
 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।  
 4.5, 4.6 और 4.7 : माह / वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।  
 4.10 से 4.12 : माह/ वित्त वर्ष के अंतिम नीलामी दिन से संबंधित है।  
 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।  
 7.1 और 7.2 : यूएस डॉलर में विदेशी व्यापार से संबंधित है।

### सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।  
 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियाँ और अल्पावधि प्रतिभूतियाँ / बॉण्ड जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी, शामिल है।

### सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया वायदा संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

### सारणी सं. 5

अन्य अर्थात् एक्सिम बैंक को विशेष पुनर्वित्त सुविधा 31 मार्च 2013 से बंद है।

### सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।  
 1.1: संचलन में मौजूद नोटों में सीबीडीसी-खुदरा (आर) और सीबीडीसी-थोक (डब्ल्यू) शामिल हैं।  
 1.4: बैंकों द्वारा धारित नकदी में सीबीडीसी-डब्ल्यू शामिल है।  
 2.2 : आईएमएफ खाता सं. 1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

### सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4 : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्ड शामिल हैं।

### सारणी सं. 8

- एनएम<sub>2</sub> और एनएम<sub>3</sub> में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।  
 2.4 : चुकता पूंजी और आरक्षित राशियां शामिल हैं।  
 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

### सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।  
 एल<sub>1</sub> और एल<sub>2</sub> मासिक आधार पर और एल<sub>3</sub> तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।  
 जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

### सारणी सं. 13

कॉलम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़े अंतिम और कॉलम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

#### सारणी सं. 14

कॉलम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

#### सारणी सं. 17

2.1.1 : राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

4: आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

#### सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

#### सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1 : बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2 : संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

#### सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

#### सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं / शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेनों से संबंधित है। हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

#### सारणी सं. 35

1.10 : पत्र-पत्रिकाओं के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

#### सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि और विपरीत क्रम का संकेतक है। 6- मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2022-23 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतित किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित हैं। नीर/रीर सूचकांकों के संकलन के लिए प्रयुक्त कार्यप्रणाली का ब्योरा आरबीआई बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में उपलब्ध है।

#### सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

**सारणी सं. 38, 39, 40 और 41**

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

**सारणी सं. 43****भाग I-ए. भुगतान प्रणाली**

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रि-पक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर 2018 से किया गया है।

**भाग II-बी भुगतान प्रणाली**

4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से किए गए डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: वॉलेट के माध्यम से माल और सेवाओं की खरीद और निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेनों के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै से संबंधित।

6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल हैं। जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृह से संबंधित है।

**भाग II-ए अन्य भुगतान चैनल**

1 : मोबाइल भुगतान -

○ इसमें बैंकों के मोबाइल ऐप और यूपीआई ऐप के जरिए किए गए लेनदेन शामिल हैं।

○ जुलाई 2017 के बाद के डेटा में मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत किए गए केवल व्यक्तिगत भुगतान और कॉरपोरेट भुगतान शामिल हैं। मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए, अन्य कॉरपोरेट भुगतान शामिल नहीं हैं।

2 : इंटरनेट भुगतान - 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

**भाग II-बी. एटीएम**

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

**भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना**

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

**सारणी सं. 45**

(-): शून्य/ नगण्य को दर्शाता है।

बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फॉर्मेट संशोधित किया है।

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में विशेष प्रतिभूतियाँ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड शामिल हैं।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉन्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है।

'अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।

सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।



#### सारणी सं. 46

जीडीपी डेटा वर्ष 2011-12 के आधार पर आधारित है। वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2023-24 से ली गई है। डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनः चुकौती सहित) और राज्य सरकार की निवल चुकौती से संबंधित हैं।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डेटा केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।

3बी. 1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में किए गए निवल निवेश को दर्शाते हैं।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी. 1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी. 1.7: खजाना बिल, वित्तीय संस्थानों से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकदी शेष निवेश खाता सहित।

#### सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्पकालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ / डब्ल्यूएमए / ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

--: नगण्य।

#### सारणी सं. 48

समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी के लिए अवधारणाएं और कार्यप्रणाली आरबीआई मासिक बुलेटिन की वर्तमान सांख्यिकी के लिए व्यापक मार्गदर्शिका में उपलब्ध हैं (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>)

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का समय शृंखला डेटा <https://data.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत व्याख्यात्मक नोट आरबीआई द्वारा जारी प्रासंगिक प्रेस प्रकाशनियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों/विज्ञप्तियों जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका में उपलब्ध हैं।

**भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन**

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2025	₹350 एक प्रति ₹250 एक प्रति (रियायती दर*) ₹4,000 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,000 (एक वर्ष रियायती दर*)	15 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति 150 अमेरिकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2024-25	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2024-25 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2023-24	₹575 एक प्रति (काउंटर पर) ₹625 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	22 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 45, सं. 1, 2024	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. पंचायती राज संस्थाओं का वित्त	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
8. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24	आरबीआई बुलेटिन जनवरी, 2025 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
9. वार्षिक रिपोर्ट 2024-25	आरबीआई बुलेटिन जून, 2025 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
10. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट-जून 2025	आरबीआई बुलेटिन जुलाई, 2025 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
11. मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अप्रैल 2025	आरबीआई बुलेटिन अप्रैल 2025 में शामिल है।	
12. नगर निगम वित्त पर रिपोर्ट - नवंबर 2024	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
13. बैंकिंग शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी)	₹100 एक प्रति (काउंटर पर) ₹150 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	

**टिप्पणियां:**

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)) पर उपलब्ध हैं।
  - टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<https://data.rbi.org.in>)।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-2008 (5 खंड), भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- \* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक / शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

## हाल के प्रकाशन

### सामान्य अनुदेश

1. सभी संचार निम्न को संबोधित किए जाएँ:  
निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग,  
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीआरकेडी, डीईपीआर),  
भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन, तल मंजिल,  
सर पी. एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स सं. 1036. मुंबई- 400 001  
टेलीफोन: 022-2260 3000 विस्तार: 4002, ईमेल: [spsdepr@rbi.org.in](mailto:spsdepr@rbi.org.in)
2. बिक्री के लिए प्रकाशन प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) उपलब्ध हैं।
3. प्रकाशनों को कैश ऑन डिलीवरी के आधार पर नहीं दिया जाएगा।
4. एक बार बेचे गए प्रकाशनों को वापस नहीं लिया जाएगा।
5. प्रकाशन के पिछले अंक आम तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं।
6. जहां रियायती मूल्य का संकेत नहीं दिया गया है, भारत में छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक/ अकादमिक संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है, बशर्ते पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
7. सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए एनईएफटी को प्राथमिकता दी जाए और भुगतानकर्ता के नाम, सदस्यता संख्या (यदि कोई हो), खाता संख्या, तारीख और राशि सहित लेनदेन विवरण [spsdepr@rbi.org.in](mailto:spsdepr@rbi.org.in) पर ईमेल किया जाए या डाक द्वारा भेजा जाए।

ए. एनईएफटी ट्रांसफर के लिए अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा और पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाता प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19

बी. गैर- डिजिटल मोड के माध्यम से सदस्यता के मामले में, कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के नाम पर मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/ चेक भेजें।

8. 'प्रकाशन प्राप्त न होने' संबंधी शिकायतें दो माह की अवधि के अंदर भेजी जाएं।